DR. M. MOHAN RAO
IAS (Retd)
CHAIRMAN

M. ARUNA MOHAN RAO
IPS (Retd)
DIRECTOR (ACADEMICS)

RAO'S ACADEMY
for Competitive Exams
(A unit of RACE)

विजनेस के लिए ढूंढ रहे हो दूकान
Bharat emart
पर मिलेगा हर समाधान

जून–2023

करेन्ट अफेयर्स मैगजीन

RAO'S ACADEMY
for Competitive Exams

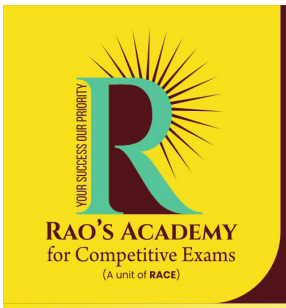

RAO'S ACADEMY
for Competitive Exams

BHOPAL | INDORE

Offering UPSC & MPPSC Courses

Both in English & Hindi Medium

Best faculties in their field of expertise

In - house Content team

Daily News Review

Monthly Current Affairs Magazine

Officers Mentorship Program

Crash Course and Intensive Test Series for Prelims 2023

EMAIL: office@raosacademy.in | WEBSITE: www.raosacademy.in

Bhopal Branch: Plot No. 132, Near Pragati Petrol Pump, Zone II, M.P. Nagar, Bhopal(M.P.) 462011
95222 05553 , 95222 05554

Indore Branch: 10,Vishnupuri, A.B.Road, Near Medi-Square Hospital Bhawar Kuwar Square, Indore (M.P.)-452001
95222 05551, 95222 05552

जून - 2023

करंट अफेयर मैगज़ीन

विषय सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
Contents	**Pg. No.**
कला एवं संस्कृति	**1-5**
इनटैक (INTACH)	
तुंगनाथ तीर्थ	
महाराणा प्रताप जयंती	
चाम नृत्य	
सेंगोल	
तिरुक्कुरल	
राजनीति और शासन	**6-16**
धर्म की स्वतंत्रता	
तलाक	
राजद्रोह कानून	
आदर्श आचार संहिता	
अनुच्छेद 355	
चलने का अधिकार	
व्हिप/ सचेतक	
इंटरनेट शटडाउन	
आदर्श कारागार अधिनियम	
फोरम शॉपिंग	
पर्यावरण और पारिस्थितिकी	**17-31**
नागरिक उड्डयन में अंतर्राष्ट्रीय जलवायु कार्रवाई	
हूज़ टिपिंग द स्केल (Who's tipping the scales)	
जलवायु वित्त कार्यक्रम	
सीमा पार सहयोग	
कोल एक्शन प्लान 2023 -24	
एल नीनो	
मध्य एशियाई फ्लाईवे	
गोवा के जंगल में आग	
विश्व जैव विविधता दिवस 2023	
गहरा महासागर मिशन	
रणथंभौर टाइगर रिजर्व (RTR)	

जाल
वन्य जीवन संरक्षण (WLP) अधिनियम, 1972
होमो सेपियन्स पदचिह्न
संवर्धित रॉक वेदरिंग
संपन्न: बदलती जलवायु में शहरों को हरा-भरा, लचीला और समावेशी बनाना
लोगों की जैव विविधता रजिस्टर

अर्थव्यवस्था **32-43**

सामान्य रिपोर्टिंग मानक
बिजनेस रेडी प्रोजेक्ट
मुद्रा और वित्त
भारत ने उत्पादों पर अनिवार्य प्रमाणीकरण लागू कर दिया है
भारत ने धन शोधन रोधी कानून में संशोधन किया
पब्लिक स्टॉकहोल्डिंग
ट्रांज़िशन बांड
पेट्रोलियम मंत्रालय ने ऊर्जा संक्रमण सलाहकार समिति की रिपोर्ट प्राप्त की
भारत का कृषि निर्यात
वित्त मंत्री ने FSDC की 27वीं बैठक की अध्यक्षता की।
एक्सचेंज ट्रेडेड कमोडिटी डेरिवेटिव्स (ETCDs)
भारतीय रिजर्व बैंक
ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस
RBI ने 2,000 रुपये के नोट वापस ले लिए

विज्ञान और तकनीक **44-59**

नीति आयोग
ट्रांस-फैट उन्मूलन
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्ट
क्लिनिकल परीक्षण
अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी जागरूकता प्रशिक्षण (START)
Android मैलवेयर
इथेनॉल सम्मिश्रण
जेम्स वेब टेलीस्कोप
वाटसनएक्स
तीन लोगों से बच्चा
रोबोटिक्स फ्रेमवर्क
LIGO-भारत परियोजना
CEIR
शनि ग्रह
अभिगृहीत मिशन-2
हिमालय चंद्र टेलीस्कोप
सुपर कंप्यूटर

सामाजिक मुद्दे **60-68**

दीमा हसाओ शांति संधि
एनडीपीएस
अंग दान
यौन उत्पीड़न
COVID-19

बाल विवाह
मातृ और नवजात मृत्यु
एसडीजी
7वां संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह

अंतर्राष्ट्रीय सम्बन्ध **69-78**

स्वदेशी मुद्दों पर संयुक्त राष्ट्र स्थायी मंच (UNPFII)
इक्वाडोर, नाइजीरिया, पनामा और भारत
भारत-संयुक्त अरब अमीरात
विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023
कलादान परियोजना
शटल कूटनीति
अफ्रीका और मध्य पूर्व में भारत
हिंद महासागर सम्मेलन (IOC)
शंघाई सहयोग संगठन
फिलिस्तीनी
हिरोशिमा शिखर सम्मेलन
FIPIC शिखर सम्मेलन

सरकारी योजना **79-87**

संशोधित CGTMSE योजना
विवाद से विश्वास I- MSME योजना के लिए राहत
कृषि मैपर ऐप
सामाजिक सुरक्षा योजनाएं
थैलेसीमिया बाल सेवा योजना
भारत E-MART
स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण
पोशन भी, पढाई भी
मिशन अमृत सरोवर
Saksham
एक स्टेशन एक उत्पाद
पारख
उड़ान 5.1

विविध **88-96**

जॉब्स रिपोर्ट 2023 का भविष्य
थर्मोबैरिक बम
गैलेंट्री पुरस्कार
हरित सागर
पोखरण द्वितीय
युवा प्रतिभा
बाओबाब के पेड़
डेटा शासन गुणवत्ता सूचकांक (DGQI)
प्रवासन के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन
1: अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में नवाचार

योजना जून 2023: टेकाडे **97-106**

2: स्टार्टअप्स- भारत की विकास गाथा में क्रांतिकारी बदलाव

3: भारत के एडटेक क्षेत्र की क्षमता
4: स्वास्थ्य सेवा में बदलाव के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना
5: क्वांटम कंप्यूटिंग-ट्रांसफॉर्मिंग टेक्नोलॉजी
6: AI चैटबॉट्स-भविष्य और चुनौतियां
7: 5G साइबर सुरक्षा चुनौतियाँ
8: डिजिटल प्रकाशन- क्षितिज का विस्तार करना
9: शहरी नियोजन में प्रौद्योगिकी का उपयोग

कुरुक्षेत्र जून 2023 : ग्रामीण शिल्प **107-112**

1: ग्रामीण शिल्प की क्षमता
2: अनुष्ठानिक और स्वदेशी परंपराओं के माध्यम से ग्रामीण शिल्प
3: बाँस पर बड़ा दाँव लगाना
4: जम्मू-कश्मीर हस्तशिल्प क्षेत्र की बदलती गतिशीलता
5: आजीविका के लिए ग्रामीण शिल्प
6: एक जनपद एक उत्पाद के माध्यम से ग्रामीण शिल्प को बढ़ावा देना
7: हथकरघा और हस्तशिल्प क्षेत्र का संवर्धन और विकास

1 कला एवं संस्कृति

इनटैक (INTACH)

खबरों में क्यों

रेल मंत्री ने ओडिशा के परलाखेमुंडी स्टेशन को हेरिटेज टैग देने का आग्रह किया

महत्वपूर्ण बिंदु

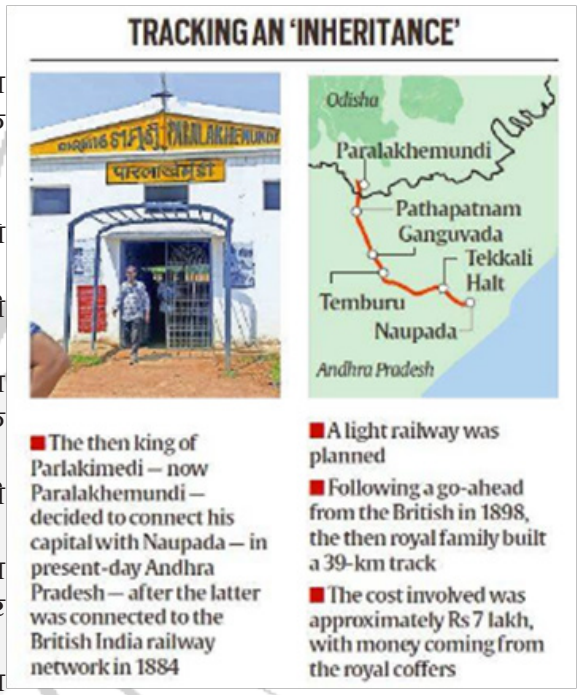

- इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज (INTACH), ओडिशा ने रेल मंत्री को पत्र लिखकर राज्य के सबसे पुराने स्टेशनों में से एक परलाखेमुंडी रेलवे स्टेशन के लिए हेरिटेज टैग की मांग की है।
- ट्रस्ट ने उनसे पुराने स्टेशन भवन को न गिराने का आग्रह किया।
- परलाखेमुंडी के महाराजाओं ने वर्ष 1899-1900 में परलाकिमेडी लाइट रेलवे (PLR) की शुरुआत की थी।
- पराालाखेमुंडी के तत्कालीन महाराजा ने 1 अप्रैल, 1900 को अपनी राजधानी पराालाखेमुंडी को नौपाड़ा से जोड़ने वाली 39 किमी लंबी लाइन खोली थी।
- बनने वाली वर्तमान नई इमारत एक ऊंचे मंच पर है और मौजूदा विरासत संरचना को ढक लेती है। यह अभी भी बहुत अच्छी स्थिति में है और इसके जीर्णोद्धार के लिए ज्यादा काम की जरूरत नहीं है।
- पराालाखेमुंडी और अयोध्या से एक ट्रेन "महेंद्रगिरी एक्सप्रेस" चलाई जानी चाहिए जो जिले में पर्यटन और तीर्थयात्रा को बढ़ावा देगी।
- PLR (पैरालाकिमेडी लाइट रेलवे) के कम से कम दो मूल हेरिटेज लोकोमोटिव को वापस लाया जाना चाहिए और हेरिटेज रेलवे स्टेशन पर ठीक से स्थापित किया जाना चाहिए।
- उन्होंने कहा कि 1899 में निर्मित लकड़ी की बॉडी वाली रॉयल कैरिज जिसका उपयोग पराालाखेमुंडी के रॉयल्टी द्वारा किया गया था, जिसे नागपुर में नैरो गेज रेलवे संग्रहालय में रखा गया है, उसे भी स्टेशन पर प्रदर्शन के लिए वापस लाया जाना चाहिए।
- PLR से संबंधित कई अन्य कलाकृतियां हैं जो नागपुर संग्रहालय में रखी गई हैं। इनमें सिग्नलिंग उपकरण, बिजली के उपकरण, तराजू, वर्दी, प्रतीक चिन्ह, जर्मन चांदी के कटलरी, शाही अलंकरण आदि शामिल हैं। ये सभी वापस आ जाने चाहिए।
- स्टेशन मास्टर की पुरानी इमारत, जो जीर्णोद्धार की स्थिति में है, को PLR और वहां प्रदर्शित सभी वस्तुओं के संग्रहालय में परिवर्तित किया जाना चाहिए।
- एक उचित कला और फोटोग्राफ गैलरी स्थापित की जानी चाहिए। यह दुनिया भर के पर्यटकों और रेल प्रेमियों के लिए एक प्रमुख आकर्षण होगा।
- पुल, पुलिया सहित PLR के रास्ते के कई स्टेशन। विरासत संरचनाओं के रूप में संरक्षित किया जाना चाहिए।
- परलाखेमुंडी स्टेशन पर गुड्स शेड एक अद्वितीय विरासत संरचना है जिसे संरक्षण की आवश्यकता है।
- INTACH ने अनुरोध किया है कि रेलवे के इतिहास के इस टुकड़े को ठीक से संरक्षित और हाइलाइट किया जाना चाहिए।

INTACH के बारे में

- यह सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत एक गैर-लाभकारी धर्मार्थ संगठन है।
- इसका मिशन विरासत को संरक्षित करना है। 2007 में, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद ने INTACH को विशेष सलाहकार का दर्जा दिया।

तुंगनाथ तीर्थ

खबरों में क्यों

पांडवों द्वारा निर्मित तुंगनाथ मंदिर को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया

महत्वपूर्ण बिंदु

- उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में स्थित तुंगनाथ न केवल दुनिया के सबसे ऊंचे शिव मंदिरों में से एक है बल्कि पांच पंच केदार मंदिरों में भी सबसे ऊंचा है।
- हाल ही में, इसे राष्ट्रीय स्मारक के रूप में नामित किया गया है।
- केंद्र सरकार ने 27 मार्च की एक अधिसूचना में तुंगनाथ को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया।

- भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) ने पुष्टि की कि वे एक महत्वपूर्ण अवधि के लिए इस मान्यता की दिशा में काम कर रहे थे।
- इस प्रक्रिया के दौरान, ASI ने सक्रिय रूप से तुंगनाथ को राष्ट्रीय धरोहर घोषित करने के संबंध में जनता की राय और आपत्तियां मांगीं।

तुंगनाथ मंदिर के बारे में:

- प्राचीन मंदिर जो समुद्र तल से 3,690 मीटर (12,106 फीट) की ऊंचाई पर स्थित है, पांडवों से जुड़ा हुआ है। कुरुक्षेत्र युद्ध में कौरवों को पराजित करने के बाद पांडव युद्ध के दौरान भ्रातृहत्या और ब्राह्मणहत्या या ब्राह्मणों की हत्या के अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने राज्य की बागडोर सौंप दी और भगवान शिव की पूजा करने और अपने पापों से मुक्त होने के लिए उनकी खोज में निकल पड़े।
- वे वाराणसी पहुंचे लेकिन युद्ध में छल और मृत्यु से बहुत परेशान होने के कारण भगवान उनसे बचना चाहते थे और नंदी का रूप धारण कर गढ़वाल में छिप गए। पांडव, उनका आशीर्वाद लेने के लिए गढ़वाल चले गए और वह भीम थे जिन्होंने बैल को देखा और उसे भगवान शिव के रूप में पहचाना। पांडवों ने शिव की पूजा करने और अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए इन सभी पांच स्थानों पर मंदिरों का निर्माण किया।
- माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण 8वीं शताब्दी के हिंदू दार्शनिक और सुधारक आदि शंकराचार्य ने किया था। मंदिर एक साधारण संरचना है, जो वास्तुकला की नागर शैली में निर्मित है। मंदिर का मुख्य देवता एक लिंगम है, जो भगवान शिव का प्रतिनिधित्व करता है। देवी पार्वती और अन्य हिंदू देवताओं के मंदिर भी हैं।
- मंदिर तीर्थयात्रियों के लिए अप्रैल से नवंबर तक खुला रहता है। सर्दियों के महीनों के दौरान, मंदिर को बंद कर दिया जाता है और भगवान शिव की मूर्ति को पास के मंदिर में ले जाया जाता है।
- तुंगनाथ मंदिर हिंदुओं का एक लोकप्रिय तीर्थ स्थल है। यह ट्रेकर्स और हाइकर्स के लिए भी एक लोकप्रिय गंतव्य है। मंदिर गढ़वाल हिमालय में स्थित है और मंदिर के लिए ट्रेक एक चुनौतीपूर्ण लेकिन पुरस्कृत अनुभव है।
- मंदिर तुंगनाथ पर्वत श्रृंखला में स्थित है, जो गढ़वाल हिमालय का हिस्सा है।
- गढ़वाल हिमालय के एक छोटे से गाँव चोपता से मंदिर तक पहुँचने में लगभग 3-4 घंटे लगते हैं।
- मंदिर तीर्थयात्रियों के लिए अप्रैल से नवंबर तक खुला रहता है।
- सर्दियों के महीनों के दौरान, मंदिर बंद कर दिया जाता है और भगवान शिव की मूर्ति को पास के मंदिर में ले जाया जाता है।
- तुंगनाथ मंदिर हिंदुओं का एक लोकप्रिय तीर्थ स्थल है।
- यह ट्रेकर्स और हाइकर्स के लिए भी एक लोकप्रिय गंतव्य है।

महाराणा प्रताप जयंती

खबरों में क्यों

भारत में महाराणा प्रताप जयंती 22 मई, 2023 को मनाई जाएगी।

महत्वपूर्ण बिंदु

- यह मेवाड़ के राजपूत राजा महाराणा प्रताप सिंह की याद में मनाया जाने वाला त्योहार है।

इतिहास

- महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई, 1540 को राजस्थान में हुआ था। मेवाड़ साम्राज्य के राजा महाराणा उदय सिंह द्वितीय उनके पिता थे।
- महाराणा प्रताप युवराज थे क्योंकि वे 25 पुत्रों में सबसे बड़े थे। अपने पिता की मृत्यु के बाद वह मेवाड़ के सिंहासन पर बैठा।
- महाराणा प्रताप एक हिंदू राजपूत राजा थे जो राजपूतों के सिसोदिया वंश के थे।
- उनकी बहादुरी और साहस के लिए राजस्थान में कई शाही परिवारों द्वारा उनका सम्मान और पूजा की जाती है।
- महान राजा को एक सच्चे देशभक्त के रूप में सम्मानित किया जाता है जिन्होंने देश के पहले स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत की थी।
- हल्दीघाटी के युद्ध में, वह सबसे प्रसिद्ध मुगल सम्राटों में से एक, अकबर के साथ लड़ा था। अंततः महाराणा प्रताप को भागना पड़ा।

Maharana Pratap Jayanti

- हालांकि, वह युद्ध के मैदान में बड़ी संख्या में विरोधियों को मारने में कामयाब रहे, जिससे उन्हें अपनी बहादुरी के लिए सम्मान और प्रशंसा मिली। इसलिए, हर साल ज्येष्ठ शुक्ल चरण के तीसरे दिन, हिंदू कैलेंडर के तीसरे महीने में, उनकी जयंती को महाराणा प्रताप जयंती के रूप में मनाया जाता है।
- जनवरी 1597 में एक शिकार दुर्घटना में वह गंभीर रूप से घायल हो गया। 29 जनवरी 1597 को 56 वर्ष की आयु में उसकी मृत्यु हो गई।
- उन्होंने अपने देश, अपने लोगों और, सबसे महत्वपूर्ण, अपने सम्मान के लिए लड़ते हुए अपनी जान दे दी।

जयंती

- जूलियन कैलेंडर के अनुसार, महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई, 1540 को हुआ था।
- जूलियन कैलेंडर अप्रचलित है और इसे ग्रेगोरियन कैलेंडर द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। प्रोलेप्टिक ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार महाराणा प्रताप का जन्म 19 मई 1540 को हुआ था।
- हालांकि, महाराणा प्रताप की जयंती हिंदू कैलेंडर के अनुसार मनाई जाती है।
- और, हिंदू कैलेंडर के अनुसार यह तृतीया, ज्येष्ठ, शुक्ल पक्ष, 1597 विक्रम संवत था जब महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था, जो पश्चिमी कैलेंडर पर मई के अंत या जून की शुरुआत में आता है।
- 2023 में महाराणा प्रताप जयंती 22 मई को पड़ती है, जो उत्तरी भारतीय राज्यों हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान में एक क्षेत्रीय सार्वजनिक अवकाश है।

महाराणा प्रताप जयंती समारोह

- उनकी याद में इस दिन पूरे देश में व्यापक विशेष पूजा, कई सांस्कृतिक कार्यक्रम और वाद-विवाद होते हैं।
- इस दिन लोग उदयपुर में उनकी स्मारक प्रतिमा के दर्शन भी करते हैं।
- राजा की विरासत को याद करने के लिए जीवंत परेड और धार्मिक अनुष्ठान भी होते हैं।

चाम नृत्य

खबरों में क्यों

चाम नृत्य: तिब्बती भिक्षुओं द्वारा एक अनुष्ठानिक नृत्य

महत्वपूर्ण बिंदु

- लद्दाख एक रहस्यमय भूमि है जिसमें बहुत सारी अनूठी चीजें हैं, जिनमें से एक उनका लोक नृत्य है जिसका नाम "द चाम डांस" है जो एक जीवंत नकाबपोश और वेशभूषा वाला अनुष्ठान है जिसकी जड़ें दृढ़ता से बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई हैं।
- तिब्बती बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है जो महान हिमालय में समृद्ध हुआ, यह एक धार्मिक परंपरा है जो भिक्षुओं द्वारा कई त्योहारों और धार्मिक आयोजनों में निभाई जाती है।
- अनुष्ठान मानवता की अधिक भलाई, बुरी आत्माओं के विनाश और दर्शकों को नैतिक शिक्षा देने के लिए किए जाते हैं।
- चाम का नृत्य अनुष्ठान आज तक हिमालय में प्रचलित है, विशेष रूप से उन स्थानों में जहां तिब्बती बौद्ध धर्म भारत के लद्दाख, धर्मशाला, लाहौल घाटी, स्पीति घाटी और सिक्किम और भूटान और तिब्बत में फला-फूला।
- नृत्य बौद्ध त्योहारों और मठों के विशेष आयोजनों का मुख्य आकर्षण है।

चाम नृत्य की उत्पत्ति

- चाम नृत्य की उत्पत्ति ऐतिहासिक या धार्मिक पुस्तकों में स्पष्ट रूप से ज्ञात नहीं है, लेकिन यह तांत्रिक रहस्यवादी कलाओं के साथ अपनी जड़ें साझा करता है।
- चाम नृत्य की उत्पत्ति हिमालय क्षेत्र में हुई मानी जाती है और अब तक तिथि और वर्ष को इस तिथि तक एक क़ीमती रहस्य के रूप में रखा जाता है।
- एक पौराणिक कथा के अनुसार, चाम नृत्य परंपरा की शुरुआत गुरु पद्मसंभव ने आठवीं शताब्दी के अंत में बुराई पर अच्छाई के प्रभुत्व को दर्शाने के लिए की थी।
- किंवदंती के अनुसार, यह भी माना जाता है कि जब तिब्बत के राजा त्रिशोंग देत्सेन ने उस जगह से बुरी आत्माओं से छुटकारा पाने के लिए गुरु पद्मसंभव को बुलाया था जहां आज हम समये मठ देख सकते हैं।
- श्रद्धेय गुरु ने भूमि को आशीर्वाद देने और इसे एक बार फिर से पवित्र बनाने के लिए नृत्य अनुष्ठान किया।
- समय के साथ वही अनुष्ठान विस्तृत चाम नृत्य बन गया, जो महायान बौद्ध धर्म के संप्रदाय के लिए विशिष्ट अभ्यास है।
- और अब यह बौद्ध धर्म, लद्दाख के त्योहारों और यहां तक कि कई आयोजनों या अनुष्ठानों में भी एक अभिन्न अंग है।

चाम नृत्य का धार्मिक महत्व

- चाम नृत्य को बुरी शक्तियों को साफ करने वाला एक कार्य माना जाता है।
- चाम नृत्य पूरे लद्दाख में विशेष अवसरों पर किया जाने वाला एक विस्तृत नकाबपोश और वेशभूषा वाला नृत्य है।
- प्रदर्शन से पहले, बौद्ध धर्म के देवताओं का आह्वान किया जाता है।
- वास्तव में, यहां तक कि नृत्य भी तांत्रिक परंपराओं से प्रेरित एक समारोह है जो सभी सत्वों की भलाई के लिए किया जाता है।
- चाम नृत्य का धार्मिक महत्व प्रदर्शन में ही है।
- परंपरा मठवासी जीवन के अनुकूल है क्योंकि नृत्य आंदोलनों पर केंद्रित नहीं है बल्कि ध्यान, हाथ के इशारों, मंत्रों, देवताओं के आह्वान और नकारात्मकता के विनाश पर इसके प्रभाव पर केंद्रित है।
- असाधारण टोपी और मुखौटों के साथ जीवंत रंगों में सजे, भिक्षु देवताओं और राक्षसों की भूमिका निभाते हैं और बुराई पर अच्छाई की जीत के साथ एक नकली लड़ाई करते हैं।

चाम नृत्य के बारे में जानकारी

- चाम प्रदर्शन दर्शकों के लिए नैतिक पाठ के रूप में भी कार्य करता है, उनके पौराणिक देवताओं के बारे में कहानियां सुनाता है और बहुत कुछ।
- चाम नृत्य लामाओं या भिक्षुओं द्वारा किए जाने वाले एक अनुष्ठान या लोक नृत्य से कहीं अधिक है क्योंकि यह एक अलग तरीके से संस्कृति में एक अंतर्दृष्टि प्रदान करता है।
- नकाबपोश नर्तकियों के कार्य और रूप भक्तों को 49 दिनों के 'बर्दो' के दौरान मिलने वाले देवताओं के प्रकार से परिचित कराने का काम करते हैं, जो कि अस्तित्व के छह रूपों में से एक में मृत्यु और पुनर्जन्म के बीच की संक्रमण अवधि है, जो किसी के कर्म अस्तित्व पर निर्भर करता है।

भारत में चाम डांस कहाँ देखें?

- भारत में आज तक चाम नृत्य बौद्ध मठों में किया जाता है, जो ज्यादातर हिमालय में छिपे हुए हैं।
- लद्दाख, सिक्किम और हिमाचल प्रदेश की तिब्बती बस्तियों में पाए जाने वाले मठ भिक्षुओं के घर हैं जो अपने धार्मिक त्योहारों पर चाम नृत्य अनुष्ठान का अभ्यास करते हैं।
- 'मिनी तिब्बत' के रूप में जाने जाने वाले क्षेत्र की बौद्ध धर्म में प्राचीन जड़ें हैं।
- जम्मू और कश्मीर में दूरस्थ "पास की भूमि" में नकाबपोश नृत्य अनुष्ठान में भाग लेने के लिए कुछ सबसे लोकप्रिय स्थान हैं।

सेंगोल

खबरों में क्यों

पीएम मोदी नए संसद भवन में सेंगोल स्थापित करेंगे

महत्वपूर्ण बिंदु

- ऐतिहासिक सेंगोल, जिसे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 1947 में अंग्रेजों से भारत में सत्ता के हस्तांतरण के प्रतीक के रूप में प्राप्त किया था, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नए संसद भवन में स्थापित किया जाना तय है।
- पवित्र राजदंड चोल साम्राज्य में अपनी उत्पत्ति का पता लगाता है।
- माना जाता है कि 'सेंगोल' शब्द तमिल शब्द 'सेम्माई' से लिया गया है, जिसका अर्थ उत्कृष्टता है।

'सेंगोल' का इतिहास

- 'सेनगोल' राजदंड का महत्व तब उभरा जब ब्रिटिश भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने नेहरू से सत्ता के प्रतीकात्मक हस्तांतरण के बारे में पूछा।
- नेहरू ने भारत के अंतिम गवर्नर-जनरल सी राजगोपालाचारी से सलाह मांगी, जो तमिलनाडु के कृष्णागिरी जिले (तत्कालीन मद्रास प्रेसीडेंसी) के थोरापल्ली से थे।
- राजाजी, जैसा कि उन्हें लोकप्रिय कहा जाता था, ने 'सेनगोल' के उपयोग का सुझाव दिया; वह चोल राजवंश से प्रेरित थे, जहां राजाओं के बीच सत्ता हस्तांतरण के लिए इसी तरह का समारोह आयोजित किया गया था।
- राजदंड की प्रस्तुति के अलावा, तमिल में 'अनाई' नामक एक आदेश भी नए राजा को सौंप दिया गया था, जिसने नए शासक को 'धर्म के सिद्धांतों के अटूट पालन के साथ शासन करने की जिम्मेदारी दी थी।

स्वतंत्र भारत के लिए 'सेनगोल'

- राजाजी ने 'सेंगोल' बनाने के लिए तमिलनाडु के तंजौर जिले में एक धार्मिक संस्था की मदद ली। चेन्नई के ज्वैलर्स वुम्मिदी बंगारू चेट्टी ने वस्तु बनाई।
- 14 अगस्त, 1947 को, तंजौर धार्मिक निकाय के तीन पुजारियों के रूप में एक महत्वपूर्ण अवसर सामने आया, जिसमें बड़ी श्रद्धा के साथ कार्यवाही की अध्यक्षता करते हुए 'सेंगोल' ले गए।
- इसके बाद उन्होंने नेहरू को 'सेनगोल' सौंप दिया, जिससे सत्ता का हस्तांतरण चिह्नित हो गया।
- 'सेंगोल' पांच फीट लंबा है और शीर्ष पर 'न्याय', या न्याय और निष्पक्षता के प्रतीक के रूप में नंदी, दिव्य बैल की राजसी आकृति है।

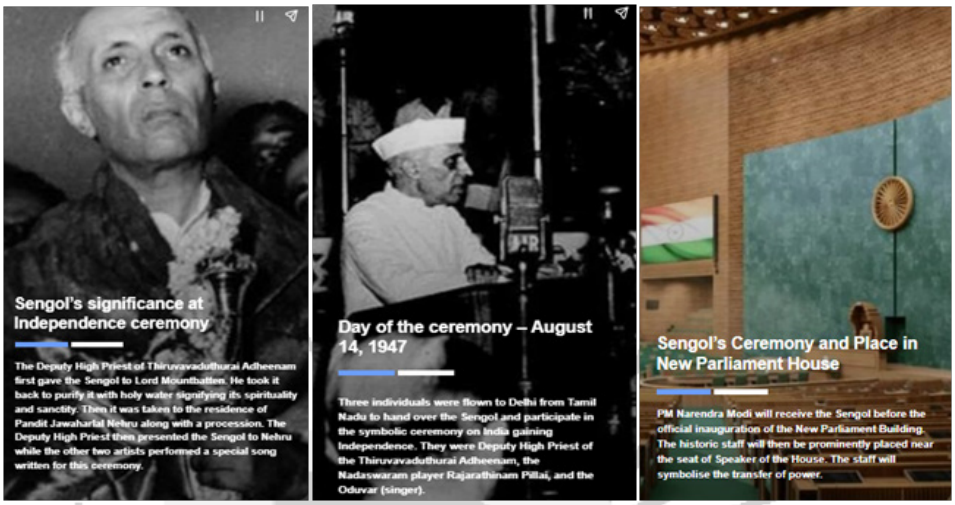

तिरुक्कुरल

खबरों में क्यों

प्रधानमंत्री ने पापुआ न्यू गिनी में पुस्तक 'थिरुक्कुरल' के टोक पिसिन अनुवाद का विमोचन किया

महत्वपूर्ण बिंदु

- भारतीय प्रधान मंत्री ने अपने पापुआ न्यू गिनी समकक्ष के साथ हाल ही में टोक पिसिन भाषा में तमिल क्लासिक 'थिरुक्कुरल' जारी किया।

तिरुक्कुरल

- तिरुक्कुरल (तमिल: "पवित्र दोहे") जिसे कुरल भी कहा जाता है, तिरुवल्लुवर द्वारा लिखित एक उत्कृष्ट तमिल पाठ है, जिसके बारे में माना जाता है कि यह दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व और 5वीं शताब्दी CE के बीच रहा होगा।
- तमिल संस्कृति और जीवन पर इसका अत्यधिक प्रभाव पड़ा है।
- यह 1,330 दोहों (कुरलों) का संग्रह है जो नैतिकता, शासन, प्रेम और आध्यात्मिकता सहित जीवन के विभिन्न पहलुओं पर कालातीत ज्ञान प्रदान करते हैं।

संरचना और विषय-वस्तु:

- तिरुक्कुरल को तीन मुख्य वर्गों या पुस्तकों में विभाजित किया गया है: अराम (पुण्य), पोरुल (धन), और इनबम (प्रेम)।
- प्रत्येक खंड विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला को शामिल करता है और पाठकों को नैतिक और व्यावहारिक मार्गदर्शन प्रदान करता है।
- दोहे संक्षिप्त और काव्यात्मक रूप में रचे गए हैं, जिससे उन्हें आसानी से याद किया जा सकता है और उद्धृत किया जा सकता है।

अराम:

- इसमें धार्मिकता, सच्चाई, कृतज्ञता और करुणा जैसे सद्गुणों की चर्चा है।
- यह एक धर्मी जीवन जीने और सभी परिस्थितियों में नैतिक मूल्यों को बनाए रखने के महत्व पर जोर देता है।

पोरुल:

- यह शासन, अर्थव्यवस्था और मित्रता सहित सांसारिक मामलों में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है।
- यह धन प्रबंधन, प्रशासन और अच्छी कंपनी के मूल्य जैसे विषयों पर ज्ञान प्रदान करता है।

इनबम:

- यह मानवीय भावनाओं, प्रेम और पारिवारिक जीवन की जटिलताओं को उजागर करता है।

टोक पिसिन

- टोक पिसिन पापुआ न्यू गिनी के पूरे देश की भाषा है, जिसे देश के अनुमानित तीन चौथाई निवासी जानते हैं। वास्तव में, यह शहरी क्षेत्रों की सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल की जाने वाली भाषा है।
- टोक पिसिन, मूल रूप से पिजिन भाषा, क्रियोल भाषा में विकसित हुई।
- पापुआ न्यू गिनी का संविधान टोक पिसिन को देश की राष्ट्रीय भाषाओं में से एक के रूप में मान्यता देता है।
- हालांकि सरकारी कामकाज के लिए अंग्रेजी का अधिक व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है, संसद में अधिकांश बहस टोक पिसिन में होती है।

2 राजनीति और शासन

धर्म की स्वतंत्रता

खबरों में क्यों

तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि भारत का संविधान लोगों को "शांतिपूर्वक अपना धर्म फैलाने" और "अपनी मान्यताओं को बदलने" का अधिकार देता है।

महत्वपूर्ण बिंदु

- हाल ही में, तमिलनाडु (TN) सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय (SC) में एक याचिका का जवाब देते हुए कहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 (धर्म की स्वतंत्रता) प्रत्येक नागरिक को अपने धर्म के प्रचार के अधिकार की गारंटी देता है।
- तमिलनाडु सरकार का कहना है कि "प्रत्येक नागरिक को अपने धर्म का शांतिपूर्वक अभ्यास करने और प्रसार करने का अवसर है"।
- तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि ईसाई धर्म फैलाने वाले मिशनरियों के बारे में कुछ भी अवैध नहीं है, जब तक कि वे ऐसा करने के लिए गैरकानूनी साधनों का इस्तेमाल नहीं करते हैं, इस बात पर जोर देते हुए कि भारत का संविधान लोगों को "अपने धर्म को शांति से फैलाने" और "अपनी मान्यताओं को बदलने" का अधिकार देता है। "।
- यह कहते हुए कि "धर्मांतरण विरोधी कानून अल्पसंख्यकों के खिलाफ दुरुपयोग के लिए प्रवण हैं", द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK) के नेतृत्व वाली सरकार ने शीर्ष अदालत में प्रस्तुत किया कि देश के नागरिकों को स्वतंत्र रूप से अपना धर्म चुनने की अनुमति दी जानी चाहिए और सरकार के लिए उनके व्यक्तिगत विश्वास और गोपनीयता के लिए भाषण देना उचित नहीं होगा।

क्या है मामला

- याचिकाकर्ता ने एनआईए (राष्ट्रीय जांच एजेंसी)/सीबीआई (केंद्रीय जांच ब्यूरो) से तमिलनाडु में एक 17 वर्षीय लड़की की मौत के "मूल कारण" की जांच की मांग की, आरोपों के एक भंवर के बीच कि उसे ईसाई धर्म में परिवर्तित करने के लिए मजबूर किया गया था। याचिका में तर्क दिया गया था कि जबरन या धोखे से धर्मांतरण मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है।
- हाल ही में दायर एक हलफनामे में तमिलनाडु सरकार इस बात पर जोर दे रही है कि पिछले कई वर्षों में दक्षिणी राज्य में जबरन धर्मांतरण की कोई घटना नहीं हुई है, क्योंकि इसने पीआईएल याचिकाकर्ता-अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय द्वारा की गई प्रार्थनाओं का विरोध किया था ताकि जबरन धर्मांतरण के कथित मामलों की सीबीआई जांच का आदेश दिया जा सके और कानून आयोग को भारत के कानून आयोग को मसौदा तैयार करने का निर्देश दिया जा सके। .
- धर्मांतरण विरोधी कानूनों का अल्पसंख्यकों के खिलाफ दुरुपयोग होने की संभावना है और राज्यों के विभिन्न धर्मांतरण विरोधी कानूनों के तहत सजा पर कोई डेटा नहीं है।
- यह सबसे सम्मानपूर्वक प्रस्तुत किया जाता है कि नागरिक उस धर्म को चुनने के लिए स्वतंत्र हैं, जिसका वे पालन करना चाहते हैं," हलफनामे में कहा गया है, उपाध्याय की ईसाई मिशनरियों को निशाना बनाने की कोशिश करने की आलोचना करते हुए, जिसे राज्य ने "धार्मिक रूप से प्रेरित याचिका" कहा है।
- राज्य ने इस कानूनी प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया कि संविधान किसी भी व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति को अपने धर्म में परिवर्तित करने का मौलिक अधिकार नहीं देता है।
- लेकिन यह किसी भी व्यक्ति को अपने धर्म का प्रचार करने का अधिकार देता है। इसी तरह, संविधान किसी भी व्यक्ति को अपनी पसंद के धर्म में परिवर्तित होने से नहीं रोकता है।
- देश के नागरिकों को अपना धर्म चुनने की आज़ादी दी जानी चाहिए और सरकार के लिए यह उचित नहीं होगा कि वह उनकी व्यक्तिगत आस्था और निजता पर कटाक्ष करे।

धर्म की स्वतंत्रता पर संवैधानिक प्रावधान

- भारत के संविधान का अनुच्छेद 25 प्रत्येक नागरिक को अपने धर्म का प्रचार करने के अधिकार की गारंटी देता है।
- इसलिए, ईसाई धर्म का प्रसार करने वाले मिशनरियों के कार्यों को अपने आप में कानून के विरुद्ध कुछ नहीं माना जा सकता है।
- लेकिन अगर उनका अपने धर्म के प्रसार का कार्य सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य और संविधान के भाग III के अन्य प्रावधानों (मौलिक अधिकारों से संबंधित) के खिलाफ है, तो इसे गंभीरता से देखा जाना चाहिए।
- जहां तक तमिलनाडु का संबंध है, पिछले कई वर्षों में जबरन धर्मांतरण की कोई घटना सामने नहीं आई है।
- संविधान के अनुच्छेद 21 और 25 का हवाला देते हुए, तमिलनाडु सरकार ने कहा कि "प्रत्येक नागरिक को अपने धर्म का शांतिपूर्वक अभ्यास और प्रसार करने का अवसर है" और किसी विशेष धर्म में आस्था रखने का अधिकार एक अनुल्लंघनीय अधिकार है जिसकी रक्षा करना राज्य का दायित्व है।

धर्मनिरपेक्षता:

- 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में 'धर्मनिरपेक्ष' शब्द जोड़ा गया। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य होने के नाते, कोई राज्य धर्म नहीं है जिसका अर्थ है कि यह किसी विशेष धर्म का पालन नहीं करता है।
- अहमदाबाद सेंट जेवियर्स कॉलेज बनाम गुजरात राज्य (1975) में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि धर्मनिरपेक्षता का मतलब न तो ईश्वर विरोधी है और न ही ईश्वर समर्थक। यह सिर्फ यह सुनिश्चित करता है कि राज्य के मामलों में ईश्वर की अवधारणा को समाप्त करते हुए धर्म के आधार पर किसी को अलग नहीं किया जाए।

धर्मांतरण विरोधी कानूनों के बारे में

- धर्मांतरण विरोधी कानून उन कानूनों को कहते हैं जो एक धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तन को रोकने या प्रतिबंधित करने के लिए बनाए गए हैं।
- इन कानूनों का उपयोग व्यक्तियों को किसी विशेष धर्म को छोड़ने से रोकने या धार्मिक समूहों को धर्मांतरण करने या अन्य धार्मिक समूहों से सदस्यों की भर्ती करने से रोकने के लिए किया जा सकता है।
- संवैधानिक प्रावधान: भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 किसी भी धर्म को मानने, मानने और प्रचार करने की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। यह सार्वजनिक नैतिकता, स्वास्थ्य और व्यवस्था के अधीन सभी धार्मिक समूहों को अपने स्वयं के धार्मिक मामलों को नियंत्रित करने का अधिकार भी देता है।
- मौजूदा कानून: धार्मिक रूपांतरण किसी भी राष्ट्रीय प्रतिबंध या नियमों के अधीन नहीं है। धार्मिक रूपांतरण को नियंत्रित करने के लिए निजी सदस्य विधेयक, हालांकि, 1954 के बाद से संसद में बार-बार पेश किए गए हैं (लेकिन कभी पारित नहीं हुए)।

धर्मांतरण विरोधी कानूनों से जुड़े मुद्दे

- धर्म की स्वतंत्रता: धर्मांतरण विरोधी कानूनों को धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार के उल्लंघन के रूप में देखा जा सकता है, जो अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कानूनों द्वारा संरक्षित है। ये कानून किसी व्यक्ति की अपनी धर्म चुनने की क्षमता को प्रतिबंधित कर सकते हैं और अल्पसंख्यक धर्मों को दबाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।
- भेदभाव: कुछ धार्मिक समूहों, विशेष रूप से अल्पसंख्यक धर्मों के खिलाफ भेदभाव करने के लिए धर्मांतरण विरोधी कानूनों का उपयोग किया जा सकता है। कुछ मामलों में, इन कानूनों का इस्तेमाल अल्पसंख्यक धार्मिक समूहों को निशाना बनाने और उन्हें सताने के लिए किया गया है।
- ज़बरदस्ती और हेरफेर: कुछ लोगों का तर्क है कि धर्म परिवर्तन में ज़बरदस्ती और हेरफेर को रोकने के लिए धर्मांतरण विरोधी कानून आवश्यक हैं। हालांकि, दूसरों का मानना है कि इन कानूनों का इस्तेमाल अक्सर अल्पसंख्यक धर्मों को दबाने और धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार को प्रतिबंधित करने के बहाने के रूप में किया जाता है।
- सामाजिक और सांस्कृतिक विभाजन: धर्मांतरण विरोधी कानून एक समुदाय या समाज के भीतर सामाजिक और सांस्कृतिक विभाजन में योगदान कर सकते हैं, खासकर यदि उनका उपयोग प्रमुख धर्म की रक्षा के लिए किया जाता है।
- अन्य कानूनों के साथ संघर्ष: धर्मांतरण विरोधी कानून कभी-कभी अन्य कानूनों के साथ संघर्ष कर सकते हैं, जैसे कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता या संघ की स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा करने वाले कानून।
- प्रभाविकता: धर्मांतरण-विरोधी कानूनों की उनके इच्छित लक्ष्यों को प्राप्त करने में प्रभावशीलता पर बहस होती है। कुछ लोगों का तर्क है कि ये कानून धर्म परिवर्तन को रोकने में प्रभावी नहीं हैं, जबकि अन्य का मानना है कि ये किसी समुदाय या समाज की सांस्कृतिक और सामाजिक एकता की रक्षा के लिए आवश्यक हैं।

तलाक

खबरों में क्यों

सुप्रीम कोर्ट का नियम है कि वह अनुच्छेद 142 के तहत सीधे विवाहित जोड़ों को तलाक दे सकता है

महत्वपूर्ण बिंदु

- सर्वोच्च न्यायालय के पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने फैसला सुनाया
- यह संविधान के अनुच्छेद 142 (1) के तहत "पूर्ण न्याय" करने के लिए इस आधार पर विवाह को भंग करने के लिए अपनी पूर्ण शक्ति का प्रयोग कर सकता है कि यह पार्टियों को पारिवारिक अदालत में संदर्भित किए बिना, जहां उन्हें आपसी सहमति से तलाक की डिक्री के लिए 6-18 महीने इंतजार करना होगा, वह अपरिवर्तनीय रूप से टूट गया था।
- न्यायमूर्ति एस के कौल के नेतृत्व वाली पीठ ने कहा कि अदालत इस शक्ति का प्रयोग करते हुए, हिंदू विवाह अधिनियम (HMA), 1955 के तहत तलाक के लिए अनिवार्य छह महीने की प्रतीक्षा अवधि को माफ कर सकती है, और असुधार्य टूटने के आधार पर विवाह के विघटन की अनुमति दें, भले ही पार्टियों में से कोई एक इच्छुक न हो। (शिल्पा शैलेश बनाम वरुण श्रीनिवासन मामला)

हिंदू विवाह अधिनियम के तहत तलाक की वर्तमान प्रक्रिया

- HMA की धारा 13बी में "आपसी सहमति से तलाक" का प्रावधान है।
- विवाह के दोनों पक्षों को एक साथ मिलकर जिला अदालत में याचिका दायर करनी चाहिए "इस आधार पर कि वे एक वर्ष या उससे अधिक की अवधि से अलग रह रहे हैं, कि वे एक साथ रहने में सक्षम नहीं हैं और वे परस्पर सहमत हैं कि विवाह को भंग कर देना चाहिए"।
- अधिनियम की धारा 13B(2) के तहत, पक्षकारों को न्यायालय के समक्ष दूसरा प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहिए "[पहली] याचिका की प्रस्तुति की तारीख के बाद छह महीने से पहले नहीं और उक्त तारीख के बाद अठारह महीने के बाद नहीं, अगर इस बीच याचिका वापस नहीं ली जाती है"।

- छह महीने की अनिवार्य प्रतीक्षा का उद्देश्य पक्षकारों को अपनी याचिका वापस लेने के लिए समय देना है।
- उसके बाद, "अदालत संतुष्ट होने पर, पार्टियों को सुनने के बाद और इस तरह की जांच करने के बाद जैसा कि वह उचित समझती है कि याचिका में दिए गए कथन सही हैं, तलाक की डिक्री पारित करें, जिसमें डिक्री की तारीख से विवाह को भंग करने की घोषणा की गई है।"
- आपसी सहमति से तलाक के लिए याचिका विवाह के एक वर्ष के बाद ही दायर की जा सकती है।
- हालांकि, HMA की धारा 14 "याचिकाकर्ता को असाधारण कठिनाई या प्रतिवादी की ओर से असाधारण भ्रष्टता" के मामले में जल्द ही तलाक की याचिका की अनुमति देती है।
- धारा 13B(2) के तहत छह महीने की प्रतीक्षा अवधि की छूट परिवार न्यायालय के समक्ष दायर एक छूट आवेदन में मांगी जा सकती है।

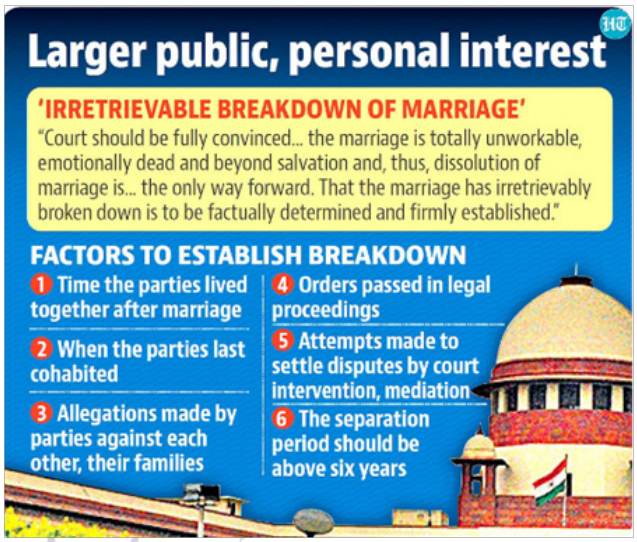

अमित कुमार बनाम सुमन बेनीवाल मामला

- अमित कुमार बनाम सुमन बेनीवाल में अपने 2021 के फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जहां सुलह का मौका है, हालांकि मामूली, तलाक याचिका दायर करने की तारीख से छह महीने की कूलिंग अवधि लागू की जानी चाहिए।
- हालांकि, यदि सुलह की कोई संभावना नहीं है, तो विवाह के पक्षकारों की पीड़ा को लम्बा खींचना व्यर्थ होगा।
- लाक की डिक्री प्राप्त करने की प्रक्रिया अक्सर समय लेने वाली और लंबी होती है, क्योंकि पारिवारिक अदालतों के समक्ष बड़ी संख्या में इसी तरह के मामले लंबित होते हैं।

संविधान का अनुच्छेद 142

- अनुच्छेद 142 की उपधारा 1 के तहत, सर्वोच्च न्यायालय "ऐसी डिक्री पारित कर सकता है या ऐसा आदेश दे सकता है जो किसी भी कारण या मामले में पूर्ण न्याय करने के लिए आवश्यक है और इस तरह पारित कोई भी डिक्री या ऐसा किया गया आदेश पूरे भारत के क्षेत्र में लागू होगा"।
- जबकि अनुच्छेद 142 के तहत उपलब्ध शक्ति व्यापक है, सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णयों के माध्यम से इसके दायरे और सीमा को परिभाषित किया है। प्रेम चंद गर्ग (1962) में बहुमत की राय ने कहा कि "पूर्ण न्याय करने का आदेश न केवल संविधान द्वारा गारंटीकृत मौलिक अधिकारों के अनुरूप होना चाहिए, बल्कि यह प्रासंगिक वैधानिक कानूनों के मूल प्रावधानों के साथ असंगत भी नहीं हो सकता।"
- सार्वजनिक नीति की मूलभूत सामान्य शर्तें मौलिक अधिकारों, धर्मनिरपेक्षता, संघवाद और संविधान की अन्य बुनियादी विशेषताओं को संदर्भित करती हैं; विशिष्ट सार्वजनिक नीति को अदालत द्वारा परिभाषित किया गया था जिसका अर्थ है "किसी भी मूल कानून में कुछ पूर्व-प्रतिष्ठित निषेध, न कि किसी विशेष वैधानिक योजना के लिए शर्तें और आवश्यकताएं"।

यदि कोई विवाह असुधार्य रूप से टूट गया है तो यह निर्णय करते समय न्यायालय किन कारकों पर विचार कर सकते हैं?

- पिछले साल मामले के लंबित रहने के दौरान, अदालत ने कहा कि वह यह निर्धारित करेगी कि संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत सीधे विवाह को भंग करते समय किन नियमों का पालन किया जाना चाहिए।
- पहली और सबसे "स्पष्ट" शर्त यह है कि अदालत को पूरी तरह से आश्वस्त और संतुष्ट होना चाहिए कि विवाह "पूरी तरह से अव्यावहारिक, भावनात्मक रूप से मृत और मोक्ष से परे है और इसलिए, विवाह का विघटन सही समाधान और आगे बढ़ने का एकमात्र तरीका है"।

अदालत ने निम्नलिखित कारकों को निर्धारित किया:

  - शादी के बाद दोनों पक्षों के साथ रहने की अवधि;
  - जब पार्टियों ने आखिरी सहवास किया था;
  - पार्टियों द्वारा एक दूसरे और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ लगाए गए आरोपों की प्रकृति;
  - समय-समय पर कानूनी कार्यवाही में पारित आदेश;
  - व्यक्तिगत संबंधों पर संचयी प्रभाव;
  - किसी अदालत द्वारा या मध्यस्थता के माध्यम से विवादों को निपटाने के लिए और कितने प्रयास किए गए, और आखिरी प्रयास कब किया गया था।
- अदालत ने यह भी कहा कि अलगाव की अवधि पर्याप्त रूप से लंबी होनी चाहिए, और "छह साल या उससे अधिक कुछ भी एक प्रासंगिक कारक होगा"।
- इसने पार्टियों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति के अनुसार कारकों का मूल्यांकन करने की आवश्यकता पर जोर दिया, जिसमें उनकी शैक्षणिक योग्यता भी शामिल है; क्या उनके कोई बच्चे हैं; उनकी उम्र; और क्या पति/पत्नी और बच्चे आश्रित हैं।

राजद्रोह कानून

खबरों में क्यों

केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा, देशद्रोह कानून पर पुनर्विचार उन्नत स्तर पर

महत्वपूर्ण बिंदु

- केंद्र ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि राजद्रोह से निपटने वाली आईपीसी की धारा 124ए की "पुन: जांच" के लिए परामर्श "काफी उन्नत चरण" पर है, जिसके बाद प्रावधान को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर कार्यवाही अगस्त 2022 के दूसरे सप्ताह तक के लिए स्थगित कर दी गई थी।
- राजद्रोह कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर प्रतिक्रिया देते हुए, केंद्र ने मई 2022 में शीर्ष अदालत से कहा था कि वह इस विषय पर "विभिन्न विचारों से पूरी तरह से अवगत है" और "धारा 124ए के प्रावधानों की फिर से जांच करने और उन पर फिर से विचार करने का फैसला किया है।"
- इसने पीठ से कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई तब तक टालने का आग्रह किया जब तक कि "उचित मंच के समक्ष" इस तरह की कवायद नहीं की जाती।
- इसने अदालत से अभ्यास पूरा होने तक सुनवाई को टालने का भी आग्रह किया।
- विचार के दोनों सेटों को संतुलित करने की आवश्यकता है, जो एक कठिन अभ्यास है।
- याचिकाकर्ताओं का मामला यह है कि कानून का यह प्रावधान 1898 से पहले का है, और संविधान से भी पहले का है, और इसका दुरुपयोग किया जा रहा है।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

- कानून 17वीं शताब्दी में इंग्लैंड में बनाए गए थे जब कानून निर्माताओं का मानना था कि सरकार की केवल अच्छी राय ही जीवित रहनी चाहिए, क्योंकि बुरी राय सरकार और राजशाही के लिए हानिकारक थी।
- कानून मूल रूप से 1837 में ब्रिटिश इतिहासकार-राजनीतिज्ञ थॉमस मैकाले द्वारा तैयार किया गया था, लेकिन 1860 में आईपीसी अधिनियमित होने पर इसे अस्पष्ट रूप से छोड़ दिया गया था।
- धारा 124ए को 1870 में सर जेम्स स्टीफेन द्वारा पेश किए गए एक संशोधन द्वारा आईपीसी में डाला गया था, जब अपराध से निपटने के लिए एक विशिष्ट धारा की आवश्यकता महसूस हुई।
- 1890 में, विशेष अधिनियम XVII के माध्यम से धारा 124ए आईपीसी के तहत देशद्रोह को एक अपराध के रूप में शामिल किया गया था।
- कानून शुरू से ही विवादों में रहा है क्योंकि इसका इस्तेमाल असहमति को दबाने और स्वतंत्रता सेनानियों को कैद करने के लिए भी किया गया था। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और बाल गंगाधर तिलक सहित स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं को कानून के तहत बुक किया गया था।
- वर्तमान में भारतीय दंड संहिता की धारा 124ए के तहत राजद्रोह एक अपराध है।

राजद्रोह कानून के बारे में

- भारतीय दंड संहिता की धारा 124 A के अनुसार, "बोले या लिखे गए शब्दों या संकेतों द्वारा या दृश्य प्रस्तुति द्वारा, जो कोई भी भारत में विधि द्वारा स्थापित सरकार के प्रति घृणा या अवमान पैदा करेगा या पैदा करने का प्रयत्न करेगा, असंतोष (Disaffection) उत्पन्न करेगा या करने का प्रयत्न करेगा, उसे आजीवन कारावास या तीन वर्ष तक की कैद और जुर्माना अथवा सभी से दंडित किया जाएगा।"
- सरल शब्दों में, इसका मतलब यह है कि कोई भी व्यक्ति जो सरकार के प्रति घृणा, अवमानना, या असंतोष पैदा करने का प्रयास करता है, उसे राजद्रोह कानून के तहत दंडित किया जा सकता है।
- 1950 में अपनाए गए मूल संविधान ने राजद्रोह कानून को मान्यता नहीं दी और मौलिक अधिकारों के तहत फ्री स्पीच का अधिकार पूर्ण संरक्षण दिया। लेकिन 1951 में लाया गया पहला संशोधन राजद्रोह कानून को मान्य करने वाले प्रतिबंधों को पेश करता है।

केदारनाथ केस

- 20 जनवरी, 1962 को केदार नाथ मामले में एक ऐतिहासिक फैसले में, सर्वोच्च न्यायालय ने राजद्रोह कानून की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा, लेकिन इसके दुरुपयोग की गुंजाइश को सीमित करने का भी प्रयास किया।
- आदेश में कहा गया है कि सरकार की मात्र आलोचना को तब तक देशद्रोह नहीं कहा जा सकता जब तक कि शब्दों का उद्देश्य हिंसा द्वारा सार्वजनिक शांति को भंग करना न हो। केदारनाथ सिंह फॉरवर्ड कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य थे।
- 1953 में बिहार की एक रैली में सिंह ने अनिवार्य रूप से यह कहा था: "सीआईडी के कुत्ते इधर-उधर आवारा घूम रहे हैं। हम हड़ताल करेंगे और इन कांग्रेसी गुंडों को बाहर निकाल देंगे।"
- 1984 में पूर्व प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद, दो व्यक्तियों ने "खालिस्तान जिंदाबाद" और "राज करेगा खालसा" के नारे लगाए थे।
- सुप्रीम कोर्ट ने 1995 में देशद्रोह के आरोप को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि "दो अकेले अपीलकर्ताओं द्वारा केवल दो बार कुछ नारे लगाना, जिसने न तो कोई प्रतिक्रिया दी और न ही सार्वजनिक रूप से किसी की ओर से कोई प्रतिक्रिया हुई, धारा 124ए के प्रावधानों को आकर्षित नहीं कर सकता है।"

लोगों पर देशद्रोह का आरोप लगाया गया

- बेंगलुरु की एक 21 वर्षीय पर्यावरण कार्यकर्ता, दिशा रवि को दिल्ली पुलिस ने 14 फरवरी, 2021 को कथित रूप से कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के विरोध पर "टूलकिट" बनाने के आरोप में गिरफ्तार किया था।
- 2016 में, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) के छात्रों के एक समूह ने 2001 के संसद हमले के दोषी अफजल गुरु की फांसी की तीसरी वर्षगांठ के अवसर पर एक कविता सत्र आयोजित किया था। दिल्ली पुलिस ने बाद में छात्रों पर देशद्रोह का आरोप लगाया।

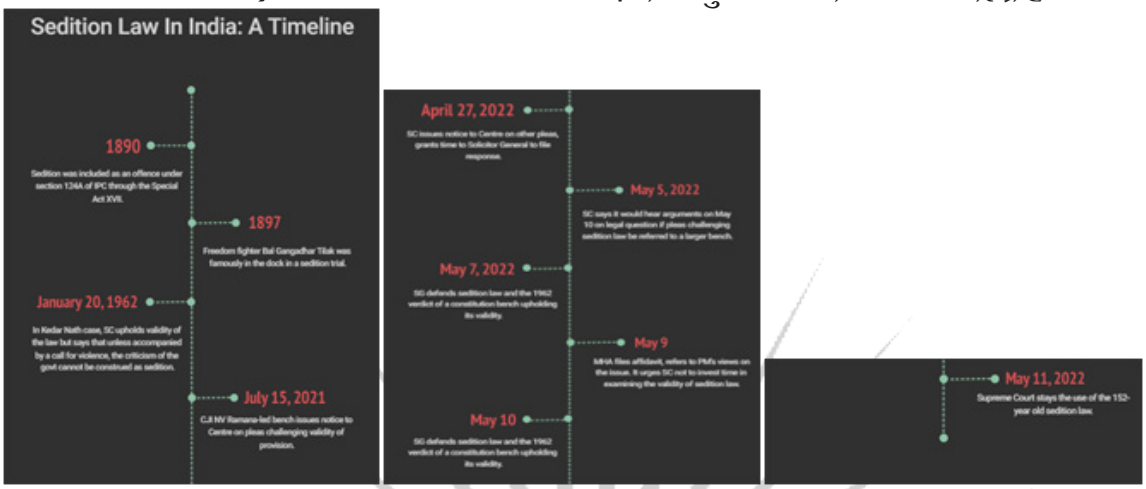

आदर्श आचार संहिता

खबरों में क्यों

ECI ने कर्नाटक विधानसभा में प्रचार अभियान के गिरते स्तर को देखते हुए सभी स्टार प्रचारकों के लिए परामर्श जारी किया

महत्वपूर्ण बिंदु

- आयोग का ध्यान हाल ही में चल रहे अभियान के दौरान व्यक्तियों, विशेष रूप से स्टार प्रचारक की वैधानिक स्थिति के साथ निवेशित लोगों द्वारा उपयोग की जाने वाली अनुचित शब्दावली और भाषा के उदाहरणों पर लाया गया है।
- ऐसे मामलों में कई तरह की शिकायतें, क्रॉस शिकायतें हुई हैं और इसने नकारात्मक मीडिया का ध्यान भी आकर्षित किया है।
- उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, सभी राजनीतिक दलों को सख्त अनुपालन के लिए जारी एक परामर्श में, आयोग ने कहा कि राष्ट्रीय दलों और स्टार प्रचारकों को आरपी अधिनियम के तहत अतिरिक्त सक्षमता प्राप्त है।
- इस प्रकार उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे "मुद्दे" आधारित बहस के स्तर को बनाए रखने और बढ़ाने में योगदान दें, अखिल भारतीय परिप्रेक्ष्य प्रदान करें, स्थानीय संवाद को गहराई प्रदान करें और निर्वाचकों के सभी वर्गों को एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव में पूरी तरह से और निडर होकर भाग लेने के लिए आश्वस्त करें।"
- परामर्श में, ECI ने आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों और अन्य वैधानिक प्रावधानों के लिए राजनीतिक दलों का ध्यान आकर्षित किया है जो क्षेत्र को पकड़ते हैं और अपेक्षित अभियान प्रवचन की रूपरेखा तय करते हैं।
- ईसीआई ने नोट किया कि MCC प्रावधानों के अनुसार, भड़काऊ और भड़काऊ बयानों का उपयोग, शालीनता की सीमा का उल्लंघन करने वाली असंयमित और अपमानजनक भाषा का उपयोग और राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों के व्यक्तिगत चरित्र और आचरण पर हमले समान खेल के मैदान को दूषित करते हैं।
- आचार संहिता की भावना न केवल प्रत्यक्ष उल्लंघन से बचना है, बल्कि यह विचारोत्तेजक या अप्रत्यक्ष बयानों या आक्षेपों के माध्यम से चुनावी स्थान को दूषित करने के प्रयासों पर भी रोक लगाती है

आदर्श आचार संहिता क्या है?

- एमसीसी चुनाव से पहले राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को विनियमित करने के लिए ईसीआई द्वारा जारी दिशानिर्देशों का एक सेट है।
- यह चुनाव आयोग को संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत दिए गए जनादेश को ध्यान में रखते हुए मदद करता है, जो इसे संसद और राज्य विधानसभाओं के स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की निगरानी और संचालन करने की शक्ति देता है।
- चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की तारीख से परिणाम की घोषणा की तारीख तक एमसीसी चालू है।

आदर्श आचार संहिता में ईसीआई की वेबसाइट पर निर्धारित नियमों की एक लंबी सूची है जिसका सभी को पालन करना है। यहां दस महत्वपूर्ण मानदंड दिए गए हैं जो आपको यह स्पष्ट रूप से समझने में मदद करेंगे कि कैसे पोल पैनल एक सुचारू और निष्पक्ष चुनावी प्रक्रिया सुनिश्चित करता है।

1. कोई भी पार्टी या उम्मीदवार ऐसी कोई गतिविधि नहीं करेगा जो मौजूदा मतभेदों को बढ़ाए या आपसी नफरत पैदा करे या विभिन्न जातियों और समुदायों, धार्मिक या भाषाई के बीच तनाव पैदा करे।
2. राजनीतिक दलों और उनके उम्मीदवारों को अपने विरोधियों की आलोचना को राजनीति, कार्यक्रमों, पिछले रिकॉर्ड और काम तक ही सीमित रखना चाहिए। किसी भी उम्मीदवार या राजनीतिक दल को व्यक्तिगत टिप्पणी या कोई अन्य बयान देने की अनुमति नहीं है जो नेताओं या कार्यकर्ताओं की सार्वजनिक गतिविधियों से संबंधित नहीं है।

3. राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों या अन्य नेताओं को जाति या सांप्रदायिक आधार पर वोट मांगने पर सख्ती से रोक लगा दी गई है। धार्मिक स्थलों को चुनाव प्रचार के मंच के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए।
4. चुनाव आयोग ने यह स्पष्ट कर दिया है कि सभी दलों और उम्मीदवारों को मतदाताओं को रिश्वत देने, मतदाताओं को डराने-धमकाने, मतदाताओं का प्रतिरूपण करने, मतदान केंद्रों के 100 मीटर के भीतर प्रचार करने, मतदान बंद होने के लिए निर्धारित समय के समाप्त होने के 48 घंटे की अवधि के दौरान सार्वजनिक बैठकें करने आदि जैसे भ्रष्ट आचरण से बचना चाहिए। .
5. मतदान पैनल व्यक्तियों के विचारों या गतिविधियों के विरोध में उनके घरों के सामने प्रदर्शन या धरना देने पर रोक लगाता है। इसके अलावा, किसी भी राजनीतिक दल या उम्मीदवार को अपने अनुयायियों को किसी व्यक्ति की भूमि, भवन का उपयोग बिना अनुमति के झंडे, बैनर, नोटिस और नारा लिखने के लिए करने की अनुमति नहीं है।
6. राजनीतिक दल या उम्मीदवार को किसी भी प्रस्तावित बैठक के स्थान और समय के बारे में स्थानीय पुलिस अधिकारियों को सुरक्षा व्यवस्था के लिए अग्रिम रूप से सूचित करना चाहिए। लाउडस्पीकर या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किसी अन्य सुविधा के लिए उचित अनुमति लेनी चाहिए।
7. हालांकि एक संगठित जुलूस के बारे में स्थानीय पुलिस अधिकारियों को उचित अग्रिम सूचना दी जानी चाहिए, चुनाव आयोग के आदर्श आचार संहिता ने ऐसे अभियानों के दौरान ध्यान में रखे जाने वाले नियमों को निर्धारित किया है। आयोजकों को यह सुनिश्चित करने के लिए पहले से कदम उठाने चाहिए कि यातायात में कोई रुकावट या बाधा न हो। राजनीतिक दलों या उम्मीदवारों को अधिकतम सीमा तक नियंत्रण रखना चाहिए। ऐसी वस्तुएं ले जाने की अनुमति नहीं है जिनका दुरुपयोग किया जा सकता है या विपक्षी दलों और नेताओं के पुतले ले जाने की अनुमति नहीं है।
8. मतदान के दिन, सभी राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को शांतिपूर्ण और व्यवस्थित मतदान सुनिश्चित करने के लिए चुनाव ड्यूटी पर अधिकारियों के साथ सहयोग करना चाहिए। उन्हें मतदान के दिन और उससे 48 घंटे पहले शराब परोसने या बांटने से बचना चाहिए।
9. मतदाताओं को छोड़कर, किसी को भी ईसीआई से वैध पास के बिना मतदान केंद्रों में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है।
10. केंद्र या राज्यों में सत्ताधारी दल को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वह चुनाव अभियान के प्रयोजनों के लिए आधिकारिक स्थिति का उपयोग करने के लिए प्रथाओं में संलग्न नहीं है। मंत्रियों को अपने आधिकारिक दौरे को चुनाव प्रचार के साथ नहीं जोड़ना चाहिए और प्रचार के लिए आधिकारिक मशीनरी या कर्मियों का उपयोग नहीं करना चाहिए।
11. चुनाव के संबंध में मैदान, हेलीपैड जैसे सार्वजनिक स्थानों पर सत्ता पक्ष का एकाधिकार नहीं होना चाहिए। अन्य दलों और उम्मीदवारों को ऐसे स्थानों और सुविधाओं के उपयोग की अनुमति उन्हीं शर्तों और शर्तों पर दी जानी चाहिए जिनका उपयोग सत्ताधारी दल करता है।

अनुच्छेद 355

खबरों में क्यों

राज्य की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए केंद्र ने मणिपुर में अनुच्छेद 355 लागू किया।

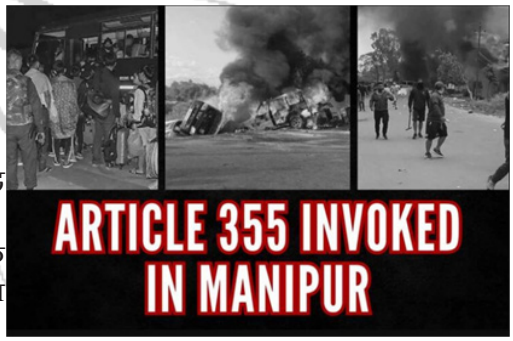

महत्वपूर्ण बिंदु

- पिछले कुछ दिनों में राज्य में अशांति और हिंसा के बाद केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 355 को लागू करके मणिपुर में सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाली है।
- प्रावधान, जिसमें कहा गया है कि बाहरी आक्रमण और आंतरिक गड़बड़ी के खिलाफ हर राज्य की रक्षा करना संघ का कर्तव्य है, राज्य में शांति और व्यवस्था बहाल करने के लिए लागू किया गया है।
- उपायों के एक भाग के रूप में, इंफाल-चुराचांदपुर सड़क को पुलिस और सुरक्षा कर्मियों द्वारा सुरक्षित कर दिया गया है, ताकि किसी भी तरह की हिंसा या अशांति को रोका जा सके।

अनुच्छेद 355 क्या है?

- अनुच्छेद 355 भारत के संविधान के भाग XVIII में अनुच्छेद 352 से 360 तक निहित आपातकालीन प्रावधानों का एक हिस्सा है।
- यह केंद्र सरकार को आंतरिक गड़बड़ी और बाहरी आक्रमण के खिलाफ राज्य की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने का अधिकार देता है।
- यह संविधान में निहित "रक्षा के कर्तव्य" के सिद्धांत पर आधारित है, जो केंद्र सरकार के लिए बाहरी और आंतरिक खतरों से हर राज्य की रक्षा करना अनिवार्य बनाता है।

प्रतिबंध की अवधि

- अनुच्छेद 355 के तहत प्रदान की जाने वाली सहायता की अवधि संविधान में निर्दिष्ट नहीं है।
- स्थिति के सामान्य होने या राज्य सरकार द्वारा ऐसा करने का अनुरोध करने पर केंद्र सरकार अपनी सहायता वापस ले सकती है।
- अनुच्छेद 355 के तहत प्रदान की गई सहायता की अवधि न्यायिक समीक्षा के अधीन है और अगर यह किसी मौलिक अधिकार या संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करती है तो इसे अदालत में चुनौती दी जा सकती है।

मणिपुर में अनुच्छेद 355 लागू करने का कारण

- यह कदम मणिपुर द्वारा अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल करने की मेइती समुदाय की मांग के खिलाफ ऑल ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन, मणिपुर द्वारा एक विरोध मार्च के दौरान राज्य के कई हिस्सों में झड़पों के बाद आया है।
- झड़पों के परिणामस्वरूप कई चोटें और मौतें हुई, जिसके कारण कर्फ्यू लगाया गया और केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई।
- मणिपुर के पहाड़ी जिलों में संघर्ष के दौरान गोली लगने से कई लोग घायल हुए हैं और दो की मौत हुई है।

- अनुसूचित जनजाति (ST) सूची में शामिल करने की मेइती समुदाय की मांग के विरोध में ऑल ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन (ATSUM) द्वारा एकजुटता मार्च के दौरान हिंसा भड़क गई।
- गोली लगने से घायल हुए पांच लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिनमें से दो की बाद में मौत हो गई।
- कर्फ्यू लगाने और अतिरिक्त अर्धसैनिक बलों की तैनाती के बावजूद स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है।
- चुराचांदपुर जिले में झड़पों के बाद सांप्रदायिक तनाव को नियंत्रित करने के लिए राज्य पुलिस के साथ सेना ने हस्तक्षेप किया।

चलने का अधिकार

खबरों में क्यों

पंजाब 'चलने के अधिकार' को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है।

महत्वपूर्ण बिंदु

- राज्य सरकार ने ये निर्देश पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में और एक अन्य सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर किए जाने के बाद अदालत के दो आदेशों के बाद जारी किए हैं।
- भविष्य में मौजूदा सड़कों के सभी विस्तार और नई सड़कों के निर्माण, साइकिल ट्रैक और फुटपाथों का अनिवार्य प्रावधान सभी सड़क के स्वामित्व वाले विभागों और एजेंसियों द्वारा किया जाना चाहिए।
- हर जगह पैदल चलने के रास्ते और साइकिल ट्रैक बनाए जाने चाहिए। हालाँकि, हमें मौजूदा ट्रैक्स का ऑडिट भी करना चाहिए और उनकी कमियों की जाँच करनी चाहिए।
- उदाहरण के लिए, ऐसे ट्रैक नियमित रूप से मोटरबाइकों द्वारा आक्रमण किए जाते हैं।

- इसके अलावा, केवल पैदल चलने वालों के लिए पटरियों में अक्सर बड़े अंतराल होते हैं, जिससे चलना एक खतरनाक व्यायाम बन जाता है।
- दूसरे शब्दों में, चलने के अधिकार को एक उचित मिशन में परिवर्तित किया जाना चाहिए और इसे सफल बनाने के लिए हर कोण का ध्यान रखा जाना चाहिए।
- एनएचएआई और शहरी विकास विभागों को समय सीमा और बजट प्रावधान के साथ फुटपाथ और साइकिल ट्रैक बनाने के लिए एक कार्य योजना तैयार करने का निर्देश दिया गया है।

राहगीरों को हुई परेशानी

- सरकारी आंकड़े बताते हैं कि सड़क दुर्घटनाओं में मरने वालों की संख्या 2019 में 25,858 से बढ़कर 2021 में 29,124 हो गई है, जो दर्शाता है कि सड़क बुनियादी ढांचे पैदल चलने वालों की सुरक्षा को पूरा नहीं करते हैं।
- 2022 की सड़क दुर्घटना की रिपोर्ट अभी तक प्रकाशित नहीं हुई है।
- सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल एक अंतरिम आदेश में राज्यों को पैदल चलने वालों, साइकिल चालकों को अलग, निर्बाध और सुरक्षित पैदल यात्री लेन और साइकिल ट्रैक प्रदान करके उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कहा था।

भारत के संविधान के तहत चलने का अधिकार

- पैदल चलने वालों के लिए सुरक्षित सुविधाएं सुनिश्चित करके "अनुच्छेद 21 के तहत चलने का अधिकार"।
- भारत के संविधान का अनुच्छेद 21: जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण
- अनुच्छेद 21 में कहा गया है कि "कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा।" इस प्रकार, अनुच्छेद 21 दो अधिकारों को सुरक्षित करता है:

1. जीवन का अधिकार, और
2. व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार।

- भारत सरकार अधिनियम, 1935 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 की स्थापना के लिए प्रदान किया गया।
- यह घोषणा करता है कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा।
- अनुच्छेद 21 भारतीय संविधान के भाग III के अंतर्गत आता है और यह भारत के सभी नागरिकों को गारंटीकृत मौलिक अधिकारों में से एक है।
- अनुच्छेद 21 एक मौलिक अधिकार है और भारतीय संविधान के भाग-III में शामिल है।
- यह अधिकार सभी नागरिकों के साथ-साथ गैर-नागरिकों के लिए समान रूप से उपलब्ध है।
- सुप्रीम कोर्ट ने इस अधिकार को "मौलिक अधिकारों का दिल" बताया है
- न्यायमूर्ति भगवती के अनुसार, अनुच्छेद 21 "लोकतांत्रिक समाज में सर्वोच्च महत्व के संवैधानिक मूल्य का प्रतीक है।"
- अनुच्छेद 21 दो अधिकारों को सुरक्षित करता है: जीवन का अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार।
- आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता है।

व्हिप/ सचेतक

खबरों में क्यों

शिवसेना मामले में SC ने कहा, व्हिप नियुक्त करने की शक्ति राजनीतिक दल के पास है।

महत्वपूर्ण बिंदु

- शिवसेना मामले में संविधान पीठ ने एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले समूह द्वारा नामांकित व्हिप को शिवसेना के मुख्य सचेतक के रूप में मान्यता देने के लिए महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष की आलोचना की।

SC अवलोकन

- न्यायालय ने घोषणा की कि श्री एकनाथ शिंदे को शिवसेना विधायक दल के नेता के रूप में स्वीकार करने का अध्यक्ष का निर्णय गैरकानूनी था क्योंकि अध्यक्ष ने यह सत्यापित नहीं किया कि निर्णय को राजनीतिक दल का समर्थन प्राप्त था या नहीं।
- न्यायालय के अनुसार, व्हिप और एक नेता नियुक्त करने की शक्ति "राजनीतिक दल" के पास है, न कि "विधायिका दल" के पास, जैसा कि संविधान की दसवीं अनुसूची में कहा गया है।
- शिंदे के नेतृत्व वाले विद्रोही समूह ने तर्क दिया कि वे "विधायिका दल" थे क्योंकि उनके पास विधायकों का बहुमत था, जिससे उन्हें पार्टी व्हिप और समूह नेता नियुक्त करने का अधिकार मिल गया।
- न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि मतदान करने या मतदान से दूर रहने का निर्देश राजनीतिक दल की ओर से आना चाहिए न कि विधायक दल की ओर से।
- न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि यदि "राजनीतिक दल" शब्द की व्याख्या "विधायिका दल" के रूप में की जाती है तो दसवीं अनुसूची निरर्थक हो जाएगी।
- न्यायालय ने घोषित किया कि विधायी शाखा को राजनीतिक दल से स्वतंत्र रूप से कार्य करने की अनुमति शासन की संवैधानिक प्रणाली के विपरीत है।
- विधायक उस राजनीतिक दल से खुद को अलग नहीं कर सकते हैं जिसके तहत उन्हें मैदान में उतारा गया था और पार्टी के अभियान और ताकत के आधार पर चुनाव जीते थे।
- खंडपीठ ने कहा कि शिवसेना विधायक दल के भीतर परस्पर विरोधी प्रस्ताव थे, जिसके कारण विभिन्न व्हिप और नेताओं की नियुक्ति हुई थी।
- यह सत्यापित किए बिना कि क्या यह राजनीतिक दल की इच्छा का प्रतिनिधित्व करता है, पार्टी के एक गुट को मान्यता देने के अध्यक्ष के निर्णय को अवैध माना गया।
- न्यायालय ने कहा कि अध्यक्ष को जांच करने के बाद पार्टी संविधान के आधार पर राजनीतिक दल द्वारा अधिकृत सचेतक और नेता को मान्यता देनी चाहिए।
- इसमें इस बात पर भी जोर दिया गया कि स्पीकर को लंबित अयोग्यता याचिकाओं पर उचित समय सीमा में निर्णय लेना चाहिए।
- न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि चुनाव आयोग द्वारा शिंदे समूह को आधिकारिक शिवसेना के रूप में मान्यता देने का केवल भावी प्रभाव होगा और पहले शुरू की गई अयोग्यता कार्यवाही को प्रभावित नहीं करेगा।
- फ्लोर टेस्ट के लिए बुलाने के राज्यपाल के फैसले और बाद में उद्धव ठाकरे के इस्तीफे के बारे में, अदालत ने कहा कि हालांकि राज्यपाल और अध्यक्ष ने गलतियां कीं, लेकिन यह ठाकरे सरकार को बहाल नहीं कर सका क्योंकि ठाकरे ने स्वेच्छा से इस्तीफा दे दिया था।
- इसलिए, कोर्ट ने एकनाथ शिंदे को भाजपा के समर्थन से सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करने के राज्यपाल के फैसले को बरकरार रखा।

दसवीं अनुसूची

- संविधान की दसवीं अनुसूची बावनवें संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा जोड़ी गई थी।
- इस संशोधन का उद्देश्य कार्यालय के लालच या अन्य समान विचारों से प्रेरित राजनीतिक दलबदल को हमारे लोकतंत्र की नींव को खतरे में डालने से रोकना था।
- प्रस्तावित उपचार संसद या राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन के किसी भी सदस्य को पद से हटाने का था, जिसे दलबदलू पाया गया था।

अयोग्यता के लिए आधार:

- यदि कोई निर्वाचित सदस्य स्वेच्छा से किसी राजनीतिक दल की सदस्यता छोड़ देता है।
- अगर वह अपने राजनीतिक दल द्वारा जारी किए गए किसी निर्देश के विपरीत सदन में मतदान करता है या मतदान से दूर रहता है।
- यदि कोई सदस्य जो स्वतंत्र रूप से निर्वाचित होता है, किसी दल में शामिल होता है।
- यदि कोई मनोनीत सदस्य 6 महीने की समाप्ति के बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल होता है।
- दलबदल के आधार पर अयोग्यता के सवालों पर निर्णय अध्यक्ष या सदन के सभापति को भेजा जाता है, और उनका निर्णय अंतिम होता है।
- इस अनुसूची के तहत अयोग्यता के संबंध में सभी कार्यवाहियों को संसद या किसी राज्य के विधानमंडल की कार्यवाही माना जाता है, जैसा कि मामला है।

भारत में व्हिप

- 'व्हिप' के कार्यालय का उल्लेख न तो भारत के संविधान में है और न ही सदन के नियमों में और न ही किसी संसदीय क़ानून में। यह संसदीय सरकार के सम्मेलनों पर आधारित है।

RAO'S ACADEMY

- व्हिप एक लिखित आदेश है जो राजनीतिक दल अपने सदस्यों को एक महत्वपूर्ण वोट के लिए उपस्थित होने के लिए जारी करता है, या यह कि वे केवल एक विशेष तरीके से मतदान करते हैं।
- एक राजनीतिक दल के पास दसवीं अनुसूची (दल-बदल विरोधी कानून) के तहत अपने विधायकों को व्हिप जारी करने का संवैधानिक अधिकार है।
- हाउस फ्लोर पर व्यवसाय के प्रभावी और कुशल संचालन के लिए व्हिप आवश्यक है।

इंटरनेट शटडाउन

खबरों में क्यों

सुप्रीम कोर्ट ने अनुराधा भसीन के मामले में निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुपालन की मांग वाली अर्जी पर नोटिस जारी किया।

महत्वपूर्ण बिंदु

- अनुराधा भसीन द्वारा एक याचिका दायर की गई थी, जिसमें जम्मू-कश्मीर के विशेष दर्जे को समाप्त करने के बाद कश्मीर क्षेत्र में इंटरनेट, मीडिया और अन्य प्रतिबंधों को चुनौती दी गई थी।

इंटरनेट बंद से संबंधित संवैधानिक प्रावधान:

- इंटरनेट के माध्यम से भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता क्रमशः अनुच्छेद 19(1)(ए) और अनुच्छेद 19(1)(जी) के तहत संवैधानिक रूप से संरक्षित अधिकार हैं।
- मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध संविधान के अनुच्छेद 19(2) और अनुच्छेद 19(6) के तहत शासनादेश के अनुसार और आनुपातिकता के परीक्षण के अनुरूप होना चाहिए।
- इंटरनेट के माध्यम से अभिव्यक्ति प्रासंगिक हो गई है और सूचना प्रसार के प्रमुख साधनों में से एक है।
- फैसले में इंटरनेट शटडाउन के लिए पूर्वापेक्षाओं के निर्धारण सहित अन्य मुद्दे शामिल थे; इंटरनेट के अनिश्चितकालीन निलंबन की अक्षमता; इंटरनेट निलंबन की अवधि समीक्षा।

निम्नलिखित मामले में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां:

- अदालतों के समक्ष कानूनी चुनौती को सक्षम करने के लिए इंटरनेट निलंबन आदेशों को प्रकाशित किया जाना चाहिए।
- आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 144 के तहत इंटरनेट निलंबन आदेश जारी नहीं किए जाते हैं क्योंकि दूरसंचार निलंबन नियम 2017 की अधिसूचना के बाद से स्थिति बदल गई है।
- टेलीकॉम सर्विसेज (पब्लिक इमरजेंसी या पब्लिक सर्विस) नियम, 2017 के अस्थायी निलंबन के तहत अनिश्चित काल के लिए इंटरनेट सेवाओं को निलंबित करने का आदेश अस्वीकार्य है।
- निलंबन नियमों के तहत जारी किए गए इंटरनेट को निलंबित करने वाले किसी भी आदेश को आनुपातिकता के सिद्धांत का पालन करना चाहिए और इसे आवश्यक अवधि से अधिक नहीं बढ़ाया जाना चाहिए।
- एक समीक्षा समिति को इंटरनेट निलंबन आदेश जारी होने के 5 दिनों के भीतर उसकी समीक्षा करनी चाहिए, उसके बाद हर 7 दिनों के भीतर समय-समय पर समीक्षा करनी चाहिए।
- निलंबन नियमों के तहत इंटरनेट निलंबित करने का कोई भी आदेश न्यायिक समीक्षा के अधीन है।

आदर्श कारागार अधिनियम

खबरों में क्यों

ब्रिटिश काल के कानून को बदलने के लिए गृह मंत्रालय मॉडल जेल अधिनियम 2023 तैयार कर रहा है

महत्वपूर्ण बिंदु

- गृह मंत्रालय ने 'आदर्श जेल अधिनियम 2023' तैयार किया है जो जेल प्रशासन में सुधार के लिए ब्रिटिश युग के कानून की जगह लेगा जो कैदियों के सुधार और पुनर्वास पर ध्यान केंद्रित करेगा।
- मॉडल अधिनियम की मुख्य विशेषताओं में जेलों में मोबाइल फोन जैसी प्रतिबंधित वस्तुओं के उपयोग के लिए कैदियों और जेल कर्मचारियों के लिए सजा के प्रावधान, उच्च सुरक्षा जेलों की स्थापना और प्रबंधन, खुली जेल (खुली और अर्ध-खुली) और कठोर अपराधियों और आदतन अपराधियों की आपराधिक गतिविधियों से समाज की सुरक्षा के प्रावधान शामिल हैं।
- इसमें अच्छे आचरण को प्रोत्साहित करने के लिए कैदियों को कानूनी सहायता, पैरोल, फरलो और समय से पहले रिहाई के प्रावधान भी शामिल हैं।
- देश में जेल और 'उसमें हिरासत में लिए गए व्यक्ति' एक राज्य का विषय हैं और इस संदर्भ में मौजूदा कानून, 1894 का जेल अधिनियम स्वतंत्रता-पूर्व युग का अधिनियम है और लगभग 130 साल पुराना है।
- दो अन्य संबंधित कानून - द प्रिजनर्स एक्ट, 1900 और द ट्रांसफर ऑफ प्रिजनर्स एक्ट, 1950 भी दशकों पुराने हैं।
- मॉडल अधिनियम राज्यों के लिए और उनके अधिकार क्षेत्र में गोद लेने के लिए एक "मार्गदर्शक दस्तावेज" के रूप में काम कर सकता है।
- देश में जेल और 'उसमें हिरासत में लिए गए व्यक्ति' एक राज्य का विषय हैं और इस संदर्भ में मौजूदा कानून, 1894 का जेल अधिनियम स्वतंत्रता-पूर्व युग का अधिनियम है और लगभग 130 साल पुराना है, यह कहा।
- दो अन्य संबंधित कानून - द प्रिजनर्स एक्ट, 1900 और द ट्रांसफर ऑफ प्रिजनर्स एक्ट, 1950 भी दशकों पुराने हैं। मॉडल अधिनियम, मंत्रालय ने कहा, राज्यों के लिए और उनके अधिकार क्षेत्र में गोद लेने के लिए एक "मार्गदर्शक दस्तावेज" के रूप में काम कर सकता है।

सीमाएं

- यह पाया गया कि मौजूदा कारागार अधिनियम में "कई खामियां" थीं और मौजूदा अधिनियम में सुधारात्मक फोकस की "स्पष्ट चूक" थी।
- मंत्रालय ने, इसलिए, पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो (बीपीआरएंडडी) को निर्देश दिया, जो पुलिस संबंधी विषयों पर केंद्र सरकार का थिंक टैंक है, कानूनों की समीक्षा करने और एक नया मसौदा तैयार करने का निर्देश दिया।
- मौजूदा अधिनियम मुख्य रूप से अपराधियों को हिरासत में रखने और जेलों में अनुशासन और व्यवस्था को लागू करने पर केंद्रित है। मौजूदा अधिनियम में कैदियों के सुधार और पुनर्वास का कोई प्रावधान नहीं है।

आदर्श कारागार अधिनियम, 2023 उद्देश्य

- एक व्यापक 'आदर्श कारागार अधिनियम, 2023' को समग्र रूप से मार्गदर्शन प्रदान करने और मौजूदा कारागार अधिनियम में अंतराल को संबोधित करने के उद्देश्य से अंतिम रूप दिया गया था, जिसमें जेल प्रबंधन में प्रौद्योगिकी का उपयोग, कैदियों को पैरोल, फरलो, छूट के प्रावधान शामिल हैं। अच्छे आचरण को प्रोत्साहित करना, महिला/ट्रांसजेंडर कैदियों के लिए विशेष प्रावधान, कैदियों की शारीरिक और मानसिक भलाई और कैदियों के सुधार और पुनर्वास पर ध्यान केंद्रित करना।
- जेल अधिनियम, 1894 के साथ, कैदी अधिनियम, 1900 और कैदियों का स्थानांतरण अधिनियम, 1950 की भी गृह मंत्रालय द्वारा समीक्षा की गई है और इन अधिनियमों के प्रासंगिक प्रावधानों को 'आदर्श जेल अधिनियम, 2023' में "सम्मिलित" किया गया है।
- सरकारें और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन आदर्श कारागार अधिनियम, 2023 को अपने अधिकार क्षेत्र में अपनाकर ऐसे संशोधनों के साथ लाभ उठा सकते हैं जिन्हें वे आवश्यक समझ सकते हैं, और अपने अधिकार क्षेत्र में मौजूदा तीन अधिनियमों को निरस्त कर सकते हैं।

केंद्र बिंदु के क्षेत्र

- मॉडल अधिनियम के कुछ फोकस क्षेत्रों में सुरक्षा मूल्यांकन और कैदियों का अलगाव, व्यक्तिगत सजा योजना; शिकायत निवारण, जेल विकास बोर्ड, कैदियों के प्रति व्यवहार में बदलाव और महिला कैदियों, ट्रांसजेंडर आदि के लिए अलग आवास का प्रावधान।
- मॉडल अधिनियम जेल प्रशासन में पारदर्शिता लाने की दृष्टि से जेल प्रशासन में प्रौद्योगिकी के उपयोग के प्रावधान, अदालतों के साथ वीडियो--कॉन्फ्रेंसिंग के प्रावधान, जेलों में वैज्ञानिक और तकनीकी हस्तक्षेप आदि के बारे में भी बात करता है।
- इसमें कहा गया है कि पिछले कुछ दशकों में विश्व स्तर पर जेलों और जेल के कैदियों के बारे में एक पूरी तरह से "नया परिप्रेक्ष्य" विकसित हुआ है। जेलों को आज प्रतिशोधात्मक निवारक के स्थान के रूप में नहीं देखा जाता है, बल्कि उन्हें सुधारात्मक और सुधारक संस्थानों के रूप में देखा जाता है जहां कैदियों को कानून का पालन करने वाले नागरिकों के रूप में समाज में परिवर्तित और पुनर्वासित किया जाता है।

फोरम शॉपिंग

खबरों में क्यों

हाल ही में भारत के मुख्य न्यायाधीश (Chief Justice of India- CJI) ने फोरम शॉपिंग की प्रथा की निंदा की।

महत्वपूर्ण बिंदु

फोरम शॉपिंग का अभ्यास:

परिचय:

- फोरम शॉपिंग अनुकूल परिणाम प्राप्त करने की आशा में एक कानूनी मामले के लिये जान-बूझकर एक विशेष अदालत का चयन करने के अभ्यास को संदर्भित करता है।
- वादी और वकील प्राय: इस रणनीति को अपनी मुकदमेबाज़ी योजना का हिस्सा मानते हैं।
- उदाहरण के लिये वे अपने मामले पर अधिक ध्यान आकर्षित करने के लिये सर्वोच्च न्यायालय (SC) जैसे उच्चतम न्यायालय का विकल्प चुन सकते हैं। हालाँकि अगर कोई स्पष्ट रूप से व्यवस्था में हेर-फेर करने या किसी विशेष न्यायाधीश से बचने की कोशिश कर रहा है, तो इसे अनुचित माना जाता है।
- इसी तरह "बेंच हंटिंग" एक अनुकूल आदेश सुनिश्चित करने के लिये किसी विशेष न्यायाधीश या बेंच द्वारा अपने मामलों की सुनवाई हेतु प्रबंधन करने वाले याचिकाकर्त्ताओं को संदर्भित करता है।

लाभ:

- यह वादी को न्यायालय में न्याय और मुआवज़े की मांग करने की अनुमति दे सकता है जो कि उसके दावों या हितों के प्रति अधिक सहानुभूतिपूर्ण है।
- यह न्यायालयों और न्यायाधीशों के बीच उनकी दक्षता और सेवा की गुणवत्ता में सुधार के लिये प्रतिस्पर्द्धा एवं नवाचार को प्रोत्साहित कर सकता है।

हानि:

- फोरम शॉपिंग की न्यायाधीशों द्वारा आलोचना की गई है क्योंकि इससे प्रतिवादी पक्ष के साथ अन्याय हो सकता है और विभिन्न न्यायालयों के कार्यभार में असंतुलन पैदा हो सकता है।

- न्यायाधीशों ने कुछ न्यायालयों पर अत्यधिक बोझ और न्यायिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप का हवाला दिया है।
- यह पूर्वाग्रह या पक्षपात की धारणा बनाकर न्यायालयों और न्यायाधीशों के अधिकार एवं वैधता को कमज़ोर कर सकता है।
- यह कानूनों के टकराव और कई कार्यवाहियों में वृद्धि कर मुकदमेबाज़ी की लागत एवं जटिलता को बढ़ा सकता है।

फोरम शॉपिंग को हतोत्साहित करना:

- यहाँ तक कि अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम के न्यायालय भी फोरम शॉपिंग को हतोत्साहित/निषेध करते हैं। कॉमन लॉ/सामान कानून वाले देशों में फोरम शॉपिंग के अभ्यास को रोकने हेतु "फोरम गैर-सुविधा" के सिद्धांत का उपयोग किया जाता है।
- संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और राष्ट्रमंडल सभी की कॉमन लॉ के साथ ब्रिटिश पृष्ठभूमि जुड़ी हुई है तथा इन राष्ट्रों की कानूनी प्रणालियाँ बड़े पैमाने पर कॉमन लॉ सिद्धांत पर आधारित हैं।
- यह सिद्धांत एक न्यायालय को किसी मामले के अधिकार क्षेत्र को अस्वीकार करने की अनुमति देता है, यदि कोई अन्य न्यायालय इसे सुनने हेतु अधिक उपयुक्त हो। यह निष्पक्षता की गारंटी देता है एवं उपयुक्त न्यायिक अधिकारियों को मामले सौंपता है।

फोरम शॉपिंग न्याय और न्यायिक प्रक्रिया पर प्रभाव:

- यह नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत से समझौता कर सकता है, जिसके लिये आवश्यक है कि निष्पक्ष न्यायाधिकरण के समक्ष प्रत्येक व्यक्ति की निष्पक्ष सुनवाई होनी चाहिये।
- यह समानता के सिद्धांत का उल्लंघन कर सकता है, जिसके लिये यह आवश्यक है कि न्यायालयों को सामान्य हित के मामलों पर एक-दूसरे के निर्णयों का सम्मान करना चाहिये और उन्हें टालना चाहिये।
- यह अंतिमता के सिद्धांत को बाधित कर सकता है, जिसके लिये आवश्यक है कि मुकदमेबाज़ी किसी बिंदु पर समाप्त होनी चाहिये और अनिश्चित काल तक लंबी नहीं चलनी चाहिये।

फोरम शॉपिंग पर सर्वोच्च न्यायालय का दृष्टिकोण:

डॉ. खैर-उन-निसा और अन्य बनाम जम्मू-कश्मीर केंद्रशासित प्रदेश एवं अन्य 2023:

- जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय ने एक ही कारण होने के बावजूद अदालत की विभिन्न शाखाओं के समक्ष कई याचिकाएँ दायर करके फोरम शॉपिंग में शामिल होने हेतु याचिकाकर्ताओं पर एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया।

विजय कुमार घई बनाम पश्चिम बंगाल राज्य 2022:

- सर्वोच्च न्यायालय ने फोरम शॉपिंग को "अदालतों द्वारा एक विवादित प्रथा" करार दिया, जिसे "कानून में कोई मंज़ूरी और सर्वोच्चता नहीं है"।

धनवंतरी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बनाम राजस्थान राज्य 2022:

- राजस्थान उच्च न्यायालय ने फोरम शॉपिंग में शामिल होने के लिये एक पार्टी पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाने के आदेश को बरकरार रखा।

भारत संघ और अन्य बनाम सिप्ला लिमिटेड 2017:

- सर्वोच्च न्यायालय ने फोरम शॉपिंग के लिये अपनाए जाने वाले "कार्यात्मक परीक्षण" को निर्धारित किया।
- सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित "कार्यात्मक परीक्षण" यह निर्धारित करने के लिये था कि क्या एक वादी वास्तव में न्याय की मांग कर रहा है या फोरम शॉपिंग के माध्यम से चालाकी की रणनीति में संलग्न है।

रोस्मेर्टा HSRP वेंचर्स प्रा. लिमिटेड बनाम दिल्ली सरकार और अन्य 2017:

- दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक निजी कंपनी पर जुर्माना लगाया जिसमें पाया गया कि वह मध्यस्थता के मामले में "फोरम हंटिंग" में लिप्त थी।

कामिनी जायसवाल बनाम भारत संघ 2017:

- सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि "बेईमान तत्त्व" हमेशा अपनी पसंद की अदालत या मंच खोजने के लिये तत्पर रहते हैं लेकिन कानून द्वारा उन्हें ऐसा करने की अनुमति नहीं है।

चेतक कंस्ट्रक्शन लिमिटेड बनाम ओम प्रकाश 1988:

- भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात पर बल दिया कि वादियों को अपनी सुविधा के लिये न्यायालय चुनने की स्वतंत्रता नहीं होनी चाहिये। कोर्ट ने कहा कि "फोरम शॉपिंग" के किसी भी प्रयास को दृढ़ता से हतोत्साहित किया जाना चाहिये।

RAO'S ACADEMY

3 पर्यावरण और पारिस्थितिकी

नागरिक उड्डयन में अंतर्राष्ट्रीय जलवायु कार्रवाई

खबरों में क्यों

भारत 2027 से नागरिक उड्डयन में अंतर्राष्ट्रीय जलवायु कार्रवाई में शामिल होगा

महत्वपूर्ण बिंदु

- भारत 2027 में इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गनाइजेशन (ICAO) की कार्बन ऑफसेटिंग एंड रिडक्शन स्कीम फॉर इंटरनेशनल एविएशन (CORSIA) और लॉन्ग-टर्म एस्पिरेशनल गोल्स (LTAG) में भाग लेना शुरू कर देगा।
- नई दिल्ली में आयोजित नागरिक उड्डयन मंत्रालय की संसद की सलाहकार समिति की बैठक में इसकी घोषणा की गई।
- बैठक की अध्यक्षता नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने की।
- ICAO को अपने फोकस क्षेत्रों में से एक के रूप में अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन से कार्बन उत्सर्जन को कम करने का काम सौंपा गया है।
- विमानन से कार्बन उत्सर्जन और जलवायु परिवर्तन पर इसके प्रभाव को कम करने के लिए, वैश्विक निकाय ने कई प्रमुख आकांक्षात्मक लक्ष्यों को अपनाया है।
- उनमें से 2050 तक दो प्रतिशत वार्षिक ईंधन दक्षता में सुधार, कार्बन तटस्थ विकास और 2050 तक शुद्ध शून्य शामिल हैं।
- ICAO ने उन्हें CORSIA और LTAG के तहत क्लब कर दिया है।
- पूर्व को तीन चरणों में लागू किया जाना है।
- 2027 से ICAO के जलवायु कार्रवाई उपायों में शामिल होने के औचित्य के रूप में।
- इससे भारत जैसे विकासशील देशों की एयरलाइनों को और अधिक विकसित होने का समय मिल सकेगा ताकि उन्हें CORSIA के कारण किसी भी प्रतिकूल वित्तीय परिणामों का सामना न करना पड़े।
- ऑफसेट के कारण होने वाले वित्तीय प्रभाव अलग-अलग एयरलाइनों द्वारा वहन किए जाते हैं, जो उनके अंतरराष्ट्रीय परिचालन पर निर्भर करता है। CORSIA केवल एक देश से दूसरे देश जाने वाली उड़ानों पर लागू होता है।
- जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के पक्षकारों के 26वें सम्मेलन (COP26) में भारत 2070 तक शुद्ध शून्य करने के लिए प्रतिबद्ध है।

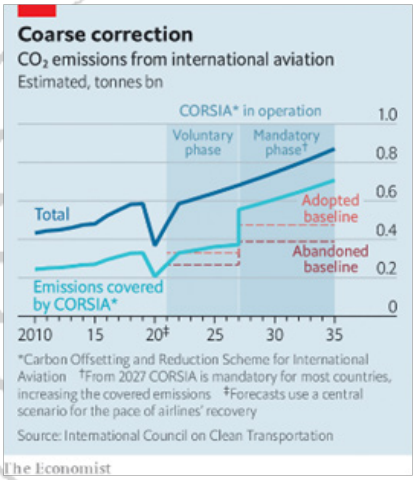

कोर्सिया (CORSIA) के बारे में:

- यह ऐसे उत्सर्जन के स्तर को स्थिर करने के लिए अंतरराष्ट्रीय विमानन CO2 उत्सर्जन को ऑफसेट करने के लिए एक वैश्विक बाजार-आधारित उपाय है।
- हवाई जहाज संचालकों द्वारा वैश्विक कार्बन बाजार से उत्सर्जन इकाइयों के अधिग्रहण और रद्दीकरण के माध्यम से CO2 उत्सर्जन की भरपाई की जाएगी।
- यह केवल एक देश से दूसरे देश जाने वाली उड़ानों पर लागू होता है।
- यह घरेलू विमानन पर लागू नहीं होता है।
- इसे 3 चरणों में लागू किया जाएगा।
- (2021-2026) के लिए केवल पहले दो चरणों में भागीदारी स्वैच्छिक है।
- भारत कोर्सिया के स्वैच्छिक चरणों में भाग नहीं लेगा।
- 2018 में, ICAO ने CORSIA को लागू करने के लिए मानक और अनुशंसित अभ्यास (SARPs) को अपनाया है।

इस दिशा में भारत सरकार की पहल:

- विमानन क्षेत्र की अन्य पहलों में जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति 2018 और जैव-विमानन टर्बाइन ईंधन कार्यक्रम जैसी नीतियां शामिल हैं।
- जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति 2018 का उद्देश्य विमानन क्षेत्र के D-कार्बोनाइजेशन के लक्ष्य को प्राप्त करना है।
- बायो-ATF कार्यक्रम का उद्देश्य विमानन में स्वच्छ ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देना है।
- भारत ICAO के असिस्टेंस कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ट्रेनिंग फॉर सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल्स (SAF) कार्यक्रम में शामिल हो गया है, जो राज्यों को SAF के विकास और तैनाती में अपनी पूरी क्षमता विकसित करने का अवसर प्रदान करेगा।
- भारतीय मानक ब्यूरो ने 2019 में बायो-जेट ATF के लिए भारतीय मानक जारी किया है।

हूज टिपिंग द स्केल (Who's tipping the scales)

खबरों में क्यों

हाल ही में, सस्टेनेबल फूड सिस्टम्स (IPES) पर विशेषज्ञों के अंतर्राष्ट्रीय पैनल द्वारा "हूज टिपिंग द स्केल" शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की गई है।

महत्वपूर्ण बिंदु

रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएं:

- गवर्नेंस और स्पेस में फर्मों की उपस्थिति बढ़ रही है, जो वैध अभिनेता होने का दावा करती हैं।
- हाल के दशकों में, निगम सरकारों को यह विश्वास दिलाने में सफल रहे हैं कि उन्हें खाद्य प्रणालियों के भविष्य पर किसी भी चर्चा में केंद्रीय होना चाहिए।
- सार्वजनिक-निजी भागीदारी और बहु-हितधारक राउंडटेबल्स द्वारा खाद्य प्रशासन और निर्णय लेने में निजी निगमों की भूमिका को सामान्य कर दिया गया है, जबकि सार्वजनिक प्रशासन की पहल निजी धन पर बहुत अधिक निर्भर हो गई है।
- संयुक्त राष्ट्र खाद्य प्रणाली शिखर सम्मेलन, 2021 को सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रशासन में कॉर्पोरेट प्रभाव के महत्व पर प्रकाश डालने के लिए एक वाटरशेड क्षण के रूप में वर्णित किया गया था।
- नागरिक समाज संगठनों, खाद्य विद्वानों, और सामाजिक आंदोलनों ने चिंता व्यक्त की है कि खाद्य प्रशासन में निगमों की बढ़ती भागीदारी सार्वजनिक भलाई को कमजोर कर सकती है और लोगों और समुदायों के अधिकारों को प्रभावित कर सकती है।
- निगमों ने दृश्य और अदृश्य तरीकों से वैश्विक खाद्य प्रशासन को प्रभावित किया है।
- बेहतर पोषण के लिए वैश्विक गठबंधन, खाद्य और भूमि उपयोग गठबंधन, और पोषण आंदोलन को बढ़ाने जैसे वैश्विक खाद्य प्रणाली प्लेटफार्मों में कॉर्पोरेट प्रभाव देखा जा सकता है।

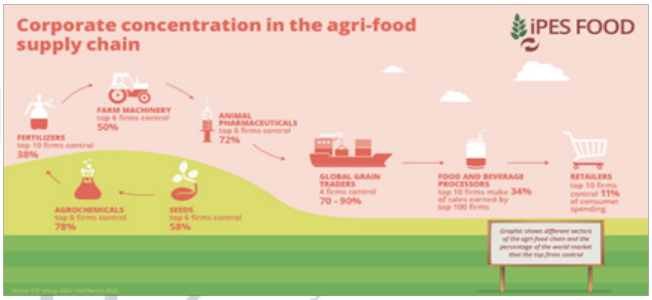

- कोविड-19 महामारी, यूक्रेन पर रूस के आक्रमण और खाद्य मुद्रास्फीति के साथ मिलकर, कॉर्पोरेट भागीदारी के मुद्दे को बढ़ा दिया।
- CGIAR (अंतर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान पर सलाहकार समूह) निजी फर्मों और खाद्य उद्योग से जुड़े निजी परोपकारी संस्थानों से वित्त पोषण पर निर्भर था।
- बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, जो 2020 में CGIAR का दूसरा सबसे बड़ा दाता था, ने लगभग 100 मिलियन अमरीकी डालर का योगदान दिया, जो संयुक्त राज्य अमेरिका सहित व्यक्तिगत सरकारों द्वारा दिए गए योगदान से कहीं अधिक था।
- यह भी पाया गया कि FAO ने अपने पूरे इतिहास में उद्योग भागीदारी के माध्यम से निगमों के साथ घनिष्ठ सहयोग किया है।

सतत खाद्य प्रणालियों पर विशेषज्ञों के अंतर्राष्ट्रीय पैनल के बारे में

- यह विशेषज्ञों का एक विविध और स्वतंत्र पैनल है जो अनुसंधान, स्थिरता और खाद्य प्रणालियों के बारे में सोचने के नए तरीकों से निर्देशित होता है।
- 2015 से, IPES-फूड ने नीति उन्मुख अनुसंधान और नीति प्रक्रियाओं के साथ सीधे जुड़ाव के माध्यम से वैश्विक खाद्य प्रणाली सुधार पर बहस को विशिष्ट रूप से आकार दिया है।
- 5 महाद्वीपों के 16 देशों के 23 विशेषज्ञों के साथ, पैनल विश्व खाद्य पुरस्कार विजेता, लेगियन डी'होनूर के धारक, एक बाल्ज़न पुरस्कार विजेता और राइट लाइवलीहुड अवार्ड के दो प्राप्तकर्ताओं सहित वैश्विक खाद्य प्रणालियों पर अग्रणी विचारकों को एक साथ लाता है।
- खाद्य प्रणाली अभिनेताओं की एक विस्तृत श्रृंखला के साथ सह-निर्माण समाधानों के ट्रैक रिकॉर्ड के साथ, आईपीईएस-फूड ज्ञान के लिए एक लोकतांत्रिक दृष्टिकोण अपनाता है जो अनुभवात्मक, स्वदेशी और पारंपरिक ज्ञान के महत्व को पहचानते हुए अत्याधुनिक विज्ञान को महत्व देता है।
- आईपीईएस-फूड सरकारों या निगमों से फंडिंग स्वीकार नहीं करता है, पैनल को स्वतंत्र विश्लेषण देने की अनुमति देता है जो सबसे अधिक दबाव वाले प्रश्नों को संबोधित करता है।

जलवायु वित्त कार्यक्रम

खबरों में क्यों

हाल ही में एडीबी ने जलवायु वित्त कार्यक्रम की घोषणा की: एशिया और प्रशांत क्षेत्र में जलवायु के लिए अभिनव वित्त सुविधा

महत्वपूर्ण बिंदु

- एशियाई विकास बैंक (ADB) ने ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के प्रति लचीले बुनियादी ढांचे के निर्माण में मदद करने के लिए धन गारंटी सुविधा की घोषणा की।
- नई फंडिंग योजना किसी विकास बैंक द्वारा विकसित की जाने वाली अपनी तरह की पहली व्यवस्था है और एशिया को बुरी तरह प्रभावित करने वाले जलवायु संकट से निपटने के लिए ऐसे उधारदाताओं को शेयरधारकों के दबाव का सामना करना पड़ता है।
- ADB ने कहा कि एशिया और प्रशांत में जलवायु के लिए नवोन्मेषी वित्त सुविधा (IAF-CAP) का नाम दिया गया, यह योजना बहुपक्षीय विकास बैंक द्वारा अपनाई गई जलवायु वित्त के लिए पहली लीवरेज्ड गारंटी तंत्र है।
- IF-CAP 2019-2030 के लिए जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए अपने स्वयं के संसाधनों से $100 बिलियन का उपयोग करने के ADB के लक्ष्य को पूरा करने में योगदान देगा।
- कार्यक्रम के तहत, डेनमार्क, जापान, दक्षिण कोरिया, स्वीडन, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका ऋणदाताओं के कुछ ऋणों की गारंटी देंगे और उनके कर्जदारों द्वारा अपने कर्ज चुकाने में चूक होने की स्थिति में उन्हें नुकसान उठाना पड़ेगा।
- यह ADB को क्रेडिट जोखिम के लिए आवश्यक पूंजी मुक्त करेगा और इसे एशिया में जलवायु से संबंधित परियोजनाओं के लिए ऋण बढ़ाने की अनुमति देगा।

- एशिया जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील क्षेत्रों में से एक है। ADB ने कहा कि सदी की शुरुआत के बाद से 40 फीसदी से अधिक जलवायु संबंधी आपदाएं एशिया और प्रशांत क्षेत्र में हुई हैं।
- दक्षिण कोरिया के इंचियोन में एशियाई वित्त नेताओं की एक बैठक से पहले इसकी फंडिंग की घोषणा, जिसमें इस बात पर बहस होने की संभावना है कि इस क्षेत्र को बाजार की अशांति के आर्थिक प्रभाव को कैसे संबोधित करना चाहिए।
- एशिया और प्रशांत में जलवायु के लिए अभिनव वित्त सुविधा (इफ-कैप) कहा जाता है, कार्यक्रम के प्रारंभिक भागीदारों में डेनमार्क, जापान, दक्षिण कोरिया, स्वीडन, UK और US शामिल हैं।
- वे ADB के साथ बैंक के संप्रभु ऋण पोर्टफोलियो के कुछ हिस्सों की गारंटी के साथ परियोजना तैयार करने के लिए अनुदान प्रदान करने के लिए चर्चा कर रहे हैं।
- ADB ने कहा कि गारंटियों द्वारा बनाए गए कम जोखिम जोखिम से बैंक को जलवायु परियोजनाओं के लिए नए ऋणों में तेजी लाने के लिए पूंजी मुक्त करने की अनुमति मिलेगी।
- बैंक ने कहा कि गारंटीशुदा प्रत्येक $1 के लिए, $5 तक नए जलवायु ऋण सृजित किए जा सकते हैं।
- बैंक ने कहा, "'$1 इन, $5 आउट' के मॉडल के साथ, गारंटियों में US $3 बिलियन की प्रारंभिक महत्वाकांक्षा पूरे एशिया और प्रशांत क्षेत्र में बहुत जरूरी जलवायु परियोजनाओं के लिए नए ऋणों में US $15 बिलियन तक बना सकती है।"

एशियाई विकास बैंक (ADB)

- 1963 में एशिया और सुदूर पूर्व के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक आयोग द्वारा आयोजित एशियाई आर्थिक सहयोग पर पहले मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में एक प्रस्ताव पारित होने के बाद 1966 में स्थापित किया गया।
- उद्देश्य: ऋण, तकनीकी सहायता, अनुदान और इक्विटी निवेश प्रदान करके एशिया के क्षेत्र में आर्थिक विकास, सहयोग और अत्यधिक गरीबी उन्मूलन को बढ़ावा देना।
- सदस्यता: 68 सदस्य।
- सर्वोच्च नीति-निर्माण निकाय बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है, जिसमें 68 सदस्य देशों में से प्रत्येक से एक प्रतिनिधि शामिल होता है।
- पांच सबसे बड़े शेयरधारक जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका हैं, इसके बाद पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, भारत और ऑस्ट्रेलिया हैं।

सीमा पार सहयोग

खबरों में क्यों

बांग्लादेश, भारत को बाघ संरक्षण के लिए सीमा-पार सहयोग की आवश्यकता है

महत्वपूर्ण बिंदु

- बांग्लादेश के पर्यावरण मंत्री ने सात बड़ी बिल्लियों के संरक्षण और संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट्स एलायंस (IBCA) के निर्माण का समर्थन करते हुए सीमा पार सहयोग को मजबूत करने की आवश्यकता पर जोर दिया।
- प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल के हिस्से के रूप में आयोजित मैसूरु में बाघ संरक्षण पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में बांग्लादेश के मंत्री ने स्थानीय समुदाय की सक्रिय भागीदारी के साथ शून्य अवैध शिकार लक्ष्यों को प्राप्त करके जंगली बाघों की संख्या को दोगुना करने के बांग्लादेश के दृष्टिकोण को प्रस्तुत किया।
- बांग्लादेश नेशनल टाइगर रिकवरी प्रोग्राम (2022 से 2034) और दूसरी पीढ़ी के बांग्लादेश टाइगर एक्शन प्लान (2018-2027) को लागू कर रहा है जिसमें बाघ सर्वेक्षण शामिल है; आनुवंशिक अध्ययन; स्मार्ट गश्त और ड्रोन के साथ सुंदरबन की निगरानी।
- सुंदरवन और बंगाल टाइगर की सुरक्षा और संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए वन विभाग के अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों के साथ-साथ स्थानीय समुदाय के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम चलाया जाता है।
- बांग्लादेश और भारत ने 2011 में सुंदरबन में रॉयल बंगाल टाइगर के संरक्षण के लिए सहयोग को मजबूत करने के लिए एक प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए।
- वन्य जीवों के अवैध व्यापार से निपटने तथा वन्य जीव शिक्षा, शोध एवं प्रशिक्षण की क्षमता को सुदृढ़ करने के लिए वन विभाग के अधीन वन्य जीव अपराध नियंत्रण इकाई की स्थापना की गई है।
- बांग्लादेश सरकार बाघ-मानव संघर्ष को कम करने के लिए विलेज टाइगर रिस्पांस टीम, को-मैनेजमेंट कमेटी और कम्युनिटी पेट्रोल ग्रुप बनाकर बाघ संरक्षण गतिविधियों में स्थानीय समुदाय को शामिल कर रही है।

तीन प्रकार के TBC क्षेत्र (TBCAs) शामिल हैं

- ट्रांसबाउंड्री संरक्षित क्षेत्र (TPA), भौगोलिक स्थान जिसमें संरक्षित क्षेत्र शामिल हैं।
- TBC लैंडस्केप और/या सीस्केप, एक पारिस्थितिक रूप से जुड़ा क्षेत्र जो पारिस्थितिक प्रक्रियाओं को बनाए रखता है और एक या अधिक अंतरराष्ट्रीय सीमाओं को पार करता है।
- सीमा पार प्रवासन संरक्षण क्षेत्र, दो या दो से अधिक देशों में वन्यजीव आवास जो प्रवासी प्रजातियों की आबादी को बनाए रखने के लिए आवश्यक हैं।
- भारतऐसे TBCA को नेपाल और भूटान के साथ साझा करता है, जैसे कंचनजंगा संरक्षण क्षेत्र, भारत और तिब्बत की सीमा के पास नेपाल के पूर्वोत्तर कोने में।
- तराई आर्क लैंडस्केप (TAL) भारतीय राज्यों उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और नेपाल की निचली पहाड़ियों में फैला हुआ है।

- पवित्र हिमालयी परिदृश्य जिसका 74% क्षेत्र नेपाल में पड़ता है, 25% भारत के सिक्किम में पड़ता है, और शेष भूटान में पड़ता है।
- पूर्वी हिमालय में ट्रांसबाउंडरी मानस संरक्षण क्षेत्र (TraMCA) जो भूटान को उत्तर पूर्व भारत से जोड़ता है।

कोल एक्शन प्लान 2023 -24

खबरों में क्यों

कोयला मंत्रालय कार्य योजना 2023 -24 लक्ष्य 1012 मिलियन टन कोयला उत्पादन

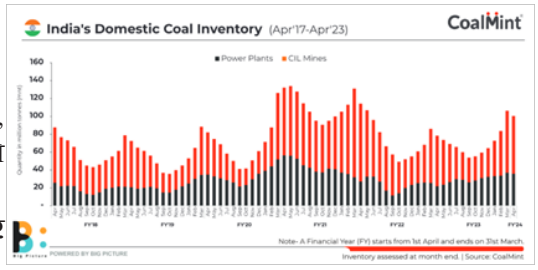

महत्वपूर्ण बिंदु

- कोयला मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कोयला क्षेत्र में उत्पादन, दक्षता, स्थिरता, नई प्रौद्योगिकियों आदि को बढ़ाकर आत्मनिर्भर भारत को प्राप्त करने के लक्ष्य के साथ एक कार्य योजना की परिकल्पना की है।
- यह एक महत्वाकांक्षी, अच्छी तरह से तैयार किया गया रोडमैप है जो नीचे बताए गए विभिन्न क्षेत्रों को कवर करता है।

1. **कोयला विश्लेषिकी:**
   - कोयला उत्पादन - मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 1012 मीट्रिक टन के कुल कोयला उत्पादन लक्ष्य को अंतिम रूप दे दिया है।
   - खानों की आउटसोर्सिंग - मंत्रालय ने कोयला उत्पादन और दक्षता बढ़ाने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं जैसे CIL खानों/ब्लॉकों के संचालन के लिए खनन डेवलपर्स सह ऑपरेटरों (MDO) और राजस्व साझेदारी के आधार पर बंद/परित्यक्त खानों में उत्पादन।
   - कोकिंग कोल रणनीति - आत्मनिर्भर भारत पर ध्यान केंद्रित करते हुए, कोयला मंत्रालय ने आयात को कम करने के लिए देश में कोकिंग कोयले की उपलब्धता बढ़ाने के लिए एक कोकिंग कोल रणनीति तैयार की है।
   - कोयले की गुणवत्ता - कोयला मंत्रालय और कोयला कंपनियों ने सभी उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण कोयले की आपूर्ति के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कई उपाय किए हैं। लोडिंग छोर पर कोयले के नमूनों के नमूने लेने और विश्लेषण करने का कार्य करने के लिए, तीसरे पक्ष की नमूना लेने वाली एजेंसियों ने बिजली और गैर-बिजली दोनों कोयला उपभोक्ताओं के लिए सूचीबद्ध किया गया है।
2. **निजी निवेश:**
   - CAPEX और संपत्ति मुद्रीकरण - वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कैपेक्स लक्ष्य 21030 करोड़ रुपये है (CIL: 16,500 करोड़ रुपये, NLCIL: 2,880 करोड़ रुपये और SCCL: 1650 करोड़ रुपये) वित्त वर्ष 2023-24 के लिए संपत्ति मुद्रीकरण योजना का समग्र अनुमानित लक्ष्य 50,118.61 करोड़ रुपये है।
   - वाणिज्यिक खनन - वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान, मंत्रालय ने 33.224 MTPA के संचयी PRC वाली कुल 23 कोयला खदानों के लिए समझौतों पर हस्ताक्षर किए और इन खानों से PRC (पीक रेटेड कैपेसिटी) पर गणना करके 4,700.80 करोड़ रुपये का वार्षिक राजस्व उत्पन्न करने की उम्मीद है। इन खानों से 44,906 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलने की उम्मीद है। वाणिज्यिक नीलामी के 6वें दौर के लिए प्राप्त अच्छी प्रतिक्रिया को देखते हुए, यह उम्मीद की जाती है कि वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान 25 कोयला खदानों को वाणिज्यिक खनन के लिए आवंटित किया जाएगा।
3. **अवसंरचना परियोजनाएं**
   - PM गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान - रेल मंत्रालय के परामर्श से, कोयला मंत्रालय नई रेलवे लाइन परियोजनाओं की बारीकी से निगरानी कर रहा है जो कोयले की निकासी के लिए महत्वपूर्ण हैं और NMP पर कोयला क्षेत्र की मैपिंग और NMP पर डैशबोर्ड का उपयोग कर रहा है।
   - कोयला निकासी- FMC और रेलवे लाइन्स - कोयले के प्रभावी और पर्यावरण के अनुकूल परिवहन के लिए कोयला मंत्रालय ने कोयला रसद नीति/योजना अपनाई है, क्योंकि रसद कोयला आपूर्ति श्रृंखला का एक महत्वपूर्ण घटक है।
4. **खानों में सुरक्षा**
   - कोयला मंत्रालय आपदा प्रबंधन, सुरक्षा प्रबंधन और प्रतिक्रिया अभ्यास, PPE आदि के उपयोग सहित कोयला खानों में सुरक्षा के लिए सर्वोत्तम सुरक्षा मानकों और सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है।
   - खानों का वैज्ञानिक समापन - खनन क्षेत्रों में पारिस्थितिक संतुलन को बहाल करने के लिए कोयला मंत्रालय द्वारा अक्टूबर, 2022 में जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार बड़ी संख्या में CIL और SCCL खानों में खदान बंद करने की गतिविधियां इस साल शुरू होंगी (साइंटिफिक क्लोजर ऑफ क्लोज्ड) / वर्ष 2009 से पहले परित्यक्त / बंद खदानें)।
5. **कोयला क्षेत्रक को प्रौद्योगिकीय सहायता:**
   - कोयला क्षेत्र में प्रौद्योगिकी रोडमैप - मंत्रालय दक्षता, सुरक्षा और पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए नई तकनीक (ड्रोन, रिमोट सेंसिंग) विस्फोट मुक्त कोयला खनन के डिजिटलीकरण और उप-प्रणालियों के एकीकरण में प्रौद्योगिकी रोडमैप के कार्यान्वयन की दिशा में कोयला कंपनियों के लिए निगरानी ढांचे को परिचालित करने जा रहा है।
   - कोयले से रसायन - स्वच्छ कोयला प्रौद्योगिकी की दिशा में एक उद्देश्य के साथ, कोयला मंत्रालय ने कोयले से हाइड्रोजन, कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण, CBM/CMM आदि जैसी विभिन्न पहलें की हैं।
   - कोल इंडिया लिमिटेड (CIL) का विविधीकरण - मंत्रालय की विविधीकरण पहलों के हिस्से के रूप में, कोल इंडिया लिमिटेड को नए व्यावसायिक क्षेत्रों (एल्यूमीनियम, बिजली, सौर वेफर, सौर ऊर्जा और नवीकरणीय) कोर के विस्तार जैसे स्थायी भविष्य के व्यवसाय (1 BT) आदि संचालन के लिए विविधतापूर्ण बनाया जा रहा है।
6. **कोयला क्षेत्र में स्थिरता:**
   - कोयला मंत्रालय सतत विकास मॉडल को बढ़ावा देने की परिकल्पना करता है जिसमें कोयला उत्पादन पर्यावरण संरक्षण, संसाधन संरक्षण, समाज की देखभाल और हमारे वनों और जैव विविधता की रक्षा के उपायों के साथ-साथ चलता है। हरित पहल, इको-पार्क/खान

पर्यटन का विकास, लाभकारी उपयोग खदान जल/ओवरबर्डन (OB) और ऊर्जा कुशल उपाय कोयला मंत्रालय द्वारा पहचानी गई कुछ प्रमुख स्थायी गतिविधियों में से हैं।

भारत में कोयला क्षेत्र

- भारत के पास दुनिया का पांचवां सबसे बड़ा कोयला भंडार है और चीन के बाद कोयला उत्पादन में दूसरे स्थान पर है।
- कोयले के सबसे बड़े आयातकों में से एक (मुख्य रूप से इंडोनेशिया, दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया से)।
- भारत में कुल स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता में कोयले की हिस्सेदारी लगभग 50% है।

कोयले का वर्गीकरण

- एन्थ्रेसाइट (उत्तम गुणवत्ता): 80-95% कार्बन सामग्री वहन करती है। जम्मू-कश्मीर में कम मात्रा में पाया जाता है।
- बिटुमिनस: 60-80% कार्बन सामग्री और नमी का निम्न स्तर वहन करता है। मुख्य रूप से मध्य और पूर्वी भारत में पाया जाता है।
- लिग्नाइट: 40-55% कार्बन सामग्री वहन करता है। राजस्थान, असम, तमिलनाडु में पाया जाता है।

एल नीनो

खबरों में क्यों

WMO ने एल नीनो वर्षों के दौरान विश्व स्तर पर अपेक्षित वर्षा पैटर्न जारी किया।

महत्वपूर्ण बिंदु

- दुनिया को अल नीनो के विकास के लिए तैयार रहना चाहिए, जो दक्षिणी एशिया, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के कुछ हिस्सों में गंभीर सूखे के साथ-साथ अत्यधिक बारिश, विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO) से जुड़ा है।
- अल नीनो वर्षों के दौरान विश्व स्तर पर अपेक्षित वर्षा पैटर्न पर जारी किए गए एक मानचित्र WMO ने जून से सितंबर मानसून के मौसम के दौरान उत्तर, उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम और मध्य भारत के अधिकांश हिस्सों में शुष्क अवधि का अनुभव किया।
- यह प्रायद्वीपीय क्षेत्र में अक्टूबर से दिसंबर के दौरान पूर्वोत्तर मानसून के मौसम के दौरान बड़े पैमाने पर वर्षा महीनों को दर्शाता है।

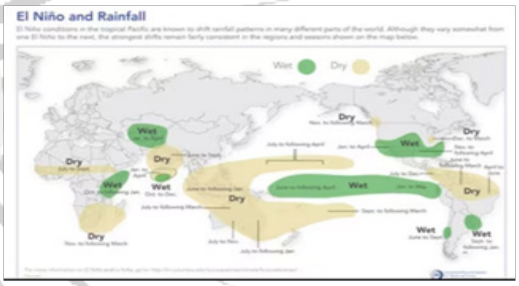

- मानसून का मौसम, जो 1 जून से शुरू होता है, भारत की अर्थव्यवस्था के मुख्य आधारों में से एक, कृषि के लिए महत्वपूर्ण है।
- यह भारत की वार्षिक वर्षा का लगभग 70% लाता है। मानसून कृषि उत्पादन को बढ़ाता है और ग्रामीण खर्च में सुधार करता है। मानसून की बारिश देश के शुद्ध खेती वाले क्षेत्र के लगभग 60% के लिए जीवन रेखा है, जिसमें सिंचाई नहीं होती है।
- मानसून मुद्रास्फीति, नौकरियों और औद्योगिक मांग को प्रभावित करता है। अच्छा कृषि उत्पादन खाद्य मुद्रास्फीति पर नियंत्रण रखता है।
- पर्याप्त फसल से ग्रामीण आय में वृद्धि होती है और अर्थव्यवस्था में मांग को बढ़ाने में मदद मिलती है।
- WMO ने कहा कि एल नीनो की स्थिति दुनिया भर में वर्षा के पैटर्न को बदलने के लिए जानी जाती है।
- हालांकि वे एक अल नीनो से दूसरे अल नीनो में कुछ हद तक भिन्न होते हैं, सबसे मजबूत बदलाव क्षेत्रों और मौसमों में काफी सुसंगत रहते हैं।
- WMO जलवायु विज्ञान या लंबी अवधि में वायुमंडलीय स्थितियों के अध्ययन की बात कर रहा है।
- आम तौर पर, एल नीनो पूर्वोत्तर मानसून के लिए अच्छा होता है लेकिन दक्षिण पश्चिम मानसून के लिए बुरा होता है लेकिन एक-से-एक संबंध नहीं होता है।
- IMD ने पिछले महीने लंबी अवधि के औसत (LPA) के 96% (+/-5% के त्रुटि मार्जिन के साथ) पर "सामान्य" मानसून का अनुमान लगाया था। जून से सितंबर के बीच मानसून के मौसम के लिए LPA 87 सेंटीमीटर है, जिसकी गणना 1971 से 2020 की अवधि के लिए की गई है।
- अल नीनो अफ्रीका के हॉर्न में सूखे और अन्य ला नीना से संबंधित प्रभावों से राहत ला सकता है लेकिन यह अधिक चरम मौसम और जलवायु घटनाओं को भी ट्रिगर कर सकता है।
- यह लोगों को सुरक्षित रखने के लिए UN अर्ली वार्निंग फॉर ऑल पहल की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है।
- WMO ने कहा कि इस मानसून के मौसम में अल नीनो के विकसित होने की संभावना बढ़ रही है। इसमें कहा गया है कि इससे दुनिया के कई क्षेत्रों में लंबे समय तक चलने वाले ला नीना और संभावित ईंधन उच्च वैश्विक तापमान पर मौसम और जलवायु पैटर्न पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा।
- ला नीना तीन साल तक बने रहने के बाद अब समाप्त हो गया है। उष्णकटिबंधीय प्रशांत वर्तमान में एक ENSO-तटस्थ स्थिति में है (न तो El नीनो और न ही La नीना)।
- मई-जुलाई 2023 के दौरान ENSO-तटस्थ से एल नीनो में संक्रमण की 60% संभावना है, और यह जून से अगस्त में लगभग 70% और जुलाई और सितंबर के बीच 80% तक बढ़ जाएगा।
- इस स्तर पर El नीनो की ताकत या अवधि का कोई संकेत नहीं है।
- 2016 एक बहुत शक्तिशाली El नीनो घटना और ग्लोबल वार्मिंग की दोहरी मार के कारण रिकॉर्ड पर सबसे गर्म वर्ष था।
- वैश्विक तापमान पर प्रभाव आमतौर पर इसके विकास के बाद के वर्ष में दिखाई देता है और ऐसा संभवत: 2024 में सबसे अधिक स्पष्ट होगा।
- भारतीय उष्ण कटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान ने कहा कि भारतीय भूभाग पर प्री-मानसून तापमान मानसून की शुरुआत की गतिशीलता को प्रभावित करने वाले कई कारकों में से एक हो सकता है।

- El नीनो यूरेशिया पर तापमान बढ़ाकर क्षोभमंडलीय तापमान प्रवणता को बढ़ा सकता है और इस तरह मानसूनी हवाओं को कमजोर कर सकता है।
- भले ही जमीन की सतह का तापमान बारिश से ठंडा हो जाता है, [अव्यक्त] गर्मी भूमि के ऊपर क्षोभमंडल/वातावरण में जारी हो जाती है। इसलिए, भूमि की सतह का तापमान अकेले मानसून को संचालित नहीं करता है।

मध्य एशियाई फ्लाईवे

खबरों में क्यों

मध्य एशियाई फ्लाईवे (CAF) में प्रवासी पक्षियों और उनके आवासों के संरक्षण प्रयासों को मजबूत करने के लिए रेंज देशों की बैठक

महत्वपूर्ण बिंदु

- मध्य एशियाई फ्लाईवे (CAF) के रेंज देशों ने प्रवासी पक्षियों और उनके आवासों के संरक्षण के प्रयासों को मजबूत करने के लिए सहयोग किया है।
- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम/प्रवासी प्रजातियों पर सम्मेलन (UNEP/CMS) के सहयोग से 2 मई से 4 मई, 2023 तक नई दिल्ली में बैठक का आयोजन किया।
- बैठक में अर्मेनिया, बांग्लादेश, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, कुवैत, मंगोलिया, ओमान, सऊदी अरब, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान सहित 11 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया, साथ ही CMS, AEWA और रैप्टर्स MOU के सचिवालयों और प्रमुख के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
- प्रतिनिधियों ने मध्य एशियाई फ्लाईवे के लिए एक संस्थागत ढांचे पर विचार-विमर्श किया, कार्यान्वयन के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर चर्चा की और CMS CAF कार्य योजना को अद्यतन करने के लिए एक मसौदा रोडमैप पर सहमति व्यक्त की।

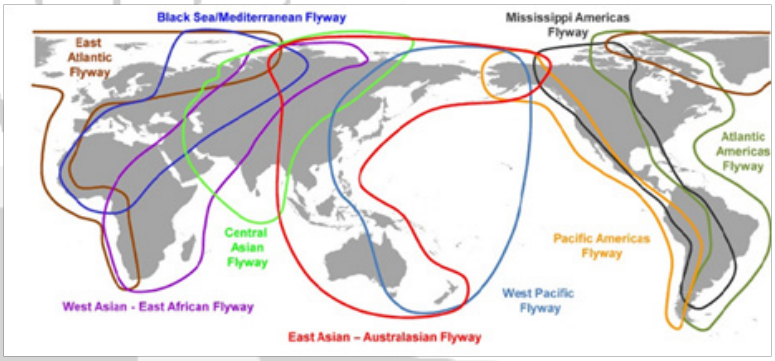

- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अनुसार, चर्चाओं ने प्रवासी पक्षियों और उनके आवासों के संरक्षण के लिए एक समन्वित दृष्टिकोण विकसित करने के लिए एक संस्थागत ढांचे तंत्र के तौर-तरीकों को भी आगे बढ़ाया।
- मध्य एशियाई फ्लाईवे पहल की औपचारिकता को प्रवासी पक्षियों और उनके आवासों के संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा गया।
- केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री ने इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया और प्रवासी पक्षियों सहित सभी जीवन रूपों के सह-अस्तित्व के लिए एक स्थायी जीवन शैली अपनाने की आवश्यकता पर जोर दिया।

ACF के बारे में

- मध्य एशियाई फ्लाईवे (CAF) आर्कटिक और हिंद महासागर के बीच यूरेशिया के एक बड़े क्षेत्र को कवर करता है।
- इस फ्लाईवे में पक्षियों के कई महत्वपूर्ण प्रवास मार्ग शामिल हैं।
- भारत सहित, मध्य एशियाई फ्लाईवे के तहत 30 देश हैं।
- फरवरी, 2020 में गांधीनगर में प्रवासी प्रजातियों पर सम्मेलन (CMS) के पक्षकारों के सम्मेलन (COP) की 13वीं बैठक में एक संकल्प (UNEP/CMS/संकल्प 12.11 (Rev.COP13) और निर्णय 13.46 को अपनाया गया था) initer-alia प्रवासी पक्षियों के लिए संरक्षण कार्रवाई पर सहमत होने के उद्देश्य से भारत के नेतृत्व में CMS की छत्रछाया में COP14 द्वारा एक संस्थागत ढांचे की स्थापना के लिए प्रदान करता है।
- अपनी प्रतिबद्धता को पूरा करने की दृष्टि से, भारत 6-7 अक्टूबर 2021 को CAF रेंज देशों के साथ दो दिवसीय ऑनलाइन बैठक आयोजित कर रहा है, जिसका आयोजन भारतीय वन्यजीव संस्थान में किया जा रहा है।
- दुनिया की 11,000 पक्षी प्रजातियों में से लगभग पांच में से एक पक्षी प्रवास करता है, कुछ बहुत अधिक दूरी तय करते हैं।
- प्रवासी पक्षियों के संरक्षण के लिए देशों के बीच और राष्ट्रीय सीमाओं के पार पूरे फ्लाईवे में सहयोग और समन्वय की आवश्यकता है।

गोवा के जंगल में आग

खबरों में क्यों

इससे पहले संसद में केंद्र सरकार की एक प्रस्तुति में कहा गया था कि लंबे समय तक सूखे का दौर, अभूतपूर्व उच्च तापमान और कम आर्द्रता के कारण राज्य में छिटपुट आग की घटनाएं हुई।

महत्वपूर्ण बिंदु

- मार्च के पहले पखवाड़े में गोवा में लगभग 4 वर्ग किमी के क्षेत्र में लगी आग की वन विभाग की जांच से पता चला है कि आग बड़े पैमाने पर प्राकृतिक कारणों से लगी थी, पिछले महीने संसद में केंद्र सरकार की प्रस्तुति की पुष्टि करते हुए कि राज्य में "लंबे समय तक सूखा, अभूतपूर्व उच्च तापमान और कम आर्द्रता" के कारण "छिटपुट" आग लगने की घटनाएं हुई।
- नौसेना और वायु सेना के हेलीकॉप्टरों ने महादेई वन्यजीव अभयारण्य में दुर्गम पहाड़ी चोटियों पर लगी आग को बुझाने के लिए कई उड़ानें भरीं।

- विपक्षी दलों और पर्यावरणविदों ने आरोप लगाया है कि आग "मानव निर्मित" थी, जानबूझकर निहित स्वार्थों द्वारा जलाई गई थी।
- यहां तक कि राज्य के वन मंत्री ने भी मार्च में कहा था कि आग "मानव निर्मित" थी।
- इस महीने की शुरुआत में दक्षिण गोवा में एक नई आग लगने की सूचना मिलने के बाद विपक्ष ने उच्च स्तरीय जांच की अपनी मांग फिर से दोहराई।

वन विभाग की जांच में क्या मिला?

- जांच रिपोर्ट के अनुसार, मार्च 2023 के पहले पखवाड़े में आग लगने की 74 घटनाएं हुईं, जिनमें से 32 में तीन वन्यजीव अभ्यारण्य प्रभावित हुए।
- 320 हेक्टेयर से अधिक वन भूमि सहित कुल 418 हेक्टेयर निजी भूमि, आरक्षित वन, सामुदायिक भूमि और संरक्षित क्षेत्र प्रभावित हुए।
- रिपोर्ट बताती है कि अनुकूल वातावरण और चरम मौसम की स्थिति पिछले मौसम में कम वर्षा, असामान्य रूप से उच्च तापमान, कम नमी और आद्रता के कारण आग लगी।
- फिर भी, भारतीय वन अधिनियम, 1927, वन्य जीवन (संरक्षण) अधिनियम, 1972, गोवा, दमन और दीव वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1984 और भारतीय दंड संहिता की रिपोर्ट कहती है कि संबंधित प्रावधानों के तहत अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ 34 प्राथमिकी दर्ज की गई हैं।

मौसम और आग के बीच क्या संबंध है?

- गोवा में पिछले साल अक्टूबर से बहुत कम बारिश हुई, साथ ही गर्मी की लहर जैसी स्थिति और कम आर्द्रता ने जंगल की आग के लिए अनुकूल स्थिति पैदा कर दी।
- एक बार जब पहाड़ी की चोटी पर सूखी पत्तियों के फ़र्श में आग लग गई, तो लपटें हवा में फैल गईं और तेज हवाओं से फैल गईं।
- अधिकारियों ने हाल ही में कहा है कि गर्मियों के दौरान गोवा में जंगल में आग लगने की घटनाएं खराब मॉनसून वर्षा के बाद के वर्षों में अधिक रही हैं। अधिकारियों ने कहा कि इसी तरह का पैटर्न कर्नाटक में भी देखा गया है।
- अधिकारियों ने स्वीकार किया कि काजू के बागानों के पास कुछ आग मालिकों द्वारा आग जलाने के कारण लगी हो सकती है। हालांकि, उन्होंने कहा कि यह एक व्यापक अभ्यास नहीं था।
- मार्च में जंगल में आग लगने की 70 से अधिक घटनाओं में से केवल 4-5 मामले ही सामने आए हैं जिनमें लोगों ने जानबूझकर आग लगाई होगी।

क्या गोवा में जंगल की आग का इतिहास है?

- मवेशियों के लिए चराई की भूमि को साफ करने के लिए ग्रामीणों द्वारा उपयोग की जाने वाली स्लेश और बर्न तकनीकों के कारण जंगल की सतह पर मामूली सतही आग लग जाती है और मृत कार्बनिक पदार्थ नष्ट हो जाते हैं।
- काजू के किसान अक्सर खरपतवारों को साफ करने और अंडरग्रोथ को कम करने के लिए मामूली आग लगाते हैं। ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां आग के पीछे छिटकी हुई बीड़ी या सिगरेट का पता लगाया गया है।
- गोवा में क्राउन फायर (पेड़ों के घर्षण के कारण) का अनुभव नहीं होता है, जो ज्यादातर विदेशों में होता है। सतही आग गोवा के नम पर्णपाती जंगलों में आम हैं।

पर्यावरणविद् क्यों चिंतित हैं?

- उन्हें डर है कि निहित स्वार्थों ने वन घनत्व को कम करने और अचल संपत्ति के विकास के लिए भूमि को साफ करने के लिए आग जलाई होगी।

भारत में जंगल में आग की बढ़ती घटनाएं

- बदलती जलवायु में जंगल की आग का प्रबंधन (ऊर्जा, पर्यावरण और जल परिषद)
- अप्रैल 2022 के एक अध्ययन में, पिछले दो दशकों में जंगल की आग में दस गुना वृद्धि देखी गई है।
- 62% से अधिक भारतीय राज्य उच्च तीव्रता वाली जंगल की आग की चपेट में हैं।
- अध्ययन में पाया गया है कि आंध्र प्रदेश, ओडिशा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, तेलंगाना और पूर्वोत्तर राज्यों में जंगल की आग का सबसे ज्यादा खतरा है।
- मिजोरम में पिछले दो दशकों में जंगल में आग लगने की घटनाएं सबसे ज्यादा देखी गई हैं और इसके 95% जिले जंगल में आग लगने के हॉटस्पॉट हैं।

ISFR 2021

- ISFR 2021 का अनुमान है कि देश के 36% से अधिक वन क्षेत्र अक्सर जंगल की आग के प्रति संवेदनशील होते हैं, 6% 'अत्यधिक' आग-प्रवण होते हैं और लगभग 4% 'अत्यंत' प्रवण होते हैं।
- जंगल में आग का मौसम आम तौर पर नवंबर से जून तक रहता है और रिपोर्ट में कहा गया है कि अधिकांश आग मानव निर्मित कारकों के कारण लगती हैं।
- 2020-21 के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की एक रिपोर्ट
- इसने पश्चिमी महाराष्ट्र, दक्षिणी छत्तीसगढ़, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों और मध्य ओडिशा को जंगल की आग के 'अत्यंत संवेदनशील' क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया है।
- 2004-21 की अवधि के दौरान जंगल की आग के बिंदुओं के स्थानिक विश्लेषण के आधार पर एक FSI अध्ययन में पाया गया है कि भारत में वनों के तहत लगभग 10.66% क्षेत्र 'अत्यंत' से 'बहुत अधिक' आग-प्रवण है।

RAO'S ACADEMY

वनों का क्या महत्व है?

- वन जीवन के लिए महत्वपूर्ण हैं; वे जैव विविधता को बनाए रखते हैं और अंतहीन अगणनीय उत्पाद और कार्बन, बाढ़ और भूस्खलन नियंत्रण, पानी, दवाओं और फसलों की स्वच्छ आपूर्ति जैसे महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र संसाधन प्रदान करते हैं।

वनों से संबंधित आंकड़े

- वैश्विक वन में 4.06 बिलियन हेक्टेयर क्षेत्र शामिल है जो कुल भूमि के 31% के बराबर है
- दुनिया भर में लगभग 6 बिलियन लोग इन वनों पर निर्भर हैं, जिनमें 300 मिलियन लोग इन वनों में रहते हैं।
- वर्ष 2000 से 2010 के बीच, वन क्षेत्र में प्रति वर्ष लगभग 5.2 मिलियन हेक्टेयर (कुल वन क्षेत्र का 0.1%) की गिरावट देखी गई है।

भारत में जंगल की आग

- भारत वैश्विक भौगोलिक क्षेत्र का केवल 5%, कुल वन क्षेत्र का 1.8% पर कब्जा करता है और यह कुल मानव आबादी के 16% का समर्थन करता है।
- भारत के 647 जिलों में से लगभग 380-445 जिलों में 2003 से 2016 तक हर साल आग लगती है

विश्व जैव विविधता दिवस 2023

खबरों में क्यों

क्या हम वैश्विक ढांचे के तहत लक्ष्यों को पूरा करने की राह पर हैं?

महत्वपूर्ण बिंदु

- प्रत्येक वर्ष 22 मई को मनाया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, मॉन्ट्रियल में किए गए वादे की याद दिलाता है।
- इस वर्ष (2023) अंतर्राष्ट्रीय दिवस का विषय उचित रूप से समझौते से कार्रवाई तक: जैव विविधता का निर्माण करें।
- कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क (GBF) पर सहमति बने सिर्फ पांच महीने हुए हैं और स्वाभाविक रूप से, बहुत कुछ नहीं किया गया है।
- ढांचे में 23 लक्ष्यों के साथ कुल चार लक्ष्य हैं जिन्हें 2030 तक पूरा करना है।
- हालांकि, यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि ढांचा 2011 में स्थापित आइची जैव विविधता लक्ष्यों की तरह समाप्त न हो जाए।
- ये लक्ष्य, जो GBF के तहत निर्धारित लक्ष्यों के समान थे, 2020 तक पूरे किए जाने थे, लेकिन दुनिया सामूहिक रूप से इनमें से किसी को भी पूरा करने में विफल रही।
- लगभग दस लाख पशु और पौधों की प्रजातियों के विलुप्त होने का खतरा है, तत्काल कार्रवाई अनिवार्य है।
- GBF के तहत निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने के लिए केवल सात वर्ष उपलब्ध हैं। कार्यान्वयन के मुद्दे पहले से ही दिखाई दे रहे हैं।
- 2022 में पार्टियों के 15वें सम्मेलन (COP15) में यह निर्णय लिया गया कि GBF के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए निवेश महत्वपूर्ण है।
- यह निर्णय लिया गया कि विकसित देश 2025 तक विकासशील देशों को 20 बिलियन डॉलर और 2030 तक 30 बिलियन डॉलर का अंतर्राष्ट्रीय वित्त प्रदान करेंगे।

- जबकि जी7 ने हाल के एक बयान में जलवायु परिवर्तन के लिए वित्त पोषण के लिए विशिष्ट संख्या प्रदान की, जैव विविधता के लिए एक समान संख्या गायब थी।
- सदस्य राज्य भी अपनी राष्ट्रीय जैव विविधता रणनीति और कार्य योजना को GBF के अनुरूप बनाने पर सहमत हुए। हालांकि, केवल स्पेन ने ही इस वर्ष पुनर्गठित NBSAP प्रस्तुत किया है।
- Türkiye में 2024 में COP16 से पहले नई योजनाओं को CBD सचिवालय में जमा करना होगा।
- वर्तमान में, सचिवालय नई योजनाओं को विकसित करने के लिए देशों को सहायता प्रदान कर रहा है। भारत इस योजना को तैयार करने की प्रक्रिया में है।
- 30 प्रतिशत भूमि और जल की रक्षा का लक्ष्य सबसे विवादास्पद लक्ष्यों में से एक था। कई लोगों के अनुसार, यह कदम स्वदेशी लोगों के अधिकारों का उल्लंघन करेगा। मई 2021 में प्रकाशित संरक्षित ग्रह रिपोर्ट के अनुसार, लगभग 16.64 प्रतिशत भूमि और अंतर्देशीय जल पारिस्थितिकी तंत्र और 7.74 प्रतिशत तटीय जल और महासागर संरक्षित थे। इसमें से 40 प्रतिशत से अधिक 2010 के बाद से हुआ है।
- दुनिया को 2030 तक 30 प्रतिशत के GBF लक्ष्य को पूरा करने में सक्षम होने के लिए प्रयास करने की आवश्यकता होगी। भारत के पास पहले से ही अपने भूमि क्षेत्र का 27 प्रतिशत संरक्षण के अधीन है और पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अनुसार लक्ष्य को आसानी से पूरा कर लेगा।
- GBF के लक्ष्यों और लक्ष्यों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए, CBD ने 23 लक्ष्यों का जवाब देने वाली 22 कार्रवाइयों की सूची के साथ एक अभियान चलाया।
- अभियान 22 दिनों तक चला, जिसमें प्रत्येक दिन 22 कार्यों/लक्ष्यों में से एक का प्रतिनिधित्व करता है।
- तुर्की में 2024 में पार्टियों के सम्मेलन की अगली बैठक में, दुनिया निर्धारित किए गए लक्ष्यों और प्रतिबद्धताओं का जायजा लेगी।

गहरा महासागर मिशन

खबरों में क्यों

केंद्रीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) पृथ्वी विज्ञान ने हाल ही में डीप ओशन मिशन की पहली उच्च स्तरीय संचालन समिति की बैठक की अध्यक्षता की।

महत्वपूर्ण बिंदु

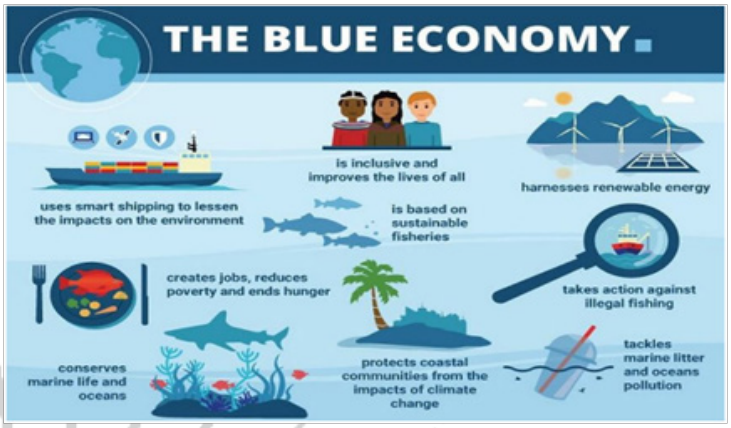

DEEP ओशन मिशन - ब्लू इकोनॉमी का मुख्य घटक

- डीप ओशन मिशन पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अनुसार, हिंद महासागर के गहरे समुद्र में रहने वाले और निर्जीव संसाधनों को बेहतर ढंग से समझने के लिए एक उच्च स्तरीय बहु-मंत्रालयी, बहु-अनुशासनात्मक कार्यक्रम है।
- मिशन का उद्देश्य गहरे समुद्र में अनुसंधान, समुद्री संसाधनों के सतत उपयोग और गहरे समुद्र में अन्वेषण के लिए प्रौद्योगिकियों के विकास को बढ़ावा देना है।
- भारत की नीली अर्थव्यवस्था में डीप ओशन मिशन की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए मंत्री ने कहा, "नीली अर्थव्यवस्था भारत की समग्र अर्थव्यवस्था में एक प्रमुख योगदानकर्ता होगी और प्रधान मंत्री द्वारा घोषित डीप ओशन मिशन इसका मुख्य घटक होगा।"
- इसके अलावा, यह गहरे समुद्र में स्थायी तरीके से संसाधनों का पता लगाने और उनका उपयोग करने के लिए देश की तकनीकी क्षमताओं और वैज्ञानिक विशेषज्ञता का लाभ उठाने का प्रयास करता है।
- बैठक के दौरान, मंत्री ने बताया कि तीन मानवों को ले जाने के लिए मानवयुक्त सबमर्सिबल की उप-प्रणालियों का डिजाइन और विकास पूरा हो चुका है और एकीकरण का कार्य प्रगति पर है।
- कोबाल्ट, निकल, तांबा और मैंगनीज जैसे रणनीतिक खनिजों की खोज से इन संसाधनों के भविष्य के वाणिज्यिक दोहन का मार्ग प्रशस्त होने की उम्मीद है।
- मिशन संचालन समिति (MCC) ने मिशन के विभिन्न घटकों की प्रगति की समीक्षा की और मिशन को व्यापक नीति दिशा प्रदान करेगी और गहरे समुद्र क्षेत्र के लिए मुख्य कार्यक्रम और शासन का अभ्यास करेगी।
- इसके अलावा, यह नीति और कार्यान्वयन रणनीतियों पर अन्य समिति को भी सलाह देगी।

अर्थव्यवस्था के लिए कई फायदे

- भारत की नीली अर्थव्यवस्था समुद्र में संपूर्ण संसाधन प्रणाली और देश के कानूनी अधिकार क्षेत्र के भीतर समुद्री, समुद्री और तटवर्ती तटीय क्षेत्रों में आर्थिक बुनियादी ढांचे से बनी है।
- मछली पालन, जलीय कृषि, बंदरगाह अवसंरचना, और समुद्री जैव प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में एक विशाल समुद्र तट और समृद्ध समुद्री संसाधनों के साथ, भारत आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा दे सकता है, निवेश आकर्षित कर सकता है और विशेष रूप से तटीय समुदायों में रोजगार सृजित कर सकता है।
- इसके अतिरिक्त, बंदरगाह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए महत्वपूर्ण प्रवेश द्वार हैं और भारत की व्यापक तटरेखा इसे समुद्री कनेक्टिविटी के लिए रणनीतिक रूप से स्थित करती है। मात्रा के हिसाब से भारत का लगभग 95 प्रतिशत व्यापार समुद्र के द्वारा होता है।
- समुद्र के विभिन्न पहलुओं की खोज, जैसे समुद्री जैव विविधता, और स्थायी प्रौद्योगिकियों और समाधानों को विकसित करना, स्थायी महासागर प्रबंधन के लिए ज्ञान पैदा करने में फायदेमंद होगा।
- कुल मिलाकर, समावेशी आर्थिक विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने के साथ-साथ समुद्री संसाधनों के सतत उपयोग को अनलॉक करने के लिए नीली अर्थव्यवस्था आवश्यक है।

मिशन में छह प्रमुख घटक शामिल हैं:

- गहरे समुद्र में खनन और मानवयुक्त सबमर्सिबल और पानी के नीचे रोबोटिक्स के लिए प्रौद्योगिकियों का विकास;
- महासागर जलवायु परिवर्तन सलाहकार सेवाओं का विकास;
- गहरे समुद्र में जैव विविधता की खोज और संरक्षण के लिए तकनीकी नवाचार;
- गहन महासागर सर्वेक्षण और अन्वेषण;
- महासागर से ऊर्जा और मीठे पानी;
- महासागर जीव विज्ञान के लिए उन्नत समुद्री स्टेशन

रणथंभौर टाइगर रिजर्व (RTR)

खबरों में क्यों

हाल ही में NCTA ने रणथंभौर से बाघिनों के पुनर्वास को मंजूरी दी है

महत्वपूर्ण बिंदु

- राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA) ने रणथंभौर टाइगर रिजर्व (RTR) से तीन बाघिनों को दो अन्य राज्य रिजर्व में स्थानांतरित करने की मंजूरी दे दी है।

- मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व (MHTR) में एकमात्र बाघिन MT-4 की बीमारी से मौत के एक दिन बाद यह खबर आई है।
- विकास की पुष्टि करते हुए, NTCA की तकनीकी समिति ने तीन बाघिनों को स्थानांतरित करने के लिए राज्य के अनुरोध को मंजूरी दे दी है।
- एक बाघिन को कोटा के MHTR और दो को बूंदी के रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व में स्थानांतरित किया जाएगा।
- एक प्लस टू (एक पुरुष, दो महिला) नियम बनाए रखने का अनुरोध किया गया था।
- बाघिनों की पहचान की जा रही है और जल्द ही सभी प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद उन्हें स्थानांतरित कर दिया जाएगा।
- MHTR में केवल एक बड़ी बिल्ली (MT-5) बची है, क्योंकि नौ वर्षीय गर्भवती बाघिन MT-4 की बीमारी से मृत्यु हो गई।
- बाघिन ने पूरी तरह से शावकों को जन्म दिया था जो अभी भी उसके गर्भ में अजन्मे थे।
- यह देश में बाघ के साथ मलाशय के आगे बढ़ने का पहला मामला था।
- बाघिन को 2019 में MHTR में और बाघ T-110 को 2022 में RTR से स्थानांतरित किया गया था।
- 2018 में, पिछली सरकार द्वारा बनाए गए दबाव के कारण बाघ पुनर्वास योजना में बदलाव किया गया था।
- NTCA की मंजूरी के खिलाफ RTR से बाघों को सेल्जार के बजाय MHTR की दर्रा रेंज में स्थानांतरित कर दिया गया था। हालाँकि, तीन शावकों सहित पाँच बाघों की मृत्यु हो जाने और एक नर बाघ MT-1 के रहस्यमय तरीके से गायब हो जाने के बाद, राज्य ने फिर से अकेली जीवित बाघिन MT-4 की जोड़ी बनाने के लिए NTCA से अनुमति मांगी।
- रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व, जिसे केंद्र ने 2021 में मंजूरी दी थी, में एक नर और एक मादा बड़ी बिल्ली है, और दो बाघिनों को चरणों में स्थानांतरित किया जाएगा।
- आरटीआर में बड़ी बिल्लियों की आबादी बढ़ रही है, और उन्हें अधिक स्थान/क्षेत्र की आवश्यकता है अन्यथा वे या तो लड़ेंगे या पलायन करेंगे।

राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA) के बारे में:

- यह पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) के तहत एक वैधानिक निकाय है।
- इसकी स्थापना 2006 में वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 के तहत की गई थी।

उद्देश्य:

- प्रोजेक्टप टाइगर को वैधानिक अधिकार प्रदान करना ताकि उसके निर्देशों का अनुपालन कानूनी हो सके।
- संघीय ढांचे के भीतर राज्यों के साथ समझौता ज्ञापन के लिए आधार प्रदान करके टाइगर रिजर्व के प्रबंधन में केंद्र-राज्य की जवाबदेही को बढ़ावा देना।
- संसद द्वारा निरीक्षण के लिए प्रदान करना।
- टाइगर रिजर्व के आसपास के क्षेत्रों में स्थानीय लोगों की आजीविका के हितों को संबोधित करना।

रणथंभौर टाइगर रिजर्व (RTR) के बारे में:

- यह राजस्थान में स्थित है।
- यह अरावली और विंध्य पर्वत श्रृंखलाओं के जंक्शन पर स्थित है।
- इसकी प्रमुख प्रजाति पैंथेरा टाइग्रिस टाइग्रिस- भारतीय या बंगाल टाइगर है।
- दक्षिण में चंबल नदी और उत्तर में बनास नदी टाइगर रिजर्व को बांधती है।
- रणथंभौर किला, विश्व धरोहर स्थल, आरटीआर के भीतर स्थित है।
- यह सूखे पर्णपाती जंगल और कई झीलों और नदियों द्वारा बिंदीदार खुले घास के मैदान के बीच वैकल्पिक रूप से रहता है।
- वनस्पति: शुष्क पर्णपाती वन।

जाल

खबरों में क्यों

हाल ही में आंतरिक विस्थापन पर वैश्विक रिपोर्ट 2023 (GRID-2023) प्रकाशित हुई

महत्वपूर्ण बिंदु

- यह नॉर्वेजियन शरणार्थी परिषद के आंतरिक विस्थापन निगरानी केंद्र (IDMC) द्वारा जारी किया गया है।
- आंतरिक विस्थापन उन लोगों को संदर्भित करता है जिन्हें अपनी सीमाओं के अंदर जाने के लिए मजबूर किया जाता है और आंतरिक विस्थापन निगरानी केंद्र की रिपोर्ट में उन लोगों को शामिल नहीं किया गया है जो विभिन्न देशों के लिए रवाना हुए हैं।
- आंतरिक प्रतिस्थापन पर हाल ही में प्रकाशित वैश्विक रिपोर्ट 2023 के अनुसार, 2022 के अंत तक दुनिया भर में आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों (IDP) की संख्या 71 मिलियन तक पहुंच गई।

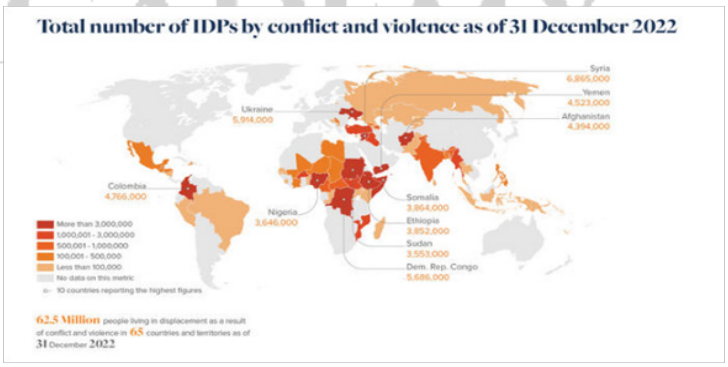

- IDMC जिनेवा में नॉर्वेजियन रिफ्यूजी काउंसिल द्वारा 1998 में स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय NGO है। यह दुनिया के आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्तियों पर निगरानी और जानकारी प्रदान करने और विश्लेषण करने पर केंद्रित है।

- आंतरिक विस्थापन उन लोगों को संदर्भित करता है जिन्हें अपनी सीमाओं के अंदर जाने के लिए मजबूर किया जाता है और रिपोर्ट में उन लोगों पर विचार नहीं किया गया है जो विभिन्न देशों के लिए रवाना हुए हैं।
- 2023 संस्करण 2022 में आपदाओं से विस्थापित लोगों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि और आपदाओं, संघर्ष और हिंसा, खाद्य सुरक्षा और ID के बीच जटिल संबंधों पर प्रकाश डालता है।

2023 रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएं

- दुनिया भर में आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों (IDP) की संख्या 2022 के अंत तक 71.1 मिलियन तक पहुंच गई, जो पिछले वर्ष की तुलना में 20 प्रतिशत अधिक है।
- संघर्ष और हिंसा ने दुनिया भर में 28.3 मिलियन आंतरिक विस्थापन को जन्म दिया।
- यूक्रेन में संघर्ष के कारण लगभग 17 मिलियन विस्थापन हुए।
- आपदाओं के कारण 32.6 मिलियन लोग विस्थापित हुए, 2021 से 40 प्रतिशत की वृद्धि बड़े पैमाने पर ला नीना के प्रभाव का परिणाम है जो जारी रहा या लगातार तीसरे वर्ष।
- कुल आपदा विस्थापन का 98 प्रतिशत बाढ़ और तूफान जैसी मौसम संबंधी घटनाओं के कारण हुआ।
- भारत ने 2.5 मिलियन विस्थापन के साथ चौथा सबसे बड़ा आपदा विस्थापन दर्ज किया।
- पाकिस्तान में 2022 में दुनिया में सबसे अधिक 8.16 मिलियन आपदा विस्थापन हुए।
- 5.44 मिलियन विस्थापन के साथ फिलीपींस दूसरे स्थान पर था
- चीन 3.63 मिलियन के साथ तीसरे और नाइजीरिया 2.4 मिलियन के साथ 5वें स्थान पर है।

वन्य जीवन संरक्षण (WLP) अधिनियम, 1972

खबरों में क्यों

वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 49N और 49 O के तहत बनाए गए नियमों की अधिसूचना (2022 में संशोधित)

महत्वपूर्ण बिंदु

- वन्य जीवन (संरक्षण) अधिनियम 1972 (1972 का 53) जंगली जानवरों की विभिन्न प्रजातियों के संरक्षण के लिए उनके निवास स्थान के प्रबंधन और जंगली जानवरों के विभिन्न भागों से प्राप्त उत्पादों के व्यापार के विनियमन और नियंत्रण के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है।
- अधिनियम में अंतिम बार 2022 में संशोधन किया गया था।
- वन्य जीव (संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2022 1 अप्रैल 2023 से लागू हो गया है।
- अधिनियम की धारा 49 N के अनुसार, कैद में प्रजनन में लगे व्यक्ति या अनुसूची IV के परिशिष्ट I में सूचीबद्ध किसी भी अनुसूचित नमूने का कृत्रिम रूप से प्रचार करने के लिए लाइसेंस के शुरू होने के नब्बे दिनों की अवधि के भीतर लाइसेंस के लिए आवेदन करना आवश्यक है। वन्य जीव (संरक्षण) संशोधन अधिनियम 2022।
- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने दिनांक 24 अप्रैल 2023 की राजपत्रित अधिसूचना के माध्यम से धारा 49N के तहत नियमों को अधिसूचित किया है।
- अधिनियम की अनुसूची IV के परिशिष्ट I में सूचीबद्ध किसी भी अनुसूचित नमूने को कैद में प्रजनन या कृत्रिम रूप से प्रचारित करने वाले सभी व्यक्तियों से वन्य जीवन (संरक्षण) अधिनियम की धारा 49 N के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार लाइसेंस के लिए आवेदन करने का अनुरोध किया जाता है। 1972 को 29 जून 2023 को या उससे पहले निर्धारित प्रपत्र में।

वन्य जीवन (संरक्षण) अधिनियम, 1972

- वन्य जीवन (संरक्षण) अधिनियम, 1972 जंगली जानवरों और पौधों की विभिन्न प्रजातियों की सुरक्षा, उनके आवासों के प्रबंधन, जंगली जानवरों, पौधों और उनसे बने उत्पादों के व्यापार के विनियमन और नियंत्रण के लिए एक कानूनी ढांचा प्रदान करता है।
- अधिनियम पौधों और जानवरों के शेड्यूल को भी सूचीबद्ध करता है जिन्हें सरकार द्वारा अलग-अलग डिग्री की सुरक्षा और निगरानी प्रदान की जाती है।
- CITES (जंगली जीवों और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर सम्मेलन) में भारत का प्रवेश वन्यजीव अधिनियम द्वारा आसान बना दिया गया था।
- इससे पहले, जम्मू और कश्मीर 1972 के वन्यजीव संरक्षण अधिनियम द्वारा कवर नहीं किया गया था। पुनर्गठन अधिनियम के परिणामस्वरूप अब भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम जम्मू और कश्मीर पर लागू होता है।

वन्यजीव संरक्षण पर संवैधानिक ढांचा

- भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत वन्य जीवन, वन और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए संवैधानिक ढांचा मौजूद है।
- जीवन के अधिकार में स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण में रहने का अधिकार शामिल है।
- राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत का अनुच्छेद 48ए पर्यावरण की रक्षा और संरक्षण और वन और वन्य जीवन की सुरक्षा के लिए राज्य पर एक गैर-बाध्यकारी दायित्व डालता है।
- अनुच्छेद 51A(G) भी देश के वन, वन्य जीवन, नदियों और जानवरों की रक्षा के लिए नागरिकों पर एक गैर-बाध्यकारी दायित्व डालता है।
- इन दायित्वों को 42वें संवैधानिक (संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा समवर्ती सूची की प्रविष्टि 17A के तहत 'वन' शब्द को जोड़कर और वन्यजीवों और पक्षियों की सुरक्षा को समवर्ती सूची की प्रविष्टि 17B में जोड़कर केंद्र और राज्य दोनों सरकारों द्वारा पूरा किया गया है।

होमो सेपियन्स पदचिह्न

खबरों में क्यों

दक्षिण अफ्रीका के केप दक्षिण तट पर दुनिया के सबसे पुराने होमो सेपियन्स पदचिह्न की पहचान की गई

महत्वपूर्ण बिंदु

- बस दो दशक पहले, जैसे ही नई सहस्राब्दी शुरू हुई, ऐसा लगा कि हमारे प्राचीन मानव पूर्वजों द्वारा छोड़े गए लगभग 50,000 वर्षों से अधिक पुराने निशान अत्यधिक दुर्लभ थे।
- उस समय पूरे अफ्रीका में केवल चार साइटों की सूचना मिली थी।
- दो पूर्वी अफ्रीका से थे: तंजानिया में लेटोली और केन्या में कोबी फोरा; दो दक्षिण अफ्रीका (नहून और लंगेबान) से थे।
- वास्तव में 1966 में रिपोर्ट की गई नहून साइट, अब तक वर्णित पहली होमिनिन ट्रैकसाइट थी।
- 2023 में स्थिति बहुत अलग है। ऐसा प्रतीत होता है कि लोग पर्याप्त मेहनत नहीं कर रहे थे या सही जगहों पर नहीं देख रहे थे।
- आज 50,000 वर्ष से पुराने दिनांकित होमिनिन इचनोसाइट्स (एक शब्द जिसमें ट्रैक और अन्य निशान दोनों शामिल हैं) के लिए अफ्रीकी टैली 14 है।
- इन्हें आसानी से पूर्वी अफ्रीकी समूह (पांच स्थल) और केप तट से दक्षिण अफ्रीकी समूह (नौ स्थल) में विभाजित किया जा सकता है।
- UK और अरब प्रायद्वीप सहित दुनिया में कहीं और दस अन्य स्थल हैं।
- यह देखते हुए कि केप तट पर अपेक्षाकृत कम कंकाल होमिनिन अवशेष पाए गए हैं, हमारे मानव पूर्वजों द्वारा छोड़े गए निशान जब वे प्राचीन परिदृश्य में चले गए, अफ्रीका में प्राचीन होमिनिन के बारे में हमारी समझ को पूरक और बढ़ाने का एक उपयोगी तरीका है।
- सबसे हाल की साइटें लगभग 71,000 साल पुरानी हैं। सबसे पुराना, जो 153,000 साल पहले का है, इस अध्ययन में दर्ज की गई अधिक उल्लेखनीय खोजों में से एक है: यह अब तक का सबसे पुराना पदचिह्न है, जिसे हमारी प्रजाति, होमो सेपियन्स के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है।
- नई तारीखें पुरातात्विक रिकॉर्ड की पुष्टि करती हैं।
- परिष्कृत पत्थर के औजार, कला, आभूषण और शंख की कटाई सहित क्षेत्र और समय अवधि के अन्य साक्ष्यों के साथ, यह पुष्टि करता है कि केप दक्षिण तट एक ऐसा क्षेत्र था जिसमें प्रारंभिक शारीरिक रूप से आधुनिक मानव जीवित रहे और फैलने से पहले विकसित हुए अफ्रीका से अन्य महाद्वीपों के लिए।

बहुत अलग साइटें

- पूर्वी अफ्रीकी और दक्षिण अफ्रीकी ट्रैकसाइट क्लस्टर के बीच महत्वपूर्ण अंतर हैं।
- पूर्वी अफ्रीकी स्थल बहुत पुराने हैं: सबसे पुराना लैटोली, 3.66 मिलियन वर्ष पुराना है और सबसे छोटा 0.7 मिलियन वर्ष पुराना है। पटरियों को होमो सेपियन्स द्वारा नहीं बनाया गया था, लेकिन पहले की प्रजातियों जैसे कि ऑस्ट्रेलोपिथेसीन, होमो हीडलबर्गेंसिस और होमो इरेक्टस द्वारा बनाया गया था।
- अधिकांश भाग के लिए, जिन सतहों पर पूर्वी अफ्रीकी पटरियां पाई जाती हैं, उन्हें श्रमसाध्य और सावधानीपूर्वक खुदाई और उजागर करना पड़ा है।
- इसके विपरीत, केप तट पर दक्षिण अफ्रीकी स्थल, काफ़ी कम उम्र के हैं। सभी को होमो सेपियन्स के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है।
- और ट्रैक पूरी तरह से अनावृत हो जाते हैं जब उन्हें एओलियनाइट्स के रूप में जाने वाली चट्टानों में खोजा जाता है, जो प्राचीन टीलों के सीमेंटेड संस्करण हैं।
- उत्खनन पर आमतौर पर विचार नहीं किया जाता है - और साइटों के तत्वों के संपर्क में आने और रेत के टीले की अपेक्षाकृत मोटे प्रकृति के कारण, वे आमतौर पर पूर्वी अफ्रीकी साइटों की तरह अच्छी तरह से संरक्षित नहीं होते हैं।
- वे कटाव के प्रति भी संवेदनशील हैं, इसलिए समुद्र और हवा से नष्ट होने से पहले हमें अक्सर उन्हें रिकॉर्ड करने और उनका विश्लेषण करने के लिए तेजी से काम करना पड़ता है।

रोशन करने वाला तरीका

- पैलियो-रिकॉर्ड - ट्रैकवे, जीवाश्म, या किसी अन्य प्रकार की प्राचीन तलछट का अध्ययन करते समय एक प्रमुख चुनौती यह निर्धारित करना है कि सामग्री कितनी पुरानी है।
- इसके बिना किसी खोज के व्यापक महत्व का मूल्यांकन करना या भूगर्भीय रिकॉर्ड बनाने वाले जलवायु परिवर्तन की व्याख्या करना मुश्किल है।
- केप साउथ कोस्ट एओलियनाईट्स के मामले में, पसंद की डेटिंग पद्धति अक्सर वैकल्पिक रूप से ल्यूमिनेसेंस को उत्तेजित करती है।
- डेटिंग की इस विधि से पता चलता है कि कितने समय पहले रेत का एक दाना सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आया था; दूसरे शब्दों में, कब तक तलछट के उस हिस्से को दफन किया गया है।
- यह देखते हुए कि इस अध्ययन में पटरियां कैसे बनाई गई - गीली रेत पर छापें, उसके बाद नई उड़ती हुई रेत के साथ दफनाना - यह एक अच्छी विधि है क्योंकि हम यथोचित रूप से आश्वस्त हो सकते हैं कि डेटिंग "घड़ी" लगभग उसी समय ट्रैकवे पर शुरू हुई थी बनाया गया था।
- केप दक्षिण तट वैकल्पिक रूप से उत्तेजित ल्यूमिनेसेंस को लागू करने के लिए एक बेहतरीन जगह है।

- सबसे पहले, तलछट क्वार्ट्ज अनाज से भरपूर होते हैं, जो बहुत अधिक चमक पैदा करते हैं।
- दूसरे, प्रचुर मात्रा में धूप, विस्तृत समुद्र तट और तटीय टिब्बा बनाने के लिए रेत के तैयार पवन परिवहन का मतलब है कि किसी भी पहले से मौजूद ल्यूमिनेसेंस संकेतों को ब्याज की दफन घटना से पहले पूरी तरह से हटा दिया जाता है, जिससे विश्वसनीय आयु अनुमान लगाया जा सकता है।
- इस पद्धति ने इस क्षेत्र में पिछली खोजों के डेटिंग को काफी हद तक रेखांकित किया है।
- होमिनिन इचनोसाइट्स के लिए हमारे निष्कर्षों की समग्र तिथि सीमा - लगभग 153,000 से 71,000 वर्ष की आयु - क्षेत्र में इसी तरह के भूगर्भीय निक्षेपों से पूर्व में रिपोर्ट किए गए अध्ययनों में आयु के अनुरूप है।
- 153,000 साल पुराना ट्रैक केप दक्षिण तट पर तटीय शहर न्यास्ना के पश्चिम में गार्डन रूट नेशनल पार्क में पाया गया था।
- दो पूर्व दिनांकित दक्षिण अफ्रीकी स्थलों, नहून और लांगेबान की आयु क्रमशः लगभग 124,000 वर्ष और 117,000 वर्ष है।

संवर्धित रॉक वेदरिंग

खबरों में क्यों

'उन्नत चट्टान अपक्षय' जलवायु परिवर्तन से निपटने में मदद कर सकता है।

महत्वपूर्ण बिंदु

- प्राकृतिक चट्टान अपक्षय प्रक्रिया, जबकि हजारों वर्षों से कार्बन को तोड़ने और इसे चट्टानों के भीतर संग्रहीत करने में प्रभावी है, जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए तत्काल समाधान प्रदान नहीं कर सकती है।
- स्थिति की अत्यावश्यकता के साथ, लाखों वर्षों की प्रतीक्षा संभव नहीं हो सकती है क्योंकि हमारा ग्रह महत्वपूर्ण शमन प्रयासों के बिना ग्रीनहाउस गैसों का संचय करना जारी रखता है।

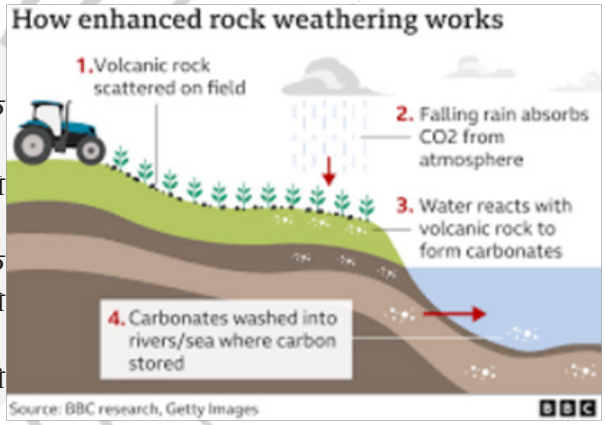

संवर्धित चट्टान अपक्षय समाधान

- एक संभावित समाधान "बढ़ी हुई चट्टान अपक्षय" है जिसका उद्देश्य प्राकृतिक प्रक्रिया को गति देना है।
- अपक्षय की दर में वृद्धि करके, बढ़ी हुई प्रक्रिया कार्बन को अधिक तेजी से पकड़ने और संग्रहीत करने की क्षमता रखती है।
- संयुक्त राष्ट्र से जुड़े वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि ग्लोबल वार्मिंग के खतरनाक स्तरों को रोकने के लिए केवल ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करना पर्याप्त नहीं होगा।
- उन्होंने वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को सक्रिय रूप से हटाने की आवश्यकता पर बल दिया।

'बढ़ी हुई चट्टान अपक्षय' CO2 को हटाने में कैसे मदद करती है ?

- लाखों वर्षों से, वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड वर्षा के पानी के साथ मिलकर कार्बोनिक एसिड बनाता रहा है।
- यह प्राकृतिक प्रक्रिया तब होती है जब एसिड पहाड़ों, जंगलों और घास के मैदानों पर गिरता है।
- परिणामस्वरूप, कार्बन डाइऑक्साइड चट्टानों और मिट्टी के साथ परस्पर क्रिया करता है, खनिजीकरण से गुजरता है और कार्बोनेट के रूप में सुरक्षित भंडारण करता है।
- संवर्धित रॉक अपक्षय सूक्ष्म रूप से कुचले गए रॉक कणों का उपयोग करके इस घटना का लाभ उठाता है।
- यह वर्षा के पानी और चट्टान के बीच संपर्क क्षेत्र को बढ़ाता है, फलस्वरूप अपक्षय प्रक्रिया को बढ़ाता है और अधिक कार्बन हटाने की सुविधा देता है।

UNDO

- UNDO, एक अग्रणी कंपनी है, जिसका उद्देश्य कृषि भूमि पर कुचली हुई बेसाल्ट चट्टान को लागू करके रॉक अपक्षय की प्रक्रिया में तेजी लाना है।
- कंपनी इस प्रक्रिया के लिए आवश्यक समय-सीमा को कम करने पर ध्यान केंद्रित करती है, इसे लाखों वर्षों से घटाकर मात्र दशकों तक कर देती है।
- एक बार जब कार्बन डाइऑक्साइड और अपक्षयित चट्टान के बीच प्रतिक्रिया हो जाती है, तो परिणामी ग्रीनहाउस गैस को अलग कर दिया जाता है और हजारों वर्षों तक सुरक्षित रूप से संग्रहीत किया जाता है।

प्रक्रिया फसल और मिट्टी की मदद कैसे करती है?

- उन्नत अपक्षय, मिट्टी में पोषक तत्वों से भरपूर चट्टानों के अनुप्रयोग के माध्यम से प्राप्त किया गया, कई लाभ प्रदान करता है।
- यह न केवल कार्बन डाइऑक्साइड भंडारण की सुविधा देता है बल्कि फास्फोरस और पोटेशियम जैसे आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करके फसल की पैदावार में भी सुधार करता है।
- इसके अलावा, यह मिट्टी की उर्वरता, पोषक तत्वों की उपलब्धता को बढ़ाता है और उर्वरकों पर निर्भरता कम करता है।
- यह प्रक्रिया बाइकार्बोनेट आयनों की रिहाई के माध्यम से समुद्र के अम्लीकरण को कम करके महासागर की बहाली में भी सहायता करती है। इसके अतिरिक्त, अपक्षय उत्पाद मृदा जल प्रतिधारण को बढ़ाते हैं, सूखे की स्थिति के दौरान पौधों की सहायता करते हैं।

संपन्न: बदलती जलवायु में शहरों को हरा-भरा, लचीला और समावेशी बनाना

खबरों में क्यों

विश्व बैंक की रिपोर्ट में शहरों के लिए एकीकृत हरित शहरी नियोजन रणनीतियों को अपनाने की तत्काल आवश्यकता पर बल दिया गया है जो हरित स्थान और स्थायी बुनियादी ढांचे में निवेश सहित परस्पर जुड़ी चुनौतियों का समाधान करती हैं।

महत्वपूर्ण बिंदु

- विश्व बैंक की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार, वैश्विक जलवायु चुनौती से निपटने में शहरों की भूमिका महत्वपूर्ण है। कागज ने स्थानीय और राष्ट्रीय नीति निर्माताओं को शहरों को हरा-भरा, अधिक लचीला और अधिक समावेशी बनाने के लिए एक कम्पास प्रदान किया।
- थ्राइविंग: मेकिंग सिटीज ग्रीन, रेजिलिएंट, एंड इनक्लूसिव इन ए चेंजिंग क्लाइमेट शीर्षक वाली रिपोर्ट में कहा गया है कि तेजी से शहरीकरण के परिणामस्वरूप दुनिया की आबादी तेजी से शहरों में रह रही है।

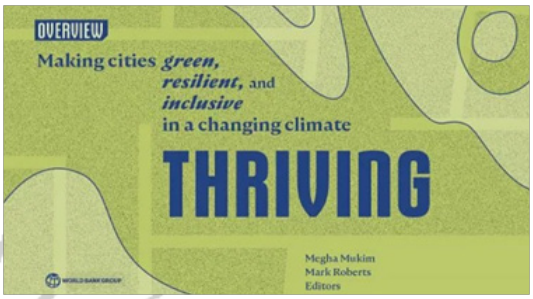

- 10,000 से अधिक शहरों के डेटा के साथ, मार्च 2023 के पेपर में देखा गया कि आज कितने हरे, लचीले और समावेशी शहर हैं। यह शहरों और जलवायु परिवर्तन के बीच दो-तरफ़ा परस्पर क्रिया की भी जाँच करता है।
- 1970 और 2021 के बीच शहरों में रहने वाले लोगों की संख्या 1.19 अरब से बढ़कर 4.46 अरब हो गई और यह वैश्विक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन के लगभग 70 प्रतिशत के लिए जिम्मेदार है।
- प्रति व्यक्ति आधार पर, उच्च और उच्च-मध्य-आय वाले देशों के शहरों में सबसे अधिक जीवाश्म कार्बन डाइऑक्साइड (CO_2) उत्सर्जन होता है और निम्न-आय वाले देशों में सबसे कम होता है।
- उत्तर अमेरिकी शहर सबसे बड़े प्रति व्यक्ति उत्सर्जक हैं, जबकि उप-सहारा अफ्रीका के शहर औसतन सबसे कम प्रति व्यक्ति उत्सर्जक हैं।
- मध्यम-आय वाले देशों में मध्यम और बड़े शहरों में मुख्य रूप से अपेक्षाकृत उच्च कार्बन उत्सर्जन और प्रदूषण का स्तर होता है, साथ में कम हरित स्थान भी होता है।
- रिपोर्ट के अनुसार, कम आय वाले देशों के शहर वैश्विक शहरी CO_2 उत्सर्जन में केवल 14 प्रतिशत का योगदान करते हैं। हालांकि, वे सबसे गंभीर जलवायु संबंधी खतरों बाढ़, गर्मी तनाव, उष्णकटिबंधीय चक्रवात, समुद्र के स्तर में वृद्धि, जल तनाव और जंगल की आग का सामना करेंगे।
- वायु प्रदूषण के मामले में कम और मध्यम आय वाले देशों में पर्यावरण प्रदूषण कम है।
- प्रमुख शहरी क्षेत्रों से वायु प्रदूषण सभी आय स्तरों पर देशों के बड़े शहरों के लिए एक बड़ी चुनौती प्रस्तुत करता है।
- समावेशन की कमी निम्न और निम्न-मध्यम-आय वाले देशों में शहरों में लचीलेपन की कमी में योगदान करती है।
- रिपोर्ट में शहरों के लिए एकीकृत हरित शहरी नियोजन रणनीतियों को अपनाने की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया गया है जो हरित स्थान और टिकाऊ बुनियादी ढांचे में निवेश सहित परस्पर जुड़ी चुनौतियों का समाधान करती हैं।
- चूंकि 2050 तक शहरी आबादी के 2.5 बिलियन तक बढ़ने की उम्मीद है, इसलिए शहरी जल संसाधनों और बुनियादी ढांचे को अतिरिक्त तनाव का सामना करना पड़ेगा, जिससे पारिस्थितिक तंत्र की सुरक्षा और बहाली होगी, जैसे वन, शहरी लचीलापन और जल सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं।
- अकेले उप-सहारा अफ्रीका में, शहरी आबादी के 95 करोड़ बढ़ने का अनुमान है, जो 2050 तक 1.26 अरब तक पहुंच जाएगी।
- कम आय वाले देशों में शहरीकरण के वर्तमान विखंडित, अलग-थलग और बिखरे हुए पैटर्न के बजाय अधिक कॉम्पैक्ट और जुड़े हुए शहरी विकास को शामिल करते हुए एक अलग विकास पथ चुनना, जलवायु और गरीबी में कमी दोनों के लिए आवश्यक है।
- कम आय वाले शहर पहले से ही विभिन्न जलवायु खतरों जैसे बाढ़, गर्मी के तनाव, चक्रवात, समुद्र के स्तर में वृद्धि, जल तनाव और जंगल की आग के जोखिम में वृद्धि का सामना कर रहे हैं।
- इसके अलावा, जब शहर जलवायु और अन्य शरणार्थियों को प्राप्त करने के लिए तेजी से विस्तार करते हैं, तो नई बस्तियां अक्सर अनौपचारिक होती हैं और सेवाओं तक सीमित पहुंच वाले शहरों के बाहरी इलाकों में स्थापित होती हैं।
- रिपोर्ट नीति निर्माताओं को मार्गदर्शन प्रदान करती है कि कैसे अपने शहरों को हरित, अधिक लचीला और अधिक समावेशी बनाने में मदद की जाए - दूसरे शब्दों में, बदलती जलवायु में अपने शहरों को कैसे फलने-फूलने में मदद की जाए।
- यह सूचना प्रसार, प्रोत्साहन, बीमा कवरेज, एकीकरण और निवेश सहित सिफारिशों का एक सेट प्रदान करता है।
- ये सिफारिशें शहरों को उनके उत्सर्जन को कम करने में मदद कर सकती हैं, जलवायु के झटकों के प्रति उनके लचीलेपन को बढ़ा सकती हैं और सबसे गरीब आबादी को जलवायु के प्रभावों को सबसे अधिक तीव्रता से महसूस करने से दूर रखने के लिए अधिक समावेशी बन सकती हैं।

लोगों की जैव विविधता रजिस्टर

खबरों में क्यों

भारत का लक्ष्य है कि हर गांव में जन जैव विविधता रजिस्टर हो, गोवा में सत्यापन अभियान शुरू किया गया।

महत्वपूर्ण बिंदु

- लोगों की जैव विविधता रजिस्टर (PBR) के अद्यतनीकरण और सत्यापन के लिए राष्ट्रीय अभियान गोवा में शुरू किया गया था, जो भारत की समृद्ध जैविक विविधता के प्रलेखन और संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
- गोवा सरकार ने इस राष्ट्रीय अभियान को शुरू करने के लिए गोवा को साइट के रूप में चुने जाने पर गर्व व्यक्त किया।

- सरकार ने जैव विविधता के संरक्षण में गोवा के लोगों के उल्लेखनीय प्रयासों को स्वीकार किया और इस क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने में स्थानीय समुदायों की भूमिका पर जोर दिया।
- इस क्षेत्र में गोवा की सफलताएं जमीन पर लोगों के उत्साह की सफलताएं हैं। सरकार जैव विविधता को संरक्षित करने के अपने प्रयास में केवल स्थानीय समुदायों का समर्थन कर सकती है, और इसलिए, हर सफलता समुदाय की है।
- आयोजन के दौरान प्रत्येक जैव विविधता प्रबंधन समिति के अनूठे उत्पादों को प्रदर्शित करने वाली एक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया।
- इस अवसर पर उत्तर और दक्षिण गोवा में सर्वश्रेष्ठ जैव विविधता प्रबंधन समिति के लिए विशेष पुरस्कारों का वितरण, ग्रीन जर्नलिस्ट अवार्ड और जैव विविधता के संरक्षण के लिए व्यक्तिगत योगदान भी देखा गया।

पीपुल्स बायोडायवर्सिटी रजिस्टर के बारे में

- पीपुल्स बायोडायवर्सिटी रजिस्टर जैव विविधता के विभिन्न पहलुओं के एक व्यापक रिकॉर्ड के रूप में कार्य करता है, जिसमें आवासों का संरक्षण, भूमि प्रजातियों का संरक्षण, लोक किस्मों और किस्मों के घरेलू स्टॉक और जानवरों की नस्लें, सूक्ष्म जीव और क्षेत्र के जैविक विविधता से संबंधित ज्ञान का संचय शामिल है।
- जैव विविधता अधिनियम 2002 के अनुसार, देश भर में स्थानीय निकायों द्वारा "जैविक विविधता के संरक्षण, सतत उपयोग और प्रलेखन को बढ़ावा देने" के लिए जैव विविधता प्रबंधन समितियां (BMC) बनाई गई हैं।
- राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में स्थानीय निकायों द्वारा BMC का गठन किया गया है और उन्हें स्थानीय समुदायों के परामर्श से पीपुल्स बायोडायवर्सिटी रजिस्टर (PBR) तैयार करने का काम सौंपा गया है।
- अब तक विभिन्न राज्यों में जैव विविधता प्रबंधन समितियों द्वारा 2,67,608 PBR तैयार किए जा चुके हैं।
- मिशन लाइफ (पर्यावरण के लिए जीवन शैली) के तहत देश भर के हर गांव में PBR स्थापित करने की योजना है, जो देश में व्यक्तिगत और सामुदायिक स्तर पर प्राकृतिक संसाधनों और विभिन्न अन्य कार्यों के सावधानीपूर्वक उपयोग के माध्यम से ग्रह पृथ्वी को संरक्षित करने के लिए कल्पना की गई है।

जैव विविधता प्रबंधन समितियां

- जैविक विविधता अधिनियम 2002 के अनुसार, देश भर में स्थानीय निकायों द्वारा "जैविक विविधता के संरक्षण, सतत उपयोग और प्रलेखन को बढ़ावा देने" के लिए BMC बनाए गए हैं।
- राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में स्थानीय निकायों द्वारा बीएमसी का गठन किया गया है और उन्हें स्थानीय समुदायों के परामर्श से PBR तैयार करने का काम सौंपा गया है।

मिशन लाइफ़ (पर्यावरण के लिए जीवन शैली)

- भारत के नेतृत्व में, मिशन LiFE एक वैश्विक कार्य योजना है जिसका उद्देश्य ग्रह को जलवायु परिवर्तन के विनाशकारी परिणामों से बचाना है।
- दृष्टि: यह मिशन प्रचलित 'उपयोग और निपटान' अर्थव्यवस्था को एक परिपत्र अर्थव्यवस्था के साथ बदलने की कल्पना करता है।
- उद्देश्य: एक पर्यावरण के प्रति जागरूक जीवन शैली को बढ़ावा देना जो 'बिना सोचे समझे और व्यर्थ उपभोग' के बजाय 'सचेत और जानबूझकर उपयोग' पर केंद्रित है।

RAO'S ACADEMY

4 अर्थव्यवस्था

सामान्य रिपोर्टिंग मानक

खबरों में क्यों

भारत OECD देशों के बीच सूचनाओं के स्वत: आदान-प्रदान (AEOI) के माध्यम से गैर-वित्तीय संपत्तियों जैसे रियल एस्टेट संपत्तियों को शामिल करने के लिए G20 में सामान्य रिपोर्टिंग मानक के दायरे का विस्तार करना चाहता है।

महत्वपूर्ण बिंदु

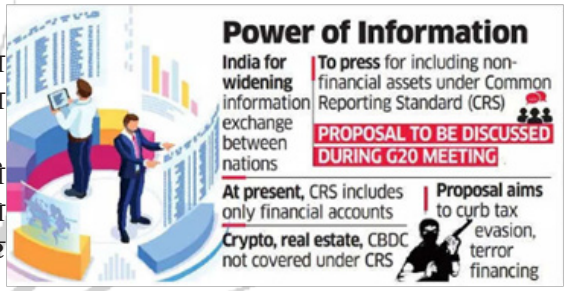

- वर्तमान में, OECD का सूचना का स्वचालित आदान-प्रदान (AEOI) ढांचा कर चोरी की जांच करने के उद्देश्य से हस्ताक्षरकर्ता देशों के बीच वित्तीय खाता विवरण साझा करने के लिए प्रदान करता है।
- अगस्त 2022 में, OECD ने क्रिप्टो-एसेट रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क (CARF) को भी मंजूरी दे दी है, जो ऐसी सूचनाओं के स्वचालित रूप से आदान-प्रदान करने की दृष्टि से एक मानकीकृत तरीके से क्रिप्टो संपत्ति में लेनदेन पर कर जानकारी की रिपोर्टिंग प्रदान करता है।
- AEOI ढांचे के तहत, हस्ताक्षरकर्ता देश एक CRS का पालन करते हैं और अपने वित्तीय संस्थानों से जानकारी प्राप्त करते हैं और स्वचालित रूप से वार्षिक आधार पर अन्य न्यायालयों के साथ उस जानकारी का आदान-प्रदान करते हैं।
- भारत में वर्तमान में वित्तीय जानकारी प्राप्त करने के लिए 108 अधिकार क्षेत्रों के साथ AEOI है और स्वचालित रूप से सूचना भेजने के लिए 79 अधिकार क्षेत्र हैं।

सामान्य रिपोर्टिंग मानक (CRS) के बारे में

- इसे G20 अनुरोध के जवाब में विकसित किया गया था और 15 जुलाई 2014 को OECD परिषद द्वारा अनुमोदित किया गया था।
- यह क्षेत्राधिकारों को अपने वित्तीय संस्थानों से जानकारी प्राप्त करने के लिए कहता है और वार्षिक आधार पर अन्य अधिकार क्षेत्रों के साथ उस जानकारी का स्वचालित रूप से आदान-प्रदान करता है।
- यह एक्सचेंज किए जाने वाले वित्तीय खाते की जानकारी, वित्तीय संस्थानों को रिपोर्ट करने के लिए आवश्यक, विभिन्न प्रकार के खातों और करदाताओं को कवर करने के साथ-साथ वित्तीय संस्थानों द्वारा पालन की जाने वाली सामान्य उचित सावधानी प्रक्रियाओं को निर्धारित करता है।

बिजनेस रेडी प्रोजेक्ट

खबरों में क्यों

हाल ही में विश्व बैंक समूह ने बिजनेस रेडी प्रोजेक्ट लॉन्च किया है

महत्वपूर्ण बिंदु

- विश्व बैंक समूह ने अपनी प्रमुख बिजनेस रेडी परियोजना के तहत 180 अर्थव्यवस्थाओं में व्यापार और निवेश के माहौल का आकलन करने के लिए काम शुरू कर दिया है, जो निजी निवेश को सुविधाजनक बनाने, रोजगार पैदा करने और उत्पादकता में सुधार करने के लिए देशों को समावेशी विकास में तेजी लाने में मदद करने के लिए अपनी नई रणनीति और टिकाऊ तरीके का एक प्रमुख साधन है।
- बिजनेस रेडी विश्व बैंक समूह के पहले के डूइंग बिजनेस प्रोजेक्ट में सुधार करता है और उसकी जगह लेता है।
- यह किसी देश के व्यवसाय और निवेश के माहौल के मूल्यांकन की दिशा में एक अधिक संतुलित और पारदर्शी दृष्टिकोण को दर्शाता है, जिसे सरकारों, निजी क्षेत्र और नागरिक समाज संगठनों सहित विश्व बैंक समूह के भीतर और बाहर के विशेषज्ञों की सिफारिशों द्वारा आकार दिया गया है।
- 54 अर्थव्यवस्थाओं को कवर करने वाली पहली वार्षिक बिजनेस रेडी रिपोर्ट 2024 के वसंत में प्रकाशित की जाएगी।

- विश्व बैंक समूह ने दो प्रमुख दस्तावेज प्रकाशित किए: बिजनेस रेडी मैनुअल और गाइड जिसमें मूल्यांकन की अखंडता सुनिश्चित करने के लिए विस्तृत प्रोटोकॉल और सुरक्षा उपायों को निर्दिष्ट किया गया है और बिजनेस रेडी मेथडोलॉजी हैंडबुक, परियोजना के संकेतकों और स्कोरिंग पद्धति का विवरण दिया गया है।
- प्रारंभिक 54 अर्थव्यवस्थाओं के कारोबारी माहौल पर डेटा संग्रह नियामक विशेषज्ञों और राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधि विश्व बैंक उद्यम सर्वेक्षणों के साथ व्यापक परामर्श के माध्यम से किया जा रहा है, जो प्रतिस्पर्धी रूप से चयनित सर्वेक्षण कंपनियों द्वारा एकत्र किया गया है।

- विश्व बैंक समूह लंबे समय से दुनिया भर में व्यापार-नियामक सुधारों को गति देने में अग्रणी रहा है।
- दुनिया भर में व्यवसाय-सक्षम वातावरण के इसके आकलन ने पिछले दो दशकों में विकासशील और विकसित अर्थव्यवस्थाओं में लगभग 4,000 नियामक सुधारों को बढ़ावा देने में मदद की है।
- उन्होंने इस क्षेत्र में उल्लेखनीय रूप से अकादमिक अनुसंधान को भी उन्नत किया है, जिसके परिणामस्वरूप 4,000 सहकर्मी-समीक्षित शोध पत्र और कम से कम 10,000 वर्किंग पेपर तैयार हुए हैं।
- देश, इसके अलावा, अपनी विकास रणनीतियों को आकार देने के लिए अक्सर इन आकलनों का उपयोग करते हैं।

शामिल विषय

- बिजनेस रेडी अपनी गतिविधियों को शुरू करने, संचालित करने या बंद करने या पुनर्गठित करने के दौरान किसी फर्म के जीवनचक्र को कवर करने वाले 10 विषयों पर ध्यान केंद्रित करता है: व्यवसाय प्रविष्टि, व्यवसाय स्थान, उपयोगिता सेवाएं, श्रम, वित्तीय सेवाएं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, कराधान, विवाद समाधान, बाजार प्रतियोगिता और व्यापार दिवालियापन।
- अगले तीन वर्षों में, परियोजना सालाना दुनिया भर में लगभग 180 अर्थव्यवस्थाओं को कवर करने के लिए विकसित होगी, 2023-24 में 54 अर्थव्यवस्थाओं से शुरू होकर, 2024-25 में 120 अर्थव्यवस्थाओं से, और 2025-26 में 180 अर्थव्यवस्थाओं तक पहुंच जाएगी।
- प्रत्येक देश के आर्थिक वातावरण को एक गतिशील निजी क्षेत्र के लिए तैयार करने के लिए परियोजना का उद्देश्य इसके नाम से परिलक्षित होता है।
- यह नाम इस तथ्य पर प्रकाश डालता है कि अर्थव्यवस्थाएँ तत्परता के विभिन्न चरणों में मौजूद हैं, और यह कि सरकारें एक व्यवसायिक वातावरण बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं जो सतत विकास के लिए अनुकूल है।
- पारदर्शिता डेटा अखंडता के लिए बिजनेस रेडी के सुरक्षा उपायों की एक प्रमुख विशेषता होगी।
- परियोजना द्वारा एकत्र की गई सभी जानकारी-कच्चा दानेदार डेटा, स्कोर, साथ ही स्कोर प्राप्त करने के लिए उपयोग की जाने वाली गणना-प्रोजेक्ट वेबसाइट पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराई जाएगी।
- इसके अलावा, रिपोर्ट में प्रस्तुत किए गए सभी परिणाम वेबसाइट पर उपलब्ध सरल टूलकिट का उपयोग करते हुए दोहराए जा सकेंगे।

मुद्रा और वित्त

खबरों में क्यों

RBI ने वर्ष 2022-23 के लिए 'मुद्रा और वित्त' पर रिपोर्ट जारी की

महत्वपूर्ण बिंदु

- RBI ने वर्ष 2022-23 के लिए मुद्रा और वित्त (RCF) पर एक रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट का विषय "टुवार्ड्स ए ग्रीनर क्लीनर इंडिया" है।
- रिपोर्ट के मुख्य आकर्षण में 2030 तक सालाना GDP के कम से कम 2.5% की अनुमानित हरित वित्तपोषण आवश्यकता शामिल है।
- इसके अलावा, भारत जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, 2023 के अनुसार जी-20 देशों में सर्वश्रेष्ठ स्थान पर है।
- इसके अलावा, रिपोर्ट भारत में टिकाऊ उच्च विकास के लिए भविष्य की चुनौतियों का आकलन करने के लिए जलवायु परिवर्तन के प्रमुख आयामों की जांच करती है।

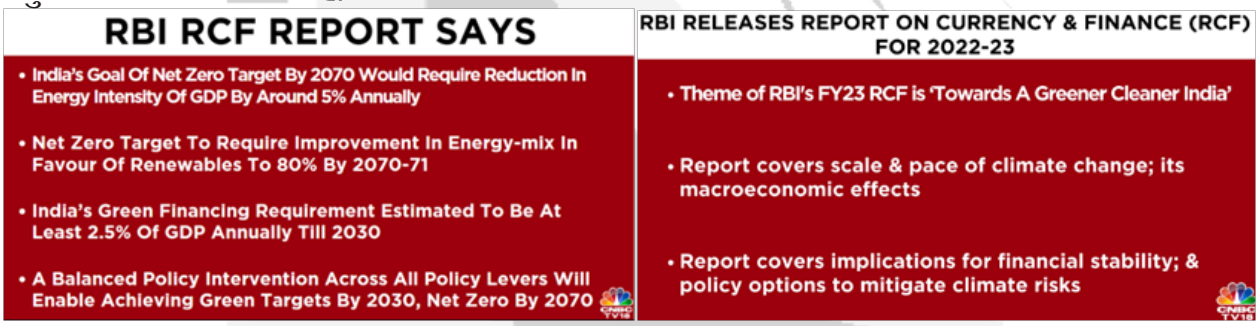

- भारत का शुद्ध-शून्य लक्ष्य वर्ष 2070 है।
- रिपोर्ट में जलवायु परिवर्तन के चार प्रमुख पहलुओं पर ध्यान दिया गया है, जिसमें इसके असाधारण आकार और तीव्रता, व्यापक आर्थिक प्रभाव, वित्तीय स्थिरता निहितार्थ और जलवायु जोखिम को कम करने की रणनीति शामिल है।
- रिपोर्ट में भारत में टिकाऊ उच्च विकास के लिए भविष्य की चुनौतियों का आकलन करने के लिए जलवायु परिवर्तन के चार प्रमुख आयामों को शामिल किया गया है।
  - जलवायु परिवर्तन का अभूतपूर्व पैमाना और गति;
  - व्यापक आर्थिक प्रभाव
  - वित्तीय स्थिरता के लिए निहितार्थ
  - जलवायु जोखिमों को कम करने के लिए नीतिगत विकल्प।
- भारत को 2070 तक अपने निवल शून्य लक्ष्य को और प्राप्त करने के लिए, आरबीआई ने कहा, देश को सकल घरेलू उत्पाद की ऊर्जा तीव्रता में सालाना लगभग 5 प्रतिशत की त्वरित कमी की आवश्यकता होगी और लगभग 80 प्रतिशत 2070-71 तक नवीकरणीय ऊर्जा के पक्ष में इसके ऊर्जा मिश्रण में महत्वपूर्ण सुधार की आवश्यकता होगी।

India's Action Related to Climate Change

Area	Salient Initiatives
Science & Research	1. Indian Network for Climate Change Assessment (INCCA) 2. Himalayan Glaciers Monitoring Programme 3. Launch of Indian Satellite to Monitor Greenhouse Gases 4. India's Forest and Tree Cover as a Carbon Sink 5. India GHG Emissions Profile
Policy Development	6. Expert Group on Low Carbon Economy 7. State Action Plan on Climate Change 8. National Policy on Biofuels
Policy Implementation	9. National Missions under National Action Plan on Climate Change 10. National Conference on Green Building Materials and Technologies 11. In-Principle Approval to 30 Solar Cities 12. Energy Efficiency Standards for Appliances 13. Fuel Efficiency Norms 14. Clean Development Mechanism (CDM) Programme
International Cooperation	15. UN Climate Technology Conference 16. SAARC Environment Ministers' Conference 17. India's Submissions to UNFCCC
Forestry	18. State of Forest Report 19. Green India Mission 20. Capacity Building of Forestry, Intensification of Forestry Management and Inclusion of Forestry within MGNREGA

Source: Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India.

भारत ने उत्पादों पर अनिवार्य प्रमाणीकरण लागू कर दिया है

खबरों में क्यों

भारत ने अब तक 115 QCOs जारी किए हैं और 14 मंत्रालयों के 675 उत्पादों के ऑर्डर विचाराधीन हैं।

महत्वपूर्ण बिंदु

- भारत सरकार द्वारा गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों (QCO) में वृद्धि के बीच और हाल ही में कोविड-19 की लहर के बाद चीनी अधिकारियों द्वारा निरीक्षण के लिए अपनी विनिर्माण सुविधाओं को कब खोला जाएगा, इस पर अनिश्चितता के बीच, चीनी सामानों का आयात घट सकता है, जिससे भारतीय उद्योग के लिए समस्याएँ खड़ी हो सकती हैं।
- भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) द्वारा निरीक्षण महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि भारत कई उत्पादों पर अनिवार्य प्रमाणीकरण लागू कर रहा है, जिनके लिए QCO जारी किए गए हैं।
- सैकड़ों QCO की घोषणाओं के लिए अब सीमा शुल्क अधिकारियों को उन उत्पादों को ब्लॉक करने की आवश्यकता है जो भारतीय मानकों के अनुरूप नहीं हैं।
- क्यूसीओ को एयर-कंडीशनर और रेफ्रिजरेटर से लेकर फुटवियर, व्हील रिम्स, केमिकल्स और औद्योगिक श्रमिकों के लिए सुरक्षात्मक कपड़ों तक के उत्पादों पर लागू किया जा रहा है।
- आयात में देरी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है क्योंकि दवा सामग्री, रसायन, मशीनरी, ऑटो पार्ट्स और चिकित्सा आपूर्ति सहित उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए चीन भारत का प्राथमिक स्रोत है।

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, मार्च में समाप्त वित्त वर्ष के दौरान चीन से कुल आयात बढ़कर 98.51 अरब डॉलर हो गया, जो पिछले वित्त वर्ष में 94.57 अरब डॉलर था।

- भारत चीन से आयात नहीं रोक रहा है। मुद्दा यह है कि चीन में यात्रा प्रतिबंधों के कारण निरीक्षण नहीं हो रहे हैं।
- चीनी अधिकारियों ने अभी तक निरीक्षण के लिए सुविधाओं को फिर से खोलने का संकेत नहीं दिया है।

- भारत ने उन सभी देशों का निरीक्षण फिर से शुरू कर दिया है जिनके दूतावासों ने हमें लिखा है कि उनकी सुविधाएं निरीक्षण के लिए खुली हैं।
- BIS निरीक्षण के बिना प्रमाणन नहीं दे सकता है।

भारत ने धन शोधन रोधी कानून में संशोधन किया

खबरों में क्यों

चार्टर्ड एकाउंटेंट, कंपनी सचिव अब मनी लॉन्ड्रिंग कानून के दायरे में

महत्वपूर्ण बिंदु

- धन शोधन निवारण अधिनियम में परिवर्तनों को अधिसूचित करते हुए, वित्त मंत्रालय ने अपने ग्राहकों की ओर से वित्तीय लेनदेन करने वाले चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, कंपनी सचिवों और लागत और कार्य लेखाकारों को मनी लॉन्ड्रिंग कानून के दायरे में लाया है।
- हालांकि, वकीलों और कानूनी पेशेवरों को PMLA के तहत आने वाली संस्थाओं की नई परिभाषा से बाहर रखा गया लगता है।
- PMLA के तहत एक गतिविधि को मान्यता दी जाएगी यदि ये पेशेवर अपने ग्राहक की ओर से किसी अचल संपत्ति की खरीद और बिक्री जैसे वित्तीय लेनदेन करते हैं; ग्राहक के पैसे, प्रतिभूतियों या अन्य संपत्तियों का प्रबंधन; बैंक, बचत या प्रतिभूति खातों का प्रबंधन; कंपनियों के निर्माण, संचालन या प्रबंधन के लिए योगदान का संगठन; कंपनियों का निर्माण, संचालन या प्रबंधन, सीमित देयता भागीदारी या ट्रस्ट और व्यापारिक संस्थाओं की खरीद और बिक्री।
- विशेषज्ञों ने कहा कि संशोधनों से जांच एजेंसियों को शेल कंपनियों और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े संदिग्ध लेनदेन के खिलाफ अपनी जांच में मदद मिलने की उम्मीद है।

PMLA (अभिलेखों का रखरखाव) संशोधन नियम, 2023

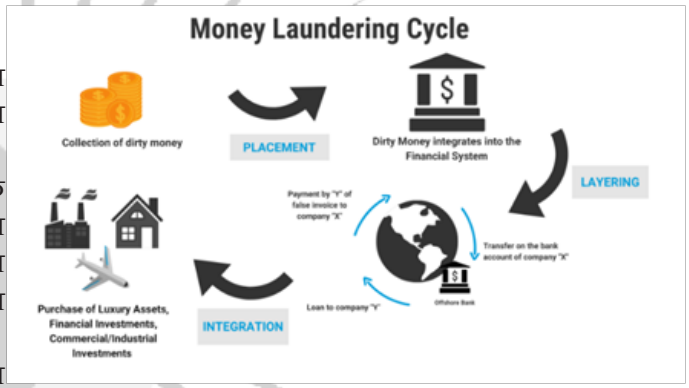

- इससे पहले मार्च, 2023 में वित्त मंत्रालय के अधीन राजस्व विभाग द्वारा धन शोधन निवारण (रिकॉर्ड का रखरखाव) संशोधन नियम, 2023 पेश किया गया था।
- इन नियमों ने FATF की सिफारिशों के अनुरूप PMLA के तहत गैर-सरकारी संगठनों और परिभाषित राजनीतिक रूप से उजागर व्यक्तियों (PEP) के लिए अधिक खुलासे को शामिल करने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग प्रावधानों के तहत रिपोर्टिंग संस्थाओं के दायरे को चौड़ा किया।
- नए नियमों में पंजीकरण प्रमाणपत्र और पैन (स्थायी खाता संख्या) जैसे दस्तावेजों के माध्यम से मौजूदा KYC आवश्यकताओं के अलावा वित्तीय संस्थानों, बैंकिंग कंपनियों, या मध्यस्थों जैसी रिपोर्टिंग संस्थाओं को लाभार्थी मालिकों का खुलासा करने की आवश्यकता है।

पृष्ठभूमि

- PMLA, 2002 में हाल ही में किए गए परिवर्तन चीनी ऐप्स घोटाले के जवाब में किए गए थे, जहां कुछ लेखा पेशेवरों ने इन ऐप्स के लिए शेल कंपनियां स्थापित करने में सहायता की थी।
- इन पेशेवरों ने इन शेल कंपनियों को पंजीकृत करने के लिए अपने कार्यालय के पते का उपयोग किया और यहां तक कि निदेशक भी बन गए, जिनमें से कुछ के पास अपने बैंक खातों तक पहुंच थी।
- इनमें से कुछ चीनी ऐप्स ने तत्काल ऋण की पेशकश की, जो कई व्यक्तियों को आकर्षक लगी। दुर्भाग्य से, ऋण प्राप्तकर्ताओं के व्यक्तिगत डेटा से समझौता किया गया और गेमिंग ऐप्स सहित अन्य ऐप्स के साथ साझा किया गया।
- इस तरह के घोटालों को रोकने के लिए, लेखाकारों को अब अपने ग्राहकों के स्वामित्व, वित्तीय स्थिति और धन के स्रोत के साथ-साथ लेन-देन के उद्देश्य का दस्तावेजीकरण करने की आवश्यकता है।
- भारत सरकार ने शामिल कुछ पेशेवरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की है और उन्हें अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया को भेजा है।

भारत में लेखा पेशेवरों द्वारा की जाने वाली कौन सी वित्तीय गतिविधियाँ PMLA द्वारा कवर की जाती हैं?

- कोई अचल संपत्ति खरीदना और बेचना।
- ग्राहक के पैसे, प्रतिभूतियों, या अन्य संपत्तियों का प्रबंधन करना।
- बैंक, बचत, या प्रतिभूति खातों का प्रबंधन।
- कंपनियों के निर्माण, संचालन या प्रबंधन के लिए योगदान का संगठन।
- कंपनियों का निर्माण, संचालन, या प्रबंधन, सीमित देयता भागीदारी या ट्रस्ट, और व्यापारिक संस्थाओं की खरीद और बिक्री।

पब्लिक स्टॉकहोल्डिंग

खबरों में क्यों

ट्रेड बॉडी मीट में भारत ने खाद्य भंडारण के स्थायी समाधान की मांग की

महत्वपूर्ण बिंदु

पब्लिक स्टॉकहोल्डिंग क्या है?

- पब्लिक स्टॉकहोल्डिंग (PSH) एक प्रकार का नीतिगत साधन है जिसका उपयोग सरकार किसी देश की खाद्य सुरक्षा को पूरा करने

के लिए करती है। कुछ देशों द्वारा गरीबी रेखा से नीचे अपना जीवन व्यतीत करने वाले और लगातार भोजन की कमी का सामना करने वाले लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए सार्वजनिक स्टॉकहोल्डिंग कार्यक्रम चलाए जाते हैं।

विश्व व्यापार संगठन में भारत

- भारत ने फरवरी 2024 में विश्व व्यापार संगठन (WTO) की मंत्रिस्तरीय बैठक में खाद्य सुरक्षा के लिए सार्वजनिक स्टॉकहोल्डिंग के मुद्दे का स्थायी समाधान खोजने का आह्वान किया है।
- इसने PSH (पब्लिक स्टॉक होल्डिंग) और SSM (स्पेशल सेफगार्ड मैकेनिज्म) से परे वैकल्पिक खाद्य सुरक्षा समाधान के तर्कों को खारिज कर दिया है और मानता है कि बाजार पहुंच और निर्यात प्रतिबंध प्रयास के लायक नहीं हैं।
- भारत ने खाद्य भंडार की कीमतों पर मुद्रास्फीति और अन्य आर्थिक कारकों के प्रभाव को दर्शाने के लिए बाहरी संदर्भ कीमतों की पुनर्गणना करने की आवश्यकता पर भी बल दिया है।
- कृषि पर विश्व व्यापार संगठन की समिति के एक विशेष सत्र के दौरान इस मुद्दे पर चर्चा की गई।
- भारत ने घोषणा की कि खाद्य सुरक्षा उद्देश्यों के लिए सार्वजनिक स्टॉकहोल्डिंग के मौजूदा प्रस्ताव को संशोधित करने का उसका कोई इरादा नहीं है और सुझाव दिया कि यह आगे बढ़ने का एकमात्र तरीका है।
- भारत ने MC13 (13वें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन) में PSH के लिए एक स्थायी समाधान का आह्वान किया।
- 13वां विश्व व्यापार संगठन (WTO) मंत्रिस्तरीय सम्मेलन (MC13) 26 फरवरी, 2024 के सप्ताह में अबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात में होगा।
- MC 164 सदस्यीय बहुपक्षीय निकाय का सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय है
- बैठक में, चीन, भारत, श्रीलंका, दक्षिण अफ्रीका और मिस्र ने PSH पर पाठ-आधारित वार्ता शुरू करने के आह्वान में भाग लिया।
- उन्होंने गंभीर खाद्य सुरक्षा समस्या का समाधान करने में मदद करने के लिए सभी विकासशील देशों, विशेष रूप से कम विकसित देशों (LDC) और शुद्ध खाद्य आयात करने वाले विकासशील देशों (NFIDC) पर PSH लागू करने के महत्व पर प्रकाश डाला।
- भारत ने गैर-समर्थकों की उनकी हठ और पुराने पदों से हटने की अनिच्छा के लिए आलोचना की, जब बातचीत के विवरण पर चर्चा शुरू हुई।
- एक स्थायी समाधान के हिस्से के रूप में, भारत ने खाद्य सब्सिडी कैप की गणना के लिए सूत्र में संशोधन और 2013 के बाद लागू कार्यक्रमों को 'शांति खंड' के दायरे में शामिल करने के लिए कहा है।
- एक अंतरिम उपाय के रूप में, दिसंबर 2013 में बाली मंत्रिस्तरीय बैठक में विश्व व्यापार संगठन के सदस्यों ने शांति खंड नामक एक तंत्र स्थापित करने पर सहमति व्यक्त की थी और एक स्थायी समाधान के लिए एक समझौते पर बातचीत करने के लिए प्रतिबद्ध थे।

शांति खंड

- शांति खंड के तहत, विश्व व्यापार संगठन के सदस्यों ने विश्व व्यापार संगठन के विवाद समाधान फोरम में एक विकासशील राष्ट्र द्वारा निर्धारित सीमा में किसी भी उल्लंघन को चुनौती देने से बचने पर सहमति व्यक्त की।
- यह खंड तब तक बना रहेगा जब तक कि खाद्य भंडार के मुद्दे का स्थायी समाधान नहीं मिल जाता।
- वैश्विक व्यापार मानदंडों के तहत, एक विश्व व्यापार संगठन सदस्य देश के खाद्य सब्सिडी बिल को 1986-88 के संदर्भ मूल्य के आधार पर उत्पादन के मूल्य के 10 प्रतिशत की सीमा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए।
- निर्धारित सीमा से अधिक की सब्सिडी को व्यापार विकृत करने के रूप में देखा जाता है। भारत जैसे विकासशील देशों के लिए यह सीमा खाद्य उत्पादन के मूल्य के 10 प्रतिशत पर तय की गई है।
- भारत ने पहले विश्व व्यापार संगठन को सूचित किया था कि उसने अपनी गरीब आबादी की घरेलू खाद्य सुरक्षा जरूरतों को पूरा करने के लिए विपणन वर्ष 2020-21 के लिए चावल किसानों को अतिरिक्त समर्थन उपाय प्रदान करने के लिए शांति खंड का उपयोग किया है।
- भारत ने SSM के लिए भी कहा, जिसका उद्देश्य गरीब और सीमांत किसानों को आयात में किसी भी वृद्धि या कीमतों में भारी गिरावट से बचाना है।
- जिनेवा स्थित 164 सदस्यीय बहुपक्षीय निकाय वैश्विक निर्यात और आयात संबंधी मानदंडों से संबंधित है। इसके अलावा, यह सदस्य देशों के बीच व्यापार विवादों का फैसला करता है।
- विश्व व्यापार संगठन की कृषि वार्ता में घरेलू समर्थन, बाजार पहुंच, निर्यात प्रतिस्पर्धा, निर्यात प्रतिबंध, कपास, खाद्य सुरक्षा उद्देश्यों के लिए सार्वजनिक स्टॉकहोल्डिंग, विशेष सुरक्षा तंत्र और पारदर्शिता के क्रॉस-कटिंग मुद्दे सहित विभिन्न विषयों को शामिल किया गया है।
- जिनेवा में 12वें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में, खाद्य सुरक्षा के मोर्चे पर प्रगति करने के बावजूद, सदस्य कृषि सुधार कार्य योजना पर एक समझौते पर पहुंचने में असमर्थ रहे।

ट्रांज़िशन बांड

खबरों में क्यों

- हाल ही में, सेबी ने पारदर्शिता और सूचित निर्णय लेने की सुविधा के लिए ट्रांज़िशन बांड जारी करने और सूचीबद्ध करने के लिए अतिरिक्त आवश्यकताओं को अनिवार्य कर दिया है।

महत्वपूर्ण बिंदु

- निवेशकों के बीच पारदर्शिता और सूचित निर्णय लेने की सुविधा के लिए, बाजार नियामक सेबी ने शुक्रवार को ट्रांज़िशन बांड जारी करने और सूचीबद्ध करने के लिए अतिरिक्त आवश्यकताओं को अनिवार्य कर दिया।
- भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने एक परिपत्र में कहा है कि इस कदम का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना भी है कि ट्रांज़िशन बांड के माध्यम से जुटाई गई धनराशि गलत तरीके से आवंटित नहीं की जा रही है।

ट्रांज़िशन बांड क्या है?

- संक्रमण बांड 'हरित ऋण सुरक्षा' की उप-श्रेणियों में से एक है।

- इन बांडों का उपयोग आम तौर पर भारत के इच्छित राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदानों के अनुरूप संचालन के अधिक टिकाऊ रूप में ट्रांज़िशन के लिए धन जुटाने के लिए किया जाता है।
- अपने सर्कुलर में, सेबी ने कहा कि एक जारीकर्ता जो ट्रांजिशन बांड जारी करना चाहता है, उसे पब्लिक इश्यू या ऐसे ट्रांजिशन बांड के निजी प्लेसमेंट के लिए ऑफर डॉक्यूमेंट में अतिरिक्त खुलासा करना होगा।

हरित ऋण सुरक्षा की अन्य श्रेणियों से ट्रांज़िशन बांड को अलग करें

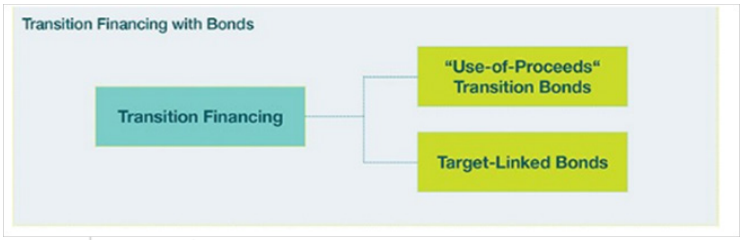

- हरित ऋण सुरक्षा की अन्य श्रेणियों से संक्रमण बांडों को अलग करने के लिए, ट्रांज़िशन बांड जारी करने वाले को 'GB-T' संकेत का उपयोग करना होगा।
- इस तरह के नोटेशन को कवर पेज पर ऑफर दस्तावेजों में और टर्म शीट में इंस्ट्रूमेंट फील्ड के प्रकार में प्रकट किया जाएगा।
- परिवर्तन योजना में लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक सांकेतिक समयरेखा के साथ-साथ अंतरिम लक्ष्यों का विवरण शामिल होना चाहिए। अंतरिम लक्ष्यों को इस संबंध में सांकेतिक आंकड़ा भी प्रदर्शित करना चाहिए कि जारीकर्ता कितना उत्सर्जन कम करने की परिकल्पना कर रहा है।
- अन्य बातों के अलावा, ट्रांज़िशन योजना में परियोजना कार्यान्वयन रणनीति के संक्षिप्त विवरण और परियोजना कार्यान्वयन के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग के बारे में विवरण और ट्रांज़िशन बांड के माध्यम से जुटाई गई धनराशि के उपयोग की निगरानी के लिए तंत्र और संक्रमण योजना के कार्यान्वयन के बारे में जानकारी होनी चाहिए।
- जारीकर्ता कार्यान्वयन की निगरानी के लिए एक समिति भी बना सकते हैं और परिभाषित लक्ष्यों को समय पर पूरा करना सुनिश्चित कर सकते हैं। कॉरपोरेट बॉन्ड के लिए केंद्रीकृत डेटाबेस में प्रकटीकरण के संबंध में, सेबी ने कहा कि एक जारीकर्ता को डीनोटेशन GB-T भरकर कॉरपोरेट बॉन्ड के लिए केंद्रीकृत डेटाबेस में डिनोटेशन का खुलासा करना होगा।
- डिपॉजिटरी कॉर्पोरेट बॉन्ड के लिए केंद्रीकृत डेटाबेस में "इंस्ट्रूमेंट विवरण" फ़ील्ड में उपसर्ग के रूप में इस डिनोटेशन को अपडेट करेंगे।

पेट्रोलियम मंत्रालय ने ऊर्जा संक्रमण सलाहकार समिति की रिपोर्ट प्राप्त की

खबरों में क्यों

हाल ही में एनर्जी ट्रांजिशन एडवाइजरी कमेटी (ETAC) ने "द ग्रीन शिफ्ट: द लो कार्बन ट्रांजिशन ऑफ इंडियाज ऑयल एंड गैस सेक्टर" पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है।

महत्वपूर्ण बिंदु

- ऊर्जा संक्रमण सलाहकार समिति (ETAC) का गठन पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (MoP&NG) के तहत किया गया था। इस समिति का उद्देश्य देश में सार्वजनिक क्षेत्र के तेल और गैस उपक्रमों के लिए ऊर्जा संक्रमण का रास्ता तैयार करना है।

ऊर्जा संक्रमण की आवश्यकता

- भारत विश्व स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा CO2 उत्सर्जक है। साथ ही, इन उत्सर्जनों के 5 गुना बढ़कर लगभग 13.6 गीगाटन प्रति वर्ष होने का अनुमान है। साथ ही, स्वच्छ ऊर्जा में परिवर्तन से उत्सर्जन में कमी आएगी।
- ऊर्जा के उत्पादन और आपूर्ति (विशेष रूप से तेल और गैस) पर कुछ देशों का एकाधिकार है और भारत अपनी अधिकांश ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आयात पर निर्भर है।
- वर्ष 2019 में भारत विश्व में जलवायु परिवर्तन से सर्वाधिक प्रभावित देशों में 7वें स्थान पर था।

सिफारिशों

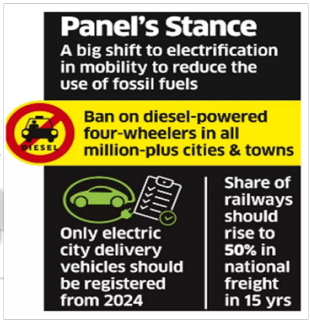

- वर्ष 2035 तक ऊर्जा खपत में ग्रिड-वितरित बिजली की हिस्सेदारी वर्तमान 18 प्रतिशत से बढ़ाकर 40 प्रतिशत की जानी चाहिए।
- जैव ईंधन की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए नए फीडस्टॉक पर अनुसंधान को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
- वर्ष 2027 तक दस लाख से अधिक आबादी वाले सभी शहरों में डीजल से चलने वाले चौपहिया वाहनों पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए।
- LPG में सम्मिश्रण के विकल्पों पर शोध करने की आवश्यकता है।
- अगले 15 वर्षों में राष्ट्रीय स्तर पर माल यातायात में रेलवे की हिस्सेदारी वर्तमान 23 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत की जानी चाहिए।
- वर्ष 2024 से इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए केवल सिटी डिलीवरी वाहनों का ही पंजीकरण कराया जाए।

भारत का कृषि निर्यात

खबरों में क्यों

31 मार्च, 2023 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में भारत से कृषि निर्यात और आयात दोनों ने नई ऊंचाई हासिल की है।

महत्वपूर्ण बिंदु

- सरकारी डेटा अप्रैल-दिसंबर (9 महीने) 2022 में कृषि निर्यात का मूल्य 39 बिलियन अमरीकी डॉलर दर्शाता है।

- यह पिछले वर्ष की इसी अवधि के लिए 36.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर से 7.9% अधिक है।
- इस दर पर, 2021-22 में हासिल किए गए रिकॉर्ड 50.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निर्यात को पार करना तय है।

निर्यात में वृद्धि के पीछे प्रमुख कारक

- भारत के कृषि-निर्यात विकास में दो बड़े योगदानकर्ता चावल और चीनी रहे हैं।
- भारत ने 2021-22 में 9.66 बिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य के 21.21 मिलियन टन (mt) चावल का अब तक का सर्वाधिक निर्यात किया।
- चीनी निर्यात 2021-22 में 4.60 बिलियन अमेरिकी डॉलर के रिकॉर्ड मूल्य पर पहुंच गया, जबकि पिछले चार वित्तीय वर्षों में यह 2.79 बिलियन अमेरिकी डॉलर, 1.97 बिलियन अमेरिकी डॉलर, 1.36 बिलियन अमेरिकी डॉलर और 810.90 मिलियन अमेरिकी डॉलर था।
- इस वित्तीय वर्ष में अप्रैल-दिसंबर 2021 में 2.78 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अप्रैल-दिसंबर 2022 में 3.99 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक 43.6% की और वृद्धि देखी गई है।
- चावल और चीनी का निर्यात 2022-23 में यदि शीर्ष पर नहीं तो क्रमशः $11 बिलियन और $6 बिलियन को छूने की ओर है।

कृषि आयात के बारे में:

- निर्यात की तरह आयात भी बढ़ रहा है।
- अप्रैल-दिसंबर 2022 में कृषि उपज का आयात 27.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा।
- यह अप्रैल-दिसंबर 2021 के लिए 24.1 अरब अमेरिकी डॉलर से 15.4% की वृद्धि है।
- इसके परिणामस्वरूप, कृषि व्यापार खाते पर अधिशेष में और कमी आई है

INDIA'S AGRICULTURAL TRADE IN MILLION US DOLLARS

YEAR	EXPORTS	IMPORTS	TRADE SURPLUS
2012-13	41726.33	18978.33	22748.00
2013-14	43251.66	15528.94	27722.72
2014-15	39080.43	21151.77	17928.66
2015-16	32808.64	22578.60	10230.04
2016-17	33696.83	25643.40	8053.43
2017-18	38897.21	24890.90	14006.31
2018-19	39203.53	20920.34	18283.19
2019-20	35600.47	21859.99	13740.48
2020-21	41895.68	21652.05	20243.63
2021-22	50240.21	32422.30	17817.91
Apr-Dec 21	36155.42	24071.55	12083.87
Apr-Dec 22	38997.92	27770.64	11227.28

आयात में वृद्धि मुख्य रूप से तीन वस्तुओं से हुई है

- पहला वनस्पति तेल है, जिसका आयात 2020-21 में 11.09 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2021-22 में 18.99 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। आयात भारत की वनस्पति तेल आवश्यकताओं का लगभग 60% पूरा करता है।
- अन्य तीन वस्तुएं कपास, काजू और मसाले हैं।

आयात में वृद्धि के पीछे प्रमुख कारक

- भारत का कपास उत्पादन 2013-14 में 398 लाख गांठ से घटकर 2021-22 में 307.05 लाख गांठ के 12 साल के निचले स्तर पर आ गया है।
- पहली पीढ़ी के BT कपास के बाद नई आनुवंशिक संशोधन (GM) प्रौद्योगिकियों की अनुमति नहीं देने के प्रभाव दिखाई दे रहे हैं, और निर्यात पर भी प्रभाव पड़ रहा है।
- खाद्य तेलों में भी एक सक्रिय दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जहां जीएम संकर सरसों के रोपण की बड़ी अनिच्छा के साथ अनुमति दी गई है।

सरकार की पहल

- कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देना एक सतत प्रक्रिया है।
- कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने राज्य/जिला स्तर पर कई कदम उठाए हैं।
- कृषि निर्यात नीति 2018: कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए, सरकार ने निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ 2018 में एक व्यापक कृषि निर्यात नीति पेश की:
  - हमारी निर्यात टोकरी, गंतव्यों में विविधता लाने और खराब होने वाली वस्तुओं पर ध्यान देने सहित उच्च मूल्य और मूल्य वर्धित कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए।
  - नए, स्वदेशी, जैविक, जातीय, पारंपरिक और गैर-पारंपरिक कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देना।
  - बाजार पहुंच को आगे बढ़ाने, बाधाओं से निपटने और स्वच्छता और फाइटोसैनेटिक मुद्दों से निपटने के लिए एक संस्थागत तंत्र प्रदान करना।
  - जल्द से जल्द वैश्विक मूल्य श्रृंखला के साथ एकीकरण करके विश्व कृषि निर्यात में भारत की हिस्सेदारी को दोगुना करने का प्रयास करना।
  - किसानों को विदेशी बाजार में निर्यात के अवसरों का लाभ प्राप्त करने में सक्षम बनाना।
- कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (APEDA) कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के लिए निर्यात प्रोत्साहन गतिविधियों में लगातार लगा हुआ है और इसने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। एपीडा 'कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात प्रोत्साहन योजना' को लागू करता है।
- योजना के विभिन्न घटकों के तहत विभिन्न विकासात्मक गतिविधियां शुरू की जाती हैं और निर्यातकों को सहायता प्रदान की जाती है। अवसंरचना विकास, बाजार विकास और गुणवत्ता विकास।

वित्त मंत्री ने FSDC की 27वीं बैठक की अध्यक्षता की।

खबरों में क्यों

केंद्रीय वित्त मंत्री ने वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद (FSDC) की 27वीं बैठक की अध्यक्षता की

महत्वपूर्ण बिंदु

- केंद्रीय वित्त मंत्री ने नई दिल्ली में वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद (FSDC) की 27वीं बैठक की अध्यक्षता की। बजट 2023-24 की घोषणा के बाद यह पहली बैठक थी।
- परिषद ने वित्तीय क्षेत्र को और विकसित करने और लोगों के लिए वित्तीय पहुंच बढ़ाने के लिए आवश्यक नीति और विधायी सुधार उपायों पर चर्चा की।

- परिषद की बैठक के दौरान, इस बात पर चर्चा की गई कि वित्तीय क्षेत्र को और विकसित करने के लिए आवश्यक नीति और विधायी सुधार उपायों को तैयार किया जा सकता है और न केवल लोगों की वित्तीय पहुंच में वृद्धि करने के लिए, बल्कि उनकी समग्र आर्थिक भलाई में भी वृद्धि की जा सकती है।

केंद्रीय वित्त मंत्री ने सलाह दी कि:

नियामकों को वित्तीय क्षेत्र की स्थिरता सुनिश्चित करने की सलाह:

- बैठक के दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि वित्तीय क्षेत्र की स्थिरता सुनिश्चित करना नियामकों की साझा जिम्मेदारी है। उन्होंने नियामकों को निरंतर सतर्कता बनाए रखने और किसी भी भेद्यता को कम करने और वित्तीय स्थिरता को मजबूत करने के लिए समय पर कार्रवाई करने की सलाह दी। नियामकों को भी सलाह दी गई थी कि वे अनुपालन बोझ को और कम करें और एक सुव्यवस्थित और कुशल नियामक वातावरण सुनिश्चित करें। केंद्रीय वित्त मंत्री जून 2023 में प्रत्येक नियामक के साथ इस संबंध में हुई प्रगति की समीक्षा करेंगे।

नियामकों से साइबर सुरक्षा तैयारियां सुनिश्चित करने का आग्रह:

- वित्त मंत्री ने नियामकों से साइबर हमलों के जोखिम को कम करने, संवेदनशील वित्तीय डेटा की रक्षा करने और समग्र प्रणाली अखंडता बनाए रखने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी प्रणालियों की साइबर सुरक्षा तैयारियों को सुनिश्चित करने का भी आग्रह किया। यह भारतीय वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता और लचीलेपन की रक्षा करेगा।

लावारिस जमाराशियों और दावों के निपटान को आसान बनाने के लिए विशेष अभियान:

- विनियामकों को बैंकिंग जमा, शेयर और लाभांश, म्युचुअल फंड, बीमा आदि जैसे सभी खंडों में वित्तीय क्षेत्र में दावा न किए गए जमा और दावों के निपटान की सुविधा के लिए एक विशेष अभियान चलाने के लिए भी कहा गया था।

बजट घोषणाओं के कार्यान्वयन पर चर्चा:

- परिषद ने 2019 से की गई बजट घोषणाओं पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट पर चर्चा की। नियामकों को सलाह दी गई कि वे बजट 2023-24 में की गई घोषणाओं को लागू करने के लिए एक केंद्रित दृष्टिकोण अपनाएं और इसके लिए समयसीमा तय की गई।

विभिन्न वित्तीय विषयों पर विचार-विमर्श:

- उपरोक्त के अलावा, परिषद ने विभिन्न विषयों पर भी विचार-विमर्श किया, जैसे अर्थव्यवस्था के लिए प्रारंभिक चेतावनी संकेतक और उनसे निपटने के लिए हमारी तैयारी, विनियामक गुणवत्ता में सुधार, कॉर्पोरेट के ऋण स्तर में सुधार करके वित्तीय क्षेत्र में विनियमित संस्थाओं पर अनुपालन बोझ को कम करना और भारत में घरेलू, डिजिटल इंडिया की जरूरतों को पूरा करने के लिए केवाईसी ढांचे का सरलीकरण और सुव्यवस्थित करना, सरकारी प्रतिभूतियों में खुदरा निवेशकों के लिए निर्बाध अनुभव, बिमाकृत भारत - बीमा को अंतिम मील तक ले जाने के लिए अद्वितीय मूल्य प्रस्ताव, और अंतर-समाधान के संदर्भ में आवश्यक समर्थन- GIFT IFSC के लिए विनियामक मुद्दे आत्मानबीर भारत में एक रणनीतिक भूमिका निभाएंगे।

FSDC उप-समिति की गतिविधियाँ और पिछले निर्णय:

- परिषद ने RBI गवर्नर की अध्यक्षता वाली FSDC उप-समिति द्वारा की गई गतिविधियों और एफएसडीसी के पिछले निर्णयों पर सदस्यों द्वारा की गई कार्रवाई पर भी ध्यान दिया।
- वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद (FSDC) भारत में एक शीर्ष स्तरीय निकाय है जिसे 2010 में वित्तीय स्थिरता बनाए रखने, वित्तीय क्षेत्र के विकास को बढ़ाने और अंतर-नियामक समन्वय के लिए तंत्र को मजबूत और संस्थागत बनाने के लिए स्थापित किया गया था।

FSDC के बारे में:

- संरचना: FSDC की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री करते हैं और इसमें वित्तीय क्षेत्र के नियामकों के प्रमुख शामिल होते हैं, अर्थात् भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI), भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI), भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) और वित्त मंत्रालय।
- उद्देश्य: FSDC का प्राथमिक उद्देश्य वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने, वित्तीय क्षेत्र के विकास को बढ़ाने और अंतर-नियामक समन्वय के लिए तंत्र को मजबूत और संस्थागत बनाना है।

कार्य: FSDC को निम्नलिखित कार्य दिए गए हैं:

- बड़े वित्तीय समूहों के कामकाज सहित अर्थव्यवस्था के मैक्रो-विवेकपूर्ण पर्यवेक्षण की निगरानी करना।
- वित्तीय क्षेत्र के कामकाज का आकलन करने और वित्तीय स्थिरता के संभावित जोखिमों की पहचान करने के लिए।
- वित्तीय क्षेत्र को मजबूत करने और इसकी दक्षता बढ़ाने के लिए नियामक सुधारों की सिफारिश करना।
- नियामकों के कामकाज का समन्वय करना और अंतर-नियामक मुद्दों को हल करना, यदि कोई हो।
- वित्तीय क्षेत्र में प्रणालीगत जोखिमों को दूर करने के लिए।
- बैठकें: वित्तीय स्थिरता और विकास से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने के लिए FSDC की समय-समय पर बैठकें होती हैं। बैठकों में वित्तीय क्षेत्र के नियामकों के प्रमुख और वित्त मंत्रालय के अन्य अधिकारी भाग लेते हैं।
- उप-समितियां: FSDC ने विशिष्ट मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए उप-समितियों का गठन किया है। वर्तमान में, तीन उप-समितियां हैं, अर्थात् वित्तीय बाजारों पर उप-समिति, वित्तीय संस्थानों पर उप-समिति और वित्तीय समावेशन और साक्षरता पर उप-समिति।
- उपलब्धियां: FSDC ने संकट के समय में वित्तीय स्थिरता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उदाहरण के लिए, 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट के दौरान, FSDC ने नियामकों के प्रयासों का समन्वय किया और यह सुनिश्चित किया कि भारतीय वित्तीय प्रणाली स्थिर रहे।

एक्सचेंज ट्रेडेड कमोडिटी डेरिवेटिव्स (ETCDs)

खबरों में क्यों

जिंस कारोबार में FPI के लिए प्रत्यक्ष बाजार पहुंच को सेबी की मंजूरी

महत्वपूर्ण बिंदु

- भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने स्टॉक एक्सचेंजों को शर्तों के अधीन एक्सचेंज ट्रेडेड कमोडिटी डेरिवेटिव्स (ETCDs) में भागीदारी के लिए FPI को डायरेक्ट मार्केट एक्सेस (DMA) सुविधा देने की अनुमति दी।
- नियामक ने अपनी कमोडिटी डेरिवेटिव्स सलाहकार समिति से इनपुट प्राप्त करने के बाद निर्णय लिया।
- नया प्रावधान तत्काल प्रभाव से लागू होगा।
- नियामक ने पहले ही श्रेणी III वैकल्पिक निवेश कोष (AIF), पोर्टफोलियो प्रबंधन सेवाओं और म्युचुअल फंड जैसे संस्थागत निवेशकों को ETCD बाजार में भाग लेने की अनुमति दे दी थी।
- DMA ब्रोकर के ग्राहकों को ब्रोकर द्वारा मैन्युअल हस्तक्षेप के बिना ऑर्डर देने या निष्पादित करने के लिए ब्रोकर के बुनियादी ढांचे के माध्यम से सीधे एक्सचेंज ट्रेडिंग सिस्टम तक पहुंचने की सुविधा प्रदान करता है।
- DMA ग्राहकों को ऑर्डर पर सीधे नियंत्रण, ऑर्डर का तेजी से निष्पादन, मैन्युअल ऑर्डर प्रविष्टि से जुड़ी त्रुटियों का कम जोखिम, गोपनीयता बनाए रखने, बड़े ऑर्डर के लिए कम प्रभाव लागत और बेहतर हेजिंग और आर्बिट्रेज रणनीतियों को लागू करने जैसे लाभों में सक्षम बनाता है।
- यह अनुमति कुछ शर्तों के अधीन है जिसके लिए दलालों को DMA, परिचालन विनिर्देशों, ग्राहक प्राधिकरण, दलाल-ग्राहक समझौते और जोखिम प्रबंधन के लिए आवेदन प्रक्रिया का पालन करने की आवश्यकता होती है।
- ETCD में भाग लेने के इच्छुक FPI जोखिम प्रबंधन के लागू उपायों के अधीन होंगे।
- इस कदम ने कुछ बाजार सहभागियों के बीच चिंता पैदा कर दी है, जिन्हें डर है कि FPI की बढ़ती भागीदारी से बाजार में अस्थिरता और अटकलों में वृद्धि हो सकती है।
- चिंताएं: बाजार की जटिलता और प्रतिभागियों की बड़ी संख्या को देखते हुए कमोडिटी डेरिवेटिव्स बाजार में FPI की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए नियामकों की क्षमता के बारे में चिंताएं हैं।
- FPI जो व्यक्ति, पारिवारिक कार्यालय और कॉर्पोरेट हैं, को किसी विशेष कमोडिटी डेरिवेटिव अनुबंध में ग्राहक-स्तर की स्थिति सीमा के 20% की स्थिति की अनुमति है।
- स्टॉक एक्सचेंज और समाशोधन निगम अतिरिक्त सुरक्षा उपायों और शर्तों को निर्दिष्ट कर सकते हैं, जैसा कि उचित समझा जाए, जोखिम का प्रबंधन करने और ETCD में व्यवस्थित व्यापार सुनिश्चित करने के लिए।

इस समय

- अगस्त में सेबी ने FPI को नकद निपटान वाले गैर-कृषि जिंस डेरिवेटिव अनुबंधों और ऐसी गैर-कृषि जिंसों वाले सूचकांकों में भाग लेने की अनुमति दी थी। इस कदम का उद्देश्य कमोडिटी डेरिवेटिव बाजारों में गहराई और तरलता बढ़ाना था।
- अक्टूबर 2018 में, सेबी ने पात्र विदेशी संस्थाओं (EFE) को भारतीय कमोडिटी बाजारों में वास्तविक जोखिम रखने वाले मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों के कमोडिटी डेरिवेटिव सेगमेंट में भाग लेने की अनुमति दी थी ताकि मुख्य रूप से उनके एक्सपोजर को हेजिंग किया जा सके।
- सेबी ने कहा कि उसने पिछले तीन वर्षों में ETCD में ऐसे EFE द्वारा गैर-भागीदारी पर विचार करते हुए इस मार्ग को बंद करने का निर्णय लिया था।

भारतीय रिजर्व बैंक

खबरों में क्यों

भारतीय रिजर्व बैंक GFIN के सहयोग से फर्मों को ग्रीनवॉशिंग टेकस्प्रिंट में भाग लेने के लिए आमंत्रित करता है

महत्वपूर्ण बिंदु

- भारतीय रिज़र्व बैंक ग्लोबल फाइनेंशियल इनोवेशन नेटवर्क (GFIN) के अब तक के पहले ग्रीनवाशिंग टेकस्प्रिंट में भाग लेने वाले 13 अंतर्राष्ट्रीय नियामकों में शामिल होगा।
- GFIN उपभोक्ताओं के हित में वित्तीय नवाचार का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध 80 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का एक समूह है और वर्तमान में इसकी अध्यक्षता वित्तीय आचरण प्राधिकरण द्वारा की जाती है।
- RBI एक सहभागी सदस्य के रूप में इस ग्रीनवाशिंग टेकस्प्रिंट में भाग लेने के लिए भारत से फर्मों को आमंत्रित कर रहा है।
- 'हरित' के रूप में विपणन किए जाने वाले या व्यापक स्थिरता के दावे करने वाले निवेश उत्पादों की संख्या बढ़ रही है। पर्यावरण, सामाजिक और शासन (ESG) क्रेडेंशियल्स के बारे में अतिरंजित, भ्रामक या निराधार दावे आत्मविश्वास को नुकसान पहुँचाते हैं
- इन उत्पादों में और RBI यह सुनिश्चित करना चाहता है कि उपभोक्ता और कंपनियां भरोसा कर सकें कि उत्पादों में स्थिरता की विशेषता है जिसका वे दावा करते हैं।
- इसलिए भारतीय रिजर्व बैंक FCA के डिजिटल सैंडबॉक्स पर होस्ट किए गए एक वर्चुअल टेकस्प्रिंट में भाग लेगा, ताकि सामूहिक प्राथमिकता के रूप में टिकाऊ वित्त को संबोधित करने के लिए अंतरराष्ट्रीय नियामकों, फर्मों और नवप्रवर्तकों को एक साथ लाया जा सके। टेकस्प्रिंट एक ऐसा उपकरण या समाधान विकसित करेगा जो नियामकों और बाजार को वित्तीय सेवाओं में ग्रीनवाशिंग के जोखिमों से प्रभावी ढंग से निपटने में मदद कर सके।

- भारतीय रिजर्व बैंक टेकस्प्रिंट में भाग लेने की इच्छुक सभी भारतीय फर्मों को आवेदन करने के लिए आमंत्रित कर रहा है। एप्लिकेशन विंडो खुली है और 21 मई 2023 को बंद हो जाएगी।
- फर्मों को दुनिया भर के नियामक विशेषज्ञों, विभिन्न हितधारकों और पेशेवरों के साथ काम करने का अवसर मिलेगा।
- इसके अतिरिक्त, आवेदन प्रक्रिया का समर्थन करने के लिए, GFIN TechSprint पर भाग लेने में रुचि रखने वाली फर्मों के लिए एक सूचना पैक प्रदान करेगा।
- फर्में जो अपने आवेदनों में सफल होंगी वे ऑन-बोर्डिंग के लिए आगे बढ़ेंगी जो 1 और 2 जून को होगी।
- यह फर्मों को डिजिटल सैंडबॉक्स पर प्रशिक्षण और टेकस्प्रिंट प्रक्रिया का गहन अवलोकन प्रदान करेगा।
- टेक स्प्रिंट 5 जून को लॉन्च होगा और सितंबर 2023 में शोकेस डे के साथ 3 महीने तक चलेगा।
- GFIN ग्रीनवॉशिंग टेकस्प्रिंट में आवेदन करने में रुचि रखने वाली कंपनियां जीएफआईएन वेबसाइट के माध्यम से भाग लेने वाले नियामकों की सूची की समीक्षा कर सकती हैं।

GFIN के बारे में

- GFIN वित्तीय नियामकों और संबंधित संगठनों का अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क है जो उपभोक्ताओं के सर्वोत्तम हित में वित्तीय नवाचार का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध है।
- ग्लोबल फाइनेंशियल इनोवेशन नेटवर्क (GFIN) को औपचारिक रूप से जनवरी 2019 में वित्तीय नियामकों और संबंधित संगठनों के एक अंतरराष्ट्रीय समूह द्वारा लॉन्च किया गया था।
- GFIN 70 से अधिक संगठनों का एक नेटवर्क है जो उपभोक्ताओं के हितों में वित्तीय नवाचार का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध है। यह नवोन्मेषी फर्मों को नियामकों के साथ बातचीत करने के लिए एक अधिक कुशल तरीका प्रदान करना चाहता है, जिससे उन्हें देशों के बीच नेविगेट करने में मदद मिलती है क्योंकि वे नए विचारों को मापते हैं।
- इसमें एक से अधिक अधिकार क्षेत्रों में नवीन उत्पादों, सेवाओं या व्यवसाय मॉडल का परीक्षण करने की इच्छुक फर्मों के लिए एक पायलट में शामिल होने के लिए आवेदन करने की क्षमता शामिल है।
- GFIN का उद्देश्य विभिन्न अनुभवों और दृष्टिकोणों को साझा करते हुए नवाचार से संबंधित विषयों पर वित्तीय सेवा नियामकों के बीच सहयोग के लिए एक नया ढांचा तैयार करना है।

ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस

खबरों में क्यों

ऊर्जा मंत्रालय ने उद्योगपतियों से ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस रूल्स (गोअर) 2022 का लाभ उठाने को कहा

महत्वपूर्ण बिंदु

- सरकार ने हरित ऊर्जा के उत्पादन, खरीद और खपत को बढ़ावा देने के लिए बिजली (हरित ऊर्जा मुक्त पहुंच के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना) नियम, 2022 अधिसूचित किया था।
- ओपन एक्सेस (OA) का अर्थ है पात्र उपभोक्ताओं, उत्पादकों और राज्य वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) को प्रदान की जाने वाली विद्युत पारेषण और वितरण प्रणाली तक गैर-भेदभावपूर्ण पहुंच।

ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस नियमों की मुख्य विशेषताएं

'ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस' की मुख्य विशेषताएं और आम उपभोक्ताओं को होने वाले लाभ इस प्रकार हैं:

a. इन नियमों को अपशिष्ट-से-ऊर्जा संयंत्रों से ऊर्जा सहित हरित ऊर्जा के उत्पादन, खरीद और खपत को बढ़ावा देने के लिए अधिसूचित किया गया है।
b. किसी भी उपभोक्ता को ग्रीन ओपन एक्सेस की अनुमति है और ग्रीन एनर्जी के लिए ओपन एक्सेस ट्रांजैक्शन की सीमा को 1 मेगावाट से घटाकर 100 kW कर दिया गया है, ताकि छोटे उपभोक्ता भी ओपन एक्सेस के जरिए अक्षय ऊर्जा खरीद सकें।
c. उपभोक्ता डिस्कॉम से हरित ऊर्जा की आपूर्ति की मांग करने के हकदार हैं। डिस्कॉम पात्र उपभोक्ताओं को हरित ऊर्जा की खरीद और आपूर्ति करने के लिए बाध्य होंगे।
d. इन नियमों ने ओपन एक्सेस देने के लिए समग्र अनुमोदन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित किया है। आवेदन में एकरूपता और पारदर्शिता लाकर समयबद्ध प्रक्रिया के साथ-साथ एक राष्ट्रीय पोर्टल के माध्यम से ओपन एक्सेस की मंजूरी अनिवार्य कर दी गई है। ग्रीन ओपन एक्सेस के लिए स्वीकृति 15 दिनों में दी जानी है अन्यथा इसे प्रदान किया गया माना जाएगा।
e. वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं को स्वेच्छा से हरित ऊर्जा खरीदने की अनुमति है।
f. ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस उपभोक्ताओं पर लगाए जाने वाले ओपन एक्सेस चार्ज पर निश्चितता प्रदान करें जिसमें ट्रांसमिशन चार्ज, व्हीलिंग चार्ज, क्रॉस सब्सिडी सरचार्ज, जहां भी लागू हो, स्टैंडबाय चार्ज, बैंकिंग चार्ज और अन्य शुल्क और लोड डिस्पैच सेंटर फीस और शेड्यूलिंग चार्ज, विचलन जैसे शुल्क शामिल हैं। आयोग के प्रासंगिक नियमों के अनुसार निपटान शुल्क।
g. क्रॉस-सब्सिडी अधिभार में वृद्धि के साथ-साथ अतिरिक्त अधिभार को हटाने पर कैप, उपभोक्ताओं को हरित होने के लिए प्रोत्साहित करती है।
h. वितरण लाइसेंसधारियों के क्षेत्र में सभी बाध्य संस्थाओं पर एक समान नवीकरणीय खरीद दायित्व (आरपीओ) होगा। इसके आरपीओ की पूर्ति के लिए ग्रीन हाइड्रोजन/ग्रीन अमोनिया को भी शामिल किया गया है।
i. उपभोक्ताओं को ग्रीन पावर का उपभोग करने पर ग्रीन सर्टिफिकेट दिया जाएगा और सुविधा भी दी जाएगी।

- विद्युत अधिनियम 2003 के अनुसार, टैरिफ उपयुक्त आयोग द्वारा निर्धारित किया जाता है।
- तदनुसार, हरित ऊर्जा के लिए टैरिफ उपयुक्त आयोग द्वारा निर्धारित किया जाएगा और इसमें नवीकरणीय ऊर्जा की औसत पूलित बिजली खरीद लागत, क्रॉस सब्सिडी शुल्क, यदि कोई हो और हरित ऊर्जा प्रदान करने के लिए वितरण लाइसेंसधारी की विवेकपूर्ण लागत को कवर करने वाले सेवा शुल्क शामिल होंगे।

RBI ने 2,000 रुपये के नोट वापस ले लिए

खबरों में क्यों

हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 2000 रुपये मूल्यवर्ग के बैंक नोटों को संचलन से वापस लेने का निर्णय लिया है।

महत्वपूर्ण बिंदु

- केंद्रीय बैंक ने जनता को 2000 रुपये के नोट जमा करने की सलाह दी है, जो 500 रुपये और 1000 रुपये के नोटों को छह साल पहले विमुद्रीकरण अभ्यास के दौरान वापस लेने के बाद उनके बैंक खातों में जमा किया गया था और उन्हें किसी भी बैंक शाखा में अन्य मूल्यवर्ग के बैंक नोटों में बदल दिया गया था।

RBI ने 2000 रुपए के नोट क्यों बंद कर दिए हैं ?

- 2000 रुपये के नोट को RBI अधिनियम, 1934 की धारा 24(1) के तहत नवंबर 2016 में पेश किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य 500 रुपये और 1000 रुपये के नोटों की कानूनी निविदा स्थिति को वापस लेने के बाद अर्थव्यवस्था की मुद्रा की आवश्यकता को तेजी से पूरा करना था।
- उस उद्देश्य की पूर्ति के साथ, और एक बार अन्य मूल्यवर्ग के नोट पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होने के बाद, 2018-19 में 2000 रुपये के नोटों की छपाई बंद कर दी गई थी।
- RBI ने मार्च 2017 से पहले 2000 रुपये मूल्यवर्ग के अधिकांश नोट जारी किए; ये नोट अब 4-5 साल के अपने अनुमानित जीवनकाल के अंत में हैं।
- यह मूल्यवर्ग अब आमतौर पर लेन-देन के लिए उपयोग नहीं किया जाता है; इसके अलावा, मुद्रा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अन्य मूल्यवर्ग में बैंक नोटों का पर्याप्त भंडार है।
- भारतीय रिजर्व बैंक की 'स्वच्छ नोट नीति' के अनुसरण में, 2000 रुपये मूल्यवर्ग के बैंक नोटों को संचलन से वापस लेने का निर्णय लिया गया है।

स्वच्छ नोट नीति क्या है?

- स्वच्छ नोट नीति जनता को बेहतर सुरक्षा सुविधाओं के साथ अच्छी गुणवत्ता वाले करेंसी नोट और सिक्के देने का प्रयास करती है, जबकि गंदे नोट चलन से बाहर हो जाते हैं।
- RBI ने पहले 2005 से पहले जारी किए गए सभी बैंक नोटों को संचलन से वापस लेने का फैसला किया था क्योंकि उनमें 2005 के बाद छपे बैंक नोटों की तुलना में कम सुरक्षा विशेषताएं हैं।
- हालांकि, 2005 से पहले जारी किए गए नोट वैध मुद्रा बने रहेंगे।
- उन्हें केवल एक ही समय में प्रचलन में कई श्रृंखलाओं के नोट नहीं रखने के मानक अंतरराष्ट्रीय अभ्यास के अनुरूप संचलन से वापस ले लिया गया है।

तो क्या 2000 रुपये के नोट वैध मुद्रा बने रहेंगे?

- 2000 रुपये का बैंकनोट अपनी कानूनी निविदा स्थिति को बनाए रखेगा।
- जनता के सदस्य अपने लेनदेन के लिए 2000 रुपये के नोटों का उपयोग करना जारी रख सकते हैं और उन्हें भुगतान के रूप में प्राप्त भी कर सकते हैं। हालाँकि, RBI को 30 सितंबर, 2023 को या उससे पहले इन बैंकनोटों को जमा करने या बदलने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

30 सितंबर के बाद क्या होगा ?

- RBI ने 30 सितंबर के बाद इन नोटों की स्थिति स्पष्ट नहीं की है।
- हालांकि, उसने कहा है कि 2000 रुपये के नोटों पर उसके निर्देश उस तारीख तक प्रभावी रहेंगे।

आपके पास जो 2000 रुपये के नोट हैं, उनका आपको क्या करना चाहिए?

- RBI ने लोगों को सलाह दी है कि इन नोटों को जमा करने और/या बदलने के लिए बैंक शाखाओं से संपर्क करें।
- सभी बैंकों में 30 सितंबर, 2023 तक खातों में जमा करने और 2000 रुपए के नोट बदलने की सुविधा उपलब्ध होगी।
- एक्सचेंज की सुविधा 30 सितंबर तक आरबीआई के उन 19 क्षेत्रीय कार्यालयों में भी उपलब्ध होगी जिनमें निर्गम विभाग हैं।

क्या आप कितने पैसे एक्सचेंज या डिपॉजिट कर सकते हैं, इसकी कोई सीमा है?

- कोई भी एक बार में 20,000 रुपये की सीमा तक 2000 रुपये के नोट बदल सकता है।
- किसी को अपने स्वयं के बैंक जाने की आवश्यकता नहीं है, बैंक का गैर-खाताधारक भी किसी भी बैंक शाखा में एक समय में 20,000 रुपये की सीमा तक 2000 रुपये के बैंकनोटों का आदान-प्रदान कर सकता है।
- एक खाताधारक के लिए प्रति दिन 4000 रुपये की सीमा तक व्यापार प्रतिनिधियों के माध्यम से 2000 रुपये के नोटों का आदान-प्रदान भी किया जा सकता है।

- अपने ग्राहक को जानो (KVEC) के मौजूदा मानदंडों और अन्य लागू वैधानिक/नियामक आवश्यकताओं के अनुपालन के अधीन प्रतिबंधों के बिना बैंक खातों में जमा किया जा सकता है।

आप 2000 रुपये के नोटों का आदान-प्रदान कब शुरू कर सकते हैं?

- बैंकों को तैयारी के लिए समय देने के लिए, RBI ने लोगों से कहा है कि वे 23 मई से RBI की शाखाओं या क्षेत्रीय कार्यालयों से संपर्क करके अपने नोट्स बदल लें।

अगर किसी के पास 2000 रुपये के नोट बहुत बड़ी संख्या में हैं तो क्या होगा?

- तकनीकी रूप से, एक व्यक्ति एक समय में 20,000 रुपये के पैकेट में कई एक्सचेंजों की मांग कर सकता है।
- हालांकि, यह प्रवर्तन एजेंसियों और आयकर विभाग का ध्यान आकर्षित करने की उम्मीद है।
- जिन लोगों के पास 2000 रुपये के नोटों में बड़ी रकम है, उनके लिए अपने पैसे का आदान-प्रदान करना मुश्किल हो सकता है।

वर्तमान में चलन में 2000 रुपये के नोटों का मूल्य क्या है?

- 2000 रुपये मूल्यवर्ग के लगभग 89% बैंक नोट मार्च 2017 से पहले जारी किए गए थे, और उनके अनुमानित 4-5 साल के जीवनकाल के अंत में हैं।
- संचलन में इन बैंकनोटों का कुल मूल्य 31 मार्च, 2018 को अपने चरम पर 6.73 लाख करोड़ रुपये से गिरकर (संचलन में नोटों का 37.3%) घटकर 3.62 लाख करोड़ रुपये हो गया है, जो 31 मार्च,2023 को प्रचलन में नोटों का केवल 10.8% है।.

YOUR SUCCESS OUR PRIORITY
RAO'S ACADEMY

5 विज्ञान और तकनीक

नीति आयोग

खबरों में क्यों

सामाजिक क्षेत्र 2023 में सर्वोत्तम प्रथाओं पर नीति आयोग का संग्रह

महत्वपूर्ण बिंदु

- नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया (नीति आयोग), भारत सरकार और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) के मार्गदर्शन और समर्थन के तहत "सामाजिक क्षेत्र में सर्वोत्तम प्रथाएं: एक संग्रह, 2023" तैयार किया गया है।
- संग्रह की तैयारी के लिए भारत के 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों से व्यापक डेटा संग्रह की आवश्यकता है।
- सामाजिक क्षेत्र समाज की समग्र प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसमें समाज के कई महत्वपूर्ण घटक शामिल हैं - स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, पेयजल और स्वच्छता, पर्यावरण, खाद्य सुरक्षा, महिला और बाल विकास, आजीविका, सामाजिक सुरक्षा, कौशल विकास आदि।
- विकास की कहानी का हिस्सा बनने के लिए समाज के हाशिए के वर्गों के लिए समान अवसर प्रदान करने के लिए भारत जैसे प्रगतिशील देश में सामाजिक क्षेत्र की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है।

प्रत्यक्ष लाभ, कृषि में पहल के लिए मुख्य चालकों के बीच आय में वृद्धि

- भारत की लगभग दो-तिहाई आबादी कृषि पर निर्भर है और यह क्षेत्र सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 19% का योगदान देता है।
- यह न केवल देश के सामाजिक ताने-बाने का एक प्रमुख घटक है बल्कि बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज के माध्यम से अर्थव्यवस्था के लिए भी महत्वपूर्ण है।
- जबकि आजीविका के लिए कृषि पर निर्भरता काफी अधिक है, यह कई मुद्दों से भरा हुआ है जो वित्तीय संकट में योगदान करते हैं।
- अप्रचलित प्रौद्योगिकी, बिचौलियों की उपस्थिति, बुनियादी ढांचे की कमी, आदि इस क्षेत्र की चुनौतियों में से हैं।
- सार-संग्रह में जिन पहलों पर प्रकाश डाला गया है उनमें से कुछ मुद्दों को संबोधित करने पर ध्यान दिया गया है।
- इस क्षेत्र के सार-संग्रह में 7 केस स्टडीज का उल्लेख किया गया है। यहाँ उनमें से कुछ का एक स्नैपशॉट है।
- नागालैंड में बड़ी इलायची के उत्पादन के लिए मूल्य श्रृंखला का विकास: पारंपरिक फसलों की तुलना में वाणिज्यिक फसलें अधिक राजस्व उत्पन्न करती हैं।
- हालांकि, फसल-विशिष्ट मूल्य श्रृंखला की कमी किसानों को इस विकल्प का पता लगाने के लिए सीमित करती है।
- फेक ऑर्गेनिक बड़ी इलायची उत्पादक कंपनी, एक किसान उत्पादक कंपनी (एफपीसी), बागवानी विभाग के सहयोग से, उत्पादन को प्रोत्साहित करती है और राज्य में जैविक बड़ी इलायची के लिए मूल्य श्रृंखला विकसित करती है।

> The objective is to develop commodity-specific organic value chain and address gaps in organic crop production, wild crop harvesting, organic livestock management and processing, handling and marketing of organic agricultural products with necessary infrastructural, technical and financial support. This will enable farmers to replace conventional and subsistence farming system with high value commercial organic enterprises.
>
> The initiative has facilitated partnerships between farmers and organic businesses in domestic and export markets in the form of FPCs, while linking cultivators with growers. The FPCs support the development of entire value chains starting from inputs, seeds, certification, creation of facilities for collection, aggregation, processing, marketing and brand-building initiations.

- किसानों और जैविक व्यवसायों के बीच साझेदारी के माध्यम से, वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि के साथ, 2018-2021 के दौरान लगभग 6.7 करोड़ रुपये का राजस्व उत्पन्न हुआ।
- मूल्य श्रृंखला ने इलायची फाइबर के उप-उत्पादों के लिए भी गुंजाइश बनाई।
- हरियाणा में फसल क्लस्टर विकास कार्यक्रम: हरियाणा के बागवानी विभाग द्वारा शुरू किए गए इस कार्यक्रम का उद्देश्य किसानों को उपज के उचित एकत्रीकरण, ग्रेडिंग/छंटाई, परिवहन और अतिरिक्त उत्पादन के प्रसंस्करण के लिए एक ऑन-फार्म सुविधा प्रदान करना है।
- ऐसे दो समूहों के अध्ययन से पता चलता है कि बेहतर बाजार पहुंच के माध्यम से किसानों की प्रत्यक्ष आय में वृद्धि हुई है। प्रभावी बाजार संपर्क के लिए आवश्यक पेशेवर विशेषज्ञता के साथ प्रमुख चुनौतियां बनी हुई हैं, जिसके लिए सरकार ने अपने समर्थन के साथ कदम बढ़ाया है।
- इसी तरह की पहल ओडिशा में भी शुरू की गई है, जिसमें बाजरा के उत्पादन पर ध्यान केंद्रित किया गया है और उपज के लिए एक मूल्य श्रृंखला तैयार की गई है।
- असम में चावल-मछली की खेती: असम के मत्स्य विभाग ने 11 जिलों में 431 हेक्टेयर जल निकायों में चावल-मछली की खेती का एक पायलट कार्यक्रम लागू किया।
- यह प्रणाली पारस्परिक सहजीविता की सुविधा प्रदान करती है, जिसमें मछली का मलमूत्र धान के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है और मछली कीटों के अंडे और लार्वा, प्लैंकटन, आदि को खाकर कीटों को नियंत्रित करती है।
- इसने किसानों के लिए एक ऑफ-सीजन बना दिया है और खर्च में वृद्धि के बिना उनकी आय बढ़ाने में मदद की है।
- एक अन्य पहल आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा डॉ. वाईएसआर रायथु भरोसा केंद्रलू है जो किसानों के लिए एक-स्टॉप समाधान प्रदान करता है।
- यह चार कार्यक्षेत्रों में काम करता है - पूर्व-परीक्षणित गुणवत्ता इनपुट की आपूर्ति, क्षमता निर्माण और ज्ञान प्रसार, किसान सलाह और कॉल सेंटर, और खरीद संचालन।

प्रौद्योगिकी और आउटरीच के माध्यम से शिक्षा और कौशल विकास में पहल

- मानव संसाधन की गुणवत्ता किसी भी समाज की प्रगति के लिए महत्वपूर्ण है।
- यह शिक्षा और कौशल विकास के माध्यम से प्राप्त किया जाता है।
- शिक्षा क्षेत्र से संबंधित 75 सर्वोत्तम प्रथाओं में से 11 और अन्य 5 को कौशल विकास के तहत वर्गीकृत किए गए सार-संग्रह में जोर स्पष्ट है।
- औपचारिक शिक्षा और कौशल विकास के तहत सीमांत वर्गों को शामिल करने के लिए व्यापक पहुंच के प्रयास इनमें से कुछ पहलों में संबोधित महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक है।
- असम में चाय समुदाय के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति योजनाएँ: आदिवासी क्षेत्रों के बच्चे समाज के हाशिए पर पड़े वर्गों में से हैं जो शिक्षा जैसे मौलिक अधिकारों से वंचित हैं, जो बदले में उनके भविष्य की संभावनाओं को बाधित करता है। ऐसा ही एक समुदाय असम में आदिवासी समुदाय है जो चाय की खेती में संलग्न है।

> The Directorate of Tea Tribes' Welfare of Assam launched a set of scholarship schemes to provide scholarship to students from class 9, to facilitate opportunities for encouraging children from the tea community to continue their higher studies, such as MBBS, B.Tech, Ph.D., and other job-oriented courses. Funded by the Government of Assam, the project covers all students belonging to the tea tribes' community in Assam, irrespective of the geographical area where they are pursuing their studies.
>
> The project covers a number of scholarship schemes:
> - Pre-matric scholarship to students of class 9 and 10
> - Post matric scholarship to HS and normal TDC courses
> - Simon-Singh Horo special post matric scholarship to students from the tribes community who have cleared HSLC and HSSLC during the current year
> - Financial assistance for higher studies to tea tribes students pursuing technical/higher education like MBBS, B.Tech, PhD and other job-oriented courses
> - Financial assistance for ANM/GNM/technical courses

- असम के चाय जनजाति कल्याण निदेशालय ने कक्षा 9 से छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए छात्र-वृत्ति योजनाओं का एक सेट शुरू किया, ताकि चाय समुदाय के बच्चों को एमबीबीएस, बीटेक, और अन्य नौकरी उन्मुख पाठ्यक्रमों जैसे उच्च अध्ययन जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करने के अवसर मिल सकें।
- असम में एक अन्य पहल असम के डारंग जिले में स्कूल दत्तक ग्रहण पहल है।
- यहां, शिक्षा के आयाम में खराब प्रदर्शन करने वाले सीखने के परिणामों में सुधार के लिए प्रत्येक स्कूल को एक स्कूल शिक्षक द्वारा अपनाया जाता है।

शिक्षा और कौशल विकास के लिए बेहतर निगरानी, गुणवत्ता में सुधार, आउटरीच आदि की सुविधा के लिए कुछ पहलों ने प्रौद्योगिकी को अपनाया है।

> Dhubri, a district on the banks of the Brahmaputra river and inter-spread into various riverine islands, has set a perfect example of public education system, where the district administration has come up with an innovative model 'Abhyudaya Dhubri: Rise of education over Brahmaputra' which ensures the students of riverine islands get access to quality education. The initiative is based on four key features: gamification of learning adapted to local conditions, continuous monitoring of performance of every student, district-level dashboard to analyze the progress of the project and providing scalable solutions for personalized learning experience to students.
>
> The initiative uses virtual reality (VR) to make learning a more fun experience for the children, where the focus has shifted from memorizing to understanding. The real-life examples used in the VR-based learning modules have created interest among students in learning something new each day. Highly animated concept videos in assamese language are used to grab the attention of the students and clear their concepts. As the medium of communication is kept in vernacular language it becomes convenient for the students to understand better.

- विद्या समीक्षा केंद्र (वीएसके), गुजरात सरकार द्वारा, सभी स्कूलों और ब्रेडों में प्रत्येक छात्र की सीखने की प्रगति की निगरानी करने के लिए एक ऑनलाइन, वास्तविक समय तंत्र है, जिसका उद्देश्य ब्रेड-उपयुक्त सीखने के परिणामों में सुधार करना है। इस पहल को 2021 में लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधान मंत्री का पुरस्कार मिला और इसे विश्व बैंक द्वारा वैश्विक अच्छा अभ्यास भी माना जाता है।
- असम के धुबरी जिले में अभ्युदय पहल छात्रों के बीच सीखने के मज़ेदार तरीकों और बेहतर वैचारिक समझ को पेश करने के लिए अत्याधुनिक आभासी तकनीक का उपयोग करती है। धुबरी जिला ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर है और इसमें कई नदी द्वीप हैं। इसने औसत स्कोरिंग प्रतिशत 43% से 65% तक बढ़ने के साथ सीखने के परिणामों में सुधार करने में योगदान दिया है।

कौशल विकास से संबंधित विभिन्न सर्वोत्तम प्रथाओं को समाज के हाशिये पर और दलित वर्गों की एक बड़ी पहुंच पर केंद्रित किया गया था।

- प्रयास, दिल्ली-एनसीआर में ट्रांसजेंडरों के लिए एक आजीविका और उद्यम प्रशिक्षण कार्यक्रम है।
- सहसपुर, उत्तराखंड में हथकरघा बुनकरों और स्थानीय कारीगरों को सक्षम बनाने के लिए एक पायलट पहल शुरू की गई, ताकि बाजार उन्मुख कौशल, गुणवत्ता मानकीकरण, मूल्यवर्धन, ब्रांडिंग, बेहतर विपणन संपर्क आदि को सक्षम बनाया जा सके।

पर्यावरण स्थिरता के लिए सर्वोत्तम अभ्यास

- पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण प्रमुख सतत विकास लक्ष्यों में से हैं। सार संग्रह में इस प्रयास में योगदान देने वाली विभिन्न सर्वोत्तम प्रथाओं का उल्लेख है।
- परिवहन क्षेत्र से उत्सर्जन कम करने और वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए दिल्ली सरकार द्वारा इलेक्ट्रिक वाहन नीति और इलेक्ट्रिकल बसों की शुरुआत।
- मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी (एमआरएफ) उडुपी, कर्नाटक में शुरू की गई। कार्यक्रम घरों से सूखा कचरा एकत्र करता है, जो अवैज्ञानिक अपशिष्ट प्रबंधन को रोकता है। आगे की गतिविधि में इस कचरे से सामग्री की पहचान करना और उन्हें सीमेंट उद्योग के लिए कच्चे माल के रूप में उपलब्ध कराना शामिल है।
- पल्ले प्रकृति वनम ग्रामीण क्षेत्रों में घने मिनी-वन बनाने के लिए तेलंगाना सरकार की एक पहल है।

Impact

- About 22,000 EVs have been registered.
- 9,633 electric vehicles have been purchased and subsidies amounting to INR 34.31 crore have been disbursed to eligible beneficiaries upon purchase of these vehicles.
- At present 28 private charging points have been installed.
- Installation of 100 public charging stations across Delhi is under way
- Bids floated for 300 e-Buses under Cluster Scheme.

सामाजिक कल्याण और महिला सशक्तिकरण के लिए हस्तक्षेप

- चाइल्ड केयर संस्थानों का डिजिटल निरीक्षण: आंगन एनजीओ के सहयोग से, पंजाब का सामाजिक सुरक्षा और महिला एवं बाल विकास विभाग SafCa ऐप के माध्यम से अपने चाइल्ड केयर संस्थानों का डिजिटल निरीक्षण करता है। निरीक्षण के दौरान पहचानी गई विसंगतियों को रंग कोडित किया गया है। यह संस्थानों के कामकाज पर बेहतर समझ और सुधार की अनुमति देता है।
- धीम्सा रेडियो: धीम्सा ओडिशा में एक सामुदायिक रेडियो पहल है, जो ग्रामीण जनता को सूचना प्रसार की सुविधा प्रदान करता है। इस मंच के माध्यम से स्थानीय भाषा और स्थानीय युवाओं का उपयोग समुदाय मंज सरकारी संदेशों को फैलाने के लिए किया जा रहा है।

Highlights:

- It reaches out to areas in a 12 km radius, covering a population of 1,25,000 people spread across 63 villages of six gram panchayats.
- It broadcasts for nine hours in a day, including one hour of live show where information on government schemes, people's rights and issues are highlighted by reporters.

The community radio is set up by the district administration and is being implemented by SOVA with support from UNICEF at Chhapar village of Koraput. The community radio broadcasts for nine hours a day and has been disseminating information on government schemes, highlighting various issues and news through narrowcasting in Desia language and other local dialects. There are listeners clubs in each village of the district. The community radio station has 12 reporters who travel extensively to all the rural areas in the district and interview villagers.

Community radio features:

- The community radio highlights many issues, from food sovereignty, organic farming to women's health and empowerment and problems faced by children.
- The radio also provides a platform to the rural residents to air their grievances and local artistes to showcase their talent.

ट्रांस-फैट उन्मूलन

खबरों में क्यों

डब्ल्यूएचओ ने देशों के लिए ट्रांस-फैट एलिमिनेशन वैलिडेशन प्रोग्राम लॉन्च किया

महत्वपूर्ण बिंदु

ट्रांस-फैट एलिमिनेशन वैलिडेशन प्रोग्राम के बारे में

- यह विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) द्वारा उन देशों को मान्यता देने की एक पहल है, जिन्होंने अपनी राष्ट्रीय खाद्य आपूर्ति से औद्योगिक रूप से उत्पादित ट्रांस-वसा को समाप्त कर दिया है।
- कार्यक्रम का उद्देश्य विश्व स्तर पर ट्रांस-फैट के उन्मूलन को बढ़ावा देना और लोगों के हृदय स्वास्थ्य की रक्षा करना है।
- ट्रांस-फैट एलिमिनेशन टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप की पहली वार्षिक बैठक देशों द्वारा WHO वैलिडेशन सर्टिफिकेट के लिए जमा किए गए आवेदनों का मूल्यांकन करेगी।
- प्रमाण पत्र के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए, देशों को यह प्रदर्शित करना चाहिए कि ट्रांस-फैट नीति का सर्वोत्तम अभ्यास लागू किया गया है और पर्याप्त निगरानी और प्रवर्तन प्रणाली मौजूद है।
- वर्तमान में, 44 देशों में वर्तमान में सर्वोत्तम अभ्यास नीतियां प्रभावी हैं, जो दुनिया की 37% आबादी को कवर करती हैं।
- अतिरिक्त छह देशों ने सर्वोत्तम अभ्यास नीतियों को पारित किया है जो जल्द ही प्रभावी होंगी, जिससे दुनिया की 44% आबादी को सुरक्षा प्रदान की जाएगी।
- सर्वोत्तम-प्रथा नीतियों को अभी लागू और कार्यान्वित करके, देश WHO से मान्यता प्राप्त करने के लिए भविष्य के चक्र के दौरान अर्हता प्राप्त कर सकते हैं।
- हमारे खाद्य पदार्थों में ट्रांस वसा गैर-संचारी रोग के लिए मुख्य जोखिम कारकों में से एक है, जिसके सेवन से कोरोनरी हृदय रोग की घटनाएं और मौतें होती हैं।
- 2018 में, WHO ने 2023 तक औद्योगिक रूप से उत्पादित ट्रांस फैट के वैश्विक उन्मूलन का आह्वान किया और सर्वोत्तम अभ्यास नीतियों को लागू करने में देशों का समर्थन करने के लिए REPLACE एक्शन फ्रेमवर्क जारी किया।
- WHO के 13वें जनरल प्रोग्राम ऑफ वर्क 2019-2023 और ट्रिपल बिलियन टारगेट्स के हिस्से के रूप में सदस्य देशों ने इस महत्वाकांक्षी लक्ष्य को पूरा करने के लिए हस्ताक्षर किए।
- WHO का नया वैलिडेशन प्रोग्राम उन देशों की कड़ी मेहनत को सार्वजनिक रूप से मान्यता देगा और पुरस्कृत करेगा जिन्होंने इस जहरीले यौगिक को सफलतापूर्वक समाप्त कर दिया है।
- 2023 उन्मूलन लक्ष्य तक पहुंचने के लिए एक वर्ष से भी कम समय बचा है, हमें उम्मीद है कि यह नए देशों को नीतियां बनाने और वैश्विक लक्ष्य की दिशा में कार्रवाई में तेजी लाने के लिए भी प्रोत्साहित करेगा।
- सत्यापन के योग्य होने के लिए, देशों को यह प्रदर्शित करना चाहिए कि एक सर्वोत्तम अभ्यास ट्रांस फैट नीति लागू की गई है और पर्याप्त निगरानी और प्रवर्तन प्रणालियां मौजूद हैं।

- WHO उन देशों को कार्रवाई करने के लिए प्रोत्साहित करता है जिनके पास सर्वोत्तम नीति नहीं है। ट्रांस फैट उन्मूलन के लिए डब्ल्यूएचओ सत्यापन प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन करने वाले देशों के लिए यह पहली कॉल है।
- ऐसे देशों के लिए भविष्य में आवेदन के अवसर होंगे जिन्होंने अभी तक ट्रांस फैट उन्मूलन नीतियों को लागू नहीं किया है।
- अभी सर्वोत्तम-प्रथा नीतियों को लागू और कार्यान्वित करके, देश भविष्य के चक्र के दौरान WHO से यह मान्यता प्राप्त करने के लिए अर्हता प्राप्त कर सकते हैं। डब्ल्यूएचओ सभी देशों से औद्योगिक रूप से उत्पादित टीएफए को खत्म कर जीवन रक्षक कार्रवाई करने का आह्वान करता है।
- डब्ल्यूएचओ सर्वोत्तम अभ्यास नीतियों वाले देशों को प्रोत्साहित करता है जो 2023 में प्रभाव में आएंगे: मिस्र, मैक्सिको, फिलीपींस, यूक्रेन।

REPLACE

- REPLACE एक्शन पैकेज 2023 तक वैश्विक उन्मूलन के लक्ष्य के साथ राष्ट्रीय खाद्य आपूर्ति से औद्योगिक रूप से उत्पादित ट्रांस फैट को खत्म करने के लिए एक रणनीतिक दृष्टिकोण प्रदान करता है।
- ट्रांस फैट का बढ़ा हुआ सेवन (> कुल ऊर्जा सेवन का 1%) कोरोनरी हृदय रोग मृत्यु दर और घटनाओं के बढ़ते जोखिम से जुड़ा है। दुनिया भर में हर साल कोरोनरी हृदय रोग से लगभग 500,000 समय से पहले होने वाली मौतों के लिए ट्रांस फैट का सेवन जिम्मेदार है।
- पैकेज में एक व्यापक तकनीकी दस्तावेज शामिल है जो कार्यान्वयन की सुविधा के लिए छह मॉड्यूल और अतिरिक्त वेब संसाधनों के साथ-साथ ट्रांस फैट उन्मूलन के लिए इस एकीकृत दृष्टिकोण के लिए एक तर्काधार और रूपरेखा प्रदान करता है।

कार्रवाई के 06 क्षेत्रों में शामिल हैं:

(i) आवश्यक नीति परिवर्तन के लिए औद्योगिक रूप से उत्पादित ट्रांस फैट के आहार स्रोतों और परिदृश्य की समीक्षा करें।
(ii) स्वस्थ वसा और तेलों के साथ औद्योगिक रूप से उत्पादित ट्रांस वसा के प्रतिस्थापन को बढ़ावा देना।
(iii) औद्योगिक रूप से उत्पादित ट्रांस फैट को खत्म करने के लिए विधायी या नियामक कार्रवाई करना।
(iv) खाद्य आपूर्ति में ट्रांस वसा सामग्री का आकलन और निगरानी और जनसंख्या में ट्रांस वसा की खपत में बदलाव।
(v) नीति-निर्माताओं, उत्पादकों, आपूर्तिकर्ताओं और जनता के बीच ट्रांस फैट के नकारात्मक स्वास्थ्य प्रभाव के बारे में जागरूकता पैदा करना।
(vi) नीतियों और नियमों के अनुपालन को लागू करें।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्ट

खबरों में क्यों

यूरोपीय संघ का महत्वाकांक्षी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्ट

महत्वपूर्ण बिंदु

- यूरोपीय संसद के सदस्य इस सप्ताह यूरोपीय संघ के महत्वाकांक्षी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्ट के एक नए मसौदे पर प्रारंभिक सौदे पर पहुंचे, जिसे पहली बार दो साल पहले तैयार किया गया था।

एआई अधिनियम क्या है?

- पहली बार 2021 में प्रस्तावित, AI अधिनियम कृत्रिम बुद्धि प्रणाली का उपयोग करने वाले किसी भी उत्पाद और सेवा को नियंत्रित करने वाले नियमों को निर्धारित करेगा।
- एआई के चार रैंकों (न्यूनतम से अस्वीकार्य के बीच) के आधार पर, जोखिम वाले अनुप्रयोगों को कठिन नियमों का सामना करना पड़ेगा, अधिक पारदर्शिता और सटीकता की आवश्यकता होगी।
- पुलिस उपकरण जिनका उद्देश्य पूर्व निर्धारित करना है कि अपराध कहाँ होंगे और किसके द्वारा प्रतिबंधित किए जाने की उम्मीद है। किसी विशिष्ट आतंकवादी खतरे का मुकाबला करने और उसे रोकने के अपवाद के साथ रिमोट फेशियल रिकॉग्निशन तकनीक पर भी प्रतिबंध लगाया जाएगा।
- उद्देश्य "एआई पर आधारित एक नियंत्रित समाज से बचना है,"
- एक बार अनुमोदित होने के बाद, यूरोपीय संघ का कहना है कि कानून में "आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर दुनिया का पहला नियम" शामिल होगा।
- दो संसदीय समितियों के बीच समझौता एक लंबी और भीषण नौकरशाही प्रक्रिया में पहला कदम है, जिसे यूरोपीय संघ के 27-सदस्यीय ब्लॉक में कानून बनने से पहले वर्षों लग सकते हैं।

अधिनियम का दायरा

- अधिनियम विस्तृत है और एआई का उपयोग करने वाले उत्पाद या सेवा प्रदान करने वाले किसी भी व्यक्ति को नियंत्रित करेगा।
- अधिनियम उन प्रणालियों को कवर करेगा जो सामग्री, भविष्यवाणियों, सिफारिशों, या वातावरण को प्रभावित करने वाले निर्णयों जैसे आउटपुट उत्पन्न कर सकते हैं।
- कंपनियों द्वारा एआई के उपयोग के अलावा, यह सार्वजनिक क्षेत्र और कानून प्रवर्तन में उपयोग किए जाने वाले एआई को भी देखेगा।
- यह जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन (GDPR) जैसे अन्य कानूनों के साथ मिलकर काम करेगा।
- एआई सिस्टम का उपयोग करने वाले जो मनुष्यों के साथ बातचीत करते हैं, निगरानी उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाते हैं, या "डीपफेक" सामग्री उत्पन्न करने के लिए उपयोग किए जा सकते हैं, उन्हें मजबूत पारदर्शिता दायित्वों का सामना करना पड़ता है।

'उच्च जोखिम' किसे माना जाता है?

- कई एआई उपकरणों को उच्च जोखिम माना जा सकता है, जैसे कि महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे, कानून प्रवर्तन, या शिक्षा में उपयोग किए जाने वाले उपकरण। वे "अस्वीकार्य" से एक स्तर नीचे हैं और इसलिए पूरी तरह से प्रतिबंधित नहीं हैं।
- इसके बजाय, उच्च जोखिम वाले एआई का उपयोग करने वालों को कठोर जोखिम आकलन पूरा करने, अपनी गतिविधियों को लॉग करने और जांच के लिए अधिकारियों को डेटा उपलब्ध कराने के लिए बाध्य होना पड़ सकता है। इससे कंपनियों के लिए अनुपालन लागत बढ़ने की संभावना होगी।
- "उच्च जोखिम" श्रेणियों में से कई जहां एआई के उपयोग को सख्ती से नियंत्रित किया जाएगा, वे कानून प्रवर्तन, प्रवासन, बुनियादी ढांचे, उत्पाद सुरक्षा और न्याय प्रशासन जैसे क्षेत्र होंगे।

'जीपीएआईएस' क्या है?

- एक GPAIS (जनरल पर्पस AI सिस्टम) एक श्रेणी है जिसे कानून निर्माताओं द्वारा एक से अधिक एप्लिकेशन वाले AI टूल के लिए प्रस्तावित किया गया है, जैसे कि ChatGPT जैसे जेनेरेटिव AI मॉडल।
- कानूनविद वर्तमान में इस बात पर बहस कर रहे हैं कि क्या GPAIS के सभी रूपों को उच्च जोखिम के रूप में नामित किया जाएगा, और प्रौद्योगिकी कंपनियों के लिए इसका क्या अर्थ होगा जो अपने उत्पादों में AI को अपनाना चाहती हैं। मसौदा स्पष्ट नहीं करता है कि एआई सिस्टम निर्माता किन दायित्वों के अधीन होंगे।

अगर कोई कंपनी नियम तोड़ती है

- प्रस्तावों में कहा गया है कि एआई अधिनियम का उल्लंघन करने वालों पर 30 मिलियन यूरो या वैश्विक लाभ का 6%, जो भी अधिक हो, का जुर्माना लगाया जा सकता है।
- Microsoft (MSFT.O) जैसी कंपनी के लिए, जो ChatGPT निर्माता OpenAI का समर्थन कर रही है, नियमों का उल्लंघन करने पर $10 बिलियन से अधिक का जुर्माना हो सकता है।

एआई अधिनियम के लिए समय सीमा

- अधिनियम पर सांसदों द्वारा चर्चा की जा रही है, और उनके आम सहमति पर पहुंचने के बाद, यूरोपीय संसद, यूरोपीय संघ की परिषद और यूरोपीय आयोग के प्रतिनिधियों के बीच एक त्रयी होगी।
- शर्तों को अंतिम रूप दिए जाने के बाद, प्रभावित पक्षों को विनियमों का पालन करने की अनुमति देने के लिए लगभग दो वर्ष की अनुग्रह अवधि होगी।

क्लिनिकल परीक्षण

खबरों में क्यों

क्लिनिकल परीक्षण करने के लिए भारत एक अनुकूल गंतव्य के रूप में उभर रहा है, रिपोर्ट से पता चलता है

महत्वपूर्ण बिंदु

- पीडब्ल्यूसी इंडिया और यूएस-इंडिया चैंबर ऑफ कॉमर्स (यूएसएआईसी) की एक संयुक्त रिपोर्ट से पता चला है कि नैदानिक परीक्षण करने के लिए भारत एक अनुकूल गंतव्य के रूप में उभर रहा है।
- रिपोर्ट को वर्चुअल रूप से आयोजित USAIC बायोफार्मा एंड हेल्थकेयर समिट में जारी किया गया।
- भारत में क्लिनिकल परीक्षण गतिविधि 2014 से लगातार बढ़ रही है, क्योंकि वैश्विक सामंजस्य के उद्देश्य से कई प्रमुख नियामक सुधार किए गए हैं, जिससे भारत में नैदानिक परीक्षणों की खुली पहुंच को सक्षम किया जा सके।
- देश की विविध आबादी, इसकी तेजी से बढ़ती स्वास्थ्य देखभाल अवसंरचना के साथ मिलकर, क्लिनिकल परीक्षणों के फलने-फूलने के लिए एक उर्वर जमीन प्रदान करती है।
- यह शीर्ष बायोफार्मा कंपनियों के लिए दीर्घकालिक रणनीति विकसित करने का एक अवसर है जो भारत में नवाचार और रणनीतिक साझेदारी के प्रमुख समर्थकों पर केंद्रित है।
- रिपोर्ट के अनुसार, बायोफार्मा भारत में निजी स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में नवाचार के महत्वपूर्ण प्रवर्तकों से लाभ उठा सकती है और देश में तेजी से बढ़ रहे स्वास्थ्य देखभाल के बुनियादी ढांचे का लाभ उठा सकती है।

रिपोर्ट से मुख्य निष्कर्ष:

- जांचकर्ताओं और मरीजों तक आसान और तेज पहुंच के साथ अधिक कुशल नैदानिक परीक्षण करने के लिए शीर्ष बायोफार्मा के लिए निजी क्षेत्र एक उपयुक्त चैनल है।
- उच्च रोग प्रसार (जैसे, कैंसर) वाले भारतीय राज्यों में भी उन्नत चिकित्सा बुनियादी ढांचे और जांचकर्ताओं की उपलब्धता के साथ टियर-1 शहरों की संख्या सबसे अधिक है। इन राज्यों को लक्षित करके बायोफार्मा कंपनियों को मरीजों, साइटों और जांचकर्ताओं तक तेजी से पहुंच प्रदान की जा सकती है
- 2015 और 2020 के बीच जांचकर्ताओं की कुल संख्या में 2 गुना की वृद्धि हुई है, अधिकांश वृद्धि आंतरिक चिकित्सा और ऑन्कोलॉजी विशेषज्ञता में हुई है। हालांकि, जांचकर्ताओं की संख्या में वृद्धि बड़े पैमाने पर टियर-1 और टियर-2 शहरों तक ही सीमित है।
- जबकि भारत में प्रमुख चिकित्सा वर्गों के लिए शीर्ष 20 फार्मा गतिविधि पिछले एक दशक में काफी हद तक स्थिर रही है, प्रमुख रोगों (जैसे, दर्द, मिर्गी, गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर) और अनाथ रोगों (बीटा-थैलेसीमिया, डचेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी) में विकास के अवसर मौजूद हैं।)
- भारत में ~3% की समग्र नैदानिक परीक्षण भागीदारी है, लेकिन सबसे अधिक प्रचलित बीमारियों (जैसे, श्वसन संक्रमण, हृदय, मधुमेह, गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर) के वैश्विक बोझ में 15% से अधिक का योगदान देता है, जो शीर्ष फार्मा के लिए अप्रयुक्त क्षमता का प्रतिनिधित्व करता है।
- शीर्ष बायोफार्मा को अपनी रणनीति को टियर-1 शहरों (जैसे, मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई) की ओर सेरेखित करना चाहिए जहां उच्च बिस्तर क्षमता, डॉक्टरों की संख्या, और तृतीयक देखभाल बहु-शहर अस्पतालों की उपस्थिति तेजी से और अधिक कुशल नैदानिक परीक्षण चलाने के सक्षम प्रयासों का समर्थन कर सकती है। .

अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी जागरूकता प्रशिक्षण (START)

खबरों में क्यों

हाल ही में, इसरो ने अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी जागरूकता प्रशिक्षण (START) नामक एक नया प्रारंभिक स्तर का ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है।

महत्वपूर्ण बिंदु

इसरो का स्टार्ट कार्यक्रम विवरण

'अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी जागरूकता प्रशिक्षण (START)' भौतिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी के स्नातकोत्तर और अंतिम वर्ष के स्नातक छात्रों के उद्देश्य से इसरो की एक पहल है।

- कार्यक्षेत्र: अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी जागरूकता प्रशिक्षण (START) कार्यक्रम में अंतरिक्ष विज्ञान के विभिन्न डोमेन शामिल होंगे, जिनमें शामिल हैं-
  - खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी,
  - हेलियोफिजिक्स और सन-अर्थ इंटरेक्शन,
  - इंस्ट्रुमेंटेशन, और

- एरोनॉमी।

- कार्यान्वयन: अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी जागरूकता प्रशिक्षण (START) पहल के तहत विभिन्न कार्यक्रम भारतीय शिक्षाविदों और इसरो केंद्रों के वैज्ञानिकों द्वारा वितरित किए जाएंगे।
- पंजीकरण: शैक्षणिक संस्थान 20 मई, 2023 तक जिज्ञासा पोर्टल के माध्यम से स्टार्ट कार्यक्रम के लिए आवेदन जमा कर सकते हैं।

उद्देश्य

- START कार्यक्रम भारतीय छात्रों को अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी में पेशेवर बनने में सक्षम बनाने के इसरो के प्रयासों का हिस्सा है, क्योंकि संगठन का अंतरिक्ष विज्ञान अन्वेषण कार्यक्रम नए डोमेन में विस्तार करना जारी रखता है।
- START कार्यक्रम का उद्देश्य छात्रों को अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी में प्रारंभिक स्तर का प्रशिक्षण प्रदान करना है, जिससे उन्हें क्षेत्र के विभिन्न पहलुओं, अनुसंधान के अवसरों और करियर विकल्पों का अवलोकन मिल सके।
- प्रशिक्षण अंतरिक्ष विज्ञान की अंतर-अनुशासनात्मक प्रकृति पर भी जोर देगा, छात्रों को यह अंतर्दृष्टि प्रदान करेगा कि उनकी व्यक्तिगत योग्यताओं को क्षेत्र में कैसे लागू किया जा सकता है।
- इसरो के START कार्यक्रम से मानव क्षमता के निर्माण में मदद मिलने की उम्मीद है जो भविष्य में अंतरिक्ष विज्ञान और अनुसंधान का नेतृत्व करेगा।

महत्व

- इसरो के START कार्यक्रम में भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान अन्वेषण कार्यक्रम और अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकियों में अनुसंधान के अवसरों पर व्याख्यान शामिल होंगे।
- प्रशिक्षण को अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विभिन्न पहलुओं का अवलोकन प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिससे छात्र क्षेत्र के लिए अपनी योग्यता को बेहतर ढंग से समझ सकें, इसकी क्रॉस-डिसिप्लिनरी प्रकृति की सराहना कर सकें और तदनुसार अपना कैरियर मार्ग चुन सकें।
- इस कार्यक्रम के माध्यम से छात्रों को विभिन्न भारतीय संस्थानों में चल रहे शोध से भी अवगत कराया जाएगा।
- START कार्यक्रम का उद्देश्य उन्हें क्षेत्र के विभिन्न पहलुओं, अनुसंधान के अवसरों और करियर विकल्पों का अवलोकन देना है।

रिमोट सेंसिंग कोर्स

- इसरो के राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र (NRSC) ने भी दो लघु पाठ्यक्रमों की घोषणा की है - सुदूर संवेदन आंकड़ा अधिग्रहण और सुदूर संवेदन आंकड़ा संसाधन।
- पाठ्यक्रम एशिया और प्रशांत (CSSTEAP) में अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी शिक्षा केंद्र के माध्यम से आयोजित किए जाते हैं और क्रमशः 21 अगस्त से 1 सितंबर और 9 से 20 अक्टूबर तक हैदराबाद के पास शादनगर में NRSC के अर्थ स्टेशन पर निर्धारित किए जाते हैं।
- CSSTEAP संयुक्त राष्ट्र से संबद्ध एक शैक्षणिक संस्थान है।

Android मैलवेयर

खबरों में क्यों

नए Android मैलवेयर का पता चला है जो आपके पासवर्ड, 2FA कोड चुराता है

महत्वपूर्ण बिंदु

- 'फ्लूहोर्स' के नाम से जाना जाने वाला एक नया एंड्रॉइड मैलवेयर खोजा गया है, जो पूर्वी एशिया के उपयोगकर्ताओं को दुर्भावनापूर्ण ऐप्स के साथ लक्षित करता है जो 1,00,000 से अधिक इंस्टाल के साथ वैध संस्करण की तरह दिखते हैं।
- चेक प्वाइंट रिसर्च के अनुसार, इन दुर्भावनापूर्ण ऐप्स को उपयोगकर्ता क्रेडेंशियल्स और टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन (2FA) कोड सहित संवेदनशील जानकारी निकालने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- FluHorse मैलवेयर पूर्वी एशिया में कई क्षेत्रों को लक्षित करता है और आमतौर पर ईमेल के माध्यम से वितरित किया जाता है।
- कुछ मामलों में, हाई-प्रोफाइल संस्थाओं जैसे सरकारी अधिकारियों को फ़िशिंग ईमेल हमले के शुरुआती चरणों में लक्षित किया गया था।
- FluHorse के सबसे चिंताजनक पहलुओं में से एक इसकी लंबे समय तक पता न चलने की क्षमता है, जिससे यह एक लगातार और खतरनाक खतरा बन जाता है जिसका पता लगाना मुश्किल होता है।
- रिपोर्ट के अनुसार, FluHorse हमले हाई-प्रोफाइल व्यक्तियों को लक्षित और दुर्भावनापूर्ण ईमेल भेजे जाने से शुरू होते हैं, जिसमें कथित भुगतान समस्या को हल करने के लिए तत्काल कार्रवाई करने का आग्रह किया जाता है।
- आमतौर पर, लक्ष्य को ईमेल में शामिल हाइपरलिंक के माध्यम से फ़िशिंग वेबसाइट पर निर्देशित किया जाता है। एक बार वहाँ, उन्हें नकली एप्लिकेशन के फोनी एपीके (एंड्रॉइड पैकेज फ़ाइल) डाउनलोड करने के लिए कहा जाता है।
- FluHorse कैरियर ऐप्स 'ETC', एक ताइवानी टोल संग्रह ऐप, और 'VPBank Neo', एक वियतनामी बैंकिंग ऐप की नकल करते हैं।
- Google Play पर, इन ऐप्स के दोनों वैध संस्करणों को एक मिलियन से अधिक डाउनलोड किया गया है।
- इसके अलावा, रिपोर्ट में कहा गया है कि इंस्टालेशन के बाद, सभी तीन नकली ऐप्स आने वाले 2FA कोड को इंटरसेप्ट करने के लिए एसएमएस एक्सेस का अनुरोध करते हैं, यदि उन्हें खातों को हाईजैक करने की आवश्यकता होती है।
- नकली ऐप्स मूल यूज़र इंटरफेस की नकल करते हैं लेकिन दो से तीन विंडो से परे कार्यक्षमता की कमी होती है जो पीड़ित की जानकारी को कैप्चर करने वाले रूपों को लोड करते हैं।

- पीड़ितों के खाते की साख और क्रेडिट कार्ड की जानकारी हासिल करने के बाद, ऐप 10 मिनट के लिए "सिस्टम व्यस्त हैं" संदेश प्रदर्शित करता है ताकि प्रक्रिया को यथार्थवादी बनाया जा सके, जबकि ऑपरेटर 2FA कोड को इंटरसेप्ट करने और चोरी हुए डेटा का लाभ उठाने के लिए पृष्ठभूमि में कार्य करते हैं।

Android मैलवेयर क्या है?

- एंड्रॉइड मैलवेयर एक दुर्भावनापूर्ण सॉफ़्टवेयर है जिसका उद्देश्य कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान पहुंचाना या दूषित करना है। मैलवेयर डेवलपर उपकरणों और नेटवर्क में घुसपैठ करने के लिए कई तरीके अपनाते हैं। लक्ष्य, किसी भी मैलवेयर की तरह, डिवाइस को नुकसान पहुंचाना और व्यक्तिगत डेटा चोरी करना है।

यह डिवाइस में कैसे प्रवेश करता है?

- हानिकारक एप्लिकेशन डाउनलोड करना - ऐप्स और डाउनलोड करने योग्य सामग्री हैकर्स द्वारा मैलवेयर संचारित करने का सबसे प्रचलित तरीका है। आधिकारिक ऐप स्टोर से प्राप्त ऐप्स आमतौर पर सुरक्षित होते हैं। अनधिकृत माध्यमों से प्राप्त ऐप्स, जैसे फटे संस्करणों या अवैध स्रोतों से, में वायरस हो सकते हैं।
- ऑपरेटिंग सिस्टम की खामियों वाले स्मार्टफोन या टैबलेट का उपयोग करना - ओएस में खामियों के कारण हैकर्स द्वारा अक्सर मोबाइल उपकरणों का शोषण किया जाता है। यदि आप अपने डिवाइस के सॉफ़्टवेयर को अद्यतित नहीं रखते हैं, तो यह इन दोषों के प्रति संवेदनशील होगा, जिन्हें आमतौर पर शीघ्रता से पहचाना और ठीक किया जाता है।
- असुरक्षित वाई-फ़ाई या यूआरएल का इस्तेमाल करना - सार्वजनिक वाई-फ़ाई नेटवर्क अक्सर असुरक्षित होते हैं, जिसका मतलब है कि हैकर आसानी से आपके डेटा को इंटरसेप्ट कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं क्योंकि यह नेटवर्क पर प्रसारित होता है। इसके अलावा, इसका उपयोग कनेक्टेड डिवाइसों में मैलवेयर और वायरस फैलाने के लिए किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, यदि आप असुरक्षित वेबसाइटों पर जाते हैं तो आपके डिवाइस से संवेदनशील डेटा से समझौता करने का जोखिम होता है। आपके फ़ोन के ब्राउज़र का उपयोग करने से आपको संभावित रूप से विभिन्न जोखिमों का सामना करना पड़ सकता है जिसके परिणामस्वरूप वेब ब्राउज़र हमले हो सकते हैं। इस प्रकार के हमले एंड्रॉइड स्मार्टफोन पर अधिक व्यापक हैं।
- पाठ संदेश या ध्वनि मेल के माध्यम से फ़िशिंग - आपको अपने या अपने डिवाइस के बारे में व्यक्तिगत जानकारी का अनुरोध करने वाले एक प्रतिष्ठित स्रोत से एक पाठ संदेश या कॉल प्राप्त हो सकता है। हैकर अक्सर इस जानकारी का उपयोग किसी भी डेटा को चुराने के लिए करते हैं, जैसे कि सामाजिक सुरक्षा नंबर, क्रेडिट कार्ड की जानकारी, और इसी तरह। इसके अलावा, असुरक्षित वेबसाइट URL को उपयोगकर्ता को टेक्स्ट संदेशों के माध्यम से भी साझा किया जा सकता है जो आपके फ़ोन के सॉफ़्टवेयर से समझौता कर सकता है।

इथेनॉल सम्मिश्रण

खबरों में क्यों

चीनी मिलों ने 12 प्रतिशत इथेनॉल सम्मिश्रण लक्ष्य हासिल करने की तैयारी की

महत्वपूर्ण बिंदु

- भारत वर्तमान इथेनॉल आपूर्ति वर्ष (ESY) के लिए पेट्रोल के साथ 12% इथेनॉल सम्मिश्रण के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में प्रगति कर रहा है।
- तेल विपणन कंपनियों (OMCs) को पहले ही ESY 2022-23 के लिए अनुबंधित 514 करोड़ लीटर इथेनॉल में से 233 करोड़ लीटर इथेनॉल प्राप्त हो चुका है, जिससे वे पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान 10% की तुलना में 11.65% मिश्रण करने में सक्षम हो गए हैं।
- उद्योग के एक अधिकारी के अनुसार, तमिलनाडु को छोड़कर, पूरे भारत में चीनी पेराई लगभग समाप्त हो गई है।
- आसवनी अब शीरे से इथेनॉल का उत्पादन शुरू कर देगी, जो पहले से ही ऑफ-सीजन के लिए भंडारित है। चीनी उत्पादन में गिरावट के बीच शीरे से इथेनॉल का उत्पादन एक उपलब्धि है।
- तेल विपणन कंपनियों ने चीनी आधारित आसवनी से 374 करोड़ लीटर इथेनॉल और अनाज आधारित संयंत्रों से 140 करोड़ लीटर इथेनॉल खरीदने का अनुबंध किया है।
- एक टन गन्ने के रस से सीधे संसाधित होने पर लगभग 70-75 लीटर इथेनॉल का उत्पादन होता है, जबकि एक टन बी-हैवी शीरा लगभग 320 लीटर जैव ईंधन का उत्पादन करता है।
- चीनी मिलों ने गन्ने के रस से बने 138 करोड़ लीटर और बी-भारी शीरे से 230 करोड़ लीटर इथेनॉल की आपूर्ति करने का अनुबंध किया है।
- सरकार ने हाल ही में 2023-24 सीजन के लिए दिसंबर से नवंबर तक इथेनॉल वर्ष को नवंबर से अक्टूबर में बदल दिया है।
- वर्तमान संक्रमण वर्ष दिसंबर से अक्टूबर तक 11 महीने चलेगा और 12% सम्मिश्रण लक्ष्य 31 अक्टूबर तक हासिल किया जाना है।
- भारत का लक्ष्य 2025 तक 20% इथेनॉल सम्मिश्रण लक्ष्य प्राप्त करना है।
- सरकार ने देश में इथेनॉल के उत्पादन और उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न पहलों और उपायों की घोषणा की है, जिसमें इथेनॉल आपूर्ति श्रृंखला का विस्तार, इथेनॉल संयंत्रों की संख्या में वृद्धि और फ्लेक्स-ईंधन वाहनों को शामिल करना शामिल है।
- सरकार इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम लागू कर रही है जिसमें ओएमसी इथेनॉल के साथ मिश्रित पेट्रोल बेचती है।
- हाल ही में, पीएम ने लक्ष्य से 2 साल पहले ई20 ईंधन के लिए एक पायलट परियोजना शुरू की।
- इथेनॉल ईंधन कम प्रदूषणकारी, लागत प्रभावी, कम आयात बिल और ऊर्जा सुरक्षा प्राप्त करने में मदद करता है। यह किसानों को ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला में भी लाता है और उन्हें ऊर्जा अर्थव्यवस्था में शामिल करता है।

इथेनॉल सम्मिश्रण क्या है?

- एथिल अल्कोहल या इथेनॉल (C2H5OH) एक जैव ईंधन है जो स्वाभाविक रूप से चीनी को किण्वित करके बनाया जाता है।
- जबकि यह ज्यादातर गन्ने से चीनी निकालकर प्राप्त किया जाता है, इसके उत्पादन के लिए खाद्यान्न जैसे अन्य कार्बनिक पदार्थ का भी उपयोग किया जा सकता है।
- कार्बन कम करने की अपनी प्रतिबद्धताओं के तहत, भारत ने जीवाश्म ईंधन की खपत को कम करने के लिए इस जैव ईंधन को पेट्रोल के साथ मिलाने के लिए इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (ईबीपी) कार्यक्रम शुरू किया है।
- इससे पहले, सरकार ने E10 लक्ष्य की उपलब्धि की घोषणा की, यानी देश में इस्तेमाल होने वाले पेट्रोल में 10% इथेनॉल होता है।

ई-20 क्यों?

- केंद्र द्वारा गठित एक विशेष विशेषज्ञ समिति की एक रिपोर्ट "भारत में इथेनॉल सम्मिश्रण के लिए रोडमैप: 2020-2025" के अनुसार, 2020-21 में 551 बिलियन डॉलर की लागत से भारत का पेट्रोलियम का शुद्ध आयात 185 मिलियन टन था।
- अधिकांश पेट्रोलियम उत्पादों का उपयोग परिवहन में किया जाता है। इसलिए, एक सफल E20 कार्यक्रम देश को प्रति वर्ष 4 बिलियन डॉलर, यानी लगभग 30,000 करोड़ रुपये बचा सकता है।
- इसके अलावा, इथेनॉल एक कम प्रदूषणकारी ईंधन है, और पेट्रोल की तुलना में कम लागत पर समकक्ष दक्षता प्रदान करता है।
- बड़ी कृषि योग्य भूमि की उपलब्धता, खाद्यान्नों और गन्ने के बढ़ते उत्पादन के कारण अधिशेष, संयंत्र आधारित स्रोतों से इथेनॉल का उत्पादन करने के लिए प्रौद्योगिकी की उपलब्धता, और वाहनों को इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल के अनुरूप बनाने की व्यवहार्यता ई20 को न केवल एक राष्ट्रीय अनिवार्यता बनाती है, बल्कि एक महत्वपूर्ण रणनीतिक आवश्यकता भी है।
- इसमें कहा गया है कि सरकार की विभिन्न एजेंसियों ने इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल के सुरक्षित और प्रभावी उपयोग के लिए एक अनुकूल नियामक और खुदरा पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करने के लिए तेजी से कदम उठाए हैं और तेल विपणन कंपनियों ने चरणबद्ध रोलआउट के लिए अपनी योजना तैयार की है, और वाहन निर्माताओं ने एक समान योजना बनाने का आश्वासन दिया है।

E20 अध्ययन और भारत के बाहर अनुसंधान एवं विकास

- ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एआरएआई), इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम (आईआईपी) और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (आर एंड डी) द्वारा 201415 के दौरान भारी उद्योग विभाग से फंडिंग के साथ उपयोग में आने वाले वाहनों के साथ 20% इथेनॉल-गैसोलीन मिश्रण (ई20) की उपयुक्तता का अध्ययन करने के लिए एक परियोजना शुरू की गई थी।
- सामग्री अनुकूलता परीक्षणों से पता चला कि धातु और धातु की कोटिंग में E20 के साथ कोई समस्या नहीं थी।
- इलस्टोमर्स का स्वच्छ गैसोलीन की तुलना में E20 के साथ निम्न प्रदर्शन था।
- E20 के साथ उपयोग करने के बाद प्लास्टिक PA66 की तन्य शक्ति में गिरावट आई थी।
- वाहन स्तर के अध्ययनों में, औसत आधार पर ईंधन की बचत 6% तक कम हुई (वाहन के प्रकार पर निर्भर करता है)।
- परीक्षण वाहनों ने E0 और E20 परीक्षण ईंधन के साथ गर्म और ठंडे परिस्थितियों में स्टार्टेबिलिटी और ड्राइवबिलिटी टेस्ट पास किया।
- सभी मामलों में, वाहन संचालन के किसी भी चरण में कोई गंभीर खराबी या स्टाल नहीं देखा गया।
- ऑन-रोड माइलेज एक्युमुलेशन ट्रायल के बाद इंजन के पुर्जों में कोई असामान्य घिसाव या जमा या इंजन ऑयल की गिरावट नहीं देखी गई।
- मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (एमआईटी) और होंडा आर एंड डी द्वारा रिपोर्ट किए गए संयुक्त अध्ययनों से संकेत मिलता है कि इंजन को ठीक से ट्यून करने पर सामान्य गैसोलीन की तुलना में ई20 के साथ सापेक्ष दक्षता में 20% तक सुधार प्राप्त किया जा सकता है।
- फोर्ड मोटर कंपनी द्वारा किए गए परीक्षणों ने निष्कर्ष निकाला कि E20 ईंधन के लिए अनुकूलित इंजन ने 5% की CO2 कमी के साथ सामान्य गैसोलीन की तुलना करने योग्य वॉल्यूमेट्रिक ईंधन अर्थव्यवस्था (माइलेज) और रेंज (किलोमीटर की दूरी तय की) दिखाई।

पर्यावरणीय प्रभाव

- यह बताते हुए कि कार्बन मोनोऑक्साइड (सीओ), हाइड्रोकार्बन (एचसी) और नाइट्रोजन के ऑक्साइड (एनओएक्स) जैसे वाहन उत्सर्जन वर्तमान में भारत में नियमन के अधीन हैं, रिपोर्ट में तर्क दिया गया है कि इथेनॉल मिश्रित गैसोलीन के उपयोग से इन उत्सर्जन में कमी आती है।
- स्वच्छ गैसोलीन की तुलना में E10 और E20 ईंधन के साथ उत्सर्जन लाभों का सारांश यहां दिया गया है:

E-20 पेट्रोल: इथेनॉल सम्मिश्रण पेट्रोल और भारत का E20 क्या है

- E20 ईंधन के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड उत्सर्जन में उच्च कमी देखी गई - दोपहिया वाहनों में 50% कम और चौपहिया वाहनों में 30% कम।
- सामान्य गैसोलीन की तुलना में इथेनॉल मिश्रण से हाइड्रोकार्बन उत्सर्जन में 20% की कमी आती है।
- नाइट्रस ऑक्साइड के उत्सर्जन में महत्वपूर्ण रुझान नहीं दिखा क्योंकि यह वाहन/इंजन के प्रकार और इंजन के संचालन की स्थिति पर निर्भर करता था।
- इथेनॉल में हाइड्रॉक्सिल समूहों की उपस्थिति के कारण, सामान्य गैसोलीन की तुलना में एसीटैल्डिहाइड उत्सर्जन जैसे अनियमित कार्बोनिल उत्सर्जन E10 और E20 के साथ अधिक थे।
- हालांकि, ये उत्सर्जन विनियमित उत्सर्जन (जो ग्राम में थे) की तुलना में अपेक्षाकृत कम (कुछ माइक्रोग्राम में) थे।
- E20 ईंधन के साथ वाष्पीकरणीय उत्सर्जन परीक्षण के परिणाम E0 के समान थे।
- समग्र रूप से, इथेनॉल सम्मिश्रण दोपहिया और चौपहिया दोनों वाहनों से होने वाले उत्सर्जन को कम करने में मदद कर सकता है।

अन्य प्रभाव

इसके अलावा, इस तरह के ईंधन के उपयोग के कई अन्य प्रभाव भी हैं - मुख्य रूप से उपभोक्ता, वाहन निर्माताओं और घटक निर्माताओं पर।

- ईंधन दक्षता: E20 ईंधन का उपयोग करते समय, E0 के लिए डिज़ाइन किए गए और E10 के लिए कैलिब्रेट किए गए 4-पहिया वाहनों के लिए ईंधन दक्षता में लगभग 6-7% की गिरावट होगी; E0 के लिए डिज़ाइन किए गए और E10 के लिए कैलिब्रेट किए गए 2-पहिया वाहनों के लिए 3%-4%; ई10 के लिए डिज़ाइन किए गए और ई20 के लिए कैलिब्रेट किए गए 4-पहिया वाहनों के लिए 1-2%। हालांकि, इंजनों (हार्डवेयर और ट्यूनिंग) में संशोधनों के साथ मिश्रित ईंधन के कारण दक्षता में कमी को कम किया जा सकता है।
- प्रारंभ करने योग्य: E20 परियोजना में, परिणामों ने संकेत दिया कि परीक्षण वाहनों ने E0 और E20 परीक्षण ईंधन के साथ गर्म और ठंडे परिस्थितियों में प्रारंभ करने और चलाने की क्षमता का परीक्षण किया। सभी मामलों में, वाहन संचालन के किसी भी स्तर पर कोई गंभीर खराबी या स्टॉल नहीं देखा गया और, वाहन निर्माताओं को अनुकूल वाहनों का उत्पादन करने के लिए उत्पादन लाइनों में निम्नलिखित परिवर्तनों की आवश्यकता है:
- ईंधन के रूप में E20 के साथ इंजन और घटकों का परीक्षण और अंशांकन करने की आवश्यकता होगी।
- E20 के साथ संगत अतिरिक्त घटकों की खरीद के लिए विक्रेताओं को विकसित करने की आवश्यकता है सभी आवश्यक घटक देश में उपलब्ध कराए जा सकते हैं।
- असेंबली लाइन में कोई खास बदलाव की उम्मीद नहीं है।

घटक निर्माताओं के लिए:

- E10 से E20 में माइग्रेट करने वाले घटकों में कोई बड़ा संरचनात्मक परिवर्तन नहीं होगा।
- पिस्टन रिंग्स, पिस्टन हेड्स, ओ-रिंग्स, सील्स, फ्यूल पंप आदि की सामग्री में बदलाव होंगे, जिनका उत्पादन देश में किया जा सकता है

जेम्स वेब टेलीस्कोप

खबरों में क्यों

जेम्स वेब टेलीस्कोप ने फोमलहौत स्टार सिस्टम में आश्चर्यजनक क्षुद्रग्रहों का खुलासा किया।

महत्वपूर्ण बिंदु

- फोमलहौत के आसपास के तीन क्षुद्रग्रह बेल्ट इन्फ्रारेड प्रकाश में सौर मंडल के बाहर देखे गए पहले क्षुद्रग्रह बेल्ट हैं। कुइपर क्षुद्रग्रह बेल्ट की तुलना में गर्म, धूल भरी संरचनाएं अधिक जटिल हैं।
- NASA के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप (JWST) ने फोमलहौट नामक एक युवा तारे के चारों ओर तीन बेल्ट पाए हैं, जो संरचनाओं के बारे में रहस्य प्रकट करते हैं।
- ये इन्फ्रारेड प्रकाश में सौर मंडल के बाहर देखे गए पहले क्षुद्रग्रह बेल्ट हैं।
- JWST, जिसे वेब भी कहा जाता है, ने फोमलहौत के चारों ओर गर्म, धूल भरी संरचनाओं की छवियों को कैप्चर किया और पाया कि वे क्षुद्रग्रह और सौर मंडल के कुइपर धूल बेल्ट की तुलना में अधिक जटिल हैं।
- नासा ने अपनी वेबसाइट पर कहा है कि तीन नेस्टेड बेल्ट फोमलहौत से 23 अरब किलोमीटर तक फैली हुई हैं।
- यह पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी के 150 गुना के बराबर है।
- दो आंतरिक बेल्ट पहले कभी नहीं देखे गए थे, और पहली बार वेब द्वारा प्रकट किए गए थे।
- अन्य सितारों के चारों ओर ग्रहों के मलबे डिस्क सौर मंडल में क्षुद्रग्रह और कुइपर बेल्ट के समान हैं, छोटे पिंडों के विन्यास को प्रकट करते हैं, और ग्रहों की उपस्थिति के लिए संकेत प्रदान करते हैं, लेखकों ने अध्ययन में उल्लेख किया है।

फोमलहॉट एक चमकीला तारा है, जो तीन डिस्क से घिरा हुआ है

- फोमलहॉट को नग्न आंखों से देखा जा सकता है क्योंकि यह दक्षिणी तारामंडल पिस्किस ऑस्ट्रिनस का सबसे चमकीला तारा है। फोमलहौत धूल भरी पेटियों से घिरा हुआ है जो बड़े पिंडों के टकराने से निकलने वाले मलबे हैं।
- मलबे की पेटियों को "डेब्रिस डिस्क" के रूप में भी संदर्भित किया जा सकता है।
- नासा ने फोमलहॉट को मिल्की वे आकाशगंगा में कहीं और पाए जाने वाले मलबे डिस्क के "आर्केटाइप" के रूप में वर्णित किया है, क्योंकि इसमें सौर मंडल में देखे गए घटकों के समान घटक हैं।
- छल्लों के पैटर्न को देखकर, वैज्ञानिक इस बात का एक छोटा सा रेखाचित्र बनाने में सक्षम हो सकते हैं कि ग्रह प्रणाली कैसी दिखनी चाहिए।

फोमलहौत के आसपास के बेल्ट कैसे बने होंगे

- इससे पहले, हबल स्पेस टेलीस्कोप, हर्शल स्पेस ऑब्जर्वेटरी, और अटाकामा लार्ज मिलिमीटर ऐरे (ALMA) ने फोमलहॉट के आसपास धूल भरी संरचनाओं के सबसे बाहरी बेल्ट की स्पष्ट छवियां ली थीं।
- वेब की टिप्पणियों के माध्यम से, वैज्ञानिकों ने पहली बार आंतरिक बेल्टों का समाधान किया है।
- वेब के मिड-इन्फ्रारेड इंस्ट्रूमेंट (MIRI) ने इन तीन नेस्टेड बेल्टों का खुलासा किया।
- संभावना है कि अनदेखे ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण बल ने इन बेल्टों को बनाया होगा।
- मध्यवर्ती पट्टी पर शायद एक अदृश्य ग्रह चर रहा है।
- बाहरी रिंग के भीतर पाया गया एक बड़ा धूल का बादल एक और धूल पैदा करने वाली टक्कर का संभावित सबूत है।
- हमारे सौर मंडल में, कुइपर बेल्ट का बाहरी किनारा बृहस्पति द्वारा गढ़ा गया है, जबकि भीतरी किनारा नेपच्यून द्वारा बनाया गया है।
- नासा के इन्फ्रारेड खगोलीय उपग्रह ने 1983 में फोमलहॉल्ट के धूल वलय की खोज की।
- लेखकों ने निष्कर्ष निकाला कि फोमलहौत एक जटिल और संभवतः गतिशील सक्रिय ग्रहीय प्रणाली का स्थल प्रतीत होता है।

जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप क्या है?

- जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप अब तक निर्मित सबसे बड़ा, सबसे शक्तिशाली अंतरिक्ष टेलीस्कोप है। यह वैज्ञानिकों को यह देखने की अनुमति देगा कि बिग बैंग के लगभग 200 मिलियन वर्ष बाद हमारा ब्रह्मांड कैसा था।
- टेलीस्कोप अब तक बनी पहली आकाशगंगाओं में से कुछ की छवियों को लेने में सक्षम होगा।
- यह मंगल ग्रह से बाहर की ओर हमारे सौर मंडल में वस्तुओं का निरीक्षण करने में सक्षम होगा, धूल के बादलों के अंदर देखने के लिए जहां नए सितारे और ग्रह बन रहे हैं और अन्य सितारों की परिक्रमा करने वाले ग्रहों के वातावरण की जांच करने में सक्षम होंगे।

जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के बारे में तथ्य

- यह इतना बड़ा है कि लॉन्च करने के लिए रॉकेट के अंदर फिट होने के लिए ओरिगेमी-शैली को मोड़ना पड़ता है।
- टेलीस्कोप खुल जाएगा, पहले सनशील्ड, एक बार अंतरिक्ष में।
- जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ब्रह्मांड को प्रकाश में देखता है जो मानव आंखों के लिए अदृश्य है। इस प्रकाश को अवरक्त विकिरण कहा जाता है।
- जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप हमारे ब्रह्मांड में धूल के माध्यम से देखने के लिए अपने इन्फ्रारेड कैमरों का उपयोग करेगा। उन धूल के बादलों के अंदर तारे और ग्रह बनते हैं, इसलिए अंदर झाँकने से रोमांचक नई खोजें हो सकती हैं।
- वेब टेलीस्कोप के कैमरे सूर्य की गर्मी के प्रति संवेदनशील होते हैं।
- टेलीस्कोप के सूर्य के सामने और छायांकित पक्षों के बीच तापमान का अंतर 600 डिग्री फ़ारेनहाइट से अधिक है।

वाटसनएक्स

खबरों में क्यों

आईबीएम ने नया वाटसनएक्स, एआई और डेटा प्लेटफॉर्म पेश किया

महत्वपूर्ण बिंदु

- इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स कॉर्प ने कंपनियों को अपने व्यवसाय में एआई को एकीकृत करने में मदद करने के लिए एक नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा प्लेटफॉर्म वाटसनएक्स लॉन्च किया।
- आईबीएम के वाटसन नामक सॉफ्टवेयर को गेम शो जिओपार्डी जीतने के लिए ध्यान आकर्षित करने के एक दशक बाद नया एआई प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है।
- आईबीएम उस समय "सीख" सकता था और मानव भाषा को संसाधित कर सकता था।
- लेकिन उस समय वॉटसन की उच्च लागत ने इसे कंपनियों के उपयोग के लिए एक चुनौती बना दिया था।
- तेजी से एक दशक आगे, चैटबॉट चैटजीपीटी की रातोंरात सफलता एआई अपनाने को कंपनियों पर ध्यान केंद्रित कर रही है, और आईबीएम नए व्यवसाय को हड़पने की तलाश में है।
- इस बार, बड़ी भाषा वाले एआई मॉडल को लागू करने की कम लागत का मतलब है कि सफलता की संभावना अधिक है।
- एआई आने वाले वर्षों में आईबीएम में कुछ बैक ऑफिस नौकरियों को कम कर सकता है।
- आईबीएम एक अधिक खुले पारिस्थितिकी तंत्र को भी अपना रहा था और ओपन-सोर्स एआई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हब हगिंग फेस और अन्य के साथ साझेदारी कर रहा था।
- आईबीएम ने कहा कि कंपनियां एआई मॉडल को प्रशिक्षित और तैनात करने के लिए वाटसनएक्स प्लेटफॉर्म का उपयोग कर सकती हैं, प्राकृतिक भाषा का उपयोग करके स्वचालित रूप से कोड उत्पन्न कर सकती हैं और रासायनिक निर्माण या जलवायु परिवर्तन मॉडलिंग जैसे विभिन्न उद्देश्यों के लिए निर्मित विभिन्न बड़े भाषा मॉडल का उपयोग कर सकती हैं।

तीन लोगों से बच्चा

खबरों में क्यों

आईवीएफ के माध्यम से पैदा हुए तीन लोगों के डीएनए वाला पहला यूके बच्चा

महत्वपूर्ण बिंदु

- पहला बच्चा यूनाइटेड किंगडम में अग्रणी आईवीएफ प्रक्रिया का उपयोग करके तीन लोगों के डीएनए से बनाया गया था।
- बच्चे को माइटोकॉन्ड्रियल डोनेशन ट्रीटमेंट (एमडीटी) नामक प्रक्रिया का उपयोग करके विकसित किया गया था जिसमें मां के एक अंडे से केंद्रक लिया जाता है, जिसमें उसका डीएनए होता है और इसे एक दाता अंडे में प्रत्यारोपित किया जाता है।
- दाता अंडे के नाभिक हटा दिए जाते हैं लेकिन इसका स्वस्थ माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए बरकरार रहता है।
- इस प्रक्रिया में आईवीएफ भ्रूणों का निर्माण शामिल है जो हानिकारक उत्परिवर्तनों से मुक्त हैं जो उनकी माताओं द्वारा किए जाते हैं और उनके बच्चों को पारित होने की संभावना है।
- सामान्य डीएनए के विपरीत, जिसमें आनुवंशिक जानकारी होती है जो सामान्य मानव बनाने में मदद करती है, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में कोशिका के लिए शक्ति होती है।
- शोधकर्ताओं ने माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए और बैटरी के बीच तुलना की है।
- विभिन्न वैज्ञानिक जोर देकर कहते हैं कि "तीन माता-पिता का बच्चा" शब्द सटीक नहीं है क्योंकि बच्चे के डीएनए का 98.8 प्रतिशत से अधिक अभी भी दो लोगों से आता है।

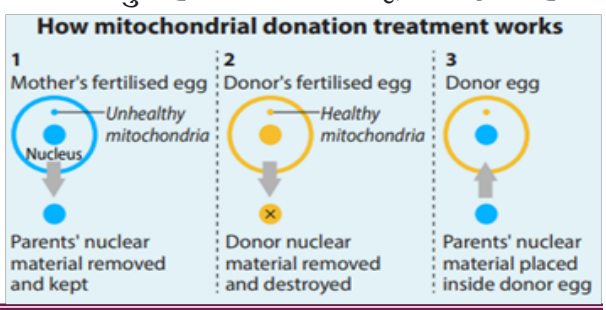

- यूके की संसद द्वारा 2015 में प्रक्रिया को हरी झंडी दी गई थी और इसके उपयोग के अनुरोधों पर मानव निषेचन और भ्रूणविज्ञान प्राधिकरण (एचएफईए) नामक नियामक निकाय द्वारा विचार किया गया था।
- ब्रिटेन का पहला "तीन माता-पिता का बच्चा" एचएफईए को किए गए सूचना की स्वतंत्रता अनुरोध में पाया गया था।
- रिपोर्टों के अनुसार, क्लिनिक ने कहा कि यूके में एमडीटी का उपयोग करके बहुत कम बच्चे पैदा हुए हैं।
- एमडीटी कार्यक्रम का उपयोग करके पैदा किए गए शिशुओं का विवरण डॉक्टरों द्वारा इस चिंता के बीच जारी नहीं किया जाता है कि विशिष्ट जानकारी के माध्यम से रोगी की गोपनीयता से समझौता किया जा सकता है।
- एचएफईए ने कहा है कि प्रौद्योगिकी का उपयोग करके 20 अप्रैल 2023 तक "पांच से कम" बच्चे पैदा हुए थे। हालांकि, एचएफईए ने परिवारों की पहचान की रक्षा के लिए सटीक संख्या प्रदान करने से इनकार कर दिया।
- खबर है कि दान किए गए माइटोकॉन्ड्रिया वाले बच्चों की एक छोटी संख्या अब ब्रिटेन में पैदा हुई है, यह अगला कदम है, जो संभवतः माइटोकॉन्ड्रियल दान का आकलन और शोधन करने की एक धीमी और सतर्क प्रक्रिया बनी रहेगी।
- ब्रिटेन पहला देश नहीं है जहां एमडीटी के जरिए बच्चों का जन्म हुआ है। 2016 में, मेक्सिको में पैदा हुए एक बच्चे के लिए भी यही प्रक्रिया अपनाई गई थी।

आईवीएफ क्या है?

- इन विट्रो फर्टिलाइजेशन (आईवीएफ) प्रक्रियाओं की एक जटिल श्रृंखला है जिसका उपयोग प्रजनन क्षमता में मदद करने या आनुवंशिक समस्याओं को रोकने और बच्चे के गर्भाधान में सहायता करने के लिए किया जाता है।
- आईवीएफ के दौरान, अंडाशय से परिपक्व अंडे एकत्र (पुनर्प्राप्त) किए जाते हैं और एक प्रयोगशाला में शुक्राणु द्वारा निषेचित किया जाता है।
- फिर निषेचित अंडे (भ्रूण) या अंडे (भ्रूण) को गर्भाशय में स्थानांतरित कर दिया जाता है। आईवीएफ के एक पूर्ण चक्र में लगभग तीन सप्ताह लगते हैं।
- कभी-कभी ये चरण अलग-अलग भागों में विभाजित हो जाते हैं और इस प्रक्रिया में अधिक समय लग सकता है।
- आईवीएफ सहायक प्रजनन तकनीक का सबसे प्रभावी रूप है।
- यह प्रक्रिया युगल के अपने अंडे और शुक्राणु का उपयोग करके की जा सकती है।
- या आईवीएफ में किसी ज्ञात या अनाम दाता से अंडे, शुक्राणु या भ्रूण शामिल हो सकते हैं।
- कुछ मामलों में, गर्भावधि वाहक - कोई ऐसा व्यक्ति जिसके गर्भाशय में भ्रूण प्रत्यारोपित हो - का उपयोग किया जा सकता है।

रोबोटिक्स फ्रेमवर्क

खबरों में क्यों

तेलंगाना सरकार ने अपनी तरह का पहला स्टेट रोबोटिक्स फ्रेमवर्क लॉन्च किया

महत्वपूर्ण बिंदु

- तेलंगाना सरकार ने एक नई नीति पेश की जिसे स्टेट रोबोटिक्स फ्रेमवर्क के नाम से जाना जाता है।
- यह एक आत्मनिर्भर रोबोटिक्स पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करने और भारत में रोबोटिक्स में राज्य को एक नेता के रूप में स्थापित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- नीति का उद्देश्य अनुसंधान और विकास के लिए सहायता प्रदान करना, शिक्षा जगत और उद्योग के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करना और विभिन्न क्षेत्रों में रोबोटिक्स प्रौद्योगिकी को अपनाने को बढ़ावा देना है।
- स्टेट रोबोटिक्स फ्रेमवर्क के हिस्से के रूप में, तेलंगाना ने परीक्षण सुविधाओं, सह-कार्यस्थलों और सह-उत्पादन या विनिर्माण विकल्पों के साथ एक रोबो पार्क स्थापित करने की योजना बनाई है।
- ये सुविधाएं या तो राज्य के स्वामित्व वाली साइटों पर या प्रतिस्पर्धी दरों पर उद्योग, शिक्षाविदों और इन्क्यूबेटरों के सहयोग से स्थापित की जाएंगी।
- इसके अलावा, राज्य एक विश्व स्तरीय रोबोटिक्स त्वरक स्थापित करने का इरादा रखता है ताकि स्टार्टअप को आवश्यक सहायता प्रदान की जा सके, जिसमें ऊष्मायन, बुनियादी ढांचा, प्राधिकरण, बाजार अंतर्दृष्टि, निवेशक कनेक्शन और सलाह शामिल है।
- यह त्वरक रोबोटिक्स क्षेत्र में उद्यमियों और स्टार्टअप्स के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन होगा, जिससे उन्हें बढ़ने और सफल होने में मदद मिलेगी।

रोबोटिक्स फ्रेमवर्क के बारे में

- स्टेट रोबोटिक्स फ्रेमवर्क एक विस्तृत योजना है जो भारत में रोबोटिक्स पारिस्थितिकी तंत्र को आगे बढ़ाने और उद्योग के विकास को बढ़ावा देने के लिए तेलंगाना के दृष्टिकोण को रेखांकित करती है।
- अखिल भारतीय रोबोटिक्स एसोसिएशन और अकादमिक, उद्योग विशेषज्ञों और हितधारकों से इनपुट के सहयोग से तेलंगाना के आईटीई और सी विभाग के इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज विंग द्वारा रूपरेखा तैयार की गई थी।
- रूपरेखा का उद्देश्य चार महत्वपूर्ण क्षेत्रों में वृद्धि और विकास को चलाने के लिए रोबोटिक्स प्रौद्योगिकी का उपयोग करना है: कृषि, स्वास्थ्य देखभाल, औद्योगिक स्वचालन और उपभोक्ता रोबोटिक्स।
- इन क्षेत्रों में परिणामों को बेहतर बनाने के लिए रोबोटिक्स का लाभ उठाने पर जोर दिया जा रहा है।

तकनीकी नीति के लाभ

- बेहतर सुरक्षा
- उन्नत परिशुद्धता या सटीकता

- प्रभावी प्रगति
- विनिर्माण, रसद, स्वास्थ्य देखभाल और कृषि सहित कई गुना उद्योगों का विकास
- इसलिए, रोबोटिक्स के एक स्थिर ढांचे के साथ, राज्य उद्योगों में विकास के लिए नए चैनल खोलेगा और आर्थिक उत्पादन को बढ़ाएगा और भारत में एक नेता के रूप में उभरेगा।
- यह स्टार्टअप्स, निवेशकों और रोबोटिक्स कट्टरपंथियों का समर्थन करने के लिए किया गया एक समर्पित प्रयास है।

रोबोटिक्स इनोवेशन सेंटर

- इस उन्नत संस्करण के साथ, समाज को वास्तविक सकारात्मक प्रभाव मिलेगा क्योंकि तेलंगाना की प्रतिभा भारत और विदेशों में प्रकट होगी।
- इस योजना के तहत, सरकार का लक्ष्य तेलंगाना रोबोटिक्स इनोवेशन सेंटर (TRIC) स्थापित करना है।
- बुनियादी सुविधाओं तक पहुंच, अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने, व्यापार सशक्तिकरण, एक सक्षम कार्यबल के विकास और जिम्मेदार तैनाती के प्रमुख स्तंभों को शुरू करने के लिए इस केंद्र की शुरुआत के माध्यम से रूपरेखा को लागू किया जाएगा।
- इसके अतिरिक्त, तेलंगाना रोबोटिक्स इनोवेशन सेंटर (TRIC) इस ढांचे के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार होगा और अधिसूचना में उल्लिखित ढांचे के मुख्य स्तंभों को स्थापित करने के लिए केंद्रीय स्थान होगा।

LIGO-भारत परियोजना

खबरों में क्यों

पीएम मोदी ने एलआईजीओ-इंडिया प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी

महत्वपूर्ण बिंदु

- प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल-वेव ऑब्जर्वेटरी - इंडिया (एलआईजीओ-इंडिया) की आधारशिला रखी, देश को उन गिने-चुने देशों में रखा जिनके पास ग्रेविटेशनल-वेव ऑब्जर्वेटरी है।
- प्रधान मंत्री ने 25वें राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के अवसर पर देश में वैज्ञानिक और तकनीकी उन्नति से संबंधित 5,800 करोड़ रुपये से अधिक की कई परियोजनाओं की भी घोषणा की।
- जिन परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई उनमें लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल-वेव ऑब्जर्वेटरी-इंडिया (एलआईजीओ-इंडिया), हिंगोली; होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, जटनी, ओडिशा; और टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, मुंबई का प्लेटिनम जुबली ब्लॉक।
- एलआईजीओ-इंडिया भारत को उन कुछ देशों में शामिल करेगा जिनके पास दुनिया में ऐसी वेधशालाएं हैं।
- यह भारतीय छात्रों और वैज्ञानिकों को नए और उन्नत अवसर प्रदान करेगा।

LIGO-भारत: यह क्या है?

- LIGO (लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल-वेव ऑब्जर्वेटरी) एक भौतिकी प्रयोग है जो गुरुत्वाकर्षण तरंगों नामक ब्रह्मांडीय तरंगों का पता लगाता है, जो उनकी उत्पत्ति के बारे में जानकारी देती हैं और गुरुत्वाकर्षण की प्रकृति का सुराग प्रदान करती हैं।
- यह अल्बर्ट आइंस्टीन के सिद्धांतों से अपनी नींव प्राप्त करता है।
- आइंस्टीन के सिद्धांत के अनुसार, जब दो विशाल वस्तुएं टकराती हैं, तो वे अंतरिक्ष और समय के ताने-बाने में एक लहर या गड़बड़ी पैदा करती हैं।
- यह अशांति स्रोत से सभी दिशाओं में फैलती है, जैसे अंतरिक्ष-समय की लहरदार तरंगें।
- इन तरंगों को गुरुत्वाकर्षण तरंगों के रूप में जाना जाता है।
- गुरुत्वाकर्षण तरंगें प्रकाश की गति से यात्रा करती हैं, और वे अपनी उत्पत्ति के बारे में जानकारी ले जाती हैं, जिससे हमें गुरुत्वाकर्षण की प्रकृति के बारे में और जानने में मदद मिल सकती है।
- भौतिकविदों का मानना है कि सबसे शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण तरंगें ब्लैक होल के टकराने, तारों के फटने, या न्यूट्रॉन सितारों के टकराने जैसी प्रलयकारी घटनाओं से उत्पन्न होती हैं।
- इन तरंगों का पता लगाकर और उनका अध्ययन करके, वैज्ञानिक ब्रह्मांड के बारे में कुछ सबसे बुनियादी सवालों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
- फरवरी 2016 में, सरकार ने LIGO-India, एक उन्नत गुरुत्वाकर्षण-तरंग वेधशाला के निर्माण के लिए सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दे दी जो एक वैश्विक नेटवर्क का हिस्सा बनेगी।
- LIGO-India भारतीय अनुसंधान संस्थानों, अमेरिका में LIGO प्रयोगशाला और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों के बीच एक सहयोगी उपक्रम है।
- वेधशाला में 4 किमी इंटरफेरोमीटर हाथ की लंबाई होगी और यह ब्लैक होल और न्यूट्रॉन सितारों जैसे बड़े खगोलीय पिंडों के विलय से उत्पन्न गुरुत्वाकर्षण तरंगों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होगी।
- परमाणु ऊर्जा विभाग और विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग अमेरिका के नेशनल साइंस फाउंडेशन के साथ-साथ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान और शैक्षणिक संस्थानों की साझेदारी में LIGO-India के निर्माण की देखरेख करेंगे।
- अमेरिका 560 करोड़ रुपये के बराबर 80 मिलियन डॉलर मूल्य की सुविधा के लिए प्रमुख घटक प्रदान करेगा।

LIGO-भारत क्यों महत्वपूर्ण है?

- LIGO-भारत वेधशाला गुरुत्वाकर्षण-तरंग खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी के क्षेत्र में वैश्विक वैज्ञानिक समुदाय की क्षमता में उल्लेखनीय सुधार करेगी।
- यह लेज़र, ऑप्टिक्स, वैक्यूम, क्वांटम मेट्रोलॉजी और नियंत्रण प्रणाली सहित अत्याधुनिक क्षेत्रों की एक विस्तृत श्रृंखला में भारतीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी को भी आगे बढ़ाएगा।

- LIGO-India जैसे मेगा-साइंस उपक्रम राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर शिक्षा, प्रयोगशालाओं और उद्योग को जोड़ने वाले निर्बाध पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए आदर्श शिक्षण मंच प्रदान करते हैं।

CEIR

खबरों में क्यों

मोबाइल ट्रैकिंग सिस्टम सीईआईआर पूरे भारत में लॉन्च के लिए तैयार

महत्वपूर्ण बिंदु

- CEIR सिस्टम, जो लोगों को अपने खोए हुए या चोरी हुए मोबाइल फोन को ब्लॉक और ट्रैक करने की अनुमति देता है, अखिल भारतीय लॉन्च के लिए तैयार है, और केंद्र सरकार इसे पूरे देश में लागू करेगी।

CEIR क्या है ?

- सीईआईआर का लक्ष्य चोरी और खोए हुए मोबाइल फोन की रिपोर्टिंग को आसान बनाना है, और देश भर में ऐसे उपकरणों को इस्तेमाल करने से रोकना है। इसके अलावा, नागरिक खोए हुए/चोरी हुए फोन को ब्लॉक करने के अपने अनुरोध की स्थिति की जांच कर सकते हैं, और एक बार डिवाइस मिल जाने पर वे इसे अनब्लॉक भी कर सकते हैं।

कैसे काम करेगा सिस्टम?

- हाल के दिनों में, CDoT, भारत सरकार के DoT का एक स्वायत्त दूरसंचार अनुसंधान और विकास (R&D) केंद्र है, जो दिल्ली, महाराष्ट्र, कर्नाटक और उत्तर-पूर्व जैसे दूरसंचार सर्किलों में CEIR प्रणाली का एक पायलट चला रहा है। . सिस्टम में, CDoT ने सभी टेलीकॉम ऑपरेटरों के लिए ऐसा करते हुए क्लोन किए गए मोबाइल फोन के उपयोग की जाँच करने के लिए सुविधाएँ जोड़ीं।
- फिर, अपने नेटवर्क पर किसी अनधिकृत डिवाइस की प्रविष्टि की जांच करने के लिए, ऑपरेटरों के पास अनुमोदित IMEI नंबरों की सूची होगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि केंद्र ने मोबाइल फोन बेचने से पहले IMEI - 15 अंकों की विशिष्ट संख्यात्मक पहचानकर्ता - का खुलासा करना अनिवार्य कर दिया है।
- अंत में, CEIR सिस्टम की मदद से, ऑपरेटर खोए हुए या चोरी हुए डिवाइस को ट्रैक करने के लिए इस IMEI जानकारी का उपयोग करेंगे।

शनि ग्रह

खबरों में क्यों

62 नए खोजे गए चंद्रमाओं के साथ, शनि ने बृहस्पति को उसके आसन से गिरा दिया

महत्वपूर्ण बिंदु

- सबसे अधिक चंद्रमाओं वाले ग्रह की उपाधि की दौड़ में शनि ने शायद अंतिम बार बृहस्पति को पीछे छोड़ दिया है।
- शनि ग्रह ने "चंद्रमाओं की सबसे अधिक संख्या वाले ग्रह" के शीर्षक को पुनः प्राप्त करने के लिए एक उल्लेखनीय वापसी की है, बृहस्पति को पीछे छोड़ते हुए, जिसने फरवरी में अपने 12 नए खोजे गए चंद्रमाओं के साथ अस्थायी रूप से बढ़त बना ली थी।
- एक नए अध्ययन ने आश्चर्यजनक रूप से 62 नए चंद्रमाओं का खुलासा किया है जो चक्राकार ग्रह की परिक्रमा कर रहे हैं, जिससे शनि के प्राकृतिक उपग्रहों की कुल संख्या 145 हो गई है।
- इसके विपरीत, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ (IAU) ने पुष्टि की है कि बृहस्पति के चंद्रमाओं की संख्या 95 है।
- शनि के नए खोजे गए चंद्रमाओं को वर्तमान में संख्या और अक्षरों के साथ नामित किया गया है।
- नियत समय में, शनि के चंद्रमाओं के लिए स्थापित परंपरा के अनुसार, इन चंद्रमाओं को गैलिक, नॉर्स और कैनेडियन इनुइट देवताओं से प्रेरित नामों से सम्मानित किया जाएगा।
- शनि ने न केवल अपने चंद्रमाओं की संख्या लगभग दुगनी कर ली है, बल्कि अब इसके पास सौर मंडल के बाकी सभी ग्रहों को मिलाकर जितने चंद्रमा हैं, उससे कहीं अधिक चंद्रमा हैं।
- एसोसिएटेड प्रेस (एपी) की रिपोर्टों के अनुसार, बृहस्पति और शनि कई छोटे चंद्रमाओं के मेजबान हैं। शोधकर्ताओं का मानना है कि ये चंद्रमा बड़े चंद्रमाओं के अवशेष हैं जो आपस में या धूमकेतुओं और क्षुद्रग्रहों से टकराए थे।
- माना जाता है कि यूरेनस और नेप्च्यून पर भी इसी तरह की प्रक्रियाएँ घटित हुई हैं, लेकिन पृथ्वी से उनकी महत्वपूर्ण दूरी के कारण, उनके चंद्रमाओं का पता लगाने और उनका अध्ययन करने का कार्य और भी चुनौतीपूर्ण हो जाता है।
- नासा का आगामी ड्रैगनफ्लाई मिशन, जिसके 2027 में लॉन्च होने की उम्मीद है, शनि के छोटे बाहरी चंद्रमाओं में से कम से कम एक के करीबी अवलोकन को सक्षम करने का वादा करता है।

चंद्रमा की खोज की तकनीक

- अध्ययन, रिपोर्ट में उद्धृत, मंद और छोटे उपग्रहों को उजागर करने के लिए "शिफ्ट और स्टैक" के रूप में जानी जाने वाली एक नवीन तकनीक का उल्लेख करता है।
- इस पद्धति में लगातार छवियों को एक ऐसी दर पर स्थानांतरित करना शामिल है जो आकाश में चंद्रमा की गति से मेल खाती है, जिसके परिणामस्वरूप डेटा संयुक्त होने पर एक उज्जवल उपस्थिति होती है।

शनि के वलय

- शनि के वलयों पर हाल के एक अध्ययन में कहा गया है कि वैज्ञानिकों ने एक उल्लेखनीय खोज की है जो दर्शाता है कि वलयों को सौर मंडल के इतिहास के भव्य कालक्रम में अपेक्षाकृत हाल ही में प्राप्त किया गया था।
- नासा के कैसिनी अंतरिक्ष यान से एकत्रित आंकड़ों का विश्लेषण करके, विशेषज्ञों ने निष्कर्ष निकाला है कि विशाल वलय ग्रह के साथ-साथ नहीं बने थे।
- इसके बजाय, उनका अनुमान है कि इन भव्य छल्लों का निर्माण 400 मिलियन वर्ष पहले नहीं हुआ था।
- यह सोचना स्वाभाविक है कि छल्लों का निर्माण शनि [जो कि] लगभग 4.5 अरब वर्ष पुराना है, के साथ मिलकर हुआ है।

अभिगृहीत मिशन-2

खबरों में क्यों

स्पेसएक्स का स्वयंसिद्ध मिशन-2 पहली सऊदी महिला के साथ लॉन्च के लिए तैयार

महत्वपूर्ण बिंदु

- एक्सियॉम स्पेस द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (आईएसएस) के लिए एक निजी मिशन फ्लोरिडा से 'एक्स-2' लॉन्च करने के लिए तैयार है, जिसमें उसके चालक दल की पहली सऊदी महिला अंतरिक्ष में यात्रा करेगी।
- एक्स-2 का प्रक्षेपण फ्लोरिडा में नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर के लॉन्च कॉम्प्लेक्स 39ए से लक्षित है।
- किंगडम ऑफ सऊदी अरब (केएसए) के दो मिशन विशेषज्ञ, अली अलकर्नी और रय्याना बरनावी उद्घाटन सऊदी राष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्री कार्यक्रम के सदस्य हैं, एक्सिओम स्पेस ने रिपोर्ट किया।
- 33 वर्षीय बरनावी एक युवा प्रयोगशाला विशेषज्ञ हैं, जिन्हें कैंसर स्टेम सेल के अनुसंधान में व्यापक अनुभव है। वह वर्तमान में एक शोध और प्रयोगशाला विशेषज्ञ के रूप में काम कर रही हैं।
- न्यूजीलैंड में ओटागो विश्वविद्यालय से प्रजनन विज्ञान, आनुवंशिक इंजीनियरिंग, और ऊतक विकास में स्नातक की डिग्री धारक, उन्होंने किंग फैसल विश्वविद्यालय से जैव चिकित्सा विज्ञान में मास्टर डिग्री प्राप्त की।
- सऊदी राजपत्र के अनुसार, उन्हें कैंसर स्टेम सेल अनुसंधान के क्षेत्र में नौ साल का शानदार अनुभव है।
- फरवरी में, सऊदी अरब ने घोषणा की कि वह 2023 की दूसरी तिमाही के दौरान पहली सऊदी महिला अंतरिक्ष यात्री रेयानाह बरनावी और पुरुष अंतरिक्ष यात्री अली अल-कर्नी को आईएसएस भेजेगा।
- स्पेसफ्लाइट को संयुक्त राज्य अमेरिका से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में लॉन्च करने के लिए निर्धारित किया गया है।
- इसके अलावा, सऊदी राजपत्र में रिपोर्ट के अनुसार, सऊदी मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम में दो और अंतरिक्ष यात्रियों - मरियम फरदौस और अली अल-गामदी - को सभी मिशन आवश्यकताओं पर प्रशिक्षण शामिल है।
- अंतरिक्ष मिशन का उद्देश्य मानव अंतरिक्ष उड़ान में सऊदी वैज्ञानिकों की क्षमताओं को सशक्त बनाना है, जो मानवता की सेवा करने और अंतरिक्ष उद्योग द्वारा पेश किए गए आशाजनक अवसरों से लाभान्वित होने के साथ-साथ स्वास्थ्य, स्थिरता और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी जैसे कई पहलुओं में वैज्ञानिक अनुसंधान में योगदान देता है।
- इस कार्यक्रम के माध्यम से, किंगडम अंतरिक्ष विज्ञान के स्तर पर वैज्ञानिक नवाचारों को सक्रिय करना चाहता है, और स्वतंत्र रूप से अपने स्वयं के अनुसंधान का संचालन करने की क्षमता को बढ़ाता है जो अंतरिक्ष उद्योग और देश के भविष्य पर भी सकारात्मक रूप से प्रतिबिंबित करेगा, सऊदी राजपत्र की सूचना दी।

हिमालय चंद्र टेलीस्कोप

खबरों में क्यों

भारत का हिमालयन टेलीस्कोप ब्रह्मांड में सबसे ऊर्जावान वस्तुओं में से एक का अवलोकन करता है

महत्वपूर्ण बिंदु

- लद्दाख के हानले में स्थित भारतीय खगोलीय वेधशाला ने 10 अन्य वैश्विक दूरबीनों के साथ हाथ मिलाया है ताकि पृथ्वी से लगभग 950 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर स्थित एक ब्लेजर बीएल लैकेर्टे (बीएल लैक) की चमक का अवलोकन किया जा सके।
- ब्लेज़र एक प्रकार की आकाशगंगा है जो एक विशाल ब्लैक होल द्वारा संचालित होती है और ब्रह्मांड में सबसे चमकदार और सबसे शक्तिशाली वस्तुओं में से एक है।
- वे गामा किरणों, एक्स-रे और रेडियो तरंगों सहित अत्यधिक ऊर्जावान कणों और विकिरण के उत्सर्जन के लिए जाने जाते हैं।
- रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट की एक टीम ने अब बीएल लाख की चमक का अध्ययन किया है, जिसे पहली बार लगभग एक सदी पहले खोजा गया था और धीरे-धीरे मैक्सिमा के करीब पहुंच रहा है।
- ये कॉम्पैक्ट संरचनाएं हैं जो समय-समय पर असामान्य चमक दिखाती हैं।
- टीम ने रेडियो, माइक्रोवेव, इन्फ्रारेड, ऑप्टिकल, अल्ट्रा-वायलेट, एक्स-रे, और गामा तरंग दैर्ध्य में दिखाई देने वाले विद्युत चुम्बकीय उत्सर्जन को लेने के लिए टेलीस्कोप के वैश्विक पूल का उपयोग किया।
- खगोलविदों ने जुलाई 2020 में संदेह किया था कि बीएल लैक भड़कना शुरू हो गया था और लद्दाख के हानले में स्थित हिमालयन चंद्र टेलीस्कोप सहित 11 दूरबीनों को 84 दिनों के लिए धधकने का निशाना बनाया गया था।
- जैसे-जैसे समय बीतता गया, यह देखा गया कि फ्लेयर धीरे-धीरे तेज होता जा रहा था, यह दर्शाता है कि बीएल लाख अधिक सक्रिय हो रहा था।

- 2020 में पहली बार बीएल लाख की चमक अपने चरम पर पहुंच गई। यह क्राको, पोलैंड में स्थित संशोधित डल-किरखम टेलीस्कोप द्वारा अच्छी तरह से कैप्चर किया गया था।
- अवलोकनों से पता चला कि बीएल लाख की चमक 14 से 11.8 तक बढ़ गई और शोधकर्ताओं की अंतरराष्ट्रीय टीम ने स्रोत के चुंबकीय क्षेत्र की गणना की, जो भड़कने के दौरान 7.5 गॉस से 76.3 गॉस तक पाया गया।
- विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि गणना, जो पहले कभी संभव नहीं थी, केवल टेलीस्कोप की बैटरी से प्राप्त डेटासेट के टेराबाइट्स की उपलब्धता के कारण की गई थी।

सुपर कंप्यूटर

खबरों में क्यों

भारत अपने सबसे तेज सुपरकंप्यूटरों की तिगुनी गति के लिए तैयार

महत्वपूर्ण बिंदु

- पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (एमओईएस) के अनुसार, भारत इस वर्ष के दौरान अपने सुपर-कंप्यूटिंग कौशल को नाटकीय रूप से बढ़ाने और 18-पेटाफ्लॉप सिस्टम स्थापित करने के लिए तैयार है।
- फ्लॉप (फ़्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस प्रति सेकंड) कंप्यूटर की प्रोसेसिंग गति का एक संकेतक है और एक पेटाफ़्लॉप 1,000 ट्रिलियन फ़्लॉप को संदर्भित करता है।
- इस हद तक प्रसंस्करण शक्ति अन्य बातों के अलावा, अगले कुछ दिनों में दो-तीन महीने तक मौसम कैसा रहेगा, इसका पूर्वानुमान लगाने के लिए आवश्यक जटिल गणितीय गणनाओं को बहुत आसान कर देती है।
- वर्तमान में भारत के सबसे शक्तिशाली, नागरिक सुपरकंप्यूटर - प्रत्यूष और मिहिर - 6.8 पेटाफ्लॉप की संयुक्त क्षमता के साथ भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान (IITM), पुणे और मध्यम श्रेणी मौसम पूर्वानुमान के लिए राष्ट्रीय केंद्र (NCMRWF), नोएडा में रखे गए हैं।
- इन्हें 2018 में 438 करोड़ रुपये के निवेश से चालू किया गया था।
- ये दोनों संगठन पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय से संबद्ध हैं।
- नए सुपरकंप्यूटर भी IITM और NCMRWF में रखे जाएंगे।

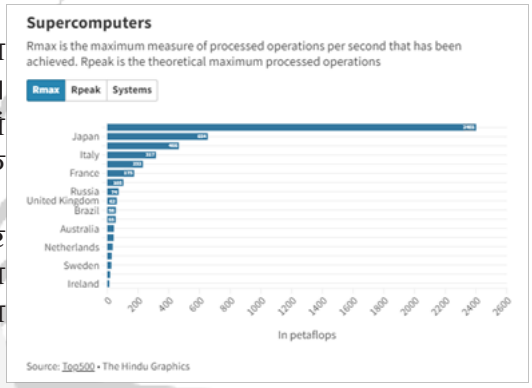

फ्रांस से आयात किया गया

- नए सुपरकंप्यूटर, जिनका नामकरण अभी बाकी है, फ्रांसीसी निगम, एटीओएस - एक सूचना प्रौद्योगिकी सेवा और परामर्श कंपनी से आयात किए गए हैं।
- मोदी सरकार ने दिसंबर 2018 में फ्रांस के साथ 2025 तक 4,500 करोड़ रुपये के उच्च प्रदर्शन वाले कंप्यूटर खरीदने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए।
- नए पृथ्वी-विज्ञान मंत्रालय के कंप्यूटरों पर 900 करोड़ रुपये खर्च होने की संभावना है।
- हर 4-5 साल में सिस्टम को अपग्रेड करना होता है।
- भारतीय वर्तमान एचपीसी 12*12 किमी के रेजोल्यूशन में मौसम और जलवायु परिवर्तन को मैप करने की अनुमति देता है।
- नई प्रणाली के साथ हम 6*6 (किमी) के रिज़ॉल्यूशन में सुधार कर सकते हैं।
- इसका मतलब है कि, कैमरों की तरह, किसी दिए गए क्षेत्र को अधिक स्पष्टता और अधिक सटीक स्थानीय पूर्वानुमान प्रदान करने के लिए चार गुना अधिक पिक्सेल का उपयोग किया जा सकता है।
- लक्ष्य अंततः 1 किमी-वर्ग ग्रिड द्वारा एक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने में सक्षम होना है और इसका उपयोग बादल फटने और ऐसी तेजी से विकसित होती मौसम प्रणालियों की चेतावनी देने के लिए किया जा सकता है।
- दुनिया में सबसे तेज़ उच्च-प्रदर्शन कंप्यूटिंग सिस्टम वर्तमान में ओकरिज नेशनल लेबोरेटरी, संयुक्त राज्य अमेरिका में फ्रंटियर-क्रे सिस्टम है।
- इसकी अधिकतम गति 1 एक्सा-फ्लॉप (या लगभग 1,000 पेटाफ्लॉप) है। गति के आधार पर शीर्ष 10 अन्य प्रणालियां लगभग 400 पेटाफ्लॉप से लेकर 60 पेटाफ्लॉप तक हैं।

RAO'S ACADEMY

6 सामाजिक मुद्दे

दीमा हसाओ शांति संधि

खबरों में क्यों

असम स्थित विद्रोही समूहों ने हाल ही में राज्य सरकार और केंद्र के साथ एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।

महत्वपूर्ण बिंदु

- असम स्थित विद्रोही समूह का प्रतिनिधित्व दिमासा नेशनल लिबरेशन आर्मी (DNLA)/दिमासा पीपुल्स सुप्रीम काउंसिल (DPSC) द्वारा किया गया था - जो दीमा हसाओ जिले में संचालित होता है।
- समझौते से उग्रवाद का पूर्ण अंत हो जाएगा और इसके साथ ही असम में अब कोई सशस्त्र समूह नहीं रह गया है।
- समझौते के तहत, DNLA के प्रतिनिधियों ने हिंसा छोड़ने, हथियारों और गोला-बारूद के आत्मसमर्पण सहित आत्मसमर्पण करने, अपने सशस्त्र संगठन को भंग करने, DNLA कैडरों के कब्जे वाले सभी शिविरों को खाली करने और मुख्यधारा में शामिल होने पर सहमति व्यक्त की है।

- इस समझौते के परिणामस्वरूप, DNLA के 168 से अधिक सशस्त्र कैडरों ने अपने हथियारों के साथ आत्मसमर्पण कर दिया और मुख्यधारा में शामिल हो गए।
- राजनीतिक, आर्थिक और शैक्षिक आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए सामाजिक, सांस्कृतिक और भाषाई पहचान की रक्षा, संरक्षण और बढ़ावा देने के लिए असम सरकार द्वारा दिमासा कल्याण परिषद की स्थापना की जाएगी और यह स्वायत्त परिषद के अधिकार क्षेत्र के बाहर रहने वाले दिमासा लोगों के त्वरित और केंद्रित विकास को सुनिश्चित करेगी। .
- समझौता ज्ञापन में भारत के संविधान की छठी अनुसूची के अनुच्छेद 14 के तहत उत्तरी कछार हिल्स स्वायत्त परिषद (एनसीएचएसी) से सटे अतिरिक्त गांवों को परिषद में शामिल करने की मांग की जांच करने के लिए एक आयोग की नियुक्ति का भी प्रावधान है।
- यह DNLA के आत्मसमर्पण करने वाले सशस्त्र संवर्गों के पुनर्वास के लिए भारत सरकार और असम सरकार द्वारा किए जाने वाले आवश्यक उपायों का भी प्रावधान करता है।
- इस आशय के लिए, NCHAC के साथ-साथ राज्य के अन्य हिस्सों में रहने वाले डिमासा लोगों के सर्वांगीण विकास के लिए भारत सरकार और असम सरकार द्वारा पांच साल की अवधि में प्रत्येक को 500 करोड़ का एक विशेष विकास पैकेज भी प्रदान किया जाएगा।
- डीएनएलए की स्थापना अप्रैल 2019 में डिमासा आदिवासियों के लिए एक संप्रभु क्षेत्र की मांग करते हुए की गई थी और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक सशस्त्र विद्रोह शुरू किया था।

दिमासा जनजाति कौन हैं?

- दिमासा लोग एक जातीय भाषाई समुदाय हैं जो वर्तमान में पूर्वोत्तर भारत में असम और नागालैंड राज्यों में निवास करते हैं।
- वे दिमासा, एक तिब्बती-बर्मन भाषा बोलते हैं। यह समुदाय काफी सजातीय और अनन्य है, जिसमें सदस्यों को माता-पिता दोनों के अलग-अलग कुलों से आकर्षित करने की आवश्यकता होती है।
- डिमास एक "सीलबंद" समाज बनाते हैं - प्रत्येक सदस्य बयालीस पुरुष कुलों में से एक से अपने पितृसत्तात्मक वंश को आकर्षित करता है (सेंगफॉन्ग- "तलवार धारक") और बयालीस महिला कुलों में से एक से मातृसत्तात्मक वंश। इन कुलों को बारह प्रादेशिक "पवित्र उपवनों" के बीच वितरित किया जाता है जिन्हें डाइखोस कहा जाता है।
- डिमास भारत के पूर्वोत्तर भाग के सबसे पुराने निवासियों में से एक हैं और कई कचहरी जनजातियों में से एक हैं।
- 18वीं शताब्दी में राजनीतिक समस्याओं के बाद, दिमासा शासक कछार के मैदानी इलाकों में आगे दक्षिण की ओर चले गए और उनके बीच एक विभाजन हुआ - पहाड़ियों दिमासा ने अपने पारंपरिक जीवन और राजनीतिक विशिष्टता को बनाए रखा, मैदानी दिमासा ने खुद को मुखर करने का कोई प्रयास नहीं किया।

एनडीपीएस

खबरों में क्यों

जेल जाने से बचने के लिए सरकार नशेड़ियों को पुनर्वास के लिए जमा करने के लिए कह सकती है

महत्वपूर्ण बिंदु

- जैसा कि केंद्र सरकार मादक दवाओं और मन:प्रभावी पदार्थों के सेवन को अपराध की श्रेणी से बाहर करने पर बहस कर रही है, यह एक नीति लाने की संभावना है जहां नशेड़ी और उपयोगकर्ताओं को उपचार केंद्रों के सामने खुद को प्रस्तुत करना होगा और आपराधिक मुकदमे से बचने के लिए खुद को इस तरह घोषित करना होगा।

- पिछले दो वर्षों में, दिल्ली, जम्मू और कश्मीर, राजस्थान, सिक्किम, गोवा, चंडीगढ़, पुडुचेरी, और त्रिपुरा के साथ असुरक्षित जिलों की संख्या (नशीली दवाओं के उपयोग के लिए) 272 से बढ़कर 372 हो गई है, जिनमें 100% जिले असुरक्षित चिह्नित हैं . इसके बाद उत्तराखंड और पंजाब हैं, जहां क्रमशः 92.30% और 86.95% जिलों को असुरक्षित चिह्नित किया गया है।
- 2018 में एम्स के माध्यम से सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा किए गए पदार्थ उपयोग सर्वेक्षण के अनुसार, शराब 17.1% प्रचलन में वयस्कों के बीच सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले पदार्थ के रूप में उभरा था।
- इसके अलावा, सर्वेक्षण से पता चला है कि भांग के उपयोग का प्रचलन सबसे अधिक 3.30% था, इसके बाद ओपिओइड (2.10%), शामक (1.21%), इनहेलेंट (0.58%) और कोकीन (0.11%) का नंबर आता है।
- वर्तमान में, नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सबस्टेंस एक्ट, 1985 के तहत, किसी भी नारकोटिक ड्रग्स या साइकोट्रोपिक पदार्थ के सेवन पर एक साल तक की जेल और/या 20,000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।

- अभी तक, जहां प्रवर्तन एजेंसियां आपूर्ति श्रृंखलाओं को लक्षित कर रही हैं, वहीं सामाजिक न्याय मंत्रालय उपयोगकर्ताओं और व्यसनी लोगों के साथ अपराधियों के बजाय पीड़ितों जैसा व्यवहार करने के लिए समवर्ती रूप से देशव्यापी जागरूकता और पुनर्वास अभियान चला रहा है।
- एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने उन देशों के उदाहरणों का हवाला देते हुए तर्क दिया कि यह एक "अप्रभावी नीति" थी।
- अवैध पदार्थों का सेवन करते हुए पकड़े गए नाबालिगों के लिए, माता-पिता की जिम्मेदारी होगी कि वे अपने बच्चों को उपयोगकर्ता या व्यसनी घोषित करें और उन्हें एक उपयुक्त सुविधा में जाँचें।
- इस विकल्प के वास्तविकता बन जाने के बाद उपयोगकर्ताओं की आमद की उम्मीद करते हुए, सामाजिक न्याय मंत्रालय अब 508 पुनर्वास और नशामुक्ति सुविधाओं के नेटवर्क को बढ़ाने की तैयारी कर रहा है, जो नशीली दवाओं की मांग में कमी के अभियान - नशा मुक्त भारत अभियान के तहत समर्थित है।
- वर्तमान में परिचालित केंद्रों में लगभग 340 एकीकृत पुनर्वास केंद्र (इन-पेशेंट केयर), लगभग 50 समुदाय-आधारित सहकर्मी-आधारित हस्तक्षेप केंद्र, 71 आउटरीच और ड्रॉप-इन केंद्र (बाह्य रोगी देखभाल), और लगभग 46 व्यसन उपचार सुविधाएं शामिल हैं।

नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक पदार्थ

- नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक पदार्थों के कई चिकित्सा और वैज्ञानिक उपयोग हैं। हालांकि, उनका दुरुपयोग और तस्करी हो सकती है और हो भी सकती है।
- नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक पदार्थों के प्रति भारत का दृष्टिकोण भारत के संविधान के अनुच्छेद 47 में निहित है जो यह आदेश देता है कि 'राज्य नशीले पेय और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक दवाओं के औषधीय उद्देश्यों को छोड़कर खपत पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास करेगा'।
- नशीली दवाओं के उपयोग को छोड़कर दवाओं के उपयोग को रोकने के समान सिद्धांत को नशीली दवाओं से संबंधित मामलों पर तीन अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भी अपनाया गया था, जैसे कि नारकोटिक ड्रग्स पर एकल सम्मेलन, 1961, मन:प्रभावी पदार्थों पर सम्मेलन, 1971 और नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक पदार्थों के अवैध अवैध व्यापार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 1988।
- भारत ने इन तीन सम्मेलनों पर हस्ताक्षर किए हैं और उनकी पुष्टि की है।
- नशीली दवाओं के दुरुपयोग और तस्करी की रोकथाम के लिए भारत की प्रतिबद्धता तीन सम्मेलनों के लागू होने से पहले की है।
- नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सबस्टेंस (एनडीपीएस) अधिनियम, 1985 को संयुक्त राष्ट्र के तीन ड्रग कन्वेंशनों के तहत भारत के दायित्वों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया था।

अंग दान

खबरों में क्यों

प्रत्यारोपण कार्यक्रम स्थापित करने के लिए नियमावली, अंग दान में सुधार के लिए समन्वयकों को प्रशिक्षित करने पर चर्चा की गई

महत्वपूर्ण बिंदु

- प्रत्यारोपण समन्वयकों के लिए पाठ्यक्रम के मानकीकरण से लेकर अस्पताल में अंग प्रत्यारोपण कार्यक्रम की स्थापना के लिए एक मैनुअल विकसित करने तक, राष्ट्रीय अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन देश में अंग दान और प्रत्यारोपण में सुधार के लिए संरचनात्मक सुधारों की दिशा में काम कर रहा है।
- संगठन "एक राष्ट्र, एक नीति" के आह्वान के साथ देश भर में अंगों को प्राप्त करने के लिए पंजीकरण और अंगों के आवंटन के लिए प्रक्रियाओं के मानकीकरण की दिशा में काम कर रहा है।
- इस लक्ष्य की दिशा में, मृतक दाताओं से अंगों के प्राप्तकर्ता के रूप में पंजीकरण के लिए 65 वर्ष की आयु सीमा को इस वर्ष की शुरुआत में अधिवास आवश्यकताओं के साथ हटा दिया गया था, जिससे एक राज्य के रोगियों को दूसरे राज्यों के अस्पतालों में पंजीकरण करने की अनुमति मिल गई थी।
- सरकार ने हाल ही में अंगों का दान करने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 42 दिनों तक का विशेष आकस्मिक अवकाश दिया है।
- देश में अंग प्रत्यारोपण की सबसे अधिक संख्या 2022 में दर्ज की गई थी, जब 15,000 अंगों-हृदय, गुर्दे और यकृत, अन्य के साथ-प्रत्यारोपित किए गए थे।

- हालांकि इन प्रत्यारोपणों के एक बड़े हिस्से ने जीवित रिश्तेदारों के अंगों का उपयोग किया, क्षेत्रीय और राज्य-स्तरीय निकायों के बीच बेहतर समन्वय के परिणामस्वरूप मृत अंगों के उपयोग में भी वृद्धि हुई है।
- आंकड़ों के अनुसार, 2016 में 930 मृतकों के 2,265 अंगों का उपयोग किया गया था। 2022 में, 904 मृतकों के 2,765 अंगों का उपयोग किया गया था।
- बैठक में, एक अस्पताल में एक प्रत्यारोपण कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए चरण-दर-चरण मार्गदर्शिका और प्रशिक्षण प्रत्यारोपण समन्वयकों के लिए एक मानक पाठ्यक्रम पर चर्चा की गई। दोनों दस्तावेज जल्द ही जारी किए जाने की संभावना है।

कार्यक्रम के उद्देश्य:

- प्रत्यारोपण के लिए अंग और ऊतक की खरीद और वितरण की एक प्रणाली को व्यवस्थित करना।
- मृतक अंग और ऊतक दान को बढ़ावा देना।
- इसके अलावा, आवश्यक जनशक्ति को प्रशिक्षित करने के लिए।
- इसके अलावा, कमजोर गरीबों को अंगों की तस्करी से बचाने के लिए।
- अंत में, अंग और ऊतक प्रत्यारोपण सेवाओं की निगरानी करना और जरूरत पड़ने पर नीति और कार्यक्रम में सुधार/परिवर्तन लाना।

कार्यक्रम के तहत प्रमुख गतिविधियों में शामिल हैं:

- प्रत्येक राज्य/केंद्र शासित प्रदेश में राज्य अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठनों (एसओटीटीओ) की स्थापना।
- राष्ट्रीय/क्षेत्रीय/राज्य जैव सामग्री केंद्रों की स्थापना।
- नए अंग प्रत्यारोपण/पुनर्प्राप्ति सुविधाओं की स्थापना और मौजूदा अंग प्रत्यारोपण/पुनर्प्राप्ति सुविधाओं को मजबूत करने के लिए वित्तीय सहायता।
- सर्जनों, चिकित्सकों, प्रत्यारोपण समन्वयकों आदि सहित प्रत्यारोपण विशेषज्ञों का प्रशिक्षण।
- मेडिकल कॉलेजों और ट्रॉमा सेंटरों में प्रत्यारोपण समन्वयकों की भर्ती के लिए वित्तीय सहायता।
- गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) रोगियों को पोस्ट-प्रत्यारोपण प्रतिरक्षा-दमनकारी दवाएं।

NOTTO के बारे में

- राष्ट्रीय अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन (NOTTO) की स्थापना नई दिल्ली में स्थित स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत की गई है।
- भारत में अंग दान को मानव अंगों और ऊतकों के प्रत्यारोपण अधिनियम, 1994 द्वारा नियंत्रित किया जाता है।

राष्ट्रीय अंग प्रत्यारोपण कार्यक्रम (एनओटीपी) के बारे में:

- राष्ट्रीय अंग प्रत्यारोपण कार्यक्रम (एनओटीपी) का उद्देश्य सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) में अंग दान और प्रत्यारोपण को बढ़ावा देना है।
- कार्यान्वयन एजेंसी: स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (DGHS), स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय राष्ट्रीय अंग प्रत्यारोपण कार्यक्रम को लागू कर रहा है।

भारत में अंग प्रत्यारोपण से संबंधित रूपरेखा

- मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम, 1994 मानव अंगों को हटाने, भंडारण और प्रत्यारोपण को विनियमित करने के लिए एक प्रणाली प्रदान करता है।
- मानव अंगों का प्रत्यारोपण (संशोधन) अधिनियम, 2011
- मानव अंगों और ऊतकों का प्रत्यारोपण नियम, 2014

यौन उत्पीड़न

खबरों में क्यों

यौन उत्पीड़न को संबोधित करने के लिए आंतरिक शिकायत समिति की कमी पर एनएचआरसी ने खेल मंत्रालय, एनएसएफ को नोटिस जारी किया।

महत्वपूर्ण बिंदु

- एक जांच से पता चला है कि भारत के 30 राष्ट्रीय खेल संघों में से आधे से अधिक 16 में आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) नहीं है, जो यौन उत्पीड़न रोकथाम (पीओएसएच) अधिनियम, 2013 के तहत एक कानूनी आवश्यकता है।
- आंतरिक शिकायत समितियां (ICCs) वैधानिक निकाय हैं जो भारत में कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 (POSH अधिनियम) के तहत स्थापित की गई हैं।
- POSH अधिनियम के अनुसार, प्रत्येक नियोक्ता जिसके पास 10 या अधिक कर्मचारी हैं, को प्रत्येक कार्यस्थल पर एक ICC का गठन करना आवश्यक है।

ICC में कम से कम चार सदस्य होने चाहिए

- कम से कम 50% महिलाएं होनी चाहिए।
- पीठासीन अधिकारी के रूप में एक वरिष्ठ महिला कर्मचारी होनी चाहिए।
- एक गैर-सरकारी संगठन या कानूनी पृष्ठभूमि से एक बाहरी सदस्य होना चाहिए।
- आईसीसी सदस्यों को 3 साल की अवधि के लिए नियुक्त किया जाना चाहिए और पॉश अधिनियम और संबंधित मुद्दों पर नियमित प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहिए।

उद्देश्य

- आईसीसी का मुख्य उद्देश्य कार्यस्थल में महिलाओं के यौन उत्पीड़न की शिकायतों को दूर करने और उनके लिए एक सुरक्षित और अनुकूल कार्य वातावरण सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र प्रदान करना है।
- लैंगिक समानता और गरिमा के संवैधानिक सिद्धांतों के अनुरूप महिलाओं के लिए एक सुरक्षित और अनुकूल कार्य वातावरण प्रदान करना।
- शिकायतों की निष्पक्ष और निष्पक्ष जांच करना, शिकायतकर्ताओं को अंतरिम राहत और सुरक्षा प्रदान करना, अपराधियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की सिफारिश करना और अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करना।

कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के खिलाफ क्या है कानून?

- कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, जिसे आमतौर पर PoSH अधिनियम के रूप में जाना जाता है, 2013 में पारित किया गया था।
- यह यौन उत्पीड़न को परिभाषित करता है, शिकायत और पूछताछ के लिए प्रक्रिया निर्धारित करता है, और यौन उत्पीड़न के मामलों में की जाने वाली कार्रवाई।

PoSH अधिनियम कैसे आया?

- 2013 के कानून को व्यापक बनाया गया और विशाखा दिशानिर्देशों के रूप में जाना जाने वाला विधायी समर्थन दिया गया, जिसे 1997 में पारित एक फैसले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित किया गया था।
- राजस्थान की एक सामाजिक कार्यकर्ता भंवरी देवी के कथित गैंगरेप को लेकर विशाखा नामक एक महिला अधिकार समूहों द्वारा विचाराधीन मामला दायर किया गया था। भंवरी ने 1992 में एक साल की बच्ची की शादी के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, और कथित तौर पर प्रतिशोध के रूप में सामूहिक बलात्कार किया गया था।
- विशाखा दिशानिर्देशों ने यौन उत्पीड़न को परिभाषित किया और संस्थानों पर तीन प्रमुख दायित्व लगाए - निषेध, रोकथाम, निवारण। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि उन्हें एक शिकायत समिति गठित करनी चाहिए, जो कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के मामलों की जांच करेगी। अदालत ने दिशानिर्देशों को कानूनी रूप से बाध्यकारी बनाया।

अधिनियम शिकायत समिति के बारे में क्या कहता है?

- PoSH अधिनियम ने बाद में यह अनिवार्य कर दिया कि प्रत्येक नियोक्ता को 10 या अधिक कर्मचारियों वाले प्रत्येक कार्यालय या शाखा में एक आंतरिक शिकायत समिति (ICC) का गठन करना चाहिए। इसने यौन उत्पीड़न के विभिन्न पहलुओं को परिभाषित किया, और शिकायत के मामले में कार्रवाई के लिए प्रक्रियाएं निर्धारित कीं।
- अधिनियम के तहत पीड़ित पीड़ित महिला "किसी भी उम्र की चाहे [कार्यस्थल पर] कार्यरत हो या नहीं" हो सकती है, जो "यौन उत्पीड़न के किसी भी कार्य के अधीन होने का आरोप लगाती है"। वास्तव में, यह अधिनियम उन सभी महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करता है जो किसी भी क्षमता में काम कर रही हैं या किसी कार्यस्थल पर जा रही हैं।

PoSH अधिनियम के तहत यौन उत्पीड़न क्या है?

2013 के कानून के तहत, यौन उत्पीड़न में निम्नलिखित "अवांछित कार्य या व्यवहार" में से "कोई एक या अधिक" सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है:

- शारीरिक संपर्क और आगे बढ़ना
- यौन अनुग्रह की मांग या अनुरोध
- यौन रंग वाली टिप्पणियां
- अश्लील साहित्य दिखाना
- यौन प्रकृति का कोई अन्य अवांछित शारीरिक, मौखिक या गैर-मौखिक आचरण।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा प्रकाशित 'कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न पर पुस्तिका' में व्यवहार के अधिक विस्तृत उदाहरण शामिल हैं जो कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न का गठन करते हैं। इन परिस्थितियों में मोटे तौर पर शामिल हैं:

- कामोत्तेजक टिप्पणी या इशारा; गंभीर या बार-बार आपत्तिजनक टिप्पणी; किसी व्यक्ति के यौन जीवन के बारे में अनुचित प्रश्न या टिप्पणी;
- सेक्सिस्ट या आपत्तिजनक तस्वीरें, पोस्टर, एमएमएस, एसएमएस, व्हाट्सएप, या ईमेल का प्रदर्शन; यौन अनुग्रह के इर्द-गिर्द डराना, धमकाना, ब्लैकमेल करना;
- इनके बारे में बोलने वाले कर्मचारी के खिलाफ धमकी, धमकी या प्रतिशोध;
- आम तौर पर छेड़खानी के रूप में देखे जाने वाले यौन संबंधों के साथ अवांछित सामाजिक निमंत्रण;
- अवांछित यौन प्रस्ताव।
- पुस्तिका कहती है कि "अप्रिय व्यवहार" का अनुभव तब होता है जब पीड़ित बुरा या शक्तिहीन महसूस करता है, और जब यह क्रोध/उदासी या नकारात्मक आत्म-सम्मान का कारण बनता है। अवांछित व्यवहार "अवैध, अपमानजनक, आक्रमणकारी, एकतरफा और शक्ति-आधारित" है।

इसके अलावा, पीओएसएच अधिनियम में पांच परिस्थितियों का उल्लेख है जो यौन उत्पीड़न की श्रेणी में आती हैं:

- उसके रोजगार में अधिमान्य व्यवहार का निहित या स्पष्ट वादा;
- हानिकारक उपचार की अंतर्निहित या स्पष्ट धमकी;
- शिकायतकर्ता के वर्तमान या भविष्य के रोजगार की स्थिति के बारे में निहित या स्पष्ट धमकी;
- शिकायतकर्ता के काम में दखलअंदाजी या आपत्तिजनक या शत्रुतापूर्ण कार्य वातावरण बनाना;
- शिकायतकर्ता का अपमानजनक व्यवहार जिससे उसके स्वास्थ्य या सुरक्षा पर प्रभाव पड़ने की संभावना है।

अधिनियम के तहत शिकायत की प्रक्रिया क्या है?

- पीड़ित पीड़ित के लिए आईसीसी को कार्रवाई करने के लिए शिकायत दर्ज करना अनिवार्य नहीं है। अधिनियम कहता है कि वह ऐसा "कर सकती है" - और यदि वह नहीं कर सकती है, तो आईसीसी का कोई भी सदस्य उसे लिखित में शिकायत करने के लिए "सभी उचित सहायता" प्रदान करेगा।
- यदि महिला "शारीरिक या मानसिक अक्षमता या मृत्यु या अन्यथा" के कारण शिकायत नहीं कर सकती है, तो उसका कानूनी उत्तराधिकारी ऐसा कर सकता है।
- अधिनियम के तहत, शिकायत "घटना की तारीख से तीन महीने के भीतर" की जानी चाहिए। हालाँकि, ICC "समय सीमा बढ़ा सकता है" यदि "यह संतुष्ट है कि परिस्थितियाँ ऐसी थीं जो महिला को उक्त अवधि के भीतर शिकायत दर्ज करने से रोकती थीं"।
- आईसीसी "जांच से पहले", और "पीड़ित महिला के अनुरोध पर, सुलह के माध्यम से उसके और प्रतिवादी के बीच मामले को सुलझाने के लिए कदम उठा सकती है" - बशर्ते कि "सुलह के आधार पर कोई मौद्रिक समझौता नहीं किया जाएगा" .
- आईसीसी या तो पीड़ित की शिकायत को पुलिस को अग्रेषित कर सकती है, या वह एक जांच शुरू कर सकती है जिसे 90 दिनों के भीतर पूरा किया जाना है। ICC के पास शपथ पर किसी भी व्यक्ति को बुलाने और उसकी जांच करने, और दस्तावेजों की खोज और उत्पादन की आवश्यकता के संबंध में दीवानी अदालत के समान अधिकार हैं।
- जब जांच पूरी हो जाती है, तो आईसीसी को 10 दिनों के भीतर नियोक्ता को अपने निष्कर्षों की एक रिपोर्ट देनी होगी। रिपोर्ट भी दोनों पक्षों को उपलब्ध कराई जाए।
- महिला, प्रतिवादी, गवाह की पहचान, पूछताछ पर कोई जानकारी, सिफारिश और की गई कार्रवाई को सार्वजनिक नहीं किया जाना चाहिए।

आईसीसी द्वारा अपनी रिपोर्ट दाखिल करने के बाद क्या होता है?

- अगर यौन उत्पीड़न के आरोप साबित होते हैं, तो आईसीसी नियोक्ता को कंपनी के "सेवा नियमों के प्रावधानों के अनुसार" कार्रवाई करने की सिफारिश करेगी। ये कंपनी से कंपनी में भिन्न हो सकते हैं।
- आईसीसी यह भी सिफारिश कर सकती है कि कंपनी दोषी पाए गए व्यक्ति के वेतन में कटौती करे, "जैसा वह उचित समझे"। मुआवजा पांच पहलुओं के आधार पर निर्धारित किया जाता है: महिला को हुई पीड़ा और भावनात्मक संकट; कैरियर के अवसर में हानि; उसके चिकित्सा व्यय; प्रतिवादी की आय और वित्तीय स्थिति; और ऐसे भुगतान की व्यवहार्यता।
- यदि पीड़ित महिला या प्रतिवादी संतुष्ट नहीं हैं, तो वे 90 दिनों के भीतर अदालत में अपील कर सकते हैं।

COVID-19

खबरों में क्यों

WHO का कहना है कि Covid-19 अब वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल नहीं है

महत्वपूर्ण बिंदु

- विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने घोषित किया है कि कोविड-19 अब "वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल" का प्रतिनिधित्व नहीं करता है।
- बयान महामारी को समाप्त करने की दिशा में एक बड़े कदम का प्रतिनिधित्व करता है और तीन साल बाद आता है जब इसने पहली बार वायरस पर अपने उच्चतम स्तर के अलर्ट की घोषणा की थी।
- बयान महामारी को समाप्त करने की दिशा में एक बड़े कदम का प्रतिनिधित्व करता है और तीन साल बाद आता है जब इसने पहली बार वायरस पर अपने उच्चतम स्तर के अलर्ट की घोषणा की थी।
- अधिकारियों ने कहा कि वायरस की मृत्यु दर जनवरी 2021 में प्रति सप्ताह 100,000 से अधिक लोगों के शिखर से गिरकर 24 अप्रैल 2023 को केवल 3,500 से अधिक हो गई थी।
- WHO ने कहा कि इस महामारी से कम से कम सात मिलियन लोगों की मौत हुई है।

'महान आशा'

- आपातकालीन समिति ने 15वीं बार बैठक की और अंतरराष्ट्रीय चिंता के सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल को समाप्त करने की घोषणा करने की सिफारिश की।
- अलर्ट के उच्चतम स्तर को हटाने का मतलब यह नहीं है कि खतरा खत्म हो गया है और कहा कि अगर स्थिति बदली तो आपातकालीन स्थिति को बहाल किया जा सकता है।
- कोई भी देश अब जो सबसे खराब काम कर सकता है, वह है इस खबर का इस्तेमाल अपने पहरेदारों को नीचा दिखाने के लिए, अपने द्वारा बनाए गए सिस्टम को खत्म करने के लिए, या अपने लोगों को यह संदेश देने के लिए कि कोविड-19 के बारे में चिंता करने की कोई बात नहीं है।
- विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पहली बार जनवरी 2020 में कोविड-19 को अंतर्राष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल (PHEIC) घोषित किया था।
- इसने लोगों को नए वायरस से बचाने के लिए समन्वित वैश्विक कार्रवाई की आवश्यकता का संकेत दिया।
- महामारी में टीके प्रमुख मोड़ बिंदुओं में से एक थे।
- WHO के अनुसार, 13 बिलियन खुराक दी जा चुकी है, जिससे कई लोगों को गंभीर बीमारी और मृत्यु से बचाया जा सकता है।
- लेकिन कई देशों में ज़्यादातर ज़रूरतमंदों तक टीके नहीं पहुँच पाए हैं।
- दुनिया भर में 76.5 करोड़ से अधिक पुष्ट कोविड संक्रमण दर्ज किए गए हैं।
- अमेरिका और ब्रिटेन, कई अन्य देशों की तरह, पहले ही "वायरस के साथ जीने" के बारे में बात कर चुके हैं और कई परीक्षणों और सामाजिक मिश्रण नियमों को समाप्त कर चुके हैं।

- डब्ल्यूएचओ ने 2005 के बाद से सात बार सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात घोषणा जारी की है। पदनाम नियमों की एक श्रृंखला को ट्रिगर करता है जो परीक्षणों और दवाओं के फास्ट-ट्रैकिंग सहित खतरनाक बीमारी के प्रकोप की प्रतिक्रिया का मार्गदर्शन करता है।
- 2019 में कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में इबोला के प्रकोप के बाद पहली बार WHO ने COVID-19 के लिए एक अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की।
- WHO ने 2023-2025 COVID-19 रणनीतिक तैयारी और प्रतिक्रिया योजना (SPRP) भी जारी की, जिसे COVID-19 के दीर्घकालिक प्रबंधन के संक्रमण में देशों का मार्गदर्शन करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- यह योजना 10 स्तंभों के तहत 5 क्षेत्रों के लिए विचार करने के लिए देशों के लिए महत्वपूर्ण कार्रवाइयों की रूपरेखा तैयार करती है

बाल विवाह

खबरों में क्यों

वैश्विक बहुसंख्यक संकट बाल विवाह को समाप्त करने के लिए कठिन संघर्ष का निर्माण कर रहा है

महत्वपूर्ण बिंदु

- यूनिसेफ के नए विश्लेषण के अनुसार, संघर्ष, जलवायु संबंधी झटके और कोविड-19 से जारी गिरावट सहित कई संकट पिछले दशक में बाल विवाह को कम करने के लिए कड़ी मेहनत से हासिल किए गए लाभ को उलटने का खतरा पैदा कर रहे हैं।

विश्व स्तर पर बाल विवाह:

- बाल विवाह एक विवाह या एक अनौपचारिक संघ है जो कानून द्वारा निर्दिष्ट एक निश्चित आयु तक पहुंचने से पहले एक व्यक्ति द्वारा किया जाता है।
- वैश्विक स्तर पर, अनुमानित 640 मिलियन लड़कियों और आज जीवित महिलाओं की शादी बचपन में कर दी गई थी।
- बचपन में शादी करने वाली महिलाओं की हिस्सेदारी 21% से घटकर 19% होने के बावजूद, 2030 तक बाल विवाह को समाप्त करने के सतत विकास लक्ष्य को पूरा करने के लिए 20 गुना तेज दर से वैश्विक कटौती की आवश्यकता है।
- उप-सहारा अफ्रीका में वर्तमान में बाल वधुओं का दूसरा सबसे बड़ा वैश्विक हिस्सा यानी 20% है।
- लैटिन अमेरिका और कैरेबियाई भी पिछड़ रहे हैं और 2030 तक बाल विवाह का दूसरा उच्चतम क्षेत्रीय स्तर होने की राह पर हैं।

भारत में बाल विवाह:

- भारत में लड़की के लिए शादी की न्यूनतम कानूनी उम्र 18 वर्ष और लड़कों के लिए 21 वर्ष है।
- भारत में बाल विवाह की दर 2015-16 में 27 प्रतिशत से घटकर 2021 में 23.3 प्रतिशत हो गई है।
- जबकि राजस्थान जैसे कुछ राज्यों ने प्रगति की है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश जैसे अन्य राज्यों को अपनी दरों को कम करने के लिए अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है।
- गरीबी और सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ापन बाल विवाह के प्रचलन में महत्वपूर्ण योगदान देता है।
- रिपोर्ट में यह भी रेखांकित किया गया है कि महामारी और जलवायु परिवर्तन के कारण होने वाली गरीबी और अन्य चुनौतियां माता-पिता को कम उम्र में अपनी बेटियों की शादी करने के लिए मजबूर कर रही हैं। हालांकि इस तर कानून महत्वपूर्ण है, लेकिन इसके क्रियान्वयन को सख्त बनाने की जरूरत है।
- इसके अतिरिक्त, गरीबी को दूर करना और लड़कियों की शिक्षा में सुधार महत्वपूर्ण उपाय हैं।
- बाल विवाह लड़कियों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं, और उन्हें अपनी क्षमता को पूरा करने के अवसर से वंचित करते हैं।
- इसके अलावा, वे प्रभावी रूप से जनसंख्या के एक महत्वपूर्ण हिस्से को राष्ट्रीय विकास से बाहर कर देते हैं, राष्ट्र को उनके उत्पादक योगदान से वंचित कर देते हैं।
- जिस तरह एक शिक्षित और नियोजित महिला अपने पुरुष समकक्षों की तुलना में राष्ट्र के लिए अधिक योगदान देती है, उसी तरह एक लड़की जो विवाहित है और शिक्षा और रोजगार के अवसरों से वंचित है, राष्ट्र के लिए नुकसान का प्रतिनिधित्व करती है।
- हालांकि भारत ने हाल के दशकों में महत्वपूर्ण प्रगति दर्ज की है, फिर भी यह वैश्विक कुल का एक तिहाई हिस्सा है।

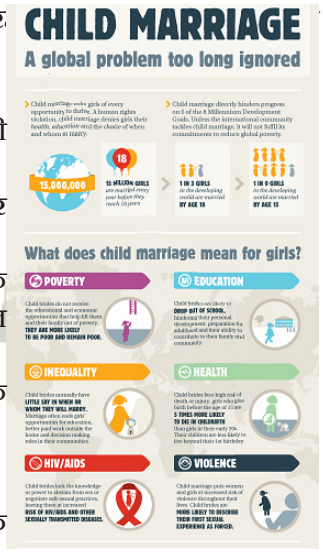

बाल विवाह के परिणाम:

- बुनियादी अधिकारों से वंचित करना जैसे शिक्षा का अधिकार, आराम और आराम का अधिकार, मानसिक या मानसिक सुरक्षा का अधिकार।
- बलात्कार और यौन शोषण सहित शारीरिक शोषण।
- प्रारंभिक गर्भावस्था के बढ़ते जोखिम के कारण बच्चे और मातृ स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं का जोखिम।
- महिलाओं का अशक्तीकरण क्योंकि वे शिक्षा की कमी के कारण निर्भर और कम शक्ति वाली रहती हैं।
- मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दे क्योंकि वे दोस्तों और परिवार के सदस्यों से अलग-थलग पड़ जाते हैं।

मातृ और नवजात मृत्यु

खबरों में क्यों

2015 के बाद से मातृ और नवजात मृत्यु के मामले में प्रगति रुकी हुई है

महत्वपूर्ण बिंदु

- गर्भावस्था, प्रसव या जन्म के पहले सप्ताह के दौरान हर साल 4.5 मिलियन से अधिक महिलाओं और शिशुओं की मृत्यु होने के बावजूद, इसे कम करने की वैश्विक प्रगति 2015 से रुकी हुई है, संयुक्त राष्ट्र (यूएन) की एक नई रिपोर्ट से पता चला है।
- स्थिर निवेश और अल्प राजनीतिक मंशा, COVID-19 महामारी, बढ़ती गरीबी और बिगड़ते मानवीय संकटों ने पहले से ही अनिश्चित स्थिति को और बढ़ा दिया है।
- मातृ और नवजात स्वास्थ्य और उत्तरजीविता में सुधार और मृत जन्म को कम करने की रिपोर्ट ने भारत को शीर्ष पर रखा है, जो वैश्विक मातृ मृत्यु, मृत जन्म और नवजात जन्म (788,000 कुल मृत्यु) का 17 प्रतिशत है।
- गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं की दुनिया भर में अस्वीकार्य रूप से उच्च दर से मृत्यु हो रही है, और COVID-19 महामारी ने उन्हें आवश्यक स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के लिए और अधिक झटके पैदा किए हैं।
- रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्षों से पता चलता है कि कैसे 2000 और 2010 के बीच अर्जित लाभ 2010 के बाद के वर्षों की तुलना में तेजी से हुआ।
- मातृ मृत्यु अनुपात में 2000 और 2009 के बीच 2.8 प्रतिशत की वार्षिक कमी दर देखी गई, जो 2010 और 2020 के बीच घटकर 1.3 प्रतिशत हो गई। वैश्विक लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अगले दशक में इस संकेतक को 11.9 प्रतिशत तक कम करने में सुधार की आवश्यकता है। एमएमआर प्रति 1,000 जीवित जन्मों पर 70 मौतों के बराबर है।
- 2000 और 2009 के बीच, मृत जन्म दर में 2.3 प्रतिशत और 2010 और 2021 के बीच 1.8 प्रतिशत की कमी आई थी। प्रति 1,000 जीवित जन्मों पर 12 मृत जन्मों से कम के वैश्विक लक्ष्य को पूरा करने के लिए 2022 और 2030 के बीच 5.2 प्रतिशत की कमी की आवश्यकता है।
- नवजात मृत्यु दर (एनएमआर) में भी यही प्रवृत्ति दर्ज की गई है; 2000 और 2009 के बीच 3.2 प्रतिशत की कमी, 2010 और 2021 में 2.2 प्रतिशत की कमी।
- नवजात शिशु मृत्यु दर को समाप्त करने के वैश्विक लक्ष्य को पूरा करने के लिए 2022 और 2030 के बीच NMR को और 7.2 प्रतिशत कम करने की आवश्यकता है।
- जबकि प्रगति चिह्नित नहीं की गई है, इस दशक के अंत तक इन लक्ष्यों को पूरा करने से अभी भी लगभग आठ मिलियन लोगों की जान बचाई जा सकती है - दस लाख से अधिक महिलाएं, 2.6 मिलियन मृत जन्म और 4.2 मिलियन नवजात शिशु।
- ऐसा करना "गर्भधारण से लेकर प्रसवोत्तर अवधि तक देखभाल की निरंतरता में गुणवत्ता और इक्विटी के साथ संयुक्त जीवन रक्षक हस्तक्षेपों के उच्च कवरेज के साथ ही संभव होगा," रिपोर्ट में कहा गया है।
- आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करके इन मातृ और शिशु स्वास्थ्य संकेतकों में उल्लेखनीय सुधार किया जा सकता है।
- इस उपलब्धता का आकलन करने के लिए तीन मानक उपायों का इस्तेमाल किया जा सकता है; कम से कम चार प्रसव पूर्व देखभाल संपर्क (ANC4), जन्म के समय एक कुशल परिचारक (SAB) होना और जन्म के बाद पहले दो दिनों के भीतर प्रसवोत्तर देखभाल (PNC) प्राप्त करना।
- जबकि ANC4 के लिए कवरेज दर 2010 में 61 प्रतिशत से 2022 में 68 प्रतिशत तक सुधरी है, यह आंकड़ा 2025 तक केवल एक प्रतिशत बिंदु तक बढ़ने का अनुमान है।
- एसएबी कवरेज दरों के लिए भी यही है, इसी अवधि में 75 प्रतिशत से 86 प्रतिशत तक और 2025 तक 88 प्रतिशत तक अपेक्षित सुधार।
- पीएनसी के लिए, कवरेज में सबसे अधिक सुधार दर्ज किया गया है - 2010 और 2022 के बीच 54 प्रतिशत से 66 प्रतिशत तक। इसके 2025 तक 69 प्रतिशत तक पहुंचने का अनुमान है। अनुमानों से यह स्पष्ट होता है कि एएनसी4 और पीएनसी कवरेज वर्तमान गति से वैश्विक लक्ष्यों को पूरा करने में विफल रहेंगे।
- "उर्ध्व रुझान आशाजनक हैं, लेकिन यदि 2025 के लक्ष्यों को प्राप्त करना है तो कवरेज बढ़ाने के लिए सुधार की दरों में तेजी लानी होगी। इसके अलावा, जब गर्भवती महिलाओं, नई माताओं और नवजात शिशुओं की सेवाओं तक पहुंच होती है, तब भी यह सुनिश्चित करना कि वे सम्मानजनक और गुणवत्तापूर्ण देखभाल से लाभान्वित हों, एक महत्वपूर्ण अंतर बना रहता है, "रिपोर्ट में कहा गया है।
- नवजात शिशुओं और गर्भवती महिलाओं के लिए आपातकालीन देखभाल की कमी को दूर करना एक और बाधा है जिसके बिना एमएमआर, एनएमआर और मृत जन्म में लक्षित कमी को प्राप्त करना संभव नहीं होगा।
- 2025 तक केवल 51 प्रतिशत देशों के 80 प्रतिशत या अधिक जिलों में छोटे और बीमार नवजात शिशुओं के लिए देखभाल इकाइयां होने की उम्मीद है।
- एक करीबी क्षेत्र-वार विश्लेषण से पता चलता है कि उप-सहारा अफ्रीका में केवल 35 प्रतिशत देशों के इस लक्ष्य को प्राप्त करने की उम्मीद है। इसके विपरीत, मध्य और दक्षिण एशिया के 71 प्रतिशत देशों ने 80 प्रतिशत या अधिक जिलों में कवरेज की योजना बनाई है।

ईएमओसी:

- मातृ मृत्यु दर को कम करने के लिए गुणवत्तापूर्ण आपातकालीन प्रसूति देखभाल (ईएमओसी) तक पहुंच महत्वपूर्ण है।
- लेकिन उप-सहारा अफ्रीका में ईएमओसी प्रदान करने वाली लगभग 36 प्रतिशत सुविधाओं को उत्तरी अफ्रीका और पश्चिमी एशिया में 62 प्रतिशत और अन्य क्षेत्रों में 80 प्रतिशत से अधिक ईएमओसी सुविधाओं की तुलना में कार्यशील माना जाता है।
- इस मोर्चे पर सुधार से मातृ मृत्यु को कम करने में काफी मदद मिल सकती है, जिसका एक प्रमुख कारण प्रसवोत्तर रक्तस्राव है - जन्म के 24 घंटे के भीतर 500 मिलीलीटर से अधिक रक्त की हानि के रूप में परिभाषित किया गया है।
- प्रसवोत्तर रक्तस्राव को प्रबंधित करने के लिए हस्तक्षेपों का एक सेट भारी रक्तस्राव को 60 प्रतिशत तक कम कर सकता है, एक नए अध्ययन से पता चला है।

- एक लिंग परिवर्तनकारी दृष्टिकोण मातृ और नवजात मृत्यु दर को संबोधित कर सकता है।
- सामाजिक-आर्थिक असमानताओं, भेदभाव, गरीबी और अन्याय जैसे खराब मातृ स्वास्थ्य परिणामों को जन्म देने वाले अंतर्निहित कारकों पर मुहर लगाना महत्वपूर्ण है।

एसडीजी

खबरों में क्यों

एसडीजी को पूरा करने की दिशा में प्रगति को ट्रैक करने वाला भोपाल पहला भारतीय शहर बन गया है

महत्वपूर्ण बिंदु

- मध्य प्रदेश में भोपाल संयुक्त राष्ट्र-अनिवार्य सतत विकास लक्ष्यों (SDG) के स्थानीयकरण को अपनाने वाला भारत का पहला शहर बन गया है।
- एमपी के राजधानी शहर में अब स्वैच्छिक स्थानीय समीक्षाएं (वीएलआर) होंगी जो स्थानीय सरकार की क्षमता और प्रतिबद्धताओं को प्रदर्शित करती हैं।
- संयुक्त राष्ट्र ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा, मध्य प्रदेश सरकार ने कार्रवाई के लिए एक एजेंडा शुरू किया: भोपाल में सतत शहरी परिवर्तन।
- एसडीजी स्थानीयकरण एजेंडे का अनुवाद कर रहा है, हमारी दुनिया को बदल रहा है: सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा (एजेंडा 2030 के रूप में जाना जाता है), स्थानीय कार्यों और प्रभावों में जो लक्ष्यों की वैश्विक उपलब्धि में योगदान देता है।
- भोपाल का वीएलआर भोपाल नगर निगम, यूएन-हैबिटेट और 23 से अधिक स्थानीय हितधारकों के सामूहिक सहयोग का परिणाम है, जो एक स्थायी और समावेशी शहरी परिवर्तन के लिए शहर की आकांक्षाओं को मापने के लिए प्रदर्शित करता है, प्रेस नोट में कहा गया है।
- इसमें 56 विकासात्मक परियोजनाओं के गुणात्मक मानचित्रण के साथ एसडीजी की समीक्षा के लिए मात्रात्मक और गुणात्मक दृष्टिकोण का मिश्रण शामिल है।
- 2015 में, संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 सदस्य देशों ने एजेंडा 2030 को अपनाया, जिसमें 17 एसडीजी और 169 लक्ष्य लोगों, ग्रह और समृद्धि के लिए कार्य योजना के रूप में शामिल थे।
- सदस्य देश स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा (वीएनआर) के माध्यम से लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में अपनी प्रगति की रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र के उच्च स्तरीय राजनीतिक मंच (एचएलपीएफ) को देते हैं।
- संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, स्थानीय और क्षेत्रीय सरकारें अपने स्वयं के उप-राष्ट्रीय समीक्षाओं, तथाकथित वीएलआर, में तेजी से संलग्न हो रही हैं, जो शहरों और क्षेत्रों के लिए उपयोगी साबित हुई हैं।
- वीएनआर के विपरीत, स्थानीय समीक्षाओं का 2030 एजेंडा या अन्य अंतर-सरकारी समझौतों में प्रत्यक्ष रूप से आधिकारिक आधार नहीं होता है, भले ही 2030 एजेंडा कई स्थानों पर इसके कार्यान्वयन पर क्षेत्रीय और स्थानीय अधिकारियों के साथ मिलकर काम करने वाली सरकारों के महत्व को रेखांकित करता है।
- एजेंडा 2030 को प्राप्त करने में शहरों और क्षेत्रों की एक महत्वपूर्ण भूमिका है क्योंकि 169 लक्ष्यों में से कम से कम 60 प्रतिशत को संभवतः प्राप्त नहीं किया जा सका है।
- वीएलआर एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में उभरे हैं जो स्थानीय कार्रवाई में सबसे आगे हैं। न्यूयॉर्क शहर 2018 में एचएलपीएफ को अपना वीएलआर पेश करने वाला पहला शहर बना। 2021 तक, कुछ 33 देशों ने 114 वीएलआर या इसी तरह के समीक्षा दस्तावेज सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराए थे।

यूएन-हैबिटेट: यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन सेटलमेंट्स प्रोग्राम

- संयुक्त राष्ट्र मानव आवास कार्यक्रम (यूएन-हैबिटेट) को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा सामाजिक और पर्यावरणीय रूप से स्थायी कस्बों और शहरों को बढ़ावा देने के लिए अनिवार्य किया गया है।
- यूएन-हैबिटेट संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के भीतर सभी शहरीकरण और मानव बस्तियों के मामलों का केंद्र बिंदु है।
- UN-Habitat समावेशी, सुरक्षित, लचीला और स्थायी शहरों और समुदायों के निर्माण के लिए भागीदारों के साथ काम करता है।
- UN-Habitat शहरीकरण को लोगों और समुदायों के लिए एक सकारात्मक परिवर्तनकारी शक्ति के रूप में बढ़ावा देता है, असमानता, भेदभाव और गरीबी को कम करता है।

उद्देश्य

- UN-Habitat ज्ञान, नीति सलाह, तकनीकी सहायता और सहयोगी कार्रवाई के माध्यम से शहरों और मानव बस्तियों में परिवर्तनकारी परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए 90 से अधिक देशों में काम करता है।
- UN-Habitat की रणनीतिक योजना 2020-2023 इक्कीसवीं सदी के शहरों और अन्य मानव बस्तियों की चुनौतियों और अवसरों को हल करने के लिए एक अधिक रणनीतिक और एकीकृत दृष्टिकोण अपनाती है।
- यूएन-हैबिटेट का मिशन संगठन की चार मुख्य भूमिकाओं को शामिल करता है, जिन्हें संक्षेप में इस प्रकार बताया जा सकता है: सोचें, करें, साझा करें और भागीदार बनें।
    - सोचें: यूएन-हैबिटेट के नियामक कार्य, जिसमें अभूतपूर्व अनुसंधान और क्षमता निर्माण शामिल है, मानक निर्धारित करता है, मानदंडों और सिद्धांतों का प्रस्ताव करता है, अच्छा अभ्यास साझा करता है, वैश्विक प्रगति की निगरानी करता है और स्थायी शहरों और मानव बस्तियों से संबंधित नीतियों के निर्माण का समर्थन करता है।
    - डीओ: यूएन-हैबिटेट के परिचालन कार्य में विभिन्न प्रकार की तकनीकी सहायता मिलती है, जो स्थायी शहरीकरण और संकट प्रतिक्रिया में अपनी अनूठी विशेषज्ञता पर आधारित है। यूएन-हैबिटेट देशों को मूल्यवर्धित और अनुरूप समर्थन प्रदान करने के लिए परियोजनाओं को लागू करता है।

7वां संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह

खबरों में क्यों

सड़क सुरक्षा 2021-2030 के लिए कार्रवाई के दशक की वैश्विक योजना

महत्वपूर्ण बिंदु

- 15-21 मई 2023 को 7वें संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किया गया। इसने नीति निर्माताओं से चलने, साइकिल चलाने और सार्वजनिक परिवहन को सुरक्षित और सुविधाजनक बनाने के लिए गतिशीलता पर पुनर्विचार करने का आह्वान किया ताकि लोग सक्रिय, टिकाऊ गतिशीलता की ओर जा सकें।
- यह मॉडल बदलाव 2021-2030 की कार्रवाई के दशक के लिए वैश्विक योजना की सिफारिशों में से एक है।
- सड़क यातायात की चोटें दुनिया भर में मौत और विकलांगता का एक प्रमुख कारण हैं, हर साल लगभग 1.3 मिलियन लोग मारे जाते हैं और लगभग 50 मिलियन लोग घायल होते हैं।
- 5-29 वर्ष की आयु के लोगों के लिए, उनके जीवन के लिए इससे बड़ा कोई खतरा नहीं है। विश्व स्तर पर, प्रत्येक 4 में से 1 मौत पैदल चलने वालों और साइकिल चालकों के बीच होती है।
- सड़क सुरक्षा 2021-2030 के लिए कार्रवाई के दशक की वैश्विक योजना 2030 तक सड़क यातायात से होने वाली मौतों और चोटों को 50% तक कम करने के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को दर्शाती है।
- यह इस बात पर प्रकाश डालता है कि संपूर्ण परिवहन प्रणाली को संबोधित करके, सुरक्षित सड़कों, वाहनों और व्यवहारों को सुनिश्चित करने के साथ-साथ आपातकालीन देखभाल में सुधार करके उन्हें रोका जा सकता है।
- डब्ल्यूएचओ, भागीदारों के सहयोग से समय-समय पर संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह आयोजित करता है।
- यह 7वां संस्करण स्थायी परिवहन पर केंद्रित है, विशेष रूप से पैदल चलने, साइकिल चलाने और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने की आवश्यकता पर।
- सड़क सुरक्षा इस बदलाव के लिए एक पूर्वापेक्षा और परिणाम दोनों है।
- सड़क यातायात की चोटें दुनिया भर में मौत और विकलांगता का एक प्रमुख कारण हैं, हर साल लगभग 1.3 मिलियन लोग मारे जाते हैं और लगभग 50 मिलियन लोग घायल होते हैं।
- सड़क हादसों में भारत दुनिया में पहले नंबर पर है।
- भारत में 99% पैदल चलने वालों को चोट लगने की संभावना है।
- डब्ल्यूएचओ ने सभी सड़क सुरक्षा और टिकाऊ गतिशीलता भागीदारों को 7 वें संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह को चिह्नित करने के लिए आमंत्रित किया है ताकि कार्यक्रमों और गतिविधियों का आयोजन किया जा सके और हैशटैग के साथ सोशल मीडिया पर संदेश और सामग्री साझा की जा सके:

  #रिथिंकमोबिलिटी

  #StreetsforLife

  #सड़क सुरक्षा

ज़रूरी सन्देश

- सरकारों और उनके भागीदारों को गतिशीलता पर पुनर्विचार करने की सख्त आवश्यकता है।
- दुनिया में हम कैसे आगे बढ़ते हैं, इसकी फिर से कल्पना करने के प्रयासों के मूल में सुरक्षा होनी चाहिए।
- सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, सड़क नेटवर्क को सबसे अधिक जोखिम को ध्यान में रखकर डिजाइन किया जाना चाहिए।
- सुरक्षित होने पर, पैदल चलना और साइकिल चलाना लोगों को स्वस्थ, शहरों को टिकाऊ और समाज को न्यायसंगत बनाने में योगदान दे सकता है।
- सुरक्षित, सस्ता, सुलभ और टिकाऊ सार्वजनिक परिवहन समाज की कई समस्याओं का समाधान है।

भारत

- सेफ इंडिया ने भारत के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुरूप स्कूल क्षेत्रों के आसपास 25 किमी/घंटा की गति सीमा की वकालत की।
- उन्होंने 16 मई 2023 को एक प्रमुख ट्रैफिक पोस्ट पर हितधारकों और पुलिस विभाग को शामिल करने वाली एक हिमायत रैली से शुरू होने वाले कार्यक्रमों की एक श्रृंखला आयोजित की।
- इसके बाद विभिन्न निर्णय निर्माताओं और नागरिक समाज संगठनों, शिक्षाविदों, सड़क सुरक्षा स्वयंसेवकों और मीडिया सहित अन्य हितधारकों के साथ एक सार्वजनिक बैठक हुई।
- इस कार्यक्रम में, उन्होंने स्कूल क्षेत्रों के आसपास 25 किमी/घंटा की गति सीमा लागू करने की अपनी प्रतिबद्धता प्राप्त करने के लिए पुलिस आयुक्त और परिवहन विभाग के अधिकारियों को एक याचिका सौंपी।
- स्थानीय अधिकारियों और निर्णय निर्माताओं, नागरिक समाज, समुदायों और मीडिया के साथ सार्वजनिक परिवहन की ओर मोडल शिफ्ट की वकालत करने की क्षमता।

7 अंतर्राष्ट्रीय सम्बन्ध

स्वदेशी मुद्दों पर संयुक्त राष्ट्र स्थायी मंच (UNPFII)

खबरों में क्यों

आदिवासी अधिकार कार्यकर्ताओं ने UNPFII के 22वें सत्र में भारत के प्रतिनिधि के वक्तव्य की आलोचना की है जिसमें उन्होंने कहा कि 'स्वदेशी लोगों' की अवधारणा भारतीय संदर्भ में लागू नहीं होती है।

महत्वपूर्ण बिंदु

- स्वदेशी लोग किसी क्षेत्र के आरंभिक ज्ञात निवासी होते हैं, विशेष रूप से वे जो अब बसने वालों के एक प्रमुख समूह द्वारा उपनिवेश बना लिया गया है।
- स्वदेशी लोग विशिष्ट सामाजिक और सांस्कृतिक समूह हैं जो उन भूमियों और प्राकृतिक संसाधनों से सामूहिक पैतृक संबंध साझा करते हैं जहां वे रहते हैं, कब्जा करते हैं या जहां से वे विस्थापित हुए हैं।

सत्र का विषय

- थीम: "मूलवासी लोग, मानव स्वास्थ्य, ग्रहीय और क्षेत्रीय स्वास्थ्य और जलवायु परिवर्तन: एक अधिकार-आधारित दृष्टिकोण" ("Indigenous Peoples, human health, planetary and territorial health and climate change: a rights-based approach").

UNPFII के बारे में

- UNPFII आर्थिक और सामाजिक परिषद के लिए एक सलाहकार निकाय है।
- यह वर्ष 2000 में आर्थिक और सामाजिक विकास, संस्कृति, पर्यावरण, शिक्षा, स्वास्थ्य और मानव अधिकारों से संबंधित स्वदेशी लोगों मुद्दों से निपटने के लिए स्थापित किया गया था।
- स्थायी फोरम की पहली बैठक मई 2002 में हुई थी, उसके बाद वार्षिक सत्र हुए।
- न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में फोरम आमतौर पर हर साल 10 दिनों के लिए मिलता है।
- 06 अनिवार्य क्षेत्रों (आर्थिक और सामाजिक विकास, संस्कृति, पर्यावरण, शिक्षा, स्वास्थ्य और मानव अधिकार) के अलावा, प्रत्येक सत्र विषयगत रूप से एक विशिष्ट मुद्दे पर केंद्रित है।
- स्थायी मंच संयुक्त राष्ट्र के उन तीन निकायों में से एक है जिसे विशेष रूप से स्वदेशी लोगों के मुद्दों से निपटने के लिए अधिकृत किया गया है।
- अन्य, मूल निवासियों के अधिकारों पर विशेषज्ञ तंत्र और मूल निवासियों के अधिकारों पर विशेष प्रतिवेदक हैं।

इक्वाडोर, नाइजीरिया, पनामा और भारत

खबरों में क्यों

इक्वाडोर, नाइजीरिया, पनामा ने जेनेरिक दवा योजनाओं के लिए भारत का दोहन किया है।

महत्वपूर्ण बिंदु

- इक्वाडोर, पनामा और नाइजीरिया उन देशों में शामिल हैं जो प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना (PMBJP) जैसी योजना के माध्यम से अपने नागरिकों को सस्ती जेनेरिक दवाएं उपलब्ध कराने के लिए भारत के साथ बातचीत कर रहे हैं।

प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना:

- PMBJP को 2008 में फार्मास्यूटिकल्स विभाग द्वारा लोगों को सस्ती कीमत पर गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया था।
- योजना के तहत, जन औषधि केंद्र स्टोर गुणवत्ता वाली दवाएं उपलब्ध कराते हैं, जिनकी कीमत ब्रांडेड दवाओं से 50-90% कम होती है।
- पिछले आठ वर्षों में, नागरिकों द्वारा बचाई गई अनुमानित राशि बढ़कर 20,000 करोड़ हो गई, जिसमें प्रतिदिन 10 लाख से अधिक लोग केंद्रों पर आते हैं।
- वर्तमान में, देश भर में 9,000 से अधिक जन औषधि केंद्र काम कर रहे हैं, और केंद्र सरकार का लक्ष्य मार्च 2024 तक संख्या को बढ़ाकर 10,000 करना है।

जेनेरिक दवा योजना के बारे में:

- जेनेरिक दवाएं ब्रांडेड दवाओं की प्रतियां होती हैं जो मूल दवा के पेटेंट की अवधि समाप्त होने के बाद बनाई जाती हैं।
- उनमें ब्रांडेड दवा के समान सक्रिय संघटक होते हैं और उसी स्थिति का उसी तरह से इलाज करने के लिए उपयोग किया जाता है।
- जन औषधि केंद्र ऐसे स्टोर हैं जो सभी के लिए सस्ती कीमत पर गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाएं, उपभोग्य वस्तुएं और सर्जिकल सामान उपलब्ध कराते हैं।
- भारत दुनिया में जेनेरिक दवाओं का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता है, वित्त वर्ष 22 में $19.02 बिलियन मूल्य के जेनेरिक का निर्यात करता है।

भारत-संयुक्त अरब अमीरात

खबरों में क्यों

भारत-UAE व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते (CEPA) को एक साल पूरा हो गया है।

महत्वपूर्ण बिंदु

- ऐतिहासिक भारत- UAE व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता (CEPA) जिस पर 18 फरवरी 2022 को दोनों देशों के बीच हस्ताक्षर किए गए थे, आधिकारिक तौर पर मई 2023 में लागू हुआ।
- संयुक्त अरब अमीरात को भारत के निर्यात में रत्न और आभूषण क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा योगदान देता है और यह एक ऐसा क्षेत्र है जिसे भारत-यूएई सीईपीए के तहत भारतीय उत्पादों के लिए प्राप्त टैरिफ रियायतों से काफी लाभ होने की उम्मीद है।
- कुल मिलाकर, भारत को अपनी 97% से अधिक टैरिफ लाइनों पर UAE द्वारा प्रदान की गई तरजीही बाजार पहुंच से लाभ होगा, जो विशेष रूप से रत्न और आभूषण, कपड़ा, चमड़ा, जूते, खेल के सामान, प्लास्टिक, फर्नीचर, कृषि और लकड़ी के उत्पाद, इंजीनियरिंग उत्पाद, फार्मास्यूटिकल्स, चिकित्सा उपकरण और ऑटोमोबाइल जैसे श्रम प्रधान क्षेत्रों से मूल्य के संदर्भ में UAE को भारतीय निर्यात का 99% है।

- CEPA से पांच वर्षों के भीतर माल के द्विपक्षीय व्यापार का कुल मूल्य US$100 बिलियन से अधिक और सेवाओं में व्यापार का कुल मूल्य US$ 15 बिलियन से अधिक होने की उम्मीद है।
- हालांकि समझौते में 100 बिलियन अमरीकी डालर के व्यापार के लक्ष्य की कल्पना की गई थी, भारत के बाजार के आकार और संयुक्त अरब अमीरात द्वारा भारत को दी जाने वाली पहुंच को देखते हुए, बहुत कुछ हासिल किया जा सकता था।
- यह देखते हुए कि समझौता दोनों देशों के नेताओं की दृष्टि का परिणाम था, भारत के लिए, संयुक्त अरब अमीरात दुनिया के लिए एक प्रवेश द्वार होगा।
- भारत सरकार रसद लागत को कम करने पर काम कर रही थी ताकि भीतरी इलाकों के उत्पाद भी प्रतिस्पर्धी हो सकें।
- पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान USD 670 बिलियन का निर्यात (सामान और सेवा) सकल घरेलू उत्पाद का 22-23% था।
- यूएई को भारतीय निर्यात 28 अरब अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 31.3 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया।
- CEPA के कारण महत्वपूर्ण निर्यात वृद्धि देखने वाले कुछ प्रमुख क्षेत्रों में शामिल हैं: खनिज ईंधन; विद्युत मशीनरी (विशेष रूप से टेलीफोन उपकरण); रत्न और आभूषण; ऑटोमोबाइल आदि।
- गुड्स डोमेन में, संयुक्त अरब अमीरात ने भारत से 99% आयात के अनुरूप अपनी टैरिफ लाइन के 97.4% पर शुल्क समाप्त कर दिया।
- भारत ने मूल्य के संदर्भ में भारत के 90% निर्यात के अनुरूप अपनी 80% से अधिक टैरिफ लाइनों पर तत्काल शुल्क समाप्त कर लिया है।
- 160 सेवा उप-क्षेत्रों में से, भारत ने संयुक्त अरब अमीरात को 100 उप-क्षेत्रों की पेशकश की है और संयुक्त अरब अमीरात ने भारत को 111 उप-क्षेत्रों की पेशकश की है।

विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023

खबरों में क्यों

हाल ही में ग्लोबल मीडिया वॉचडॉग रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स (RSF) द्वारा वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 रिपोर्ट प्रकाशित की गयी।

महत्वपूर्ण बिंदु

- ग्लोबल मीडिया वॉचडॉग रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स (RSF) की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार, भारत 2023 विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में 180 देशों में से 161वें स्थान पर खिसक गया है।
- रिपोर्ट RSF द्वारा जारी की गई थी, और यह प्रेस स्वतंत्रता के लिए भारत की रैंकिंग में गिरावट का संकेत देती है।
- देश में वर्तमान में 100,000 से अधिक समाचार पत्र (36,000 साप्ताहिक सहित) और 380 टीवी समाचार चैनल चल रहे हैं।
- 1 जनवरी, 2023 से देश में एक पत्रकार की हत्या कर दी गई, जबकि 10 पत्रकार सलाखों के पीछे हैं।
- इस वर्ष की रिपोर्ट से पता चलता है कि पत्रकारों के साथ उनके व्यवहार के लिए "संतोषजनक" माने जाने वाले देशों की संख्या थोड़ी बढ़ रही है, लेकिन यह संख्या भी है जहां स्थिति "बहुत गंभीर" है।
- रैंकिंग पांच श्रेणियों पर आधारित है - राजनीतिक, विधायी, आर्थिक, सामाजिक-सांस्कृतिक और पत्रकारों की सुरक्षा।

भारत की स्थिति

- सुरक्षा संकेतक श्रेणी में भारत की रैंक विशेष रूप से चिंताजनक है, क्योंकि 2023 विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में 180 देशों में से यह 172वें स्थान पर आ गया है। इसका मतलब यह है कि पत्रकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के मामले में केवल आठ देशों की रैंकिंग भारत से खराब है।
- इस पैरामीटर के संदर्भ में, भारत चीन, मैक्सिको, ईरान, पाकिस्तान, सीरिया, यमन, यूक्रेन और म्यांमार को छोड़कर अन्य सभी देशों की तुलना में खराब स्थान पर है, जिसमें म्यांमार सबसे कम रैंकिंग वाला है।
- विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भी भारत का प्रदर्शन दक्षिण एशिया के अन्य देशों की तुलना में खराब है। बांग्लादेश 163वें स्थान पर भारत से थोड़ा खराब है, जबकि पाकिस्तान भारत से 150वें स्थान पर है।
- आश्चर्यजनक रूप से, यहां तक कि अफगानिस्तान, जहां तालिबान सरकार स्वतंत्र पत्रकारिता को प्रतिबंधित करने के लिए जानी जाती है, की भारत से बेहतर रैंकिंग 152 है। भूटान की रैंकिंग 90 से बेहतर है, जबकि श्रीलंका की रैंक 135 है।

वैश्विक स्तर पर

- नॉर्वे, आयरलैंड और डेनमार्क जैसे नॉर्डिक देश क्रमशः शीर्ष तीन स्थान पर रहे जबकि वियतनाम, चीन और उत्तर कोरिया सूचकांक में नीचे के तीन देश थे।
- रूस, जहां की सरकार ने काफी हद तक स्वतंत्र मीडिया को कुचलने का काम पूरा कर लिया है, नौ स्थान गिरकर 164वें स्थान पर आ गया है। रूसी आक्रमण और कुलीन वर्गों के साथ अपने स्वयं के मुद्दों के बावजूद, यूक्रेन 27 पायदान ऊपर 79वें स्थान पर पहुंच गया।

रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स (RSF):

- यह एक अंतरराष्ट्रीय NGO है जिसका स्व-घोषित उद्देश्य मीडिया की स्वतंत्रता की रक्षा करना और उसे बढ़ावा देना है।
- मुख्यालय: पेरिस, फ्रांस।
- इसे संयुक्त राष्ट्र के साथ सलाहकार का दर्जा प्राप्त है।
- RSF प्रेस की स्वतंत्रता को "राजनीतिक, आर्थिक, कानूनी और सामाजिक हस्तक्षेप से स्वतंत्र और उनकी शारीरिक और मानसिक सुरक्षा के लिए खतरों के अभाव में सार्वजनिक हित में समाचारों का चयन, उत्पादन और प्रसार करने के लिए व्यक्तियों और सामूहिक रूप से पत्रकारों की क्षमता" के रूप में परिभाषित करता है। "

कलादान परियोजना

खबरों में क्यों

भारत ने कलादान परियोजना के तहत सितवे बंदरगाह के लिए शिपमेंट को हरी झंडी दिखाई।

महत्वपूर्ण बिंदु

- स्वीकृत होने के पंद्रह साल बाद, कलादान मल्टीमॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट (KMTTP) का जलमार्ग घटक अगले महीने संचालित होने के लिए तैयार है, जिसमें कोलकाता से म्यांमार में सितवे बंदरगाह तक पहला वाणिज्यिक कार्गो मूवमेंट शुरू होगा।
- सितवे में गहरे पानी का बंदरगाह 3,200 करोड़ रुपये की कलादान मल्टी-मोडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट (KMTTP) का हिस्सा है। विदेश मंत्रालय द्वारा संचालित और पहली बार 2008 में स्वीकृत इस परियोजना का उद्देश्य भारत और म्यांमार के बीच व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देना और अन्य दक्षिण एशियाई देशों तक पहुंच को आसान बनाना है।
- एक बार तैयार हो जाने पर, यह स्थलरुद्ध पूर्वोत्तर राज्यों को शेष भारत से जोड़ने और मौजूदा संकीर्ण सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर दबाव कम करने के लिए एक रणनीतिक वैकल्पिक लिंक भी प्रदान करेगा।
- भारत के अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (IWAI) द्वारा विकसित - केंद्रीय शिपिंग मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संगठन - सितवे बंदरगाह का निर्माण 2018 में पूरा हो गया था।
- लेकिन म्यांमार में राजनीतिक उथल-पुथल और चिन और रखाइन राज्य में तीव्र संघर्ष के कारण अनुमोदन और लाइसेंस प्राप्त करने में देरी सहित कई बाधाओं के कारण इसे चालू नहीं किया जा सका।

कलादान परियोजना:

- कलादान मल्टीमॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट (KMTTP) 484 मिलियन डॉलर की एक परियोजना है, जो भारत के पूर्वी बंदरगाहों से म्यांमार और आगे म्यांमार के माध्यम से देश के उत्तर-पूर्वी हिस्सों तक कार्गो शिपमेंट के लिए एक मल्टी-मॉडल प्लेटफॉर्म बनाने के लिए भारत से अनुदान सहायता के तहत बनाई गई है। .
- परियोजना का प्राथमिक उद्देश्य पूर्वोत्तर और मुख्य भूमि भारत को जोड़ने के लिए एक वैकल्पिक मार्ग बनाना है क्योंकि संकीर्ण सिलीगुड़ी चिकन नेक कॉरिडोर परिवहन के लिए एकमात्र व्यवहार्य मार्ग है।
- कलादान परियोजना भारत और म्यांमार के बीच सहयोग और प्रतिबद्धताओं का एक उदाहरण है जो म्यांमार, हमारे उत्तर-पूर्वी राज्यों और दक्षिण एशियाई देशों के साथ व्यापार, वाणिज्य और आर्थिक संबंधों को और बढ़ाएगा।

सितवे बंदरगाह:

- सितवे बंदरगाह को मिजोरम से बंदरगाह को जोड़ने वाली कलादन नदी पर एक बहुविध पारगमन परिवहन सुविधा के निर्माण और संचालन के लिए भारत और म्यांमार के बीच एक रूपरेखा समझौते के तहत विकसित किया गया है।
- बंदरगाह एक अंतर्देशीय जलमार्ग के माध्यम से म्यांमार में पलेटवा से और सड़क घटक के माध्यम से मिजोरम में पलेटवा से ज़ोरिनपुई से जुड़ता है।
- यह परियोजना कोलकाता से सितवे की दूरी लगभग 1328 किमी कम कर देगी और संकीर्ण सिलीगुड़ी कॉरिडोर के माध्यम से माल परिवहन की आवश्यकता को कम कर देगी।

क्षेत्र में कनेक्टिविटी में सुधार के लिए अन्य पहलें

- भारत और बांग्लादेश के बीच अंतर्देशीय जल पारगमन और व्यापार पर प्रोटोकॉल।
- भारत-म्यांमार-थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग (IMT) भारत में मोरेह को म्यांमार के माध्यम से थाईलैंड में माई सॉट से जोड़ता है।
- भारत-जापान एक्ट ईस्ट फोरम (AEF) का उद्देश्य एनईआर के भीतर और एनईआर और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना है।
- बांग्लादेश-भूटान-भारत-नेपाल मोटर वेहिकल एग्रीमेंट।

शटल कूटनीति

खबरों में क्यों

जापान, दक्षिण कोरिया ऐतिहासिक क्षेत्रीय बदलाव में संबंधों में सुधार करते हैं

महत्वपूर्ण बिंदु

- जापान और दक्षिण कोरिया संबंधों को आगे ले जाने और लंबे समय से चले आ रहे ऐतिहासिक विवादों से आगे बढ़ने पर सहमत हुए, एक ऐसे रिश्ते को बदलने का संकल्प लिया जिसका क्षेत्र के लिए व्यापक प्रभाव हो सकता है।
- जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा रविवार को 12 वर्षों में सियोल की यात्रा करने वाले पहले जापानी नेता बने। यह यात्रा मार्च में दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक येओल द्वारा जापान की यात्रा के बाद हुई।
- जिसे "शटल डिप्लोमेसी" करार दिया गया है, वह दो अमेरिकी सहयोगियों के बीच संबंधों को बदलने का वादा करता है जो ऐतिहासिक मुद्दों पर उलझे हुए हैं, मुख्य रूप से जापान की अपने कब्जे के दौरान किए गए अत्याचारों के लिए माफी मांगने की अनिच्छा।

- हालांकि, दोनों को न केवल उत्तर कोरिया के परमाणु कार्यक्रम पर बल्कि चीन की क्षेत्रीय ताकत पर साझा चिंताओं के कारण एक साथ लाया गया है।
- जापान की युद्धकालीन कार्रवाइयों पर मतभेदों के बावजूद, जो दक्षिण कोरिया और चीन में एक भावनात्मक मुद्दा बना हुआ है, राष्ट्रपति यून ने आगे बढ़ने के लिए मामला बनाकर घरेलू राजनीतिक नतीजों को जोखिम में डाल दिया है और यह तर्क दिया है कि जहां ऐतिहासिक मुद्दों का समाधान जारी है, वहीं संबंधों को अभी भी भविष्य की ओर देखने की जरूरत है .
- उस अंत तक, मार्च में दोनों पक्ष दक्षिण कोरियाई लोगों को मुआवजा देने के लिए एक कोष के साथ आने पर सहमत हुए, जो जापानी मजबूर श्रम कार्यक्रमों के तहत पीड़ित थे।
- मार्च समझौते के तहत, मुआवजे का भुगतान एक संयुक्त कोष द्वारा किया जाएगा, न कि, जैसा कि दक्षिण कोरिया में कई लोगों ने मांग की थी, पूरी तरह से जापानी कंपनियों द्वारा वित्त पोषित किया गया था, जिनमें से दो ने 2018 में, दक्षिण कोरिया मं1 191045 के कब्जे के दौरान अपने रिकॉर्ड को लेकर कानूनी कार्रवाई का सामना किया था। .
- जापानी सेना द्वारा हजारों कोरियाई महिलाओं को भी यौन गुलामी के लिए मजबूर किया गया था।
- श्री यून की मार्च यात्रा ने बर्फ को तोड़ दिया, और एक मेल-मिलाप को आगे बढ़ाया जिसका दोनों नेताओं ने दृढ़ता से समर्थन किया है। वर्तमान यात्रा ने दोनों पक्षों को घनिष्ठ आर्थिक और रक्षा संबंधों का पता लगाने के लिए देखा है।
- जापानी नेता ने श्री यून को इस महीने के अंत में टोक्यो में आयोजित होने वाले जी-7 शिखर सम्मेलन में भी आमंत्रित किया, जिसकी हाल के दिनों में संभावना नहीं थी।
- जापानी नेताओं ने लंबे समय से इस मंत्र को दोहराया है कि 1965 के समझौते के माध्यम से सब कुछ पहले ही तय हो गया था और कोरियाई लोगों के खिलाफ जापान के युद्धकालीन अपराधों के बारे में विशिष्ट शब्दों में औपचारिक माफी देने से इनकार कर दिया।

अफ्रीका और मध्य पूर्व में भारत

खबरों में क्यों

अफ्रीका और मध्य पूर्व में 49% तेल पाइपलाइन परियोजनाएं विकसित करने वाले शीर्ष 5 देशों में से भारत है।

महत्वपूर्ण बिंदु

- वैश्विक ऊर्जा मॉनिटर, एक गैर-लाभकारी संस्था जो ऊर्जा परियोजनाओं पर नज़र रखती है, के एक विश्लेषण के अनुसार, भारत तेल पाइपलाइनों के शीर्ष पांच डेवलपर्स में से एक है, जो निर्माणाधीन और प्रस्तावित हैं।
- देश 1,630 किलोमीटर लंबी तेल संचरण पाइपलाइनों का निर्माण कर रहा है, जो निर्माणाधीन श्रेणी की पाइपलाइनों में विश्व स्तर पर दूसरे स्थान पर है। 1,194 किलोमीटर लंबी प्रस्तावित पाइपलाइनों के साथ, भारत ने 10वां स्थान हासिल किया, जैसा कि विश्लेषण से पता चलता है।
- भारत के साथ, निर्माणाधीन और प्रस्तावित पाइपलाइनों वाले अन्य शीर्ष देशों में संयुक्त राज्य अमेरिका, इराक, ईरान और तंजानिया शामिल हैं।
- वैश्विक स्तर पर करीब 9,100 किलोमीटर तेल संचरण पाइपलाइन निर्माणाधीन हैं और 21,900 किलोमीटर प्रस्तावित हैं।
- विकास की इन पाइपलाइनों पर पूंजीगत व्यय में $131.9 बिलियन खर्च होने का अनुमान है।
- कुल मिलाकर, वैश्विक स्तर पर करीब 31,000 किलोमीटर तेल पाइपलाइनों का विकास किया जा रहा है। यह पिछले साल इस समय से लगभग 30 प्रतिशत की वृद्धि का प्रतिनिधित्व करता है।
- इसमें से 49 प्रतिशत तेल पाइपलाइनें विकसित की जा रही हैं जो अफ्रीका और मध्य पूर्व में हैं। बुनियादी ढांचे की लागत करीब 25.3 अरब डॉलर होने का अनुमान है।
- दोनों क्षेत्रों में 14.4 बिलियन डॉलर की अनुमानित लागत से 4,400 किमी लंबी कच्चे तेल की संचरण पाइपलाइनें हैं।

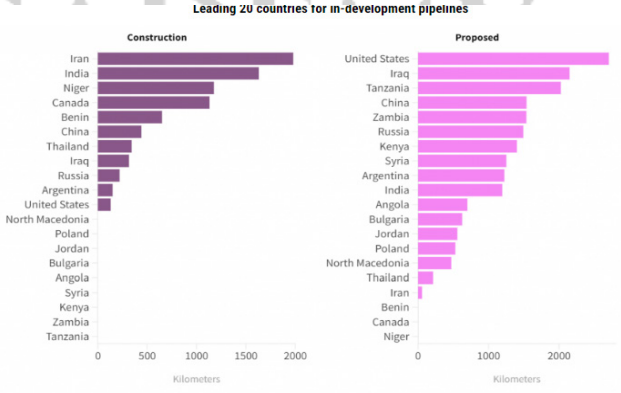

- साथ ही, इन क्षेत्रों में 59.8 बिलियन डॉलर की अनुमानित लागत से 10,800 किमी पाइपलाइन बिछाने का प्रस्ताव है।
- अफ्रीका और मध्य पूर्व में कच्चे तेल के विस्तार को वैश्विक ऊर्जा मांग की अराजकता के लिए एक रामबाण के रूप में पंप किया गया है, जो रूस के बाहर तेल और गैस के लिए यूरोप की हाथापाई से बड़े हिस्से में संचालित है।
- बुनियादी ढाँचा महंगा है, और जैसे-जैसे दुनिया स्वच्छ ऊर्जा की ओर बढ़ रही है, वैसे-वैसे यह अटकी हुई संपत्तियों को पीछे छोड़ देगी।
- उदाहरण के लिए, तेल पाइपलाइनें फंसी हुई संपत्ति बन सकती हैं जब वे अब उपयोग में नहीं हैं और उनके आर्थिक जीवनकाल के अंत से पहले एक दायित्व के रूप में समाप्त हो सकती हैं।
- तेल संचरण पाइपलाइनों को विकसित करने वाली शीर्ष पांच कंपनियों में राज्य के स्वामित्व वाले उद्यमों के साथ-साथ निजी कंपनियां भी शामिल हैं: ईरान का पेट्रोलियम मंत्रालय, चीन का राष्ट्रीय पेट्रोलियम निगम, इराक का तेल मंत्रालय, भारत की नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड और फ्रांस की टोटल एनर्जी।
- भारत में, पारादीप नुमालीगढ़ क्रूड पाइपलाइन (निर्माणाधीन) और न्यू मुंद्रा-पानीपत ऑयल पाइपलाइन (प्रस्तावित) दुनिया की सबसे लंबी तेल पाइपलाइनों में से एक होंगी।

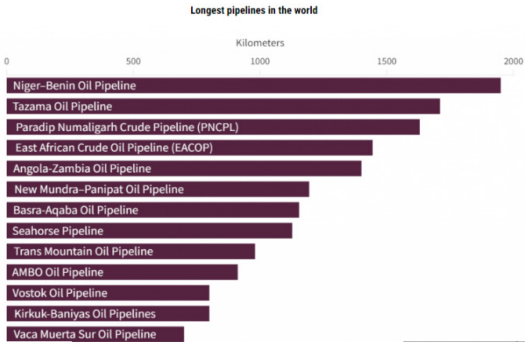

- पारादीप नुमालीगढ़ क्रूड पाइपलाइन पारादीप बंदरगाह में शुरू होगी। यह ओडिशा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार और असम से होकर गुजरेगी और असम में नुमालीगढ़ रिफाइनरी में समाप्त होगी।
- इस परियोजना का स्वामित्व असम में सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनी नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड के पास है। इसके 2024 में काम करना शुरू करने की उम्मीद है।
- प्रस्तावित नई मुंद्रा-पानीपत तेल पाइपलाइन गुजरात के कच्छ जिले के चुडवा में शुरू होगी और राजस्थान के नागौर, जालौर, झुंझुनू, सीकर, जोधपुर और पाली जिलों से होकर गुजरेगी, इसके बाद इंडियन ऑयल कंपनी लिमिटेड की पानीपत रिफाइनरी हरियाणा, भारत में समाप्त होगी।

हिंद महासागर सम्मेलन (IOC)

खबरों में क्यों

छठा हिंद महासागर सम्मेलन (IOC 2023) बांग्लादेश में हुआ।

महत्वपूर्ण बिंदु

- छठा IOC ढाका, बांग्लादेश में हुआ और इसका आयोजन इंडिया फाउंडेशन द्वारा विदेश मंत्रालय, बांग्लादेश सरकार और सिंगापुर में एस. राजारत्नम स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज के सहयोग से किया जा रहा है। सम्मेलन का विषय "शांत भविष्य के लिए शांति, समृद्धि और साझेदारी" है।
- सम्मेलन का उद्देश्य हिंद महासागर क्षेत्र को मजबूत करने के लिए प्रमुख हितधारकों की एक विशिष्ट सभा को एक साथ लाना है।
- बैठक में कम से कम 25 देशों के 150 उपस्थित हैं, लेकिन म्यांमार, वर्तमान में रोहिंग्या संकट के संबंध में अंतरराष्ट्रीय दबाव का सामना कर रहा है, उपस्थिति में नहीं है।
- बांग्लादेश सरकार ने संघर्ष-मुक्त वातावरण सुरक्षित करने के लिए हिंद महासागर क्षेत्र के सदस्यों के बीच समुद्री कूटनीति पर ध्यान केंद्रित किया जो क्षेत्रीय समृद्धि में योगदान कर सकता है।
- बांग्लादेश सरकार भी आईओआर में "शांति की संस्कृति" को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल देती है।

- बांग्लादेश म्यांमार में रोहिंग्या शरणार्थियों की वापसी की सुविधा के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से सहायता का अनुरोध करता है।

भारत की भूमिका

- विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने जोर देकर कहा कि इंडो पैसिफिक का विजन 21वीं सदी में एक वास्तविकता बन गया है।
- उन्होंने बांग्लादेश की राजधानी में छठे हिंद महासागर सम्मेलन-2023 के दौरान यह बयान दिया, जहां उन्होंने बांग्लादेश की "इंडो पैसिफिक आउटलुक" की हालिया घोषणा को भी स्वीकार किया और उन देशों के खिलाफ चेतावनी दी जो इस क्षेत्र की प्रगति को बाधित करने की कोशिश करते हैं।
- जयशंकर ने कहा कि इंडो-पैसिफिक समकालीन वैश्वीकरण का प्रतिनिधित्व करता है, और 1945 में स्थापित ढांचे से प्रस्थान करता है, जिसे बनाए रखने में कुछ देशों का अभी भी निहित स्वार्थ है।

IOC में भारत का दृष्टिकोण

- हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) में कनेक्टिविटी में सुधार और वृद्धि करना देशों की प्राथमिकता होनी चाहिए।
- भारत ने इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन (IORA), इंडियन जैसे समर्पित निकायों के माध्यम से IOR की प्रगति के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाई है।
- महासागर नौसेना संगोष्ठी (IONS), नेबरहुड फर्स्ट नीति आदि।

हिंद महासागर सम्मेलन- IOC के बारे में:

- हिंद महासागर सम्मेलन (IOC) 2016 में शुरू किया गया था और पिछले छह वर्षों में यह क्षेत्रीय मामलों में क्षेत्र के देशों के लिए प्रमुख परामर्शी मंच के रूप में उभरा है।
- सम्मेलन क्षेत्र के महत्वपूर्ण राज्यों और प्रमुख समुद्री भागीदारों को एक साझा मंच पर एक साथ लाने का प्रयास करता है ताकि क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास (सागर) के लिए क्षेत्रीय सहयोग की संभावनाओं पर विचार-विमर्श किया जा सके।
- सम्मेलन का पहला संस्करण 2016 में सिंगापुर में आयोजित किया गया था। इसमें मंत्रियों, राजनीतिक नेताओं, राजनयिकों, रणनीतिक विचारकों, शिक्षाविदों और मीडिया सहित 22 देशों के 300 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया था।
- दूसरा IOC 2017 में कोलंबो, श्रीलंका में आयोजित किया गया था और इसमें 40 से अधिक देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तीसरे IOC की मेजबानी 2018 में हनोई, वियतनाम में की गई थी और इसमें 44 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था।
- IOC के चौथे संस्करण की मेजबानी 2019 में मालदीव में की गई थी और इसे 36 देशों के वक्ताओं ने संबोधित किया था और इसमें 40 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था।
- IOC के पांचवें संस्करण का आयोजन 2021 में अबू धाबी, UAE में किया गया था और इसे 21 देशों के 37 वक्ताओं ने संबोधित किया था।

शंघाई सहयोग संगठन

खबरों में क्यों

एससीओ सदस्यों ने डिजिटल पब्लिक इन्फ्रा के लिए भारत के प्रस्ताव को अपनाया

महत्वपूर्ण बिंदु

- एससीओ देशों ने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (डीपीआई) के विकास के लिए भारत के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है।
- भारत ने आधार, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, डिजिलॉकर और कोविन जैसी डिजिटल तकनीकों और सेवाओं तक पहुंच बढ़ाने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण प्रगति करना जारी रखा है।
- भारतीय मंत्री ने शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के सदस्य देशों के आईसीटी मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की जहां उन्होंने सर्वसम्मति से भारत के प्रस्ताव को अपनाया।
- DPI यह सुनिश्चित करने के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है कि प्रौद्योगिकी का लोकतांत्रीकरण हो।
- सदस्य राज्यों द्वारा विकसित की जा रही विभिन्न प्रणालियों के बीच अंतःसंचालनीयता की आवश्यकता महसूस की गई और निकाय ने सदस्य राज्यों के बीच डिजिटल प्रणालियों की अंतरसंचालनीयता के लिए सामान्य मानक स्थापित करने के लिए एक संगठन स्थापित करने की आवश्यकता को पहचाना।
- नेशनल पेमेंट्स कोऑपरेशन ऑफ इंडिया के आंकड़ों से पता चलता है कि यूपीआई लेनदेन किए गए।
- 2021 में, UPI प्लेटफॉर्म ने 71.54 लाख करोड़ रुपये की राशि के 38 बिलियन से अधिक लेनदेन को संभाला।
- भारत के कोविड-19 टीकाकरण ऐप CoWin का उपयोग करके अब तक 2.2 बिलियन खुराक दी जा चुकी है।

- इंडिया स्टैक, जो इन डिजिटल संपत्तियों का विवरण देता है, "ओपन एपीआई और डिजिटल पब्लिक गुड्स का एक सेट है, जिसका उद्देश्य आबादी के पैमाने पर पहचान, डेटा और भुगतान की आर्थिक प्राथमिकताओं को अनलॉक करना है।
- हालांकि इस परियोजना के नाम में इंडिया शब्द है, इंडिया स्टैक का विजन एक देश तक सीमित नहीं है; इसे किसी भी राष्ट्र पर लागू किया जा सकता है, चाहे वह विकसित देश हो या उभरता हुआ।
- सरकार ने पहले कहा है कि कई देशों ने इंडिया स्टैक में रुचि दिखाई है।
- भारत ने दूर-दराज के इलाकों में गांवों तक मोबाइल कनेक्टिविटी पहुंचाने के लिए 3 अरब डॉलर और सभी 250 हजार ग्रामीण परिषदों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी लाने के लिए 5 अरब डॉलर के निवेश के बारे में एससीओ सदस्य देशों के साथ साझा किया।
- इंडिया स्टैक के प्रमुख परिणामों में से एक यूपीआई है, जिसने भारत में भुगतान प्रणाली को बदल दिया है, वित्तीय समावेशन मीट्रिक को 5% चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर से आगे बढ़ाया है।
- अन्य देशों में यूपीआई का निर्यात उल्लेखनीय रूप से बढ़ा है, एनपीसीआई की अंतरराष्ट्रीय शाखा ने यूके, यूएई, सिंगापुर, मलेशिया, हांगकांग, भूटान, नेपाल जैसे देशों के साथ भागीदारी की है।
- डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के विकास के लिए भारत के प्रस्ताव को अपनाने के लिए एससीओ सदस्य राज्यों द्वारा हाल ही में हस्ताक्षर, वैश्विक स्तर पर डिजिटल रूप से समावेशी विकास की दिशा में भारत के प्रयासों की एक महत्वपूर्ण मान्यता है।

एससीओ के बारे में

- एससीओ समूह में कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान, उजबेकिस्तान और भारत शामिल हैं। इसके चार पर्यवेक्षक राज्य भी हैं - अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान और मंगोलिया। इसके अलावा, अंतर-सरकारी निकाय में छह डायलॉग पार्टनर भी हैं, जैसे आर्मेनिया, अजरबैजान, कंबोडिया, नेपाल, श्रीलंका और तुर्की।
- एससीओ एक स्थायी अंतरसरकारी अंतरराष्ट्रीय संगठन है।
- यह एक यूरेशियन राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य संगठन है जिसका उद्देश्य क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखना है।
- इसे 2001 में बनाया गया था।

- एससीओ चार्टर पर 2002 में हस्ताक्षर किए गए थे, और 2003 में लागू हुआ।
- 2001 में अपनी स्थापना के बाद से, एससीओ ने मुख्य रूप से क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दों, क्षेत्रीय आतंकवाद, जातीय अलगाववाद और धार्मिक उग्रवाद के खिलाफ लड़ाई पर ध्यान केंद्रित किया है।
- आज तक, एससीओ की प्राथमिकताओं में क्षेत्रीय विकास भी शामिल है।
- एससीओ 2005 से संयुक्त राष्ट्र महासभा में पर्यवेक्षक रहा है।
- अप्रैल 2010 में, संयुक्त राष्ट्र और एससीओ सचिवालयों ने सहयोग पर एक संयुक्त घोषणापत्र पर हस्ताक्षर किए।

फिलिस्तीनी

खबरों में क्यों

संयुक्त राष्ट्र पहली बार 1948 की फिलिस्तीनी 'तबाही' को मनाने के लिए

महत्वपूर्ण बिंदु

- पहली बार, संयुक्त राष्ट्र आधिकारिक रूप से सैकड़ों हज़ारों फ़िलिस्तीनियों के पलायन की 75वीं वर्षगांठ पर, जो अब इसराइल है, उनकी उड़ान की याद में मनाएगा - संयुक्त राष्ट्र द्वारा ब्रिटिश शासित फ़िलिस्तीन के अलग यहूदी में विभाजन से उपजी एक कार्रवाई और अरब राज्य।
- फ़िलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास यू.एन. के उस स्मरणोत्सव को सुर्ख़ियों में रख रहे हैं जिसे फ़िलिस्तीनी "नकबा" या "तबाही" कहते हैं।
- फिलिस्तीनी संयुक्त राष्ट्र के राजदूत, ने संयुक्त राष्ट्र के पालन को "ऐतिहासिक" और महत्वपूर्ण कहा क्योंकि महासभा ने फिलिस्तीन के विभाजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
- फ़िलिस्तीनियों के पास अभी भी एक स्वतंत्र राज्य नहीं है, और उन्हें अपने घरों में लौटने का अधिकार नहीं है जैसा कि दिसंबर 1948 में अपनाए गए महासभा के प्रस्ताव में कहा गया था।
- महासभा, जिसके 1947 में 57 सदस्य राष्ट्र थे, ने फिलिस्तीन को 33-13 मतों से विभाजित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी जिसमें 10 अनुपस्थित थे।
- यहूदी पक्ष ने संयुक्त राष्ट्र विभाजन योजना को स्वीकार कर लिया और 1948 में ब्रिटिश शासनादेश समाप्त होने के बाद, इज़राइल ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की।
- अरबों ने योजना को खारिज कर दिया और पड़ोसी अरब देशों ने यहूदी राज्य के खिलाफ युद्ध शुरू कर दिया।
- नकबा अनुमानित 700,000 फ़िलिस्तीनियों को याद करता है जो 1948 में अपने घरों से भाग गए थे या उन्हें मजबूर कर दिया गया था।
- इन शरणार्थियों और उनके वंशजों का भाग्य - पूरे मध्य पूर्व में अनुमानित 5 मिलियन से अधिक - अरब-इजरायल संघर्ष में एक प्रमुख विवादित मुद्दा बना हुआ है।

- इजरायल लंबे समय से खोए हुए घरों में शरणार्थियों की सामूहिक वापसी की मांग को खारिज करता है, यह कहते हुए कि इससे देश के यहूदी चरित्र को खतरा होगा।
- जैसे-जैसे 75वीं वर्षगांठ नजदीक आ रही है, अब 193-सदस्यीय महासभा ने पिछले साल 90-30 मतों से एक प्रस्ताव को मंजूरी दे दी, जिसमें 47 लोगों ने भाग नहीं लिया और फ़िलिस्तीनी लोगों के अयोग्य अधिकारों के प्रयोग पर संयुक्त राष्ट्र समिति से एक उच्च-स्तरीय कार्यक्रम आयोजित करने का अनुरोध किया। नकबा को याद करने के लिए।
- संयुक्त राज्य अमेरिका उन देशों में शामिल था जो प्रस्ताव के खिलाफ मतदान में इजरायल में शामिल हुए थे, और अमेरिकी मिशन ने कहा कि कोई भी अमेरिकी राजनयिक सोमवार के स्मरणोत्सव में शामिल नहीं होगा।
- एक राज्य के रूप में संयुक्त राष्ट्र की मान्यता ने फिलिस्तीनियों को संधियों में शामिल होने, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, जो कि संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च न्यायाधिकरण है, में इजरायल के कब्जे के खिलाफ मामलों को ले जाने और 2019 में 77 के समूह की अध्यक्षता करने में सक्षम बनाया। 134 मुख्य रूप से विकासशील देशों और चीन के संयुक्त राष्ट्र गठबंधन।
- नकबा स्मरणोत्सव तब आता है जब इजरायल-फिलिस्तीनी लड़ाई बढ़ गई है।

फिलिस्तीन के बारे में

- फ़िलिस्तीन 1922 में राष्ट्र संघ द्वारा ब्रिटेन के प्रशासन के तहत रखे गए पूर्व तुर्क क्षेत्रों में से एक था।
- फ़िलिस्तीन को छोड़कर, ये सभी क्षेत्र अंततः पूरी तरह से स्वतंत्र राज्य बन गए, जहाँ "प्रशासनिक सहायता और सलाह प्रदान करने" के अलावा, ब्रिटिश शासनादेश ने 1917 के "बाल्फ़ोर घोषणा" को शामिल किया, जिसमें "यहूदी लोगों के लिए एक राष्ट्रीय घर की फ़िलिस्तीन में स्थापना" के लिए समर्थन व्यक्त किया गया था।"
- अधिदेश के दौरान, 1922 से 1947 तक, मुख्य रूप से पूर्वी यूरोप से बड़े पैमाने पर यहूदी आप्रवासन हुआ, 1930 के दशक में नाजी उत्पीड़न के साथ संख्या में वृद्धि हुई।
- स्वतंत्रता के लिए अरब की मांगों और अप्रवासन के प्रतिरोध के कारण 1937 में एक विद्रोह हुआ, जिसके बाद दोनों ओर से आतंकवाद और हिंसा जारी रही।
- यूके ने हिंसा से तबाह देश को आजादी दिलाने के लिए विभिन्न फॉर्मूलों पर विचार किया।
- 1947 में, यूके ने फ़िलिस्तीन समस्या को संयुक्त राष्ट्र को सौंप दिया।

G7 हिरोशिमा शिखर सम्मेलन

खबरों में क्यों

सबसे शक्तिशाली लोकतंत्रों में से सात के नेता इस सप्ताह के अंत में हिरोशिमा में सात शिखर सम्मेलन के समूह के लिए एकत्रित होंगे

महत्वपूर्ण बिंदु

- नेताओं से न केवल अर्थशास्त्र, बल्कि राजनीति और रूस के फरवरी 2022 में यूक्रेन पर पूर्ण पैमाने पर आक्रमण पर चर्चा करने की उम्मीद है।
- चीन, जो विवादित दक्षिण चीन सागर और स्व-शासित ताइवान पर अपने दावों में तेजी से मुखर हो गया है, उत्तर कोरिया के हथियारों के परीक्षण के साथ-साथ एक मुद्दा होने की भी संभावना है।

G7: एक नज़र में और उससे आशाएं:

G7 शिखर सम्मेलन क्या है?

- G7 प्रमुख औद्योगिक लोकतंत्रों का एक अनौपचारिक समूह है जिसका कोई स्थायी सचिवालय या कानूनी दर्जा नहीं है।
- इसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल हैं।
- इस समूह की स्थापना - G6 के रूप में - 1973 के तेल संकट के बाद वैश्विक आर्थिक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए सबसे अमीर देशों के लिए एक मंच के रूप में की गई थी। इसके देशों का संयुक्त वार्षिक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) $40 ट्रिलियन है - जो विश्व अर्थव्यवस्था का आधा हिस्सा है।
- संस्थापक सदस्यों ने 1975 में फ्रांस में अपना पहला शिखर सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें इस बात पर चर्चा की गई कि तेल उत्पादन कार्टेल, ओपेक द्वारा लगाए गए प्रतिबंध के बाद आई गहरी मंदी से कैसे निपटा जाए।
- कनाडा एक साल बाद सातवां सदस्य बना।
- रूस 1998 में G8 के गठन में शामिल हुआ, लेकिन मास्को द्वारा 2014 में क्रीमिया पर कब्जा करने के बाद उसे निष्कासित कर दिया गया था।
- शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता सात सदस्यों के बीच होती है, और इस वर्ष जापान की मेजबानी की बारी है। 2024 में, यह इटली होगा।
- यूरोपीय संघ (ईयू) के दो प्रतिनिधि भी शामिल होते हैं, और हाल के वर्षों में कुछ गैर-जी7 देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के नेताओं के कुछ सत्रों में भाग लेने की प्रथा बन गई है।
- नेता आर्थिक नीति, सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा और लिंग सहित कई मुद्दों पर चर्चा करते हैं।

भागीदार

- इस वर्ष, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कोमोरोस (अफ्रीकी संघ का अध्यक्ष), कुक आइलैंड्स (प्रशांत द्वीप समूह फोरम का अध्यक्ष), भारत (G20 अध्यक्ष), इंडोनेशिया (दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ का अध्यक्ष), दक्षिण कोरिया के नेता और वियतनाम को आमंत्रित किया गया है, जो जापानी प्रधान मंत्री फुमियो किशिदा के विकासशील देशों, साथ ही साथ अमेरिकी सहयोगियों और भागीदारों तक पहुंचने के महत्व पर जोर देता है।
- G7 के बाहर के नेताओं को निमंत्रण व्यापक श्रेणी के देशों में सहयोग बढ़ाने के लिए हैं।
- लेकिन ब्राजील, चीन और भारत सहित राष्ट्रों के आर्थिक विस्तार (ब्रिक्स समूह के सभी सदस्य जिसमें रूस और दक्षिण अफ्रीका भी शामिल हैं) ने G7 की प्रासंगिकता और विश्व अर्थव्यवस्था का नेतृत्व करने में इसकी भूमिका के बारे में सवाल उठाए हैं जो तेजी से धनी देशों से परे विकास पर निर्भर है।
- संयुक्त राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, विश्व बैंक, विश्व स्वास्थ्य संगठन और विश्व व्यापार संगठन के नेता भी अतिथि सूची में हैं।

चर्चा का विषय

- शिखर सम्मेलन यूक्रेनी राष्ट्रपति वलोडिमिर ज़ेलेंस्की द्वारा जी7 के कई नेताओं से मिलने के लिए यूरोप के चारों ओर एक बवंडर यात्रा पूरी करने के कुछ ही दिनों बाद हो रहा है।
- ज़ेलेंस्की के दौरे का उद्देश्य मॉस्को की सेना द्वारा कब्जा की गई भूमि को पुनः प्राप्त करने के लिए व्यापक रूप से प्रत्याशित जवाबी हमले से पहले राजनीतिक समर्थन का निर्माण करना और नए हथियारों की प्रतिबद्धता हासिल करना था।
- उम्मीद है कि G7 नेता यूक्रेन के खिलाफ रूस के युद्ध की कड़ी निंदा करेंगे और साथ ही यूक्रेन के लिए अपना समर्थन जारी रखने का संकल्प भी लेंगे। ज़ेलेंस्की इंटरनेट के माध्यम से सत्र में शामिल होंगे।
- यूक्रेन के लिए समर्थन और रूस के खिलाफ प्रतिबंध चर्चा के मुख्य विषय होंगे।
- ताइवान के खिलाफ बीजिंग के बढ़ते खतरों पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा, स्व-शासित लोकतांत्रिक द्वीप बीजिंग अपना दावा करता है, और चीन पर पश्चिमी लोकतंत्रों की आर्थिक और आपूर्ति श्रृंखला निर्भरता को कम करने के तरीके।
- सात नेताओं ने यह भी संकेत दिया है कि तीन दिवसीय वार्षिक शिखर सम्मेलन के एजेंडे में चीन के दंडात्मक व्यापार उपायों का उपयोग अधिक होगा।
- हाल के वर्षों में एशिया प्रशांत और यूरोप में चीन द्वारा ज़बरदस्त आर्थिक चालों का उपयोग बढ़ती चिंता का विषय रहा है, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और लिथुआनिया सभी को बीजिंग के साथ कोविड की उत्पत्ति से संबंधित मुद्दों पर विवादों के बाद व्यापार प्रतिबंधों का सामना करना पड़ रहा है। -19 महामारी ताइवान के लिए।
- विकासशील देशों के लिए, जिसमें पश्चिमी शक्तियों के कई पूर्व उपनिवेश शामिल हैं, जिनके रूस और चीन के साथ संबंध और संबंध अलग-अलग हैं, G7 स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा और बुनियादी ढांचे में अधिक सहायता की पेशकश करने के लिए तैयार है ताकि घनिष्ठ संबंधों को मजबूत किया जा सके।
- विकसित देशों ने 2009 में 2020 और 2025 के बीच तेजी से गंभीर जलवायु से जुड़े प्रभावों और आपदाओं से प्रभावित संवेदनशील राज्यों को $100bn सालाना हस्तांतरित करने का वादा किया था - लेकिन वह लक्ष्य कभी पूरा नहीं हुआ।

- ब्रिटिश एनजीओ ऑक्सफैम के अनुसार, अमीर जी7 देशों पर गरीबों को लगभग 13 ट्रिलियन डॉलर की अवैतनिक विकास सहायता और साथ ही जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में सहायता का बकाया है।
- मूल रूप से एजेंडे में नहीं, जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) चैटबॉट चैटजीपीटी का तेजी से विकास का मतलब है कि जी7 नेता अब इसके द्वारा उठाए गए मुद्दों की अनदेखी नहीं कर सकते हैं।

स्थल का चुनाव

- हिरोशिमा को दुनिया भर में परमाणु हथियार से प्रभावित होने वाले पहले शहर के रूप में जाना जाता है।
- 1945 की बमबारी ने द्वितीय विश्व युद्ध को समाप्त करने में मदद की, लेकिन हिरोशिमा और नागासाकी को तबाह कर दिया, जिससे हजारों नागरिक मारे गए।
- हिरोशिमा के लिए जगह का चुनाव शिखर सम्मेलन के एजेंडे के शीर्ष पर परमाणु निरस्त्रीकरण और अप्रसार को रखने के उनके दृढ़ संकल्प को दर्शाता है।
- यूक्रेन में रूस के हालिया परमाणु हथियारों के खतरों के साथ-साथ उत्तर कोरिया के बार-बार बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षणों और ईरान द्वारा अपने परमाणु कार्यक्रम के विस्तार के साथ परमाणु निरस्त्रीकरण का मार्ग अधिक कठिन दिखाई दिया है।

FIPIC शिखर सम्मेलन

खबरों में क्यों

तीसरा भारत-प्रशांत द्वीप सहयोग मंच (FIPIC) शिखर सम्मेलन 2023, पीएम मोदी ने प्रशांत द्वीप राष्ट्रों के नेताओं के साथ बातचीत की।

महत्वपूर्ण बिंदु

- पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पैर छूना काफी चर्चा का विषय बना है।
- यह भारत-प्रशांत द्वीप सहयोग फोरम (FIPIC) शिखर सम्मेलन, 2023 के लिए भारत के प्रधान मंत्री द्वारा देश की अपनी पहली यात्रा के लिए राजधानी शहर पोर्ट मोरेस्बी में उतरने के ठीक बाद हुआ।

FIPIC क्या है?

- नवंबर 2014 में भारतीय प्रधानमंत्री की फिजी यात्रा के दौरान फोरम फॉर इंडिया-पैसिफिक आइलैंड्स कोऑपरेशन (FIPIC) की शुरुआत की गई थी।
- FIPIC में 14 द्वीप देश शामिल हैं - कुक आइलैंड्स, फिजी, किरिबाती, मार्शल आइलैंड्स, माइक्रोनेशिया, नाउरू, नीयू, पलाऊ, पापुआ न्यू गिनी, समोआ, सोलोमन आइलैंड्स, टोंगा, तुवालु और वानुअतु - जो कि प्रशांत महासागर में स्थित हैं। ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व।

FIPIC के पीछे क्या विचार था?

- समूह की वेबसाइट के अनुसार, उनके अपेक्षाकृत छोटे आकार और भारत से काफी दूरी के बावजूद, इनमें से कई द्वीपों में बड़े विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र (EEZ) हैं।
- ईईजेड वह दूरी है जिस तक एक तटीय राष्ट्र का समुद्र पर अधिकार क्षेत्र है, जिसमें जीवित और निर्जीव दोनों संसाधन शामिल हैं। यह आम तौर पर किसी देश के प्रादेशिक समुद्र से 200 समुद्री मील या 230 मील (लगभग 370 किमी) तक जाता है।
- भारत का बड़ा ध्यान हिंद महासागर पर है जहां उसने एक प्रमुख भूमिका निभाने और अपने सामरिक और वाणिज्यिक हितों की रक्षा करने की मांग की है।

- FIPIC पहल तब प्रशांत क्षेत्र में भी भारत की भागीदारी का विस्तार करने के लिए एक गंभीर प्रयास का प्रतीक है।
- "हिंद-प्रशांत क्षेत्र में विकास" और "एक मुक्त, खुले और समावेशी भारत-प्रशांत के लिए दृष्टि" के संदर्भों को क्षेत्र में चीन के बढ़ते दावे से संबंधित माना जाता है।
- प्रधान मंत्री ने FIPIC शिखर सम्मेलन में भी कहा, "ज़रूरत में काम आने वाला दोस्त ही सच्चा दोस्त होता है", और 14 देशों के नेताओं से कहा कि जिन लोगों को वे भरोसेमंद मानते थे वे "ज़रूरत के समय हमारे पक्ष में नहीं खड़े थे" - फिर से ऐसा माना गया चीन का संदर्भ बनें।
- 2021-22 के आंकड़ों के आधार पर, प्लास्टिक, फार्मास्यूटिकल्स, चीनी, खनिज ईंधन और अयस्क जैसी वस्तुओं में भारत और प्रशांत द्वीप देशों के बीच कुल वार्षिक व्यापार $570 मिलियन का है।
- उनमें से पापुआ न्यू गिनी मूल्य के मामले में सबसे बड़ा व्यापार भागीदार है।

FIPIC समिट क्या है?

- यह आयोजित होने वाला तीसरा FIPIC शिखर सम्मेलन था।
- FIPIC-I, 2014 में, फिजी की राजधानी सुवा में आयोजित किया गया था।
- भारत ने जलवायु परिवर्तन, व्यापार, अर्थव्यवस्था, टेलीमेडिसिन और टेलीएजुकेशन, आईटी, सामुदायिक विकास परियोजनाओं के लिए अनुदान आदि के क्षेत्रों में विभिन्न विकास सहायता पहलों और अन्य सहयोग परियोजनाओं की घोषणा की।
- जयपुर में 2015 में FIPIC-II में, भारत ने फिर से इसी तरह की पहल की घोषणा की। भारत ने "दोनों श्रेणियों में विस्तारित और संशोधित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में छोटे द्वीप विकासशील राज्यों के लिए समर्पित सीट" की मांग करते हुए, एक बड़े कूटनीतिक दृष्टिकोण से भी इस कार्यक्रम का रुख किया।
- 2019 में, भारत-प्रशांत छोटे द्वीप विकासशील राज्यों (PSIDS) नेताओं की बैठक (14 प्रशांत द्वीप समूह देशों में से 12 के प्रतिनिधिमंडल शामिल हैं) 24 सितंबर, 2019 को न्यूयॉर्क में 74वें संयुक्त राष्ट्र महासभा के मौके पर आयोजित की गई थी।

- तब भारत सरकार ने उनकी पसंद के क्षेत्र में उच्च प्रभाव वाली विकासात्मक परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए $12 मिलियन अनुदान (प्रत्येक पीएसआईडीएस के लिए $1 मिलियन) के आवंटन की घोषणा की।
- इसके अलावा, प्रत्येक देश की आवश्यकता के आधार पर सौर, नवीकरणीय ऊर्जा और जलवायु संबंधी परियोजनाओं को शुरू करने के लिए पीएसआईडीएस द्वारा प्राप्त की जा सकने वाली $150 मिलियन की रियायती लाइन ऑफ क्रेडिट की घोषणा की गई।

FIPIC शिखर सम्मेलन 2023 में क्या हुआ?

- तीसरा FIPIC शिखर सम्मेलन 2020 की शुरुआत में आयोजित किया जाना था, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। अपनी समापन टिप्पणी के दौरान, प्रधान मंत्री ने निम्नलिखित पहलों की घोषणा की:
  - फिजी में एक सुपर स्पेशियलिटी कार्डियोलॉजी अस्पताल की स्थापना। भारत सरकार इस मेगा ग्रीनफील्ड परियोजना की पूरी लागत वहन करेगी।
  - सभी 14 प्रशांत द्वीप देशों को समुद्री एंबुलेंस प्रदान की जाएगी।
  - 2022 में, फिजी में एक जयपुर फुट कैंप आयोजित किया गया था जहां 600 से अधिक लोगों को कृत्रिम अंग मुफ्त में प्रदान किए गए थे। इसी तरह का फुट कैंप इस साल पापुआ न्यू गिनी में लगाया जाएगा और 2024 से प्रशांत द्वीप देशों में हर साल ऐसे दो कैंप आयोजित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री ने प्रत्येदक प्रशांत द्वीप देश के लोगों के लिए अलवणीकरण इकाइयां प्रदान करने का भी वचन दिया।

YOUR SUCCESS OUR PRIORITY
RAO'S ACADEMY

8 सरकारी योजना

संशोधित CGTMSE योजना

खबरों में क्यों

MSME के केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में सूक्ष्म और लघु उद्यमों (CGTMSE) योजना के लिए संशोधित क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट लॉन्च किया है।

महत्वपूर्ण बिंदु

- CGTMSE को वित्त वर्ष 2023-24 के केंद्रीय बजट में सूक्ष्म और लघु उद्यमों को 2 लाख करोड़ रुपये की अतिरिक्त गारंटी प्रदान करने के लिए अपनी योजना में सुधार के लिए 9,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त कॉर्पस समर्थन प्रदान किया गया है।
- तदनुसार, सुधार के प्रमुख उपाय शुरू किए गए और ऋणदाता संस्थानों को प्रसारित किए गए।
- संशोधनों में न्यूनतम गारंटी शुल्क को केवल 0.37% प्रति वर्ष के स्तर पर लाते हुए 1 करोड़ रुपये तक के ऋण के लिए गारंटी शुल्क में 50% की कमी शामिल है।
- एक और बड़े बदलाव की घोषणा की गई, गारंटी के लिए सीमा को 2 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपये करना और कानूनी कार्रवाई शुरू किए बिना दावा निपटान की सीमा को बढ़ाकर 10 लाख रुपये करना।
- यह भी घोषणा की गई थी कि CGTMSE MSME के लिए वित्तीय समावेशन केंद्र स्थापित करने के लिए राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम संस्थान (ni-msme) हैदराबाद के साथ सहयोग करेगा।

CGTMSE योजना के बारे में

- MSME मंत्रालय ने वित्तीय संस्थानों और बैंकों की जोखिम धारणा को कम करके सूक्ष्म और लघु उद्यमों को ऋण का बेहतर प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए 30 अगस्त 2000 को सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड योजना शुरू की।
- योजना को क्रियान्वित करने के लिए, भारत सरकार और सिडबी ने सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (CGTMSE) की स्थापना की।
- CGTMSE के कोष में सरकार और सिडबी द्वारा क्रमशः 4:1 के अनुपात में योगदान दिया जा रहा है।

विवाद से विश्वास I- MSME योजना के लिए राहत

खबरों में क्यों

वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) को COVID-19 अवधि के लिए राहत प्रदान करने के लिए "विवाद से विश्वास I – MSMEs को राहत" योजना शुरू की है।

महत्वपूर्ण बिंदु

- केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा केंद्रीय बजट 2023-24 में इस योजना की घोषणा की गई थी। केंद्रीय बजट भाषण के पैरा 66 में श्रीमती सीतारमण ने घोषणा की थी:-
- "MSMEs द्वारा COVID अवधि के दौरान अनुबंधों को निष्पादित करने में विफलता के मामलों में, बोली या प्रदर्शन सुरक्षा से संबंधित जब्त की गई राशि का 95 प्रतिशत सरकार और सरकारी उपक्रमों द्वारा उन्हें वापस कर दिया जाएगा। इससे MSME को राहत मिलेगी"।
- कोविड-19 महामारी, मानव इतिहास के सबसे बड़े संकटों में से एक, का अर्थव्यवस्था, विशेष रूप से MSME पर विनाशकारी प्रभाव पड़ा है। इस योजना के तहत प्रदान की जाने वाली राहत MSME क्षेत्र को बढ़ावा देने और बनाए रखने में सरकार के प्रयासों के क्रम में है।
- इस योजना के तहत, मंत्रालयों को प्रदर्शन सुरक्षा, बोली सुरक्षा और COVID-19 महामारी के दौरान ज़ब्त/कटौती किए गए नुकसान को वापस करने के लिए कहा गया है। COVID-19 अवधि के दौरान अनुबंधों के निष्पादन में चूक के लिए प्रतिबंधित MSMEs को भी कुछ राहत प्रदान की गई है।
- वित्त मंत्रालय ने इस योजना के माध्यम से, COVID-19 अवधि के दौरान प्रभावित पात्र MSMEs को निम्नलिखित अतिरिक्त लाभ देने का निर्णय लिया:
  - जब्त की गई प्रदर्शन सुरक्षा का 95% वापस किया जाएगा।
  - बोली सुरक्षा का 95% वापस किया जाएगा।
  - परिनिर्धारित नुकसान (एलडी) का 95% काटा गया वापस किया जाएगा।
  - वसूली गई जोखिम खरीद राशि का 95% वापस किया जाएगा।
  - यदि किसी फर्म को केवल ऐसे अनुबंधों के निष्पादन में चूक के कारण प्रतिबंधित किया गया है, तो खरीद इकाई द्वारा उचित आदेश जारी करके इस तरह के प्रतिबंध को भी रद्द कर दिया जाएगा।

हालांकि, अगर किसी फर्म को अंतरिम अवधि (यानी इस आदेश के तहत प्रतिबंधित करने की तारीख और निरस्त करने की तारीख) में प्रतिबंध के कारण किसी अनुबंध की नियुक्ति के लिए नजरअंदाज कर दिया गया है, तो कोई दावा नहीं किया जाएगा।

- ऐसी वापस की गई राशि पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा।

विवाद से विश्वास योजना I के लिए पात्रता

- "विवाद से विश्वास I - MSMEs के लिए राहत" योजना के तहत, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) को किसी भी विभाग, मंत्रालय, संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालय द्वारा वस्तुओं और सेवाओं की खरीद के लिए सभी अनुबंधों में राहत प्रदान की जाएगी। एक स्वायत्त निकाय, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (CPSE) या सार्वजनिक क्षेत्र की वित्तीय संस्था आदि, बशर्ते कि MSME निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करे:

1. आपूर्तिकर्ता या ठेकेदार को 31.03.2022 तक MSME मंत्रालय के साथ MSME के रूप में पंजीकृत होना चाहिए।
2. अनुबंध की मूल पूर्णता या डिलीवरी अवधि 19.02.2020 और 31.03.2022 के बीच आती है।

इस राहत का उद्देश्य COVID-19 महामारी से प्रभावित MSMEs को सहायता प्रदान करना और इससे होने वाली वित्तीय कठिनाइयों को दूर करने में उनकी मदद करना है।

कृषि मैपर ऐप

खबरों में क्यों

हाल ही में केंद्रीय कृषि मंत्री ने कृषि मैपर ऐप का उद्घाटन किया।

महत्वपूर्ण बिंदु

- मंत्रालय ने वर्ष 2023-24 के लिए खाद्यान्न, दलहन और तिलहन के उत्पादन का राष्ट्रीय लक्ष्य क्रमशः 3320, 292.5 और 440 लाख टन निर्धारित किया है।
- भारत में 2022-23 में खाद्यान्न, दलहन, तिलहन और गन्ने का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ, जो क्रमशः 3235, 278, 400 और 4688 लाख टन अनुमानित है।
- सरसों मिशन ने पिछले तीन वर्षों में रेपसीड और सरसों का उत्पादन 40% बढ़ाकर 91.2 से 128.2 लाख टन कर दिया है।

ऐप के बारे में

- यह कृषि में भू-स्थानिक डेटा के लिए एक एकीकृत ऐप है।
- यह प्रयासों के दोहराव को कम करेगा और भारत में नवप्रवर्तकों को विश्लेषण के लिए तैयार डेटा उत्पाद प्रदान करेगा।
- यह क्रेडिट तक पहुंच को सुगम बनाएगा, क्षेत्र के लिए विभिन्न स्तरों पर ग्रेन्युलैरिटी के करीब रीयल-टाइम स्ट्रेस वॉच के साथ तनाव के तहत अलग-अलग भूमि पार्सल तक ड्रिल डाउन करने की क्षमता और लगभग रीयल-टाइम मूल्यांकन और दावों का प्रसंस्करण।
- यह भूमि आधारित हस्तक्षेप में मदद कर सकता है जैसे कि विभिन्न योजनाओं के तहत खेतों की जियोटैगिंग और फसल डेटा के साथ एकीकरण, विशेषताओं के साथ फसलों की मैपिंग और समय-समय पर फसल फेनोलॉजिकल स्टेज इम्पैक्ट असेसमेंट और क्लस्टर/जोग्राफी के प्रदर्शन के आधार पर तस्वीरें एकत्र करना बेंचमार्किंग और प्राकृतिक खेती रूपांतरणों की निगरानी करना।

सामाजिक सुरक्षा योजनाएं

खबरों में क्यों

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMJJBY), प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMSBY) और अटल पेंशन योजना (APY) ने सामाजिक सुरक्षा कवर प्रदान करने के 8 साल पूरे कर लिए हैं।

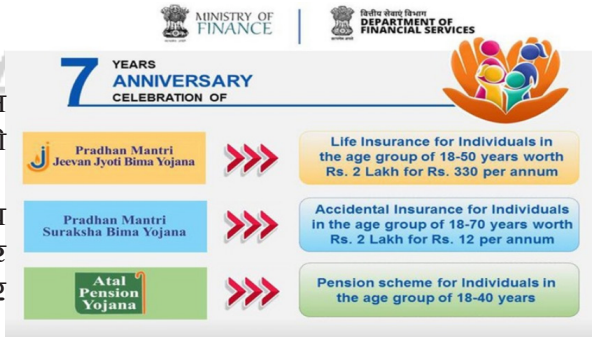

महत्वपूर्ण बिंदु

- तीन योजनाएं नागरिकों के कल्याण के लिए समर्पित हैं, जो मानव जीवन को अप्रत्याशित घटना और वित्तीय अनिश्चितताओं से सुरक्षित करने की आवश्यकता को पहचानती हैं।
- यह सुनिश्चित करने के लिए कि देश के असंगठित वर्ग के लोग वित्तीय रूप से सुरक्षित हैं, सरकार ने दो बीमा योजनाएं शुरू कीं-PMJJBY और PMSBY; और वृद्धावस्था में अत्यावश्यकताओं को कवर करने के लिए APY भी पेश किया।

1. प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY)

- योजना: PMJJBY एक साल की जीवन बीमा योजना है जो किसी भी कारण से मृत्यु के लिए कवरेज की पेशकश करने के लिए साल-दर-साल नवीकरणीय है।
- पात्रता: 18-50 वर्ष के आयु वर्ग के व्यक्ति जिनके पास एक व्यक्तिगत बैंक या डाकघर खाता है, वे इस योजना के तहत नामांकन के

पात्र हैं। 50 वर्ष की आयु पूरी करने से पहले योजना में शामिल होने वाले लोग नियमित प्रीमियम के भुगतान पर 55 वर्ष की आयु तक जीवन के जोखिम को जारी रख सकते हैं।

- लाभ: किसी भी कारण से मृत्यु के मामले में 436 रुपये प्रति वर्ष के प्रीमियम के बदले 2 लाख रुपये का जीवन बीमा।
- नामांकन: योजना के तहत नामांकन खाताधारक के बैंक की शाखा/BC पॉइंट या वेबसाइट पर जाकर या डाकघर बचत बैंक खाते के मामले में डाकघर में जाकर किया जा सकता है। योजना के तहत प्रीमियम खाताधारक के एकमुश्त शासनादेश के आधार पर ग्राहक के बैंक खाते से हर साल ऑटो डेबिट किया जाता है।
- उपलब्धियां: 26.04.2023 तक, योजना के तहत संचयी नामांकन 16.19 करोड़ से अधिक और रुपये की राशि रही है। 6,64,520 दावों के लिए 13,290.40 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है।

2. प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY)

- योजना: PMSBY एक साल की दुर्घटना बीमा योजना है जो दुर्घटना के कारण मृत्यु या विकलांगता के लिए कवरेज की पेशकश के लिए साल-दर-साल नवीकरणीय है।
- पात्रता: 18-70 वर्ष के आयु वर्ग के व्यक्ति जिनके पास एक व्यक्तिगत बैंक या डाकघर खाता है, वे इस योजना के तहत नामांकन के पात्र हैं।
- लाभ: दुर्घटना के कारण मृत्यु या विकलांगता के लिए 2 लाख रुपये का दुर्घटना मृत्यु सह विकलांगता कवर (आंशिक विकलांगता के मामले में 1 लाख रुपये) प्रति वर्ष 20/- रुपये के प्रीमियम के बदले।
- नामांकन: योजना के तहत नामांकन खाताधारक के बैंक की शाखा/बीसी पॉइंट या वेबसाइट पर या डाकघर बचत बैंक खाते के मामले में डाकघर में जाकर किया जा सकता है। योजना के तहत प्रीमियम खाताधारक के एकमुश्त शासनादेश के आधार पर ग्राहक के बैंक खाते से हर साल ऑटो डेबिट किया जाता है।
- उपलब्धियां: 26.04.2023 तक, योजना के तहत संचयी नामांकन 34.18 करोड़ से अधिक रहा है और 1,15,951 दावों के लिए 2,302.26 करोड़ रुपये की राशि का भुगतान किया गया है।

3. अटल पेंशन योजना (APY)

- पृष्ठभूमि: अटल पेंशन योजना (APY) सभी भारतीयों, विशेष रूप से गरीबों, वंचितों और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए एक सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा प्रणाली बनाने के लिए शुरू की गई थी।
- यह असंगठित क्षेत्र के लोगों के लिए वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने और भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सरकार की एक पहल है। APY को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के समग्र प्रशासनिक और संस्थागत ढांचे के तहत पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) द्वारा प्रशासित किया जाता है।
- पात्रता: APY 18 से 40 वर्ष की आयु के सभी बैंक खाता धारकों के लिए खुला है जो आयकर दाता नहीं हैं और चुने गए पेंशन राशि के आधार पर योगदान अलग-अलग हैं।
- लाभ: योजना में शामिल होने के बाद ग्राहक द्वारा किए गए योगदान के आधार पर, ग्राहकों को 60 वर्ष की आयु के बाद 1000 रुपये या 2000 रुपये या 3000 रुपये या 4000 रुपये या 5000 रुपये की गारंटीकृत न्यूनतम मासिक पेंशन प्राप्त होगी।
- योजना के लाभों का वितरण: मासिक पेंशन ग्राहक को उपलब्ध है, और उसके बाद उसके पति या पत्नी को और उनकी मृत्यु के बाद, ग्राहक के 60 वर्ष की आयु में संचित पेंशन राशि, ग्राहक के नामांकित व्यक्ति को वापस कर दी जाएगी।
- सब्सक्राइबर की असामयिक मृत्यु (60 वर्ष की आयु से पहले मृत्यु) के मामले में, सब्सक्राइबर का जीवनसाथी शेष निहित अवधि के लिए सब्सक्राइबर के APY खाते में योगदान जारी रख सकता है, जब तक कि मूल सब्सक्राइबर 60 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता।
- केंद्र सरकार द्वारा अंशदान: न्यूनतम पेंशन की गारंटी सरकार द्वारा दी जाएगी अर्थात, यदि योगदान के आधार पर संचित कोष निवेश पर अनुमानित रिटर्न से कम अर्जित करता है और न्यूनतम गारंटीकृत पेंशन प्रदान करने के लिए अपर्याप्त है, तो केंद्र सरकार इस तरह की अपर्याप्तता को वित्तपोषित करेगी। वैकल्पिक रूप से, यदि निवेश पर प्रतिफल अधिक है, तो अभिदाताओं को बढ़ा हुआ पेंशन लाभ मिलेगा।
- भुगतान की आवृत्ति: सदस्य मासिक/तिमाही/छमाही आधार पर APY में योगदान कर सकते हैं।
- योजना से निकासी: सरकारी सह-योगदान और उस पर वापसी/ब्याज की कटौती पर, कुछ शर्तों के अधीन सदस्य स्वैच्छिक रूप से APY से बाहर निकल सकते हैं।
- उपलब्धियां: 27.04.2023 तक 5 करोड़ से अधिक व्यक्तियों ने योजना की सदस्यता ली है।

थैलेसीमिया बाल सेवा योजना

खबरों में क्यों

स्वास्थ्य मंत्री ने थैलेसीमिया बाल सेवा योजना के तीसरे चरण का शुभारंभ किया

महत्वपूर्ण बिंदु

- केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री ने स्वास्थ्य मंत्रालय की थैलेसीमिया बाल सेवा योजना (TBSY) के तीसरे चरण का शुभारंभ किया, जिसे कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा समर्थित किया जा रहा है।

TBSY के बारे में

- थैलेसीमिया एक वंशानुगत रक्त विकार है जिसके कारण शरीर में हीमोग्लोबिन सामान्य से कम हो जाता है।
- केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के तहत 2017 से TBSY को लागू कर रहा है और हाल ही में मार्च 2023 में इसका दूसरा चरण पूरा किया था।

- कोल इंडिया CSR-वित्तपोषित हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांट (HSCT) कार्यक्रम एक अनूठी पहल है, जिसका उद्देश्य वंचित थैलेसीमिया रोगियों को एक बार इलाज का अवसर प्रदान करना है, जिनके पास एक मेल खाने वाला दाता है, लेकिन इलाज की लागत को कवर करने के लिए वित्तीय संसाधन नहीं हैं।
- कार्यक्रम ने दो चरणों के दौरान भारत में 10 सूचीबद्ध अस्पतालों में थैलेसीमिया रोगियों के लिए 356 अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण सफलतापूर्वक पूरा किया है।

थैलेसीमिया

- थैलेसीमिया एक आनुवंशिक रक्त विकार है जो आमतौर पर शरीर में हीमोग्लोबिन के असामान्य उत्पादन की विशेषता है।
- असामान्यता के कारण अनुचित ऑक्सीजन परिवहन और लाल रक्त कोशिकाओं का विनाश होता है।
- इसका मानव शरीर पर व्यापक प्रभाव पड़ता है जैसे लोहे की अधिकता, हड्डी की विकृति और गंभीर मामलों में हृदय रोग हो सकता है।
- इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है और थैलेसीमिया से पीड़ित लोगों को जीवन को लम्बा करने के लिए एक प्रभावी उपाय के रूप में नियमित रक्त संक्रमण की आवश्यकता होती है।

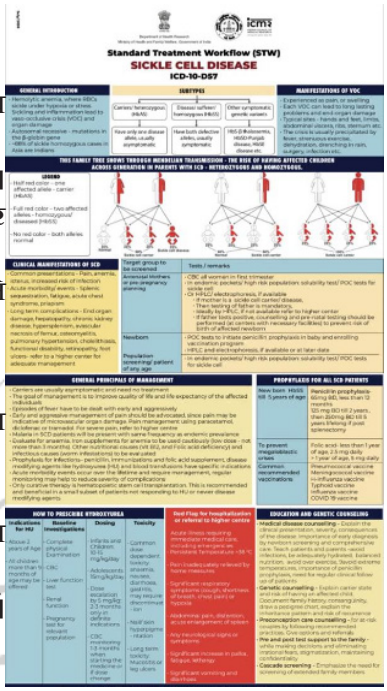

भारत की स्थिति

- भारत 40 मिलियन वाहकों और 1,00,000 से अधिक रोगियों के साथ विश्व की थैलेसीमिया राजधानी है।
- राष्ट्रीय स्तर पर कोई रोकथाम और नियंत्रण कार्यक्रम नहीं है।
- भारत में निवारक स्वास्थ्य जांच आदर्श नहीं होने के कारण, थैलेसीमिया से पीड़ित लोग अनजाने में अपने बच्चों को यह अनुवांशिक विकार दे रहे हैं।
- देश भर में 1,00,000 से अधिक रोगी उपचार की कमी के कारण 20 वर्ष की आयु से पहले ही मर जाते हैं।

ई-रक्तकोष पोर्टल

- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 2016 में ई-रक्तकोश पोर्टल लॉन्च किया गया था।
- यह एक केंद्रीकृत ब्लड बैंक प्रबंधन प्रणाली है जो पूरे देश में ब्लड बैंकों की मानक संचालन प्रक्रियाओं, दिशानिर्देशों और कार्यप्रवाह को मानकीकृत और सुव्यवस्थित करने के लिए एक व्यापक आईटी समाधान प्रदान करती है।

भारत E-MART

खबरों में क्यों

ONDC में शामिल होगा भारतीय डाक; CAIT, तृप्ता टेक्नोलॉजीज के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर

महत्वपूर्ण बिंदु

- भारतीय डाक ने 'भारत ईमार्ट' नामक एक पोर्टल के संचालन की सुविधा के लिए कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (CAIT) और तृप्ता टेक्नोलॉजीज के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
- समझौता 'भारत ईमार्ट' पोर्टल के संचालन की सुविधा प्रदान करता है, जो व्यापारियों के परिसरों से खेपों के पिक-अप की सुविधा प्रदान करेगा और देश भर में खेपों के दरवाजे पर डिलीवरी सुनिश्चित करेगा।
- CAIT से जुड़े अनुमानित आठ करोड़ व्यापारियों को समझौते से लाभ होगा।
- हाल के दिनों में इंडिया पोस्ट ने सरकार के E-मार्केटप्लेस (GeM) और ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (TRIFED) के क्षेत्रीय केंद्रों के साथ इसी तरह के समझौते किए हैं ताकि लोगों के घर पर पार्सल की पिक-अप और डिलीवरी प्रदान की जा सके।
- इंडिया पोस्ट जल्द ही खुद को ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ONDC) प्लेटफॉर्म पर भी शामिल कर लेगा, जिसे वाणिज्य मंत्रालय द्वारा एक रसद सेवा प्रदाता के रूप में विकसित किया जा रहा है।
- डाक विभाग ने समय बीतने और जनता की मांगों के साथ खुद को बदल दिया है और तकनीकी प्रवेश और नई सेवाओं के अतिरिक्त ने भारतीय डाक को एक आधुनिक सेवा प्रदाता बना दिया है।
- आज, यह 1.59 लाख डाकघरों के अपने नेटवर्क के माध्यम से हर गांव में सरकार द्वारा चलाई जा रही कई कल्याणकारी योजनाओं के लाभों का बैंकिंग, बीमा और अंतिम छोर तक वितरण प्रदान करता है।

भारत E-MART:

- Bharat E-Mart एक ई-कॉमर्स मार्केटप्लेस है जिसे कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (CAIT), इंडिया पोस्ट और तृप्ता टेक्नोलॉजीज द्वारा बनाया गया है।
- पोर्टल भारत में छोटे व्यापारियों को रसद सहायता प्रदान करता है, जिससे उनके व्यवसाय और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
- पोर्टल व्यापारियों के परिसरों से खेपों के पिक-अप की सुविधा प्रदान करता है और देश भर में खेपों के दरवाजे पर डिलीवरी सुनिश्चित करता है।

- पोर्टल से CAIT से जुड़े आठ करोड़ व्यापारियों को लाभ होने की उम्मीद है।
- भारत ईमार्ट पोर्टल के संचालन के माध्यम से इंडिया पोस्ट करोड़ों व्यापारियों के लिए लॉजिस्टिक्स पार्टनर बन गया है।

स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण

खबरों में क्यों

भारत के 50% गांवों ने चरण 2 में ODF+ स्थिति प्राप्त की

महत्वपूर्ण बिंदु

- स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण (SBM-G) पहल के तहत एक और उल्लेखनीय उपलब्धि, भारत के कुल गांवों में से 50% ने मिशन के दूसरे चरण के तहत ODF प्लस का दर्जा हासिल कर लिया है।
- एक ODF प्लस गांव वह गांव है जिसने ठोस या तरल अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों को लागू करने के अलावा सफलतापूर्वक अपने खुले में शौच मुक्त (ODF) स्थिति को बनाए रखा है।
- अब तक, 2.96 लाख से अधिक गांवों ने खुद को ओडीएफ प्लस घोषित किया है, जिसे 2024-25 तक SBM-G चरण II लक्ष्यों को साकार करने की दिशा में एक बहुत ही सकारात्मक विकास के रूप में देखा जा सकता है।
- स्वच्छ भारत मिशन नौ साल से चल रहा है, और 50% ODF प्लस गांवों के मील के पत्थर तक पहुंचना भारत के लिए एक उल्लेखनीय उपलब्धि है।
- यह उपलब्धि दर्शाती है कि भारत पूरी तरह से स्वच्छता हासिल करने के लिए केवल शौचालयों के निर्माण और उपयोग से आगे बढ़ चुका है, यानी ODF से ODF+ तक।
- ODF+ गांवों के उच्चतम प्रतिशत वाले राज्यों में 100% के साथ तेलंगाना, 99.5% के साथ कर्नाटक, 97.8% के साथ तमिलनाडु और 95.2% के साथ उत्तर प्रदेश हैं, जबकि शीर्ष प्रदर्शन करने वाले छोटे राज्य 95.3% के साथ गोवा और 69.2 के साथ सिक्किम हैं।
- केंद्र शासित प्रदेशों में, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दादरा नगर हवेली और दमन दीव और लक्षद्वीप ने 100% ODF+ मॉडल गांवों का लक्ष्य हासिल कर लिया है।
- इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने ओडीएफ प्लस का दर्जा हासिल करने में महत्वपूर्ण प्रगति की है, और उनके योगदान ने इस मील के पत्थर तक पहुंचने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

स्वच्छ भारत मिशन और SBM-G

- सार्वभौमिक स्वच्छता कवरेज की उपलब्धि में तेजी लाने और स्वच्छता के मुद्दों पर ध्यान आकर्षित करने के लिए, भारत के प्रधान मंत्री ने 2 अक्टूबर, 2014 को स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की।
- इस मिशन का उद्देश्य भारत के सभी गांवों, ग्राम पंचायतों, जिलों, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 2 अक्टूबर 2019 तक ग्रामीण भारत में 100 मिलियन से अधिक शौचालयों का निर्माण करके "खुले में शौच से मुक्त" (ODF) बनाना है, जो महात्मा गांधी की 150वीं जयंती है।
- खुले में शौच मुक्त स्थिति को बनाए रखने के लिए, यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई भी पीछे न छूटे, और ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन सुविधाओं तक पहुंच की गारंटी के लिए, मिशन ने ODF+ कहे जाने वाले SBGM के दूसरे चरण में संक्रमण किया था।
- स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के दूसरे चरण के तहत, ओडीएफ प्लस गतिविधियों का उद्देश्य ODF व्यवहार को सुदृढ़ करना और गांवों में ठोस और तरल कचरे के सुरक्षित निपटान के उपाय प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करना है।

ODF+ स्थिति की विभिन्न श्रेणियां

- कुल 296,928 ODF+ गांवों में से, 208,613 गांवों को ODF+ आकांक्षी माना जाता है, क्योंकि उन्होंने ठोस अपशिष्ट या तरल अपशिष्ट के प्रबंधन के उपायों को लागू किया है।
- इस बीच, 32,030 गांवों को ओडीएफ प्लस राइजिंग के रूप में वर्गीकृत किया गया है, क्योंकि उन्होंने ठोस अपशिष्ट और तरल अपशिष्ट प्रबंधन दोनों की व्यवस्था की है।
- शेष 56,285 गांवों ने उच्चतम श्रेणी हासिल की है, जिसे ओडीएफ प्लस मॉडल के रूप में जाना जाता है, जिसका अर्थ है कि उन्होंने अपनी खुले में शौच मुक्त स्थिति को बनाए रखा है, उनके पास ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन दोनों की व्यवस्था है और दृष्टिगत रूप से साफ हैं, जिनमें कूड़े या स्थिर अपशिष्ट जल का कोई संकेत नहीं है।
- इसके अलावा, ये गांव ओडीएफ प्लस सूचना, शिक्षा और संचार (IEC) संदेशों को भी प्रदर्शित करते हैं।
- अब तक, 165,048 गांवों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली स्थापित की जा चुकी है, 239,063 गांवों में तरल अपशिष्ट प्रबंधन उपायों को लागू किया गया है, 457,060 गांवों में न्यूनतम स्थिर पानी है और 467,384 गांवों में न्यूनतम कचरा है।

पोशन भी, पढाई भी

खबरों में क्यों

केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री ने मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के तहत प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा कार्यक्रम "पोषण भी, पढाई भी" का शुभारंभ किया

महत्वपूर्ण बिंदु

ECCE मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 (मिशन पोषण 2.0) का एक महत्वपूर्ण घटक है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत इसकी परिकल्पना की गई है।

पोषण भी पढाई भी कार्यक्रम क्या है?

- यह NEP 2020 के सुझाव के अनुसार भारत के पास दुनिया का सबसे बड़ा, सार्वभौमिक, उच्च गुणवत्ता वाला प्री-स्कूल नेटवर्क सुनिश्चित करने के लिए एक अग्रणी ECCE कार्यक्रम है।
- उद्देश्य न केवल आंगनवाड़ी केंद्रों को पोषण केंद्र बनाना है, बल्कि शिक्षा प्रदान करने वाले केंद्रों को भी बनाना है - दैनिक आधार पर कम से कम दो घंटे की उच्च गुणवत्ता वाली प्री-स्कूल शिक्षा प्रदान करना।
- इसके तहत, सरकार राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा में उल्लिखित हर क्षेत्र में बच्चों के विकास को लक्षित करेगी, जैसे शारीरिक और मोटर विकास, संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक-भावनात्मक-नैतिक विकास, आदि।
- यह विकासात्मक रूप से उपयुक्त शिक्षाशास्त्र के उपयोग को भी सुनिश्चित करेगा और प्राथमिक शिक्षा के साथ-साथ प्रारंभिक बाल्यावस्था स्वास्थ्य और पोषण सेवाओं के साथ संबंधों पर जोर देगा।
- यह देश की भावी पीढ़ियों की नींव को मजबूत करने में समुदायों को शामिल करने के लिए एक जन आंदोलन बनाने में मदद करेगा।

मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0:

- यह 15वें वित्त आयोग की अवधि 2021-22 से 2025-26 के दौरान कार्यान्वयन के लिए अनुमोदित एक एकीकृत पोषण सहायता कार्यक्रम है।
- यह बच्चों, किशोरियों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं में कुपोषण की चुनौतियों का समाधान निम्नलिखित के माध्यम से करना चाहता है-
  - पोषण सामग्री और वितरण में एक रणनीतिक बदलाव और
  - स्वास्थ्य, कल्याण और प्रतिरक्षा को पोषित करने वाली प्रथाओं को विकसित करने और बढ़ावा देने के लिए एक अभिसरण पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण।
- पोषण 2.0 के तहत मौजूदा घटकों (चल रहे पोषण कार्यक्रम के) को नीचे दिए गए प्राथमिक कार्यक्षेत्रों में पुनर्गठित (कार्यान्वयन में सुधार करने के लिए) किया गया है:
- बच्चों (06 महीने से 6 वर्ष), गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं (PWLM) के लिए पूरक पोषण कार्यक्रम (SNP) के माध्यम से पोषण सहायता; और आकांक्षी जिलों और उत्तर पूर्वी क्षेत्र (NER) में किशोरियों (14 से 18 वर्ष) के लिए;
- ECCE [3-6 वर्ष] और प्रारंभिक उत्तेजना (0-3 वर्ष);
- आधुनिक, उन्नत सक्षम आंगनवाड़ी सहित आंगनवाड़ी अवसंरचना; और
- पोशन अभियान: 2018 में लॉन्च किया गया, इसका फोकस किशोरियों, गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं और 0-6 वर्ष की आयु के बच्चों के पोषण की स्थिति पर जोर देना है।

भारत में आंगनवाड़ी:

- वैश्विक साक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए कि 85% मस्तिष्क विकास 6 वर्ष की आयु तक प्राप्त कर लिया जाता है, आंगनवाड़ी इको-सिस्टम बच्चों के आधार के निर्माण के लिए एक महत्वपूर्ण पहुंच बिंदु बन जाता है।
- देश भर में करीब 9 लाख संचालित आंगनवाड़ी केंद्र लगभग 8 करोड़ लाभार्थी बच्चों (6 वर्ष से कम आयु) को पूरक पोषण और प्रारंभिक देखभाल और शिक्षा प्रदान कर रहे हैं।
- यह इसे दुनिया में ऐसी सेवाओं का सबसे बड़ा सार्वजनिक प्रावधान बनाता है।
- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने ECCE को लागू करने के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण के लिए 600 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।
- राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान (NIPCCD) को आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण के लिए अनुबंधित किया गया है।

मिशन अमृत सरोवर

खबरों में क्यों

हाल ही में, मिशन अमृत सरोवर के तहत 50,000 से अधिक जल निकायों का समय से पहले कायाकल्प किया गया है।

महत्वपूर्ण बिंदु

- मिशन, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव के उत्सव के एक भाग के रूप में शुरू किया गया।
- इसका उद्देश्य 15 अगस्त, 2023 तक 50,000 'अमृत सरोवर' बनाने के लक्ष्य के साथ देश के प्रत्येक जिले में कम से कम 75 जल निकायों का कायाकल्प करना है।
- मंत्रालय ने कहा कि लक्ष्य निर्धारित समय से पहले हासिल कर लिया गया है और कहा, "अब तक, 50,071 'अमृत सरोवर' पूरा हो चुका है"।
- मिशन अमृत सरोवर के माध्यम से वर्षा जल संरक्षण और संचयन के संकल्प को प्राप्त करने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय ने नोडल मंत्रालय के रूप में कार्य किया।
- लुप्त होने की कगार पर पहुँच चुके जल निकायों के जीर्णोद्धार से लेकर नवीन जल निकायों के निर्माण तक विस्तृत कार्य योजना तैयार की गई।
- मिशन के सभी पहलुओं के दौरान 'संपूर्ण सरकार' दृष्टिकोण और 'जन भागीदारी' के माध्यम से किए गए प्रयासों के कारण 50,000 'अमृत सरोवर' का लक्ष्य समय से पहले प्राप्त किया जा सका।
- जिला प्रशासन, पंचायत राज अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों, पंचायतों,

स्वैच्छिक संगठनों, विभिन्न संस्थाओं और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जनभागीदारी के समन्वित प्रयासों से लगभग 1,05,243 स्थलों को 'अमृत सरोवर' के रूप में चिन्हित किया गया।

- इनमें से 72,297 स्थलों पर काम शुरू हो चुका है और 50,071 अमृत सरोवर पूरे हो चुके हैं।
- मिशन का उद्देश्य 'अमृत सरोवर' का निर्माण या नवीनीकरण इस तरह से करना है कि वे स्थानीय सामुदायिक गतिविधियों का केंद्र बन जाएं।
- प्रत्येक सरोवर के लिए एक उपयोगकर्ता समूह बनाया जा रहा है ताकि जल निकाय के रखरखाव में सामुदायिक स्वामित्व हो।
- अब तक 59,282 उपयोगकर्ता समूह 'सरोवर' को बनाए रखने और इससे अपनी आजीविका उत्पन्न करने के मिशन में शामिल हो चुके हैं।
- अब तक 1,784 स्वतंत्रता सेनानियों, शहीदों के 684 परिवारों, स्वतंत्रता सेनानियों के 448 परिवारों, पंचायतों के 18,173 वरिष्ठ सदस्यों और 56 पद्म पुरस्कार विजेताओं ने मिशन में भाग लिया है।

Saksham

खबरों में क्यों

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सक्षम लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम लॉन्च किया

महत्वपूर्ण बिंदु

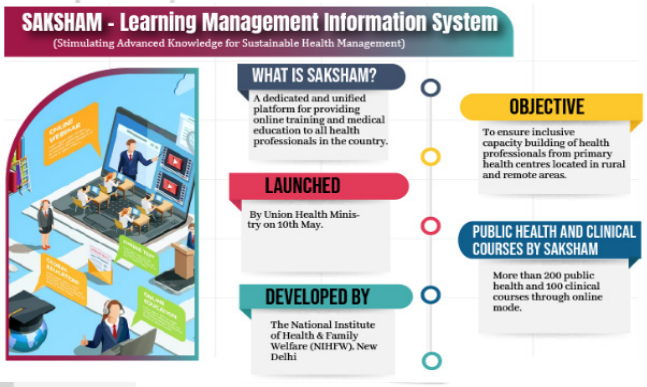

- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (MoHFW) की लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम (LMIS) जिसे SAKSHAM (सस्टेनेबल हेल्थ मैनेजमेंट के लिए उन्नत ज्ञान को उत्तेजित करना) कहा जाता है, केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव द्वारा लॉन्च किया गया था।
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान (NIHFW), नई दिल्ली द्वारा विकसित, डिजिटल प्लेटफॉर्म को भविष्य में सभी मिश्रित शिक्षण कार्यक्रमों के लिए उपयोग करने की कल्पना की गई है।
- आगे बढ़ते हुए, यह देश में प्रशिक्षित स्वास्थ्य पेशेवरों के एक केंद्रीय डेटाबेस के रूप में कार्य करेगा और इस क्षेत्र में केस-आधारित शिक्षा के लिए एक समर्थकारी के रूप में भी काम करेगा।

सक्षम के बारे में

- सक्षम भारत में सभी स्वास्थ्य पेशेवरों को चिकित्सा शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से एक एकीकृत और विशेष ऑनलाइन शिक्षण मंच है।
- यह डिजिटल प्रणाली प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में काम करने वालों के साथ-साथ महानगरीय शहरों में स्थित तृतीयक देखभाल और कॉर्पोरेट अस्पतालों में कार्यरत स्वास्थ्य पेशेवरों के व्यापक विकास की गारंटी देगी।
- विश्व स्तर पर प्रासंगिक ज्ञान प्राप्त करने में मदद करके स्वास्थ्य पेशेवरों को सकारात्मक रूप से प्रभावित करने के लिए डिज़ाइन किया गया, MoHFW की एक लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम (LMIS), सस्टेनेबल हेल्थ मैनेजमेंट के लिए उन्नत ज्ञान (SAKSHAM) को मानक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए एक मिशन पर काम करेगा। सार्वजनिक और निजी देखभाल उप-क्षेत्रों के क्षितिज में स्वास्थ्य कर्मचारी, ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में स्थित प्राथमिक देखभाल केंद्रों से लेकर महानगरीय शहरों में तृतीयक देखभाल और कॉर्पोरेट अस्पतालों तक के पेशेवर शामिल हैं।
- वर्तमान में सक्षम: LMIS ऑनलाइन मोड के माध्यम से 200 से अधिक सार्वजनिक स्वास्थ्य और 100 नैदानिक पाठ्यक्रमों की मेजबानी कर रहा है। स्वास्थ्य पेशेवर url: https://lmis.nihfw.ac.in/ के माध्यम से पोर्टल पर इन पाठ्यक्रमों के लिए खुद को पंजीकृत कर सकते हैं और अपेक्षित प्रशिक्षण प्राप्त करने और आवश्यक मूल्यांकन मानदंडों को पूरा करने के बाद प्रमाणन प्राप्त कर सकते हैं।
- यह ध्यान रखना उचित है कि पोर्टल में पेश किए जाने वाले पाठ्यक्रम WHO, UNICEF, UNDP, और प्रतिष्ठित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों सहित वैश्विक स्वास्थ्य एजेंसियों के सहयोग से विकसित किए गए हैं और संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञों द्वारा समीक्षा की गई और अनुमोदित भी हैं।

एक स्टेशन एक उत्पाद

खबरों में क्यों

रेलवे ने 'वन स्टेशन वन प्रोडक्ट' योजना के तहत स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं

महत्वपूर्ण बिंदु

- दक्षिण रेलवे ने केंद्र की 'वन स्टेशन वन प्रोडक्ट' (OSOP) योजना के तहत स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए इच्छुक कारीगरों, बुनकरों और अन्य पात्र व्यक्तियों से रुचि की अभिव्यक्ति (EoI) आमंत्रित की है।
- रेलवे ने केंद्र सरकार के 'वोकल फॉर लोकल' विजन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से OSOP की शुरुआत की, जो स्थानीय और स्वदेशी उत्पादों के लिए एक बाजार प्रदान करता है, जिससे समाज के वंचित वर्गों के लिए अतिरिक्त आय के अवसर पैदा होते हैं।
- इस साल मई तक, दक्षिण रेलवे के केरल अधिकार क्षेत्र में 20 OSOP स्टॉल खोले गए थे।
- इन OSOP स्टालों को एकरूपता के लिए राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान के माध्यम से डिज़ाइन किया गया है।
- OSOP योजना ने केरल में अपनी स्थापना के बाद से 202 लाभार्थियों के लिए व्यवसाय के अवसर भी प्रदान किए हैं।

RAO'S ACADEMY

- इस योजना के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए आउटलेट के आवंटन के लिए एक पारदर्शी तंत्र का पालन किया जा रहा है।
- इस प्रयोजन के लिए स्टेशन स्तर पर गठित समिति द्वारा ड्रा के आधार पर चयन किया जाता है।
- पात्र लाभार्थी आवेदन के साथ मामूली टोकन शुल्क के भुगतान पर 15 दिनों के लिए स्वदेशी उत्पादों को बेचने के लिए रेलवे स्टेशन पर स्टॉल लगा सकता है।
- OSOP आउटलेट चलाने का इच्छुक लाभार्थी विकास आयुक्त हस्तशिल्प, विकास आयुक्त हथकरघा या आवश्यक राज्य/केंद्र सरकार प्राधिकरण द्वारा जारी कारीगर/बुनकर ID कार्ड धारक होना चाहिए या ट्राइफेड/NHDC के साथ नामांकित/पंजीकृत व्यक्तिगत कारीगर/बुनकर/कारीगर/KVIC आदि या PMEGP के साथ पंजीकृत स्वयं सहायता समूह या समाज के हाशिए / कमजोर वर्गों के किसी भी योग्य सदस्य, रेलवे द्वारा जारी एक विज्ञप्ति में कहा गया है।

वन स्टेशन वन प्रोडक्ट (OSOP) योजना

- OSOP योजना 'वोकल फॉर लोकल' को बढ़ावा देने के विजन के साथ शुरू की गई थी।
- इससे स्थानीय विनिर्माताओं को अपना उत्पाद बेचने में मदद मिलेगी और समाज के वंचित वर्गों के लिए आय के अतिरिक्त अवसर सृजित होंगे।
- योजना के तहत, सभी पात्र आवेदकों को बारी-बारी से आवंटन किया जाता है।
- योजना का पायलट 25 मार्च, 2022 को शुरू किया गया था।
- OSOP योजना स्थानीय कारीगरों, कुम्हारों, बुनकरों, आदिवासियों आदि का कल्याण कर रही है।
- पात्र आवेदक को रेलवे के पास 1,000 रुपये जमा करने पर 15 दिनों की अवधि के लिए एक अस्थायी स्टॉल या कियोस्क आवंटित किया जाएगा।
- जोनल रेलवे स्टेशनों, योग्य उत्पादों और विक्रेताओं की पहचान करेगी।

OSOP योजना के तहत उत्पादों में शामिल हैं

- खाद्य पदार्थ (मौसमी या प्रसंस्कृत या अर्ध प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ)
- हस्तशिल्प
- कलाकृतियाँ
- कपड़ा
- हथकरघा
- पारंपरिक वस्त्र
- स्थानीय कृषि उपज
- स्थानीय खिलौने
- चर्म उत्पाद
- स्थानीय रत्न और आभूषण

पारख

खबरों में क्यों

शिक्षा मंत्रालय ने 60 स्कूल बोर्डों को एकीकृत करने के उद्देश्य से पहली बैठक बुलाई

महत्वपूर्ण बिंदु

- शिक्षा मंत्रालय ने विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में संचालित 60 स्कूल परीक्षा बोर्डों को एक छतरी के नीचे एकीकृत करने के उद्देश्य से नई दिल्ली में एक कार्यशाला का आयोजन किया।
- पारख को NCERT के तहत संगठन के रूप में स्थापित किया गया है। यह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्कूल बोर्डों को एक साझा मंच पर लाने का काम करेगा।
- पारख एक समग्र दृष्टिकोण विकसित करने के लिए सभी संबंधित हितधारकों की बातचीत के लिए एक सामान्य मंच के रूप में कार्य करेगा जो एक निष्पक्ष मूल्यांकन प्रणाली सुनिश्चित करता है जो प्रदर्शन में समानता और छात्रों के मूल्यांकन में समानता को बढ़ावा देता है।
- कार्यशाला देश भर में स्कूल मूल्यांकन, परीक्षा प्रथाओं और बोर्डों की समानता का अध्ययन करेगी।
- इस योजना का मुख्य घटक पारख या राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र है जिसे राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के तहत एक संगठन के रूप में स्थापित किया गया है।
- पारख का काम राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्कूल बोर्डों को एक साझा मंच पर लाना है।
- पहले कदम के रूप में, पारख पर एक कार्यशाला एक समग्र दृष्टिकोण विकसित करने के लिए सभी संबंधित हितधारकों की बातचीत के लिए एक सामान्य मंच के रूप में कार्य करेगी जो एक निष्पक्ष मूल्यांकन प्रणाली सुनिश्चित करती है जो प्रदर्शन में समानता और छात्रों के मूल्यांकन में समानता को बढ़ावा देती है।

- सरकार का उद्देश्य एक एकीकृत ढांचा स्थापित करना है जो विभिन्न बोर्डों या क्षेत्रों के बीच छात्रों के लिए निर्बाध बदलाव को सक्षम बनाता है।
- इसमें विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए पाठ्यचर्या मानकों, ग्रेडिंग सिस्टम, और मूल्यांकन पद्धतियों को संरेखित करना, प्रमाणपत्रों की मान्यता और सभी बोर्डों में प्राप्त ग्रेड शामिल हैं।
- चर्चा हमारी शिक्षा प्रणाली में प्रचलित रटकर परीक्षा संस्कृति के पुनर्मूल्यांकन की आवश्यकता के इर्द-गिर्द घूमती है।
- एक बढ़ता हुआ अहसास है कि एक छात्र की क्षमताओं और क्षमता के विभिन्न आयामों को शामिल करते हुए समग्र मूल्यांकन समान रूप से महत्वपूर्ण हैं।
- इसने स्कूलों और बोर्डों में निष्पक्षता और निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए अच्छी तरह से डिज़ाइन किए गए और मानकीकृत प्रश्न पत्रों की आवश्यकता पर बल दिया।
- इसके अतिरिक्त, एक छात्र की प्रगति को प्रभावी ढंग से मापने के साथ-साथ उच्च-दांव वाली परीक्षाओं के बोझ को कम करते हुए रचनात्मक और योगात्मक आकलन के बीच संतुलन बनाने का आह्वान किया गया है।
- माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक बोर्डों के परीक्षा परिणामों का विश्लेषण भी प्रस्तुत किया गया।

उड़ान 5.1

खबरों में क्यों

नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने उड़ान 5.1 लॉन्च किया, जिसे विशेष रूप से हेलीकॉप्टर मार्गों के लिए डिज़ाइन किया गया है

महत्वपूर्ण बिंदु

- क्षेत्रीय संपर्क योजना (RCS) के चार सफल दौरों के बाद - उड़े देश का आम नागरिक (उड़ान) और पांचवें दौर के संस्करण 5.0 के साथ, नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने दूरस्थ क्षेत्रों में कनेक्टिविटी को और बढ़ाने के लिए उड़ान 5.1 लॉन्च किया है। देश के और हेलीकाप्टरों के माध्यम से अंतिम मील कनेक्टिविटी प्राप्त करें।
- RCS-उड़ान के तहत पहली बार, इस दौर को विशेष रूप से हेलीकॉप्टर मार्गों के लिए डिज़ाइन किया गया है।

मुख्य विशेषताओं में शामिल हैं:

  - ऑपरेटरों के लिए संचालन के दायरे में वृद्धि जिसमें योजना अब उन मार्गों की अनुमति देगी जहां मूल या गंतव्य स्थानों में से एक प्राथमिकता क्षेत्र में है। पहले दोनों बिंदुओं को प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में होना था।
  - यात्रियों के लिए हेलीकाप्टरों में उड़ान को और अधिक किफायती बनाने के लिए विमान किराया सीमा को 25% तक कम कर दिया गया है।
  - सम्मानित मार्गों के संचालन के लिए वित्तीय व्यवहार्यता बढ़ाने के लिए एकल और जुड़वां इंजन दोनों हेलीकाप्टरों के लिए ऑपरेटरों के लिए वायबिलिटी गैप फंडिंग (VGF) कैप में काफी वृद्धि की गई है।
- उड़ान योजना का नवीनतम दौर भारतीय नागरिक उड्डयन में दो उभरती घटनाओं का प्रमाण है, एक अंतिम मील कनेक्टिविटी पर ध्यान देने के साथ हवाई यात्रा का गहरा जनतंत्रीकरण।
- दूसरा, पर्यटन में सहायता के लिए हेलीकॉप्टरों की बढ़ती भूख।
- इस तरह के प्रयासों के माध्यम से अधिक से अधिक हेलीकॉप्टर पहुंच पर्यटन, आतिथ्य और इस प्रकार, हमारी स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को बढ़ावा देने में मदद करेगी। उड़ान 5.1 ने न केवल नागरिक उड्डयन के लिए, बल्कि भारत के दूरस्थ और सेवा से वंचित क्षेत्रों के लिए भी एक नई सुबह की शुरुआत की है।
- योजना का वर्तमान संस्करण हेलीकॉप्टर ऑपरेटरों सहित सभी हितधारकों के साथ परामर्श के बाद तैयार किया गया है।
- जबकि लक्षित लक्ष्य अंतिम-मील कनेक्टिविटी प्रदान करना है, यह भारतीय नागरिक उड्डयन उद्योग के हेलीकॉप्टर खंड को बहुत आवश्यक बढ़ावा देने के लिए भी अनुमानित है।
- यह उल्लेख किया जा सकता है कि योजना के पिछले दौर के तहत अब तक 46 हेलीकॉप्टर मार्गों का संचालन किया जा चुका है, जिससे कई पहाड़ी और उत्तर पूर्व राज्य लाभान्वित हो रहे हैं और यह दौर बहुत बड़ी संख्या में मार्गों के कवरेज को लक्षित कर रहा है।
- उड़ान योजना के तहत यात्रियों को हवाई संपर्क का लाभ मिला है, एयरलाइनों को क्षेत्रीय मार्गों के संचालन के लिए रियायतें मिली हैं, और सेवा से वंचित क्षेत्रों को उनके आर्थिक विकास के लिए हवाई संपर्क का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाभ मिला है।
- योजना का वर्तमान संस्करण देश के दूर-दराज के गंतव्यों के लिए किफायती किराए पर हवाई यात्रा करने के लिए आम आदमी को अनुमति देने के माननीय प्रधान मंत्री के दृष्टिकोण की दिशा में एक और कदम होगा।

9 विविध

जॉब्स रिपोर्ट 2023 का भविष्य

खबरों में क्यों

वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट का 2023 संस्करण हाल ही में जारी किया गया था।

महत्वपूर्ण बिंदु

- रिपोर्ट मुख्य रूप से बताती है कि 2027 तक लगभग एक चौथाई नौकरियां बदलने वाली हैं।
- यह सर्वेक्षण 11 मिलियन से अधिक कर्मचारियों को रोजगार देने वाली लगभग 800 कंपनियों के इनपुट पर आधारित है और 673 मिलियन नौकरियों के डेटासेट का उपयोग करता है।
- रिपोर्ट में यह पता चला कि बढ़ती मांग की रिपोर्ट करने वाली कंपनियों के उच्चतम हिस्से वाले कौशल में विश्लेषणात्मक और रचनात्मक सोच शामिल है, इसके बाद तकनीकी साक्षरता, जिज्ञासा और आजीवन सीखने, लचीलापन और लचीलापन, सिस्टम थिंकिंग और एआई और बिग डेटा शामिल हैं।
- सर्वेक्षण की गई कंपनियों ने कार्यस्थल में जटिल समस्या-समाधान के बढ़ते महत्व को दर्शाते हुए संज्ञानात्मक कौशल को सबसे तेजी से महत्व में वृद्धि करते हुए दिखाया है।
- डब्ल्यूईएफ की रिपोर्ट के अनुसार, मांग में कम कौशल में वैश्विक नागरिकता, संवेदी प्रसंस्करण क्षमताएं और मैनुअल निपुणता, धीरज और सटीकता शामिल हैं।
- रिपोर्ट से पता चला कि नौकरियों में सबसे बड़ा पूर्ण लाभ शिक्षा (3 मिलियन नौकरियों) और कृषि (4 मिलियन नौकरियों) से आएगा, जो आंशिक रूप से जनसांख्यिकी द्वारा और आंशिक रूप से इन क्षेत्रों में नई तकनीकों के अनुप्रयोगों द्वारा संचालित होगा।
- इसके अलावा रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रबंधन कौशल, जुड़ाव कौशल, प्रौद्योगिकी कौशल, नैतिकता और शारीरिक क्षमताओं को आमतौर पर ज्ञान, आत्म-प्रभावकारिता और दूसरों के साथ काम करने की तुलना में कम महत्वपूर्ण माना जाता है।
- "प्रौद्योगिकी अपनाने और बढ़ते डिजिटलीकरण को आगे बढ़ाने से श्रम बाजार में महत्वपूर्ण बदलाव आएगा," यह कहा।
- सबसे तेजी से घटती भूमिकाओं में बैंक टेलर और कैशियर जैसी सचिवीय और लिपिकीय भूमिकाएं होंगी, जिन्हें स्वचालित किया जा सकता है, जबकि एआई मशीन लर्निंग विशेषज्ञों और साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों की मांग में उल्लेखनीय वृद्धि होने की उम्मीद है।

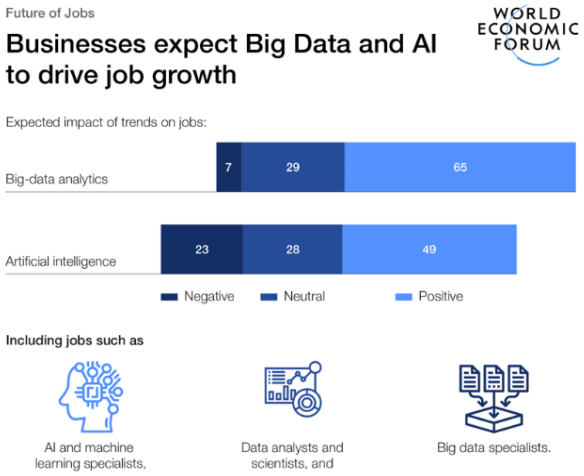

2023 में कोर जॉब स्किल्स की मांग

इस सूची में जबकि संज्ञानात्मक कौशल ने शीर्ष दो स्थान प्राप्त किए, आत्म-प्रभावकारिता, दूसरों के साथ काम करना और प्रौद्योगिकी कौशल ने शेष सात स्थानों पर कब्जा कर लिया। यहाँ एक विस्तृत रूप है:

- विश्लेषणात्मक सोच- कंपनियों द्वारा रिपोर्ट किए गए मूल कौशल का औसतन 9% होता है।
- रचनात्मक सोच- कंपनियों द्वारा रिपोर्ट किए गए मूल कौशल का औसतन 7% हिस्सा है।
- लचीलापन, लचीलापन और चपलता- 6% के अनुमानित औसत के साथ, इस आत्म--प्रभावकारिता कौशल ने तीसरा स्थान प्राप्त किया।
- प्रेरणा और आत्म-जागरूकता-लचीलापन, लचीलापन और चपलता की तरह इसने भी औसत कौशल सेट ग्राफ में अनुमानित 6% प्रवेश किया।
- जिज्ञासा और आजीवन सीखना- एक और आत्म-प्रभावकारिता कौशल, जिज्ञासा और आजीवन सीखने का औसत कौशल सेट ग्राफ में 6% है
- तकनीकी साक्षरता- सर्वेक्षण में शामिल 40% से कुछ अधिक कंपनियों ने पाया कि तकनीकी साक्षरता कर्मचारियों में अपेक्षित कौशल सेट का 5% है।
- निर्भरता और विस्तार पर ध्यान - इसी तरह के एक आंकड़े में, कंपनियों ने यह भी प्रमाणित किया कि निर्भरता और विस्तार पर ध्यान अनुमानित 5% औसत कौशल सेट की मांग है।

- सहानुभूति और सक्रिय सुनना- कंपनियों द्वारा रिपोर्ट किए गए अनुमानित औसत कोर कौशल का 5% से कम समानुभूति और सक्रिय सुनना था
- नेतृत्व और सामाजिक प्रभाव- अन्य कौशल सेट के साथ काम करने वाले इस कोर ने सर्वेक्षण किए गए संगठनों में श्रमिकों के बीच 4% से थोड़ा अधिक की अनुमानित औसत संरचना दर्ज की।
- गुणवत्ता नियंत्रण- इस सूची में एकमात्र प्रबंधन कौशल, दसवीं रैंकिंग के बावजूद कर्मचारियों के कौशल का 5% है, गुणवत्ता नियंत्रण व्यवसायों के एक सीमित समूह के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण कौशल का एक उदाहरण है।

कौशलयुक्त रोजगार की मांग बढ़ रही है-

- विश्लेषणात्मक सोच
- रचनात्मक सोच
- तकनीकी साक्षरता
- जिज्ञासा और आजीवन सीखने
- लचीलापन, लचीलापन, चपलता
- प्रणालियों की सोच
- एआई और बिग डेटा
- प्रेरणा और जागरूकता
- प्रतिभा प्रबंधन
- सेवा उन्मुखीकरण और ग्राहक सेवा

थर्मोबैरिक बम

खबरों में क्यों

हाल ही में मानवाधिकार समूहों ने म्यांमार की सेना पर थर्मोबैरिक बम के इस्तेमाल का आरोप लगाया था।

महत्वपूर्ण बिंदु

- एक मानवाधिकार निगरानी समूह ने आरोप लगाया कि म्यांमार की सेना ने पिछले महीने सैन्य शासन के विरोधियों द्वारा आयोजित एक समारोह में एक हवाई हमले में एक "उन्नत विस्फोट" गोला-बारूद का इस्तेमाल किया, जिसे ईंधन-वायु विस्फोटक के रूप में जाना जाता है, जिसमें कई बच्चों सहित 160 से अधिक लोग मारे गए थे।
- ह्यूमन राइट्स वॉच ने सेना पर हथियार गिराने का आरोप लगाया, जिसे थर्मोबैरिक या वैक्यूम बम के रूप में भी जाना जाता है, म्यांमार के केंद्रीय सागैंग क्षेत्र में पाज़िगी गांव के बाहर देश के प्रतिरोध आंदोलन के स्थानीय कार्यालय के उद्घाटन के लिए एकत्रित हुई भीड़ पर।
- यह क्षेत्र देश के दूसरे सबसे बड़े शहर मांडले से लगभग 110 किलोमीटर (70 मील) उत्तर में है।
- इस हमले के कारण "अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी कानून का उल्लंघन करते हुए अंधाधुंध और अनुपातहीन नागरिक हताहत हुए, और यह एक स्पष्ट युद्ध अपराध था।

थर्मोबैरिक बम के बारे में

- थर्मोबैरिक हथियारों में एक ईंधन कंटेनर और दो अलग-अलग विस्फोटक चार्ज होते हैं, जिसमें पहला विस्फोट ईंधन कणों को तितर--बितर करने के लिए होता है और दूसरा हवा में फैले हुए ईंधन और ऑक्सीजन को प्रज्वलित करता है, अत्यधिक दबाव और गर्मी की एक विस्फोट लहर पैदा करता है जो एक बंद स्थान में एक आंशिक वैक्यूम बनाता है
- यह हथियार को विशेष रूप से एक संलग्न स्थान में लोगों के लिए घातक बनाता है, जैसे कि कार्यालय जिसे खोला जा रहा था।
- थर्मोबैरिक बम को एरोसोल बम, ईंधन वायु विस्फोटक या वैक्यूम बम के रूप में भी जाना जाता है।
- इन्हें वैक्यूम बम कहा जाता है क्योंकि ये उच्च-वोल्टेज विस्फोट उत्पन्न करने के लिए आसपास के क्षेत्रों से ऑक्सीजन चूसते हैं।
- यह एक ईंधन कंटेनर है जिसके अंदर दो अलग-अलग विस्फोटक आवेश होते हैं।
- थर्मोबैरिक बम को हवाई जहाज से बम के रूप में गिराया जा सकता है या रॉकेट के रूप में लॉन्च किया जा सकता है।

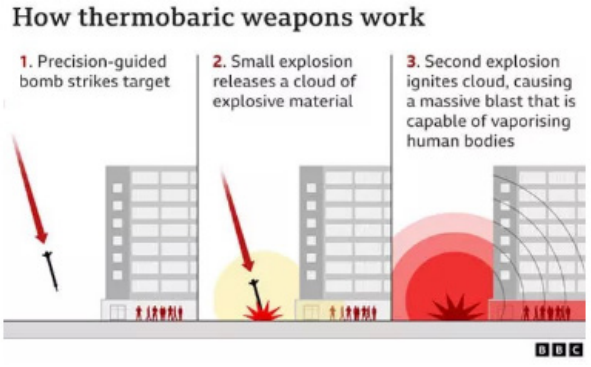

- जब यह अपने लक्ष्य से टकराता है, तो पहला विस्फोटक आवेश कंटेनर को खोलता है और व्यापक रूप से ईंधन मिश्रण को एक बादल के रूप में बिखेरता है।
- एक दूसरा चार्ज फिर बादल में विस्फोट करता है, जिसके परिणामस्वरूप एक विशाल आग का गोला, एक विशाल विस्फोट की लहर और एक निर्वात होता है जो आसपास के सभी ऑक्सीजन को चूस लेता है।
- विशेष रूप से उनके उपयोग पर प्रतिबंध लगाने वाला कोई अंतरराष्ट्रीय कानून नहीं है।
- एक थर्मोबारिक हथियार तुलनात्मक आकार के पारंपरिक बम की तुलना में काफी अधिक तबाही मचाता है।

पृष्ठभूमि

- फरवरी 2021 में सेना द्वारा आंग सान सू की की चुनी हुई सरकार को अपदस्थ करने और अहिंसक विरोधों को बेरहमी से दबाने के बाद शुरू हुई हिंसा से म्यांमार तबाह हो गया है।

- इसने देश के कई हिस्सों में सशस्त्र प्रतिरोध और लड़ाई शुरू कर दी, साथ ही सेना विरोध और सुरक्षित क्षेत्र का मुकाबला करने के लिए तेजी से हवाई हमले कर रही है।
- ह्यूमन राइट्स वॉच ने कहा कि यह अपने निष्कर्ष पर आधारित है कि हमलों के बाद पीड़ितों के शरीर की 59 तस्वीरों और साइट के एक वीडियो की समीक्षा पर एक थर्मोबैरिक हथियार का इस्तेमाल किया गया था।
- इस हमले में 168 नागरिक मारे गए, जिनमें 18 वर्ष से कम उम्र के 40 बच्चे शामिल थे। एक 6 महीने की बच्ची सबसे कम उम्र की शिकार थी और एक 76 वर्षीय व्यक्ति सबसे बुजुर्ग था।
- म्यांमार की सेना ने हमले को स्वीकार किया लेकिन क्षेत्र में सरकार विरोधी ताकतों पर आतंक का हिंसक अभियान चलाने का आरोप लगाते हुए अपने कार्यों का बचाव किया।

थर्मोबैरिक हथियारों का उपयोग

- थर्मोबेरिक हथियारों के उपयोग को शायद ही कभी सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया जाता है क्योंकि वे अंधाधुंध विनाश कर सकते हैं।
- संयुक्त राज्य अमेरिका ने वियतनाम, अफगानिस्तान और इराक में संघर्षों में विभिन्न प्रकार के ईंधन-वायु विस्फोटकों का उपयोग किया है।
- अफ़ग़ानिस्तान में, अमेरिकी वायु सेना ने अपने "सबसे बड़े गैर-परमाणु पारंपरिक हथियार" के रूप में वर्णित 9,840 किलोग्राम (21,693-पाउंड) भारी आयुध वायु विस्फोट बम गिराया।
- रूस, जो ईंधन-वायु गोला-बारूद के उत्पादन को स्वीकार करता है, पर यूक्रेन सहित कई संघर्षों में उनका उपयोग करने का आरोप लगाया गया है।
- अज़रबैजान द्वारा पड़ोसी अर्मेनिया के खिलाफ लड़ाई में और सीरिया के गृहयुद्ध में सरकारी बलों द्वारा हथियारों का इस्तेमाल किए जाने की भी सूचना मिली है।

गैलेंट्री पुरस्कार

खबरों में क्यों

भारत के राष्ट्रपति ने हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह (चरण -1) के दौरान आठ कीर्ति चक्र और 29 शौर्य चक्र सहित 37 वीरता पुरस्कारों से सम्मानित किया।

महत्वपूर्ण बिंदु

गैलेंट्री पुरस्कारों के बारे में:

- उन्हें भारत सरकार द्वारा सशस्त्र बलों के अधिकारियों/कार्मिकों, अन्य कानूनी रूप से गठित बलों और नागरिकों की बहादुरी और बलिदान के कार्यों का सम्मान करने के लिए स्थापित किया गया है।
- इन गैलेंट्री पुरस्कारों की घोषणा वर्ष में दो बार की जाती है - पहले गणतंत्र दिवस के अवसर पर और फिर स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर।

पृष्ठभूमि:

- 26 जनवरी, 1950 को भारत सरकार द्वारा परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र नामक तीन वीरता पुरस्कारों की स्थापना की गई थी।
- इसके बाद, अन्य तीन वीरता पुरस्कार, अर्थात् अशोक चक्र वर्ग-I, अशोक चक्र वर्ग-II और अशोक चक्र वर्ग-III 1952 में स्थापित किए गए। इन पुरस्कारों को क्रमशः 1967 में अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र नाम दिया गया।
- वरीयता का क्रम: इन पुरस्कारों की वरीयता का क्रम परमवीर चक्र, अशोक चक्र, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, वीर चक्र और शौर्य चक्र है।
- सभी गैलेंट्री पुरस्कारों को मरणोपरांत प्रदान किया जा सकता है।
- पुरस्कार के लिए अनुशंसित व्यक्तियों को किसी भी प्रतिकूल रिपोर्ट में शामिल नहीं किया जाना चाहिए या उन्हें कोर्ट मार्शल की कार्यवाही में या प्रशासनिक कार्रवाई के माध्यम से कोई नाराजगी या निंदा या कोई सजा नहीं दी जानी चाहिए।

अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र:

- पात्रता: व्यक्तियों की निम्नलिखित श्रेणियां अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र के लिए पात्र होंगी:
- सेना, नौसेना और वायु सेना के सभी रैंकों के अधिकारी और पुरुष और महिलाएं, किसी भी रिजर्व बल, प्रादेशिक सेना, मिलिशिया और किसी भी अन्य कानूनी रूप से गठित बलों के।
- सशस्त्र बलों की नर्सिंग सेवाओं के सदस्य।
- जीवन के सभी क्षेत्रों में किसी भी लिंग के नागरिक नागरिक और केंद्रीय अर्ध-सैन्य बलों और रेलवे सुरक्षा बल सहित पुलिस बलों के सदस्य।

पात्रता की शर्तें:

- अशोक चक्र सबसे विशिष्ट बहादुरी या कुछ साहसी कार्य या वीरता या आत्म-बलिदान के किसी अन्य कार्य के लिए दिया जाता है, न कि दुश्मन का सामना करने के लिए।
- कीर्ति चक्र को दुश्मन का मुकाबला करने के अलावा विशिष्ट वीरता के लिए प्रदान किया जाता है।
- शौर्य चक्र को शत्रु का सामना करने के बजाय अन्य वीरता के लिए प्रदान किया जाता है।
- वरीयता क्रम: परमवीर चक्र, अशोक चक्र, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, वीर चक्र और शौर्य चक्र।

वीर गाथा परियोजना

- भारत सरकार ने आज़ादी का अमृत महोत्सव के एक भाग के रूप में "वीर गाथा परियोजना" शुरू की, जिसके तहत सरकार भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष को चिह्नित करने के लिए कई कार्यक्रमों की शुरुआत कर रही है।

- स्कूली बच्चों को युद्ध नायकों और बहादुर दिलों की कहानियों से अवगत कराकर उन्हें प्रेरित करने के लिए वीर गाथा परियोजना शुरू की गई।
- परियोजना का उद्देश्य छात्रों के बीच सशस्त्र बलों के अधिकारियों/कर्मियों, अन्य कानूनी रूप से गठित बलों और नागरिकों की बहादुरी के कार्यों और जीवन गाथाओं के विवरण का प्रसार करना था।
- छात्रों को वीरता पुरस्कार विजेताओं पर कविता/पैराग्राफ/निबंध/पेंटिंग/मल्टीमीडिया प्रस्तुति (अभिनयन वीडियो) के रूप में विभिन्न परियोजनाओं को तैयार करने के लिए प्रेरित किया गया और रक्षा मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर 25 सर्वश्रेष्ठ परियोजनाओं को पुरस्कृत किया जाना था।
- इन इंटरैक्टिव सत्रों के दौरान, छात्रों के प्रश्नों का उत्तर दिया गया और छात्रों के साथ लघु वीडियो/पीपीटी/वृत्तचित्र/ब्रोशर और विभिन्न अन्य संसाधन सामग्री साझा की गई।

वीर गाथा 2.0 प्रोजेक्ट

- वीर गाथा संस्करण-1 की जबर्दस्त प्रतिक्रिया और सफलता के बाद, रक्षा मंत्रालय ने शिक्षा मंत्रालय के साथ मिलकर अब प्रोजेक्ट वीर गाथा 2.0 लॉन्च करने का फैसला किया है, जिसका समापन जनवरी 2023 में पुरस्कार वितरण समारोह के साथ होना प्रस्तावित है।
- पिछले संस्करण के अनुसार, परियोजना सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सभी स्कूलों के लिए खुली होगी।
- पहल के हिस्से के रूप में, यह प्रस्तावित है कि वीरता पुरस्कार विजेताओं की सेवा करने वाले अपने संबंधित स्टेशनों में स्थित स्कूलों का दौरा करेंगे।
- सेवा कर्मी छात्रों के प्रश्नों का उत्तर देंगे। जहां संभव हो, छात्रों के साथ लघु वीडियो/पीपीटी/वृत्तचित्र/ब्रोशर और अन्य संसाधन सामग्री साझा की जाएगी।

हरित सागर

खबरों में क्यों

बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने 'हरित सागर' ग्रीन पोर्ट दिशानिर्देश 2023 लॉन्च किया।

महत्वपूर्ण बिंदु

- कार्बन उत्सर्जन में कमी और सतत और समावेशी विकास हासिल करना सरकार के एजेंडे के केंद्र में है।
- इसके अनुरूप, बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने नई दिल्ली में ग्रीन पोर्ट दिशानिर्देश 'हरित सागर' लॉन्च किया।
- हरित सागर दिशानिर्देश 2023 प्रमुख बंदरगाहों के लिए एक व्यापक रूपरेखा प्रदान करते हैं, उन्हें एक व्यापक कार्य योजना बनाने के लिए सशक्त बनाते हैं जिसका उद्देश्य निर्धारित समयसीमा में कार्बन उत्सर्जन में मात्रात्मक कमी प्राप्त करना है।

कार्बन उत्सर्जन को कम करना

- दिशा-निर्देशों का उद्देश्य बंदरगाह संचालन से शून्य अपशिष्ट निर्वहन प्राप्त करने के लिए रिड्यूस, पुन: उपयोग, पुन: उपयोग और पुनर्चक्रण के माध्यम से कचरे को कम करना है।
- इसके अलावा, यह पर्यावरण प्रदर्शन संकेतकों के आधार पर निगरानी को भी बढ़ावा देता है।
- दिशा-निर्देशों का एक अन्य प्रमुख कारक यह है कि वे बंदरगाह संचालन में स्वच्छ और हरित ऊर्जा के उपयोग पर जोर देते हैं, भंडारण के लिए बंदरगाह क्षमता विकसित करना, संभालना, और हरित हाइड्रोजन और हरी अमोनिया जैसे हरित ईंधन को बंकर करना।
- बंदरगाह आर्थिक गतिविधियों के प्रमुख केंद्र हैं।
- हैंलांकि, इस उच्च स्तर की गतिविधि के परिणामस्वरूप दूसरों के बीच वायु और जल प्रदूषण सहित महत्वपूर्ण पर्यावरणीय प्रभाव हो सकते
- इस तरह की हरित पहलें प्रदूषण को कम करने, संसाधनों के संरक्षण और टिकाऊ प्रथाओं को बढ़ावा देकर इन प्रभावों को कम करने में मदद करती हैं।
- हरित सागर ग्रीन पोर्ट दिशानिर्देश हमारे स्थिरता लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
- ये दिशानिर्देश सभी बंदरगाहों पर पर्यावरण के अनुकूल प्रथाओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से तैयार किए गए हैं।
- अब से, बंदरगाह पर्यावरणीय संकेतकों पर खुद का मूल्यांकन करने में सक्षम होंगे ताकि पर्यावरणीय पहलुओं में उनकी क्षमता का पता चल सके।
- जैसा कि वैश्विक स्तर पर व्यवसायों और उपभोक्ताओं के लिए स्थिरता एक बढ़ती हुई चिंता है, भारतीय बंदरगाह पर्यावरणीय जिम्मेदारी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता का प्रदर्शन कर रहे हैं।
- भारत स्थिरता को बढ़ावा देने और पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने के लिए अपने बंदरगाहों में हरित पहलों को अपनाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है।
- भारत के चार प्रमुख बंदरगाह दीनदयाल बंदरगाह, विशाखापत्तनम बंदरगाह, न्यू मैंगलोर बंदरगाह और वीओसी बंदरगाह पहले से ही अपनी मांग से अधिक नवीकरणीय ऊर्जा पैदा कर रहे हैं।

सागर श्रेष्ठ सम्मान पुरस्कार

- इसके अलावा, सरकार ने वित्त वर्ष 2022-2023 के दौरान चुनिंदा परिचालन और वित्तीय मापदंडों पर अपने सर्वकालिक सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए प्रमुख बंदरगाहों को 'सागर श्रेष्ठ सम्मान' पुरस्कार भी प्रदान किया।
- दीनदयाल पोर्ट, कांडला को 137.56 एमएमटी के उच्चतम कार्गो को संभालने के लिए वर्ष 2022-23 के लिए सर्वश्रेष्ठ पूर्ण प्रदर्शन पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

- पारादीप पोर्ट को पिछले साल 16.56% की उच्चतम कार्गो विकास दर प्राप्त करने के लिए सर्वश्रेष्ठ वृद्धिशील प्रदर्शन से सम्मानित किया गया।
- उल्लेखनीय प्री-बर्थिंग डिटेंशन टाइम के लिए कामराजर पोर्ट को पुरस्कार दिया गया, जबकि मोरमुगाओ पोर्ट को वृद्धिशील श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ शिप बर्थ डे आउटपुट के लिए सम्मानित किया गया।

पोखरण द्वितीय

खबरों में क्यों

भारत ने पोखरण-II की 25वीं वर्षगांठ देखी

महत्वपूर्ण बिंदु

- 11 मई, 1998 को भारत ने भारतीय सेना के पोखरण परीक्षण रेंज में तीन परमाणु बम परीक्षण विस्फोट किए। दो दिन बाद 13 मई को दो और बमों का परीक्षण किया गया।
- कोडनाम ऑपरेशन शक्ति (शाब्दिक रूप से, "ताकत"), ये परीक्षण 200 किलोटन तक की क्षमता वाले विखंडन और थर्मोन्यूक्लियर हथियार बनाने की भारत की क्षमता को प्रदर्शित करेंगे, जिससे भारत को परमाणु हथियारों को तैनात करने की क्षमता वाले देशों के अत्यधिक संरक्षित क्लब में प्रवेश करने में मदद मिलेगी।
- हालांकि, पोखरण-द्वितीय, जैसा कि परीक्षणों की श्रृंखला अधिक लोकप्रिय है, एक लंबी यात्रा की पराकाष्ठा भी थी जो 1940-50 के दशक में वापस शुरू हुई थी - कठिनाइयों से भरी यात्रा, हर कोने में असफलता के साथ।

होमी जे भाबा ने रखी नींव

- भारत के परमाणु कार्यक्रम को भौतिक विज्ञानी होमी जे भाभा के काम में खोजा जा सकता है।
- 1945 में, भाबा की भारत के सबसे बड़े औद्योगिक परिवार की सफल पैरवी के बाद, बॉम्बे में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च खोला गया।
- टीआईएफआर परमाणु भौतिकी के अध्ययन के लिए समर्पित भारत का पहला शोध संस्थान था।
- आजादी के बाद, भाबा ने बार-बार प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से मुलाकात की और परमाणु ऊर्जा के महत्व और इसके विकास के लिए संसाधनों को आवंटित करने के लिए भारत की आवश्यकता के बारे में आश्वस्त किया।
- इस प्रकार, 1954 में, भाभा के निदेशक के रूप में परमाणु ऊर्जा विभाग (DAE) की स्थापना की गई।
- जबकि नेहरू ने सार्वजनिक रूप से परमाणु हथियारों का विरोध किया, निजी तौर पर, उन्होंने भाबा को परमाणु प्रौद्योगिकी के नागरिक और सैन्य उपयोग दोनों के लिए आधारशिला रखने की खुली छूट दी थी।
- उसके अधीन, डीईए स्वायत्तता के साथ और महत्वपूर्ण सार्वजनिक जांच से दूर संचालित होता था।

चीन और पाकिस्तान का खतरा

- भारत की परमाणु यात्रा में एक महत्वपूर्ण क्षण 1962 के चीन-भारतीय युद्ध में करारी हार और 1964 में लोप नोर में चीन के बाद के परमाणु बम परीक्षण के बाद आया।
- भारत की संप्रभुता और अमित्र चीन की उभरती ताकत के बारे में चिंतित, परमाणु हथियारों के प्रति राजनीतिक प्रतिष्ठान का मूड धीरे-धीरे बदल रहा था।
- जबकि नए प्रधान मंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने पहली बार स्थापित परमाणु हथियार वाले राज्यों से परमाणु गारंटी प्राप्त करने की कोशिश की, जब ऐसी गारंटी साzमने नहीं आई, तो एक अलग रास्ता अपनाना पड़ा।
- चीजें तब और तेज हो गईं, जब 1965 में, भारत एक बार फिर पाकिस्तान के साथ युद्ध में गया, चीन ने इस बार खुले तौर पर पाकिस्तान का समर्थन किया।
- प्रभावी रूप से, भारत दो अमित्र राष्ट्रों से घिरा हुआ था, और आत्मनिर्भरता के निर्माण की दिशा में कदम उठाने की आवश्यकता थी।
- हालांकि, परमाणु हथियार हासिल करने की राह आसान नहीं होगी।

"भेदभावपूर्ण" एनपीटी

- 1960 के दशक तक, परमाणु निरस्त्रीकरण और अप्रसार के बारे में बातचीत मुख्यधारा में स्थानांतरित हो गई थी क्योंकि शीत युद्ध के हथियारों ने अमेरिका और यूएसएसआर को चरम सीमा पर धकेल दिया था।
- चीन द्वारा अपने स्वयं के बम का सफलतापूर्वक परीक्षण करने के बाद, बड़ी शक्तियों के बीच अप्रसार संधि की आवश्यकता के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय सहमति बढ़ रही थी।

- 1968 में अप्रसार संधि (NPT) अस्तित्व में आई।
- संधि परमाणु-हथियार वाले राज्यों को उन राज्यों के रूप में परिभाषित करती है जिन्होंने 1 जनवरी, 1967 से पहले एक परमाणु विस्फोटक उपकरण का निर्माण और परीक्षण किया है - अमेरिका, रूस (पूर्व यूएसएसआर), यूके, फ्रांस और चीन - और किसी अन्य राज्य को परमाणु हथियार प्राप्त करने से प्रभावी रूप से प्रतिबंधित करता है। .
- जबकि इस संधि पर दुनिया के लगभग हर देश ने हस्ताक्षर किए हैं, भारत कुछ गैर-हस्ताक्षरकर्ताओं में से एक है।
- भारत सरकार ने संधि की शर्तों को मानने से इनकार कर दिया क्योंकि यह भारत की गलतफहमी को दूर करने में विफल रही; विशेष रूप से, गैर-परमाणु राज्यों का निरंतर परमाणु संयम परमाणु हथियार वाले राज्यों द्वारा स्पष्ट पारस्परिक दायित्वों से जुड़ा नहीं था।

पोखरण-I और उसके परिणाम

- 1970 के दशक तक, भारत परमाणु बम परीक्षण करने में सक्षम था।
- डीएई में भाबा के उत्तराधिकारी, विक्रम साराभाई ने भारत की परमाणु तकनीक को महत्वपूर्ण रूप से व्यापक बनाने के लिए काम किया था और अब सवाल राजनीतिक इच्छाशक्ति का अधिक था, विशेष रूप से वैश्विक व्यवस्था के संदर्भ में जो परमाणु प्रसार से बेहद सावधान है।
- इंदिरा गांधी ने 1966 में शास्त्री की आकस्मिक मृत्यु के बाद देश की बागडोर संभाली। कभी कांग्रेस के वरिष्ठ नेतृत्व के हाथों की कठपुतली मानी जाने वाली, वह जल्द ही अपना साहस दिखाएंगी, 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ एक और परीक्षण युद्ध के माध्यम से भारत का नेतृत्व करेंगी और बाद के चुनावों में भारी जनादेश जीतेंगी।
- 18 मई, 1974 को, इंदिरा के समर्थन से, भारत ने पोखरण परीक्षण स्थल पर अपना पहला परमाणु परीक्षण किया। पोखरण- I, कोडनेम ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा, को "कुछ सैन्य निहितार्थ" के साथ "शांतिपूर्ण परमाणु विस्फोट" के रूप में देखा जाएगा।
- लगभग सार्वभौमिक निंदा हुई और अमेरिका और कनाडा जैसे देशों ने भारत पर महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंध लगाए।
- ये प्रतिबंध भारत की परमाणु यात्रा के लिए एक बड़ा झटका होगा, और इसकी प्रगति को काफी हद तक धीमा कर देगा।

दो परीक्षणों के बीच की अवधि

- अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों से परे, भारत की परमाणु यात्रा घरेलू राजनीतिक अस्थिरता से भी बाधित रही।
- 1975 के आपातकाल और प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के परमाणु हथियारों के विरोध के कारण कार्यक्रम ठप्प पड़ गया।
- हालांकि, 1980 के दशक में एक बार फिर से परमाणु हथियार विकसित करने के लिए कोलाहल तेज हो गया, क्योंकि पाकिस्तान की तेजी से बढ़ती परमाणु क्षमताओं पर रिपोर्ट सामने आई।
- 1983 में, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) की फंडिंग बढ़ा दी गई और डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम को भारत के मिसाइल कार्यक्रम का प्रभारी बना दिया गया।
- उस वर्ष, भारत ने प्लूटोनियम को हथियार ग्रेड में पुन: संसाधित करने की क्षमता भी विकसित की।
- इसके अलावा, पूरे दशक में, भारत ने अपने प्लूटोनियम भंडार में तेजी से वृद्धि की।
- 1990 के दशक की शुरुआत में उनके साथ परमाणु हथियारों को तेजी से विकसित करने का दबाव बढ़ा। 1991 में यूएसएसआर के पतन के साथ, भारत ने अपने सबसे बड़े सैन्य सहयोगियों में से एक को खो दिया, जब इंदिरा गांधी ने 1971 में इसके साथ 20 साल के सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए थे।
- इसके अलावा, अमेरिका ने अपने परमाणु हथियार कार्यक्रम के बारे में अपनी गलतफहमी के बावजूद पाकिस्तान को सैन्य सहायता देना जारी रखा। अंत में, संयुक्त राष्ट्र में एक व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि (CTBT) के बारे में भी चर्चा चल रही थी (इसे 1996 में अंतिम रूप दिया जाएगा, भारत ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किया था)।
- भारत के लिए, ऐसा लगा जैसे उसके अवसर की खिड़की तेजी से बंद हो रही थी।
- इस प्रकार, 1995 में, तत्कालीन प्रधान मंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने दिसंबर 1995 में परमाणु परीक्षण करने की तैयारी की अनुमति दी।
- हालाँकि, तार्किक और राजनीतिक कारणों ने परीक्षणों को और पीछे धकेल दिया।

पोखरण-द्वितीय: भारत की ताकत का प्रक्षेपण

- कुछ वर्षों के घरेलू उथल-पुथल के बाद जब परमाणु परीक्षण करने की राजनीतिक इच्छाशक्ति कम हो रही थी, 1998 में, भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में सत्ता में आया।
- इसके घोषणापत्र में प्रमुख वादों में से एक भारत के शस्त्रागार में "परमाणु हथियारों को शामिल करना" था।
- मार्च 1998 में, पाकिस्तान ने गौरी मिसाइल लॉन्च की - जिसे चीन की सहायता से बनाया गया था।
- दो महीने बाद, भारत ने ऑपरेशन शक्ति के साथ जवाब दिया।
- जबकि 1974 के परीक्षण स्पष्ट रूप से शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए किए गए थे, 1998 के परीक्षण भारत की परमाणु हथियारीकरण प्रक्रिया की पराकाष्ठा थे।
- नतीजतन, भारत सरकार ने पोखरण-द्वितीय के बाद खुद को परमाणु हथियार रखने वाले राज्य के रूप में घोषित किया
- जबकि 1998 में परीक्षणों ने भी कुछ देशों (जैसे अमेरिका) से प्रतिबंधों को आमंत्रित किया था, निंदा 1974 की तरह सार्वभौमिक थी।
- भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था और बाजार की क्षमता के संदर्भ में, भारत अपनी जमीन पर खड़ा होने में सक्षम था और इस प्रकार एक प्रमुख राष्ट्र राज्य के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत किया।

युवा प्रतिभा

खबरों में क्यों

MyGov ने IHM पूसा के साथ मिलकर 'युवा प्रतिभा - पाक कला प्रतिभा खोज' शुरू की

महत्वपूर्ण बिंदु

- प्रतियोगिता का उद्देश्य भारत की समृद्ध पाक विरासत को बढ़ावा देना और दुनिया के लिए इसके मूल्य और महत्व को प्रदर्शित करना है। इसका उद्देश्य खोए हुए व्यंजनों को बाहर लाना और युवा शेफ और घरेलू रसोइयों की पाक प्रतिभा को बढ़ावा देना है।
- 2023 में, संयुक्त राष्ट्र ने इसे बाजरा के लिए वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करने के भारत के प्रस्ताव के बाद इसे 'बाजरा का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष' घोषित किया। बाजरा सदियों से भारतीय आहार का अभिन्न अंग रहा है।
- प्रतियोगिता का उद्देश्य बाजरा के उत्पादन और खपत को बढ़ाना और उनकी बहुमुखी प्रतिभा और स्वास्थ्य लाभों के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना है।
- प्रतियोगिता प्रतिभागियों को स्वस्थ और टिकाऊ सामग्री, विशेष रूप से बाजरा के साथ खाना पकाने में अपनी रचनात्मकता और नवीनता दिखाने का एक अनूठा अवसर प्रदान करती है।
- इसका उद्देश्य हमारे आहार में बाजरा के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करना और इसके सेवन को बढ़ावा देना है।
- इस प्रतियोगिता में बाजरा के मिश्रण से युवा रसोइयों और घरेलू रसोइयों को अपने खाना पकाने में बाजरा का पता लगाने और प्रयोग करने के लिए प्रेरित होने की उम्मीद है।

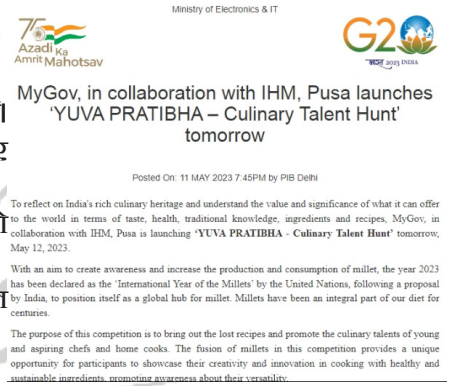
Ministry of Electronics & IT

MyGov, in collaboration with IHM, Pusa launches 'YUVA PRATIBHA – Culinary Talent Hunt' tomorrow

Posted On: 11 MAY 2023 7:45PM by PIB Delhi

To reflect on India's rich culinary heritage and understand the value and significance of what it can offer to the world in terms of taste, health, traditional knowledge, ingredients and recipes, MyGov, in collaboration with IHM, Pusa is launching **'YUVA PRATIBHA - Culinary Talent Hunt'** tomorrow, May 12, 2023.

With an aim to create awareness and increase the production and consumption of millet, the year 2023 has been declared as the 'International Year of the Millets' by the United Nations, following a proposal by India, to position itself as a global hub for millet. Millets have been an integral part of our diet for centuries.

The purpose of this competition is to bring out the lost recipes and promote the culinary talents of young and aspiring chefs and home cooks. The fusion of millets in this competition provides a unique opportunity for participants to showcase their creativity and innovation in cooking with healthy and sustainable ingredients, promoting awareness about their versatility.

लक्ष्य और उद्देश्य:

- इसका उद्देश्य युवा भारतीयों के पाक कौशल को प्रोत्साहित करना और प्रदर्शित करना है।
- प्रतियोगिता का उद्देश्य खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने और पोषण में सुधार करने के लिए बाजरा के पोषण मूल्य और महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है।
- इस आयोजन का उद्देश्य राष्ट्रीय स्तर पर बाजरा को बढ़ावा देना और उनकी खपत को बढ़ाना है।
- प्रतिभागियों को उनके खाना पकाने में बाजरा को शामिल करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, जिससे उनकी बहुमुखी प्रतिभा और स्वास्थ्य लाभ को बढ़ावा मिलेगा।

कैसे भाग लें:

- प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए इनोवेटइंडिया वेबसाइट पर जाएं।
- केवल 18 से 40 वर्ष की आयु के भारत के नागरिक ही भाग लेने के पात्र हैं।
- प्रविष्टियां MyGov पोर्टल पर जमा की जानी चाहिए। किसी अन्य मोड के माध्यम से सबमिट की गई प्रविष्टियों का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा।
- पकवान/नुस्खा घर का बना होना चाहिए, और कम से कम 50% सामग्री बाजरा होनी चाहिए।
- प्रतिभागियों को 3 तस्वीरें जमा करनी होंगी: (i) इस्तेमाल की गई सामग्री की एक तस्वीर; (ii) तैयार पकवान की एक तस्वीर, और (iii) पकवान के साथ प्रतिभागी की एक तस्वीर।
- डिश का विवरण शामिल सभी चरणों सहित स्पष्ट और सटीक होना चाहिए।
- सामग्री हिंदी और अंग्रेजी दोनों में उपलब्ध है।
- प्रतिभागियों को केवल एक प्रविष्टि जमा करने की अनुमति है।
- शीर्ष 3 विजेताओं की घोषणा नई दिल्ली में एक भौतिक कार्यक्रम में की जाएगी।

पुरस्कार और मान्यता:

- प्रथम पुरस्कार विजेता को 1,00,000/- रुपये, एक ट्रॉफी और एक प्रमाण पत्र प्राप्त होगा।
- द्वितीय पुरस्कार विजेता को 75,000/- रुपये, एक ट्रॉफी और एक प्रमाण पत्र प्राप्त होगा।
- तृतीय पुरस्कार विजेता को 50,000/- रुपये, एक ट्रॉफी और एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा।
- फाइनल राउंड में पहुंचने वाले बारह प्रतियोगियों में से प्रत्येक को 5,000 रुपये के नकद पुरस्कार से पुरस्कृत किया जाएगा।

बाओबाब के पेड़

खबरों में क्यों

वन विभाग बाओबाब के पेड़ों के स्थानान्तरण की अनुमति नहीं दे सकता।

महत्वपूर्ण बिंदु

- मध्य प्रदेश सरकार ने फैसला किया है कि धार के प्रसिद्ध बाओबाब पेड़ों, जिनमें से कुछ सदियों पुराने हैं, को स्थानांतरित करने की अनुमति वन विभाग नहीं दे सकता है और यह केवल राज्य जैव विविधता बोर्ड द्वारा किया जा सकता है।
- अफ्रीका के मूल निवासी पेड़ों की विरासत और ऐतिहासिक मूल्य पर प्रकाश डालने वाली एक रिपोर्ट के बाद निर्णय लिया गया था, लेकिन संभवतः 10वीं और 17वीं शताब्दी के बीच स्थानीय इस्लामिक साम्राज्यों द्वारा काम पर रखे गए अफ्रीकी सैनिकों द्वारा मध्य प्रदेश के इस कोने में लाया गया था।
- रिपोर्ट में हैदराबाद के एक व्यवसायी रामदेव राव द्वारा बाओबाब पेड़ों के स्थानांतरण के खिलाफ आदिवासियों के विरोध का भी उल्लेख किया गया है।
- पेड़ों को बायोडाइवर्सिटी एक्ट के तहत रखकर बैन लगाया गया है, यानी उन्हें व्यावसायिक रूप से इस्तेमाल करने की इजाजत स्टेट बायोडायवर्सिटी बोर्ड से लेनी होगी।
- अब, जैव विविधता बोर्ड की अनुमति के बिना पेड़ों का व्यावसायिक उपयोग नहीं किया जा सकता है।
- ऐसे जैविक संसाधनों का प्रबंधन जैव विविधता अधिनियम 2002 के तहत जारी नियमों/निर्देशों के तहत किया जाना बाध्य है।

बाओबाब पेड़ों के बारे में

- मुख्य भूमि अफ्रीका और मेडागास्कर के द्वीप देश के मूल निवासी, पर्णपाती बाओबाब एडानसोनिया डिजिटाटा 2,000 साल तक जीवित रह सकते हैं और विश्व स्तर पर खतरे वाली प्रजाति है।
- मध्य प्रदेश के धार जिले में मांडू, शायद भारत का एकमात्र ऐसा स्थान है जहां मांडू शहर की परिधि में अनुमानित 1,000 पेड़ों के साथ बाओबाब के पेड़ बहुतायत में पाए जाते हैं।
- अब, राज्य सरकार की योजना खोरासनी इमली या बाओबाब के फल के लिए एक भौगोलिक संकेत टैग के लिए आवेदन करने की है, जिसका उद्देश्य बेहतर मान्यता प्राप्त करना, किसानों को आर्थिक लाभ और दुर्लभ पेड़ की सुरक्षा करना है।
- मांडू के अलावा जहां यह सबसे प्रचुर मात्रा में है, उत्तर प्रदेश में प्रयागराज (पूर्व में इलाहाबाद), महाराष्ट्र में वाई और गुजरात और आंध्र प्रदेश में कुछ स्थानों पर बाओबाब के पेड़ दर्ज किए गए हैं।

जीआई टैग

- एक भौगोलिक संकेत टैग एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में एक उत्पाद के लिए एक ट्रेडमार्क के रूप में कार्य करता है जिसमें अद्वितीय या मूल्यवान गुण होते हैं।
- भौगोलिक संकेत टैग कृषि, बागवानी या वानिकी उत्पादों जैसे फल, सब्जियां, बीज, फूल और पेड़ों के अन्य उत्पादों को दिया जा सकता है।
- टैग संबंधित वस्तुओं के उत्पादकों या उनका प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था द्वारा लागू किया जा सकता है।
- आवेदन की जांच और जांच की जाती है, जिसके बाद यदि स्वीकार किया जाता है, तो यह पंजीकरण की प्रक्रिया से गुजरता है।
- अब तक, मध्य प्रदेश में कड़कनाथ ब्लैक चिकन और चंदेरी साड़ियों जैसे विभिन्न उत्पादों के लिए कम से कम 10 भौगोलिक संकेत टैग हैं, जिन्हें अनधिकृत उपयोग के खिलाफ कानूनी सुरक्षा मिलती है।
- टैग उत्पाद को एक विशिष्ट पहचान प्रदान करता है जो स्थानीय समुदाय को इसे बेहतर ढंग से बाजार में लाने और अधिक लाभ उठाने में मदद करता है।

आदिवासी आजीविका

- बाओबाब मांडू के लोगों को आजीविका प्रदान करते हैं।
- दुकानदार फलों की फलियों को पर्यटकों को स्मारिका के रूप में बेचते हैं।
- मांडू किले में जामी मस्जिद के सामने स्मृति चिन्ह बेचने वाले एक फल के आकार के हिसाब से इसकी अच्छी कीमत 50 रुपये से लेकर 200 रुपये तक मिलती है।
- इसके अलावा, लुगदी और बीज उनके औषधीय गुणों के लिए अलग से 10 रुपये प्रति पैकेट के हिसाब से बेचे जाते हैं।
- दुकानदार, ज्यादातर भील जनजाति के सदस्य, या तो उन्हें पास के जंगल से इकट्ठा करते हैं या बाओबाब उगाने वाले लोगों से खरीदते हैं।
- आदिवासी अब तक इन पेड़ों को बचाने में अहम भूमिका निभाते रहे हैं।
- बाओबाब वृक्ष भारत में मांडू का पर्याय है।
- फल विटामिन सी का एक समृद्ध स्रोत है और इसमें प्रचुर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं।
- इसका उपयोग पेट विकारों के इलाज के लिए किया जाता है। यहां तक कि इसकी छाल का इस्तेमाल कई बीमारियों को दूर करने के लिए भी किया जाता है।

भील जनजाति

- भील छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और राजस्थान में रहने वाले सबसे बड़े आदिवासी समूहों में से एक हैं।
- यह नाम 'बिल्लू' शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है धनुष।
- भील उत्कृष्ट धनुर्धर होने के साथ-साथ अपने स्थानीय भूगोल के बारे में गहन ज्ञान के लिए जाने जाते हैं।
- परंपरागत रूप से, गुरिल्ला युद्ध के विशेषज्ञ, आज उनमें से ज्यादातर किसान और खेतिहर मजदूर हैं। वे कुशल मूर्तिकार भी हैं।
- भील महिलाएं पारंपरिक साड़ी पहनती हैं जबकि पुरुष लंबी फ्रॉक और पायजामा पहनते हैं। महिला ने चांदी, पीतल से बने भारी आभूषणों के साथ मोतियों की माला और चांदी के सिक्के और कान की बाली पहन रखी थी।

डेटा शासन गुणवत्ता सूचकांक (DGQI)

खबरों में क्यों

हाल ही में, बंदरगाहों, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय (MoPSW) को FY23 की तिमाही (Q3) के लिए डेटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स (DGQI) के आकलन में 66 मंत्रालयों में से दूसरा स्थान दिया गया है।

महत्वपूर्ण बिंदु

- मंत्रालय ने 5 में से 4.7 अंक हासिल किए, जो डेटा गवर्नेंस में उत्कृष्टता के लिए अपनी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
- विकास निगरानी और मूल्यांकन कार्यालय (डीएमईओ), नीति आयोग द्वारा संचालित, डीजीक्यूआई सर्वेक्षण का उद्देश्य प्रशासनिक डेटा सिस्टम के परिपक्वता स्तर और केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं और केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं के कार्यान्वयन पर विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के निर्णय लेने में उनके उपयोग को मापना है। .
- यह इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए स्पष्ट मार्गों को परिभाषित करते हुए मंत्रालय के भीतर निर्बाध डेटा विनिमय और इसके सहक्रियाशील उपयोग की सीमा तक पहुंचने के लिए सुधारों की पहचान भी करता है।
- DGQI मूल्यांकन में डेटा निर्माण, डेटा गुणवत्ता, प्रौद्योगिकी का उपयोग, डेटा विश्लेषण, उपयोग और प्रसार, डेटा सुरक्षा और मानव संसाधन क्षमता, और केस स्टडी सहित छह प्रमुख विषय शामिल हैं।

- DGQI मूल्यांकन में MoPSW की सफलता को IIT मद्रास में बंदरगाहों, जलमार्गों और तटों के लिए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी केंद्र (NTCPWC) के ठोस प्रयासों से सहायता मिली, जिसे DGQI मानकों के अनुपालन में MoPSW की प्रबंधन सूचना प्रणाली (MIS) में सुधार करने का काम सौंपा गया था।
- विशेष रूप से, NTCPWC को MoPSW द्वारा MoPSW की एक प्रौद्योगिकी शाखा के रूप में सागरमाला के तहत विकसित किया गया है।
- DGQI ने MoPSW की पांच योजनाओं - सागरमाला, अनुसंधान और विकास, नौवहन, ALHW (अंडमान, लक्षद्वीप हार्बर वर्क्स), IWAI (भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण) और IWT (अंतर्देशीय जल परिवहन) के लिए MIS पोर्टल्स का मूल्यांकन किया है ताकि डेटा प्रवाह बढ़ाया जा सके, डेटा गुणवत्ता में वृद्धि हो सके और AI/ML जैसी उभरती हुई तकनीकों को शामिल किया जा सके।

- MoPSW के लिए डेटा-संचालित निर्णय लेने का प्रभाव महत्वपूर्ण रहा है, क्योंकि इसने मंत्रालय को सरकारी नीतियों, योजनाओं और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन ढांचे में सुधार के लिए सुधारों की पहचान करने और अपने वांछित लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करने में सक्षम बनाया है।
- मंत्रालयों/विभागों का ऐसा रिपोर्ट कार्ड लाने के लिए डीएमईओ, नीति आयोग का प्रयास अत्यंत सराहनीय है। यह वांछित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सरकारी नीतियों, योजनाओं और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन ढांचे को बेहतर बनाने में बहुत मदद करेगा।
- डेटा-संचालित दृष्टिकोण नीति निर्माताओं को प्रवृत्तियों, अवसरों और सुधार के क्षेत्रों की सटीक रूप से पहचान करने में सक्षम बनाता है।
- विश्वसनीय डेटा के साथ, मंत्रालय सूचित निर्णय ले सकते हैं जो नागरिकों के लिए बेहतर परिणाम प्रदान करते हैं।
- इसके अलावा, डेटा-संचालित निर्णय लेना लागत प्रभावी है और पारदर्शिता बढ़ाता है, जिससे योजनाओं और नीतियों की प्रगति को ट्रैक करना आसान हो जाता है।
- डेटा और प्रौद्योगिकी का लाभ उठाकर, MoPSW ने अन्य मंत्रालयों और विभागों के अनुकरण के लिए एक उच्च मानक निर्धारित किया है।

प्रवासन के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन

खबरों में क्यों

एमी पोप संयुक्त राष्ट्र की प्रवासन एजेंसी की प्रमुख बनने वाली पहली महिला चुनी गई

महत्वपूर्ण बिंदु

- संयुक्त राष्ट्र प्रवासन एजेंसी के सदस्य देशों ने संयुक्त राज्य अमेरिका के एमी पोप को अपना अगला महानिदेशक चुना।
- पोप ने अपने बॉस, पुर्तगाल के एंटोनियो विटोरिनो को कोहनी मारकर इंटरनेशनल ऑर्गनाइजेशन फॉर माइग्रेशन (IOM) के महानिदेशक की नौकरी दी और 1951 में स्थापित जिनेवा स्थित एजेंसी की प्रमुख बनने वाली पहली महिला बनीं।
- पोप वर्तमान में विटोरिनो के डिप्टी के रूप में कार्य करता है और नौकरी के लिए उसके खिलाफ दौड़ा।
- उनका पांच साल का कार्यकाल 1 अक्टूबर 2023 से शुरू होगा।
- आमना-सामना इस मायने में असामान्य था कि पोप सहयोगियों के बीच एक प्रतियोगिता में अपने बॉस को हटाना चाह रहे थे: संयुक्त राज्य अमेरिका और
- पुर्तगाल नाटो के साथी सदस्य हैं।
- पोप की उम्मीदवारी का पुरजोर समर्थन करने वाली अमेरिकी सरकार ने इस खबर का स्वागत किया।

आईओएम के बारे में

- यह 1951 में स्थापित किया गया था, यह प्रवासन के क्षेत्र में अग्रणी अंतर सरकारी संगठन है।
- आईओएम संबंधित संगठन के रूप में संयुक्त राष्ट्र प्रणाली का हिस्सा है।
- इसके 175 सदस्य देश हैं (भारत एक सदस्य है)।
- यह प्रवास के मुद्दे पर अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रवासन के व्यवस्थित और मानवीय प्रबंधन को सुनिश्चित करने में मदद करने के लिए काम करता है।

10 योजना जून 2023: टेकाडे

1: अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में नवाचार

- अपनी स्थापना के बाद से, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) अंतरिक्ष अन्वेषण और प्रौद्योगिकी में सबसे आगे रहा है।
- संगठन और इसके महत्वपूर्ण संसाधनों की मदद से अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाकर भारत वर्षों से अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी रहा है।
- इसरो ने कई तकनीकी सीमाओं पर अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और नवाचार की प्रगति का अनुभव किया था।

अंतरिक्ष परिवहन प्रणाली:

- ठोस-प्रणोदन-आधारित साउंडिंग रॉकेट के आविष्कार के साथ, जो 30 किलोग्राम कार्गो को 120 किमी की ऊंचाई तक उठा सकता है, 1970 के दशक में अंतरिक्ष परिवहन प्रणाली का जन्म हुआ।
- तरल प्रणोदन के उपयोग से उपग्रह प्रक्षेपण यान (SLV) और संवर्धित एसएलवी (ASLV) जैसे प्रक्षेपण यानों की पहली पीढ़ी का निर्माण उसके बाद आया।
- ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान (PSLV), जो ध्रुवीय कक्षा में 1700 किलोग्राम पेलोड वितरित कर सकता है, ठोस और तरल प्रणोदन के विलय और कई महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों के विकास के परिणामस्वरूप बनाया गया था।
- तीसरी पीढ़ी के रॉकेट, या GSLV लॉन्च वाहनों के निर्माण में महत्वपूर्ण तकनीकी प्रगति, जो भू-सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट (GTO) में 2000 किलोग्राम पेलोड डालने में सक्षम हैं, क्रायोजेनिक प्रोपल्सिव इंजन का घरेलू निर्माण था।
- उच्च-थ्रूपुट संचार उपग्रह प्रक्षेपण के लिए लॉन्च वाहन MK3 (LVM3) के निर्माण की आवश्यकता थी, जो एक अधिक परिष्कृत प्रक्षेपण वाहन है।
- LVM3 दुनिया में तीसरे सबसे बड़े ठोस बूस्टर के साथ-साथ उच्च क्षमता वाले तरल और क्रायोजेनिक इंजन से लैस है, और यह GTO में 4000 किलो पेलोड लॉन्च करने में सक्षम है।
- लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान (ASLV) इसरो का एक नया प्रक्षेपण यान है।

अंतरिक्ष अवसंरचना:

- शुरुआत में, ISRO ने SLV-3 और ASLV जैसे उपग्रह लॉन्चर बनाने पर ध्यान केंद्रित किया, जिनका उपयोग छोटे उपग्रहों को पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित करने के लिए किया जाता था।
- GSLV, एक अधिक शक्तिशाली रॉकेट जो भू-समकालिक स्थानांतरण कक्षा में बड़े पेलोड ले जा सकता है, 1990 के दशक के अंत में इसरो द्वारा प्रारंभिक अध्ययन का विषय था।
- 2001 में GSLV के प्रारंभिक सफल प्रक्षेपण के बाद से, इसका उपयोग करते हुए कई महत्वपूर्ण उपग्रहों को प्रक्षेपित किया गया है।
- 2008 में चंद्रयान-1, भारत के पहले चंद्र मिशन के प्रक्षेपण के साथ, इसरो ने 2000 के दशक में गहरे अंतरिक्ष अन्वेषण पर ध्यान केंद्रित करना शुरू किया।
- मार्स ऑर्बिटर मिशन, जिसे 2013 में लॉन्च किया गया था, अगला था। इस लॉन्च के साथ, भारत अपने शुरुआती प्रयास में सफलतापूर्वक मंगल ग्रह पर एक अंतरिक्ष यान भेजने वाला पहला राष्ट्र बन गया।
- भारतीय क्षेत्रीय नौवहन उपग्रह प्रणाली (IRNSS), एक उपग्रह आधारित नौवहन प्रणाली है जिसकी तुलना GPS से की जा सकती है, जिसे इसरो द्वारा 2016 में पेश किया गया था।
- यह प्रणाली, जिसे अब NAVIC के रूप में जाना जाता है, पूरे भारत और पड़ोसी क्षेत्रों में उपयोगकर्ताओं को सटीक स्थिति संबंधी डेटा देती है।
- इसरो हाल के वर्षों में मानव अंतरिक्ष उड़ान के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे का निर्माण कर रहा है।
- इसमें क्रू एस्केप मैकेनिज्म का परीक्षण करना और अंतरिक्ष यात्रियों को ले जाने के लिए क्रू मॉड्यूल बनाना शामिल है। गगनयान, ISRO का पहला चालक दल मिशन, 2024 में लॉन्च होने वाला है।

अंतरिक्ष अनुप्रयोग:

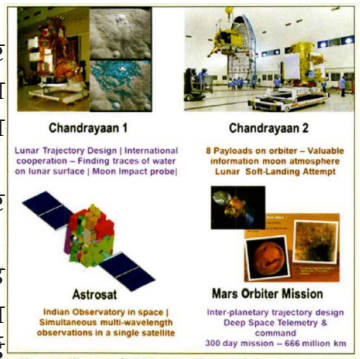

- राष्ट्रीय सुरक्षा, कृषि, कृषि वानिकी, आपदा प्रबंधन, मत्स्य पालन, भूमि उपयोग और भूमि कवर (LULC), संसाधन मानचित्रण, योजना, निगरानी और मूल्यांकन के साथ-साथ महत्वपूर्ण प्रमुख सरकारी कार्यक्रमों के लिए निर्णय समर्थन पर ध्यान देने के साथ ISRO द्वारा पृथ्वी अवलोकन (EO) के लिए आवेदन कई उपयोगकर्ता मंत्रालयों/विभागों में संस्थागत हैं।
- सुदूर संवेदन/PO अनुप्रयोगों के लिए उपरोक्त आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इमेजिंग और ग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी प्रगति हुई है।
- मल्टी-ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग रडार, पृथ्वी अवलोकन उपग्रहों के लिए एक एकीकृत मल्टी-मिशन ग्राउंड सेगमेंट, पोलारिमेट्रिक डॉपलर वेदर रडार और भारती स्टेशन, अंटार्कटिका में पृथ्वी अवलोकन उपग्रहों के लिए एक अत्याधुनिक उन्नत ग्राउंड स्टेशन ग्राउंड टेक्नोलॉजी के उदाहरण हैं। कई अंतरिक्ष वस्तुओं पर नज़र रखने के लिए जिसने उपग्रह सेवाओं का लगातार उपयोग करना आसान बना दिया है।

जारी प्रोजेक्ट:

- पुन: प्रयोज्य लॉन्च वाहन, स्टेज रिकवरी और पुन: उपयोग, वर्टिकल टेक-ऑफ और लैंडिंग (VTVL), LOX-मीथेन इंजन, वायु श्वास/हाइब्रिड प्रणोदन, अंतरिक्ष रोबोटिक्स, ह्यूमनॉइड रोबोट, उन्नत जड़त्वीय प्रणाली, कम लागत वाले अंतरिक्ष यान, क्वांटम संचार, उन्नत वैज्ञानिक पेलोड, अंतरिक्ष आधारित निगरानी और परमाणु घड़ी ऐसे सभी क्षेत्र हैं जहां अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी नवाचार अभी भी प्रगति कर रहा है।
- अंतरिक्ष और अंतरिक्ष पर्यटन के लिए सस्ती पहुंच के लिए प्रौद्योगिकी विकसित करने के प्रयास में इसरो एक पुन: प्रयोज्य लॉन्च वाहन (RLV) कार्यक्रम पर काम कर रहा है।
- इसरो भविष्य के लिए लागत प्रभावी अंतरिक्ष परिवहन प्रणाली के लिए पुन: प्रयोज्य वायु श्वास प्रणोदन भी विकसित कर रहा है।
- एयरफ्रेम इंटीग्रेटेड सिस्टम (HAVA) के साथ हाइपरसोनिक एयर ब्रीथिंग व्हीकल एक एकीकृत स्क्रैमजेट इंजन है जो अब इसरो के अनुसंधान और विकास प्रयासों का केंद्र बिंदु है।

2: स्टार्टअप्स- भारत की विकास गाथा में क्रांतिकारी बदलाव

- स्टार्टअप्स हाल के वर्षों में भारत के आर्थिक विकास में एक महत्वपूर्ण शक्ति बन गए हैं। नवाचार और उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करने पर सरकार के जोर के परिणामस्वरूप भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम का तेजी से विस्तार हुआ है।
- NASSCOM सर्वेक्षण के अनुसार, 50,000 से अधिक फर्मों के साथ भारत में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र है।
- पिछले कई वर्षों में, धन उगाहने वाली गतिविधियों ने देश के उद्यमशीलता पारिस्थितिकी तंत्र में तेजी से विस्फोट किया है। केवल 2022 में, भारतीय कंपनियों ने लगभग 25 बिलियन डॉलर जुटाए।
- भारतीय यूनिकॉर्न भी तेजी से गतिमान, गतिशील वातावरण में फल-फूल रहे हैं, रचनात्मक समाधानों के साथ आ रहे हैं और इस प्रक्रिया में बहुत सारी नौकरियां पैदा कर रहे हैं।
- आज भारत की आबादी में लगभग 108 यूनिकॉर्न हैं, जो इसे दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा यूनिकॉर्न देश बनाता है।

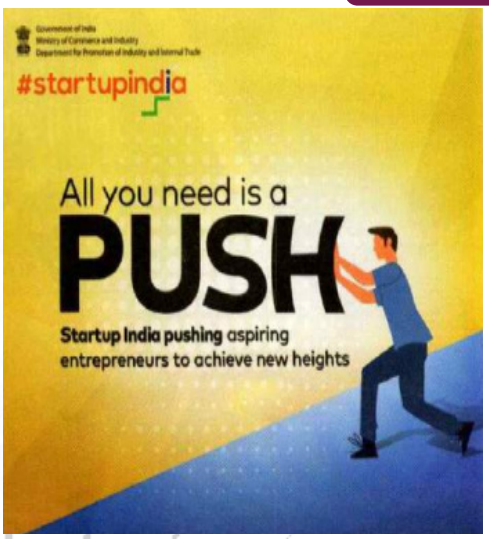

वित्त पोषण में वृद्धि:

- स्टार्टअप्स के लिए विकास के शुरुआती चरणों में डिजिटाइजेशन के बढ़ते उपयोग और वित्त की आसान पहुंच, स्टार्टअप्स के लिए फंडिंग में उछाल के मुख्य चालक थे।
- प्रारंभिक और परिपक्व दोनों चरणों में धन प्राप्त करने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित और तेज करने के लिए, स्टार्टअप इंडिया ने कई कार्यक्रम बनाए हैं।
- स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम (SIFSS), जिसका बजट 945 करोड़ रुपये है और एंजल निवेशकों और उद्यम पूंजी फर्मों से प्रारंभिक चरण के वित्त पोषण का समर्थन करता है, प्रारंभिक चरण के स्टार्टअप को अवधारणा के प्रमाण, प्रोटोटाइप विकास, उत्पाद के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। परीक्षण, बाजार में प्रवेश और व्यावसायीकरण।
- फंड ऑफ फंड्स कार्यक्रम, जिसे 2016 में स्थापित किया गया था, व्यवसायों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए समर्पित एक अन्य सरकारी पहल है।
- कई प्रबंधकीय और नियामक चुनौतियों के अलावा, स्टार्टअप्स द्वारा सामना की जाने वाली सबसे बड़ी समस्याओं में से एक उनकी पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शुरुआती चरण के ऋण तक आसान पहुंच है। पारंपरिक उधार देने वाले संस्थान, जैसे कि वाणिज्यिक बैंक, उसी पुराने शासनादेश पर भरोसा करते हैं।
- सरकार ने सेबी पंजीकृत वैकल्पिक निवेश कोष के तहत अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFC), और वेंचर डेट फंड (VDF) द्वारा DPIIT-मान्यता प्राप्त स्टार्टअप को ऋण गारंटी प्रदान करने के लिए स्टार्टअप्स के लिए क्रेडिट गारंटी योजना की स्थापना की है।

3: भारत के एडटेक क्षेत्र की क्षमता

- "एडटेक" या "एजुकेशन टेक्नोलॉजी" शब्द शिक्षण और सीखने में सुधार के लिए हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर या दोनों के अनुप्रयोग को संदर्भित करता है।
- आजकल, EdTech ऐप्स इंस्टॉल किए गए स्मार्टफोन शिक्षा का पर्याय बन गए हैं। दूरस्थ स्थानों में गरीब बच्चों तक पहुँचने के लिए एडटेक की क्षमता ने क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और आने वाले वर्षों में भी ऐसा करना जारी रखेगी।
- हर बच्चे की अलग-अलग मांगें होती हैं, साथ ही सीखने की अलग-अलग शैली और गति भी होती है। उनकी उम्र या समझ का स्तर कुछ भी हो, एडटेक हर किसी के लिए उच्च स्तर की शिक्षा प्राप्त करना संभव बनाता है।

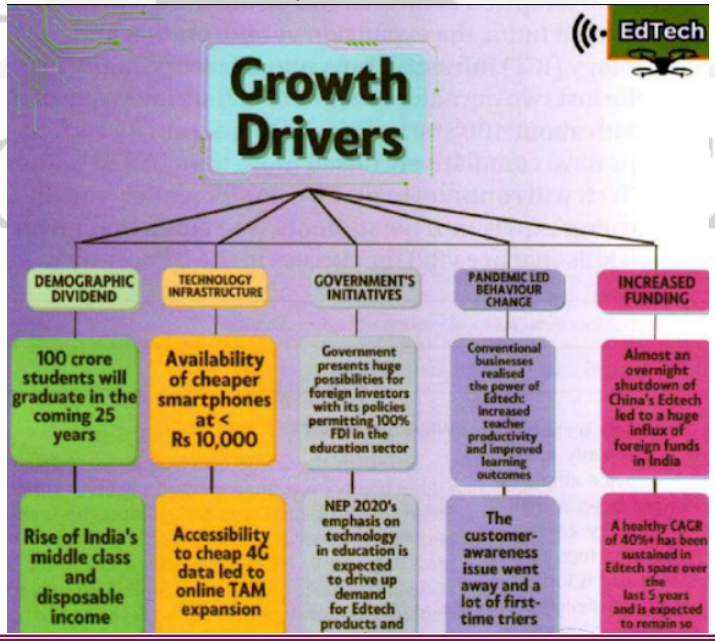

भारत की ICT क्रांति:

- EdTech की सफलता के लिए एक मजबूत सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (ICT) पारिस्थितिकी तंत्र सुलभ और उपलब्ध होना चाहिए।
- पिछले 25 वर्षों में, भारतीय ICT क्षेत्र ने उल्लेखनीय वृद्धि का अनुभव किया है। वित्त वर्ष 2022 में उद्योग का कुल राजस्व और कार्यबल क्रमशः 200 बिलियन अमेरिकी डॉलर और 5 मिलियन से अधिक हो गया। 2023 के अंत तक ICT पर U55144 बिलियन खर्च करने की उम्मीद है।
- इस निवेश का लगभग 52% सेवा क्षेत्र में जाने का अनुमान है। व्यवसाय रखरखाव से लेकर उद्यम समाधान आपूर्ति तक उद्योग के बदलाव में एडटेक की महत्वपूर्ण भूमिका शामिल है।
- एडटेक के उदय और त्वरित गति को भारत के त्वरित डिजिटलीकरण, ICT बुनियादी ढांचे के विस्तार और पिछले दो दशकों में प्रौद्योगिकी और सूचना की पहुंच से भी जोड़ा जा सकता है।
- 2010 में भारत में 92.5 मिलियन इंटरनेट उपयोगकर्ता थे; 2022 तक, यह संख्या 10 से गुणा होकर 932.2 मिलियन तक पहुंच जाएगी। 2040 तक, यह 1.53 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान है।
- यह इस तथ्य से भी संबंधित हो सकता है कि एक GB मोबाइल डेटा की कीमत सिर्फ 14 रुपये है, जो 2013 से 90% कम है, जिससे भारत अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सबसे कम डेटा मूल्य वाले देशों में से एक बन गया है।
- भारत में स्मार्टफोन उपयोगकर्ताओं की संख्या में 27 गुना वृद्धि हुई है, जो 2010 में 34 मिलियन से बढ़कर 2022 में 931 मिलियन हो गई है। 2040 तक इसके 1.53 बिलियन तक बढ़ने की उम्मीद है।
- इन कारकों के विकास और शिक्षण-सीखने की प्रक्रिया में एडटेक द्वारा प्रदान किए जाने वाले मूर्त लाभों ने एडटेक क्षेत्र और इसके विविध खिलाड़ियों के लिए अपनी उपस्थिति और अनुकूलन क्षमता का विस्तार करने का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रस्तुत किया है।

छात्रों और शिक्षकों के लिए एडटेक का महत्व:

- प्रौद्योगिकी के उपयोग से, शिक्षा अब सभी सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के लोगों के लिए सुलभ है।
- भारत में डिजिटल क्रांति के परिणामस्वरूप, एडटेक ने देश के अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंच का विस्तार किया है।
- छात्रों के लिए, एडटेक तीन मुख्य लाभ प्रदान करता है:
- जब आप सीखते हैं तब खेलना: एडटेक में गेमिफाइड दृष्टिकोण का उपयोग, विशेष रूप से ग्रेड K-6 के बच्चों के लिए, विद्यार्थियों को विचारों को समझने में मदद करता है और सीखने को सुखद बनाता है।
- कभी भी और कहीं भी कक्षाएं: भारत के अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचकर, एडटेक शिक्षा को सभी के लिए सुलभ बनाता है। छात्र इन कार्यक्रमों में अपनी सुविधा और गति से नामांकन कर सकते हैं। कामकाजी व्यक्ति अपने खाली समय का उपयोग नए कौशल सीखने में कर सकते हैं।
- योग्य प्रशिक्षकों तक पहुंच: एडटेक भारत के कस्बों और गांवों में योग्य शिक्षकों तक पहुंच बनाना संभव बनाता है।
- उनके निर्देश का समर्थन करने के लिए दिलचस्प शैक्षणिक तकनीकों की पेशकश करके, शैक्षिक तकनीक न केवल छात्रों बल्कि शिक्षकों को भी लाभान्वित करती है।
- इसमें इंटरैक्टिव व्हाइटबोर्ड, निर्देशात्मक फिल्में, VR/AR सिमुलेशन और अन्य ऑनलाइन टूल शामिल हो सकते हैं जो छात्रों को उनकी शिक्षा में अधिक शामिल होने का एहसास करा सकते हैं।
- ऑटोमेटेड ग्रेडिंग, क्लासरूम मैनेजमेंट टूल्स, पेपरलेस क्लासरूम, और अनुमान लगाने को हटाने के माध्यम से, एडटेक शिक्षाविदों के प्रशासन में भी मदद कर सकता है।
- अधिक सहयोगी, कम अराजक कार्यस्थल को बढ़ावा देने में कक्षा प्रबंधन सहायता के लिए उपकरण। पेपरलेस क्लासरूम प्रिंटिंग की लागत कम करते हैं और पर्यावरण के अनुकूल प्रथाओं का समर्थन करते हैं।
- एडटेक वास्तविक समय में छात्र की क्षमताओं और जरूरतों का मूल्यांकन कर सकता है, जिसके परिणामस्वरूप कठिन छात्रों की सहायता करने और अनिश्चितता को दूर करने के लिए सक्रिय कार्यक्रम होते हैं।

4: स्वास्थ्य सेवा में बदलाव के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना

- सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और सेवाएं सभी एक एकीकृत मंच पर "डिजिटल स्वास्थ्य" के रूप में जाने जाने वाले व्यापक अंतःविषय ढांचे में शामिल हैं।
- बेहतर गुणवत्ता, अधिक दक्षता और स्वास्थ्य सेवाओं तक आसान पहुंच पर जोर देने के साथ, डिजिटल स्वास्थ्य स्वास्थ्य देखभाल समाधानों के लिए प्रौद्योगिकी हस्तक्षेपों के उपयोग और स्वास्थ्य सेवा चाहने वालों और प्रदाताओं (व्यक्तियों, समुदाय या पेशेवर देखभालकर्ताओं, डॉक्टरों, पैरामेडिकल कार्यबल सहित और दवा और चिकित्सा उपकरण उद्योग) को सशक्त बनाने को संदर्भित करता है।
- ई-स्वास्थ्य, टेलीहेल्थ, टेलीमेडिसिन, टेली-परामर्श, स्वास्थ्य अनुप्रयोग आदि कुछ ऐसी शब्दावली हैं जिनका उपयोग किया जाता है।
- डिजिटल स्वास्थ्य की व्यापक परिभाषा में डेटा का डिजिटलीकरण (रोगी डेटा सहित), डेटा स्टैक, E-रजिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड (ENO), स्वास्थ्य सूचना विज्ञान और विश्लेषण प्लेटफॉर्म, स्व-स्वास्थ्य मॉनिटर और सेंसर के साथ पहनने योग्य स्वास्थ्य उपकरण शामिल हैं।

- एक ही सांस में, AI से जैव प्रौद्योगिकी, जीनोमिक्स और चिकित्सा सहायता जैसे हाल के क्षेत्रों के बारे में भी चर्चा होती है।
- इंटरनेट ऑफ मेडिकल थिंग्स (IoMT), जो विभिन्न प्रकार की नेटवर्किंग तकनीकों का उपयोग करके स्वास्थ्य IT प्रणालियों से जुड़ता है, ने हाल ही में चिकित्सा उपकरणों और अनुप्रयोगों का भी विलय कर दिया है।
- इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) के अनुप्रयोगों में रोगी-चिकित्सक संपर्क बढ़ाने, संक्रामक बीमारियों के जोखिम को कम करने के लिए टेलीमेडिसिन तकनीक और विभिन्न प्रकार की स्मार्ट सेंसर प्रौद्योगिकियां शामिल हैं जो उपयोगकर्ता स्तर पर डेटा एकत्र कर सकती हैं।

डिजिटल स्वास्थ्य हस्तक्षेपों का विकास:

- 2022 में डिजिटल स्वास्थ्य का वैश्विक बाजार मूल्य 332.53 बिलियन अमेरिकी डॉलर होने और 2032 तक 1,694.21 बिलियन अमेरिकी डॉलर के शिखर पर पहुंचने की उम्मीद है।
- यद्यपि मोबाइल-समर्थित स्वास्थ्य हस्तक्षेपों का उपयोग कुछ समय के लिए हुआ है, यह आमतौर पर स्वीकार किया जाता है कि विश्वव्यापी महामारी ने डिजिटल स्वास्थ्य अग्रिमों के उपयोग को महत्वपूर्ण रूप से त्वरित और मुख्यधारा में ला दिया है।
- प्रौद्योगिकी ने सेवाओं को बढ़ाने के लिए समाधानों की सुविधा प्रदान की और बड़ी संख्या में उन लाभार्थियों को शामिल करने के लिए उनका विस्तार किया, जो ऐसे समय में अपने घरों के आराम से अक्सर उच्च गुणवत्ता वाली सेवाओं तक पहुंच सकते हैं, जब स्वास्थ्य सेवा चाहने वालों और प्रदाताओं दोनों से स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता और ध्यान दिया जाता है।
- टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म और रिमोट मॉनिटरिंग टूल्स के व्यापक उपयोग के कारण हेल्थकेयर प्रैक्टिशनर अब रोगी के स्वास्थ्य की निगरानी करने और दूर से देखभाल करने में सक्षम हैं।
- यह उल्लेख किया गया है कि दुनिया भर में स्वास्थ्य और फिटनेस के लिए कई ऐप, स्मार्टफोन के बढ़ते उपयोग के साथ, डिजिटल स्वास्थ्य बाजार की उपस्थिति और विस्तार के प्रमुख चालक होने का अनुमान है।
- इसके अतिरिक्त, यह माना जाता है कि हेल्थकेयर IT अवसंरचना में त्वरित निवेश, विशेष रूप से विकासशील और विकसित देशों में, उद्योग के विकास को बढ़ाने में मदद करेगा।
- टेलीमेडिसिन के मुख्य लाभों में से एक यह है कि इससे समय और प्रयास की बचत हो सकती है, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों के रोगियों के लिए जिन्हें परामर्श और उपचार के लिए दूर जाने की आवश्यकता नहीं होती है।
- हाशिए पर और गरीब आबादी द्वारा स्वास्थ्य देखभाल के लिए यात्रा के साथ अक्सर काम के घंटों में कमी, आय में कमी और कम उत्पादकता के साथ, यह यात्रा-संबंधी खर्चों में कमी के साथ भी होता है।
- एक NGO द्वारा हाल ही में किए गए प्रभाव विश्लेषण के अनुसार, आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में प्रत्येक टेली-परामर्श रोगियों को औसतन 21.58 किलोमीटर तक की यात्रा करने और चिकित्सा व्यय पर 941 रुपये से अधिक खर्च करने से रोकता है।
- महिला देखभालकर्ताओं वाले परिवार, विशेष रूप से वे जो गर्भवती हैं या नर्सिंग हैं, को यात्रा संबंधी तनाव का अनुभव करने की सूचना मिली है।
- आबादी के एक बड़े हिस्से के लिए उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच की गारंटी देकर, डिजिटल स्वास्थ्य 2030 तक दुनिया को अपने सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद कर सकता है।

भारत में डिजिटल स्वास्थ्य समाधान:

- डिजिटल स्वास्थ्य समाधान एक मजबूत और अधिक लचीली राष्ट्रीय स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली के आवश्यक स्तंभ साबित हुए हैं।
- डिजिटल उपकरणों के अधिक व्यापक उपयोग के परिणामस्वरूप भारतीय स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में बदलाव की उम्मीद है, जिससे बेहतर नागरिक सेवा, स्वास्थ्य चाहने वालों की संतुष्टि, गुणवत्ता और दक्षता के अधिक स्तर और पारदर्शिता और जवाबदेही में वृद्धि होगी।
- भारत सरकार की डिजिटल पहलों में समावेशिता, बहुभाषी प्लेटफॉर्म, स्केलेबिलिटी और इंटरऑपरेबिलिटी सहित कई महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। एक अरब से अधिक लोग उनसे लाभान्वित हुए हैं।
- निम्नलिखित कुछ पहलें हैं जिन्हें असंख्य लाभों के साथ लोगों के बीच व्यापक स्वीकृति मिली है।
- आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन
- कोविन: काउइन का मतलब है कोविड वैक्सीन इंटेलीजेंट नेटवर्क। मंच का अनावरण केंद्र सरकार द्वारा जनवरी 2021 में देश भर में एक वैक्सीन अभियान शुरू करने के लिए किया गया था।

टेली-मानस

- निक्षय 2.0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 2025 तक टीबी को खत्म करने के लिए 'प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान' और निक्षय 2.0 पोर्टल लॉन्च किया।
- निक्षय 2.0 तपेदिक के निदान वाले व्यक्तियों के लिए सामुदायिक सहायता के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है।
- इस पोर्टल का उद्देश्य निक्षय योजना के लिए प्रौद्योगिकी बैकअप प्रदान करना है, जिसका उद्देश्य समुदायों, हितधारकों, निर्वाचित प्रतिनिधियों, कॉरपोरेट्स, NGO और व्यक्तियों को अतिरिक्त नैदानिक, पोषण और व्यावसायिक के माध्यम से मरीजों की मदद करने के लिए दाताओं के रूप में आगे आना है।

स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी आकलन (HTA):

- स्वास्थ्य के क्षेत्र में पारदर्शिता और साक्ष्य-सूचित निर्णय लेने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए, भारत सरकार ने स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग (DHR) के तहत भारत में स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी आकलन (HTAIn) के रूप में जाना जाने वाला एक संस्थागत ढांचा स्थापित किया।
- यह देश की नई और मौजूदा स्वास्थ्य तकनीकों की लागत-प्रभावशीलता और उपयुक्तता का आकलन प्रदान करता है।
- HTA रोगी-केंद्रित, सुरक्षित और लागत प्रभावी स्वास्थ्य नीतियों के विकास में सहायता करने का प्रयास करता है जो पैसे के मूल्य को अधिकतम करती हैं।

5: क्वांटम कंप्यूटिंग-ट्रांसफॉर्मिंग टेक्नोलॉजी

- पारंपरिक कंप्यूटर सूचनाओं को एनकोड करने के लिए Os और 1s के "बिट्स" बाइनरी अंकों का उपयोग करता है। क्वांटम कंप्यूटिंग, इसके विपरीत, क्वांटम बिट्स का उपयोग करती है।
- केवल दो अवस्थाओं (अर्थात, 0 और 1) के बजाय, क्वांटम कंप्यूटिंग क्वांटम बिट्स या "क्विबिट्स" का उपयोग करती है, जो एक साथ कई अवस्थाओं में मौजूद हो सकते हैं।
- क्वांटम कंप्यूटर पारंपरिक कंप्यूटरों की तुलना में परिमाण के कई कम्प्यूटेशनल ऑपरेशंस ऑर्डर को तेजी से पूरा करने में सक्षम हैं क्योंकि क्यूबिट्स"सुपरपोजिशन' विशेषता है।
- इसके अलावा, उलझाव, क्वांटम भौतिकी की एक विशेषता जो दो क्यूबिट्स को इस तरह से युग्मित करने की अनुमति देती है कि उनके राज्य स्वाभाविक रूप से एक दूसरे से प्रभावित होते हैं, क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए प्रेरणा के एक अन्य स्रोत के रूप में कार्य करता है।
- अनुसंधान और नवाचार में रणनीतिक सहयोग और निवेश के माध्यम से राष्ट्र और उद्योग धीरे-धीरे क्वांटम कंप्यूटिंग तरंग का लाभ उठाने के लिए तैयार हो रहे हैं।

क्वांटम कम्प्यूटिंग का प्रभाव:

- क्वांटम कंप्यूटिंग का भविष्य उभरते हुए कौशल बल की कौशल आवश्यकताओं और क्षमताओं को मौलिक रूप से बदल देगा, जो धीरे-धीरे डेटा विज्ञान, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मशीन सीखने और निर्णय विज्ञान के क्षेत्र में आधार प्राप्त कर रहा है। यह सूचना प्रौद्योगिकी (IT) और IT-सक्षम सेवाओं के क्षेत्र में भारत की बढ़ती क्षमताओं के कारण है।
- औद्योगिक डेटा विज्ञान अनुप्रयोग जो डेटा का अधिक तेज़ी से विश्लेषण करते हैं: पारंपरिक कंप्यूटिंग लॉजिक की तुलना में क्वांटम कंप्यूटर द्वारा कुछ संगणनाएँ कहीं अधिक तेज़ी से पूरी की जा सकती हैं। यह बड़े डेटा के युग में व्यावसायिक चुनौतियों के लिए तेजी से डेटा विश्लेषण का कारण बन सकता है, विशेष रूप से उच्च वेग के साथ बड़े पैमाने पर डेटासेट के लिए, क्योंकि इस प्रकार की गणनाओं का दायरा और पैमाने में विस्तार होता है।
- बेहतर मशीन लर्निंग परिणाम: पूर्वानुमानित क्षमताएं और बेहतर डेटा-संचालित निर्णय लेना ऐसे दो क्षेत्र हैं जहां मशीन लर्निंग एल्गोरिदम को अधिक से अधिक नियोजित किया जा रहा है।
- ये एल्गोरिदम कंप्यूटर दृष्टि का उपयोग करके विभिन्न कॉर्पोरेट और सामाजिक मुद्दों को संबोधित करने के लिए संज्ञानात्मक कंप्यूटिंग के युग में फ़ोटो और वीडियो जैसे जटिल डेटा प्रकारों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं।
- इन एल्गोरिदम के अधिक प्रभावी अनुकूलन को सक्षम करके, क्वांटम कंप्यूटर मशीन लर्निंग को बढ़ा सकते हैं और कंप्यूटर दृष्टि की गति, सटीकता और दक्षता को बढ़ा सकते हैं।
- क्वांटम कंप्यूटिंग में ऐसे आर्किटेक्चर का निर्माण करने की क्षमता है जो सुझाव प्रदान करने के लिए डिजिटल दुनिया में सूचना के नेटवर्क के वास्तविक समय के अपडेट की जांच करता है, जिसका अर्थ है कि उत्पादक कृत्रिम बुद्धि के ये अनुप्रयोग मजबूत अनुशंसाओं से लाभान्वित हो सकते हैं।

अभ्यास और नीति के लिए निहितार्थ:

- क्वांटम कंप्यूटिंग के अत्याधुनिक क्षेत्र में, अनुसंधान और विकास अभी भी अपनी प्रारंभिक अवस्था में हैं।
- यह भारत को शीर्ष प्रौद्योगिकी संस्थानों में अच्छी तरह से वित्त पोषित अनुसंधान केंद्र उत्कृष्टता बनाने का अवसर प्रदान करता है।
- प्रसिद्ध तकनीकी इंजीनियरिंग संस्थानों में प्रमुख बुनियादी ढांचे और कार्यबल विकास पहलों के वित्तपोषण की अनुमति देते हुए, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की ओर से दीर्घकालिक योजनाओं का प्रस्ताव किया जा सकता है।
- घरेलू क्वांटम प्रौद्योगिकी क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए, इसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों को शामिल करने की आवश्यकता होगी।

6: AI चैटबॉट्स-भविष्य और चुनौतियां

- चैटबॉट कंप्यूटर प्रोग्राम हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का उपयोग करके पाठ या आवाज के माध्यम से उपयोगकर्ताओं के

साथ मानव-समान संचार को दोहराते हैं। उनके पास उपयोग की एक विस्तृत श्रृंखला है, जिसमें बिक्री, ग्राहक सेवा और व्यक्तिगत सहायक शामिल हैं।

- नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग (NLP) एक तकनीक है जिसका इस्तेमाल चैटबॉट्स उपयोगकर्ता इनपुट को समझने और उसकी व्याख्या करने और उचित उत्तर देने के लिए करते हैं।
- व्यक्तिगत उपयोग के मामले और परिष्कार के आवश्यक स्तर के आधार पर, उन्हें अकेले या मानव ऑपरेटरों के सहयोग से काम करने के लिए बनाया जा सकता है।
- वे तेजी से जटिल, संदर्भ-जागरूक और स्व-शिक्षण एल्गोरिदम में विकसित हो गए हैं जो प्रश्नों और उत्तरों के व्यापक ज्ञान आधार का निर्माण करने के लिए गहन शिक्षण और मशीन लर्निंग पर निर्भर करते हैं।
- परिणामस्वरूप, वे धीरे-धीरे उपभोक्ताओं की जरूरतों का अनुमान लगाने और सटीक समाधान पेश करने की अपनी क्षमता में सुधार कर रहे हैं।

काम का भविष्य:

- चैटबॉट हमारे काम करने और सामग्री तैयार करने के तरीके में क्रांति ला रहे हैं।
- ग्राहक सेवा, अपॉइंटमेंट लेना और डेटा इनपुट करना सभी दोहराए जाने वाले, उबाऊ काम हैं जो चैटबॉट कर सकते हैं। अधिक कठिन कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मानव कर्मचारियों को अधिक समय देकर, इससे फर्मों को समय बचाने और दक्षता बढ़ाने में मदद मिल सकती है।
- एक तकनीकी दिग्गज ने हाल ही में अपने अनुप्रयोगों की श्रेणी में एक शक्तिशाली जनरेटिव AI तकनीक को शामिल करने की घोषणा की। इस चैटबॉट द्वारा कई ऐप्स में कई कार्यों को स्वचालित किया जा सकता है।
- चैटबॉट चौबीसों घंटे काम कर सकते हैं, ग्राहकों और स्टाफ के सदस्यों को जरूरत पड़ने पर सहायता प्रदान कर सकते हैं। बेहतर ग्राहक सेवा और त्वरित प्रतिक्रिया समय प्रदान करके, यह फर्मों को प्रतिस्पर्धी बने रहने में मदद कर सकता है।
- इंटरनेट खोज एक ऐसा क्षेत्र है जहां जनरेटिव अल का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ रहा है। जनरेटिव एआई, या एक AI की शुरूआत जो ताजा डेटा या टेक्स्ट, फोटो या यहां तक कि वीडियो जैसी सामग्री बना सकती है, ने लोगों को इंटरनेट पर खोज करने के तरीके को पूरी तरह से बदल दिया है। यह तकनीक क्रांति ला रही है कि हम ऑनलाइन जानकारी कैसे खोजते हैं और भविष्य में खोज इंजनों पर इसका महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की संभावना है।

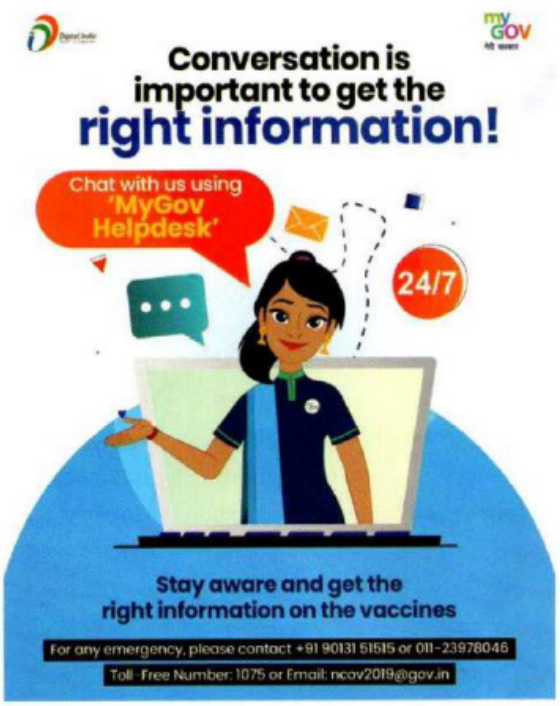

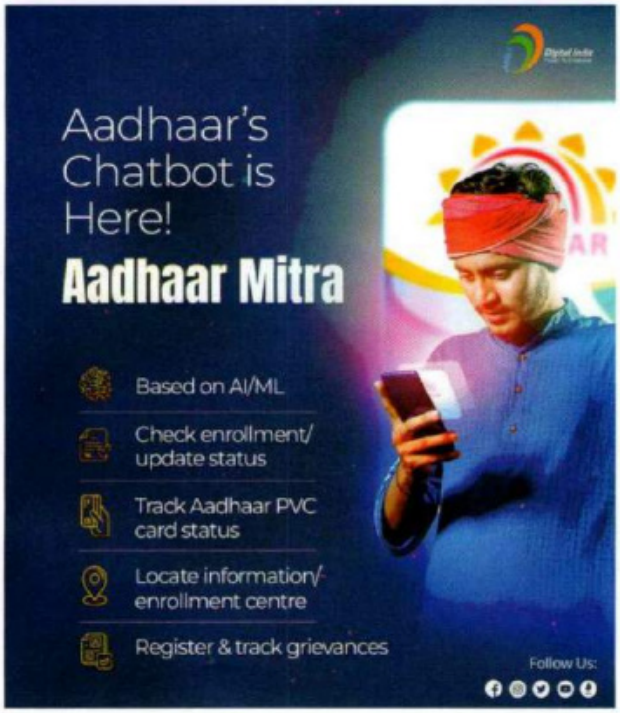

चैटबॉट्स के मामले:

- रोगियों और स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों को सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करके, AI चैटबॉट्स में स्वास्थ्य सेवा उद्योग में क्रांति लाने की क्षमता है। वे आभासी सहायकों के रूप में सेवा कर सकते हैं जो रोगियों को स्वास्थ्य देखभाल के बारे में उनके प्रश्नों के साथ मदद करते हैं। चौबीसों घंटे उनकी पहुंच लोगों को जब भी और जहां भी जरूरत हो बुनियादी स्वास्थ्य सेवा प्राप्त करने में सक्षम बनाकर स्वास्थ्य सेवा प्रणाली पर पड़ने वाले दबाव को कम करती है।
- लक्षण निदान और चिकित्सा सिफारिश सहित स्वास्थ्य संबंधी कार्यों में सहायता के लिए चैटबॉट्स को नियोजित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, एडा वेबसाइट पर चैटबॉट निदान और उपचार रणनीति प्रदान करने के लिए उपयोगकर्ताओं से उनके लक्षणों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता है।
- उपयोगकर्ता अपने कैलेंडर प्रबंधित करने, रिमाइंडर बनाने और यहां तक कि खाने का ऑर्डर देने के लिए निजी सहायक के रूप में चैटबॉट का उपयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, उपभोक्ता डोमिनोज़ की वेबसाइट पर चैटबॉट का उपयोग करके ऑर्डर दे सकते हैं।
- चैटबॉट मानव संसाधन प्रक्रियाओं को स्वचालित करने में सहायता कर सकते हैं, जिसमें नए नियुक्तियों को उन्मुख करना और

मानव संसाधन से संबंधित प्रश्नों का उत्तर देना शामिल है। उदाहरण के लिए, यूनिलीवर वेबसाइट पर चैटबॉट स्टाफ के सदस्यों को पास के डेकेयर केंद्रों की पहचान करने और लाभ और पेरोल के बारे में जानकारी देने में मदद कर सकता है।

- ई-कॉमर्स व्यवसायों द्वारा अल चैटबॉट्स का उपयोग अपने ग्राहकों को उन वस्तुओं को खोजने में सहायता करने के लिए किया जा रहा है जो वरीयताओं के बारे में पूछताछ करके और प्रासंगिक उत्पादों को प्रदर्शित करके उनकी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। वे चीजों को ऑर्डर करने और भुगतान करने जैसी प्रक्रियाओं के माध्यम से भी उनका मार्गदर्शन कर सकते हैं।
- शिक्षा एक प्रमुख क्षेत्र है जहां अल चैटबॉट तेजी से प्रासंगिक होते जा रहे हैं। जनरेटिव AI हमारी शिक्षा प्रणाली के डिजिटल परिवर्तन में मदद कर सकता है और इसे अधिक कुशल और सुलभ बना सकता है। यह सामग्री निर्माण में मदद कर सकता है, शैक्षिक सामग्री का कई भाषाओं में अनुवाद कर सकता है और यहां तक कि जहां शिक्षण संसाधनों की कमी है वहां एक शिक्षक या प्रशिक्षक की भूमिका भी निभा सकता है।

चुनौतियां:

- अल चैटबॉट्स के साथ प्रमुख चिंता यह है कि जैसे-जैसे उनका उपयोग बढ़ता है, यदि अल मानव उत्पादन और बुद्धि से मेल खाने की क्षमता विकसित करता है तो बड़ी संख्या में नौकरियां खो सकती हैं।
- स्लैंग, क्षेत्रीय बोलियाँ, और संदर्भ मानव भाषा की पेचीदगियों के कुछ ही उदाहरण हैं जिन्हें चैटबॉट को देखने और समझने में सक्षम होना चाहिए। निरंतर विकास और मानव भाषा के परिवर्तन को देखते हुए, यह एक सतत कार्य है।
- चैटबॉट के रचनाकारों और डेटा स्रोतों के पूर्वाग्रहों और भेदभावपूर्ण प्रथाओं को बॉट्स पर पारित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, पक्षपाती डेटा के साथ प्रोग्राम किया गया चैटबॉट कुछ लोगों को गलत तरीके से जवाब दे सकता है। डेवलपर्स को पक्षपात कम करने के लिए कार्रवाई करनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके चैटबॉट निष्पक्ष और स्वागत करने वाले हैं।
- चैटबॉट्स को खुला और विश्वसनीय होना चाहिए, विशेष रूप से निजी या संवेदनशील डेटा को संभालते समय। उपयोगकर्ताओं को निश्चित होना चाहिए कि चैटबॉट उनके डेटा का दुरुपयोग नहीं कर रहे हैं और इसे सही तरीके से प्रबंधित किया जा रहा है।
- सुरक्षा जोखिम, जैसे हैकिंग या फ़िशिंग प्रयास, चैटबॉट को प्रभावित कर सकते हैं।
- सहज उपयोगकर्ता अनुभव के लिए, चैटबॉट्स को ग्राहक संबंध प्रबंधन (CRM) सॉफ़्टवेयर जैसी मौजूदा प्रणालियों से जोड़ा जाना चाहिए। पुराने सिस्टम से निपटना जो समकालीन चैटबॉट तकनीक के साथ काम नहीं कर सकता है, इससे यह मुश्किल हो जाता है। मौजूदा वर्कफ़्लोज़ को प्रभावित किए बिना चैटबॉट्स को पुराने सिस्टम से जोड़ने के लिए, डेवलपर्स को एक समाधान खोजना होगा।

7: 5G साइबर सुरक्षा चुनौतियाँ

- मोबाइल नेटवर्क की पांचवीं पीढ़ी या 5G। 1G, 2G, 3G और 4G नेटवर्क के बाद, यह एक नया अंतरराष्ट्रीय वायरलेस मानक है।
- यह नेटवर्क के एक बिल्कुल नए वर्ग को संभव बनाता है, जिसका उद्देश्य मशीनों, चीजों और गैजेट्स सहित व्यावहारिक रूप से सभी को और सब कुछ एक साथ जोड़ना है।
- जबकि 4जी के लिए सबसे तेज़ इंटरनेट डेटा गति आमतौर पर 1 GBPS बताई गई है, 5G के हाई-बैंड स्पेक्ट्रम के परीक्षण से पता चला है कि इंटरनेट की गति 20 GBPS (गीगाबिट्स प्रति सेकंड) तक जा सकती है।

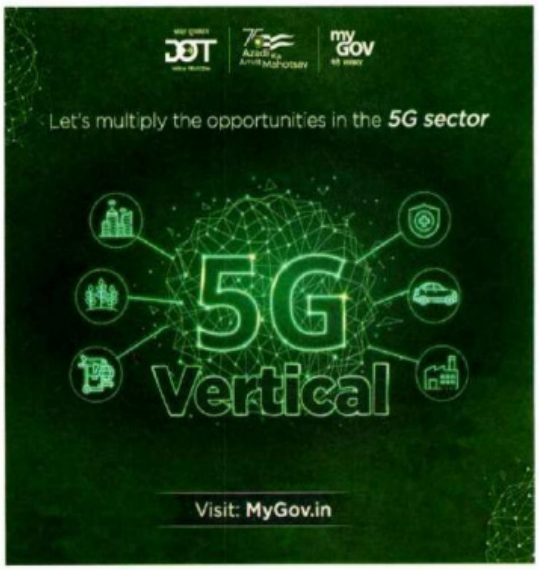

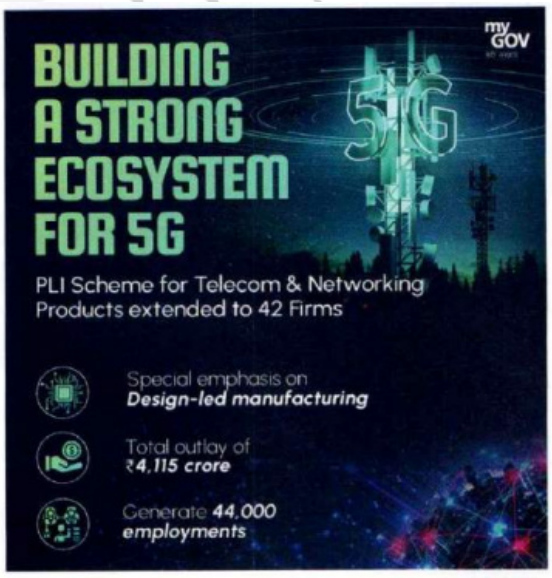

5G की भू-राजनीति:

- हमारे डिजिटल भविष्य पर प्रभाव डालने और आर्थिक क्रांति लाने की इसकी क्षमता के कारण बड़े अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार नेताओं ने 5जी तकनीक विकसित करने का बीड़ा उठाया है।
- चीनी दूरसंचार कंपनियां, जो सक्रिय रूप से प्रौद्योगिकी का व्यावसायीकरण करके और अपने प्रतिद्वंद्वियों की तुलना में इसे कम कीमतों पर प्रदान करके नए बाजारों में प्रवेश कर रही हैं, फिर भी, इस क्षेत्र को आगे बढ़ा रही हैं।
- इस संभावना पर चिंता व्यक्त की गई है कि चीन सक्रिय रूप से इन व्यवसायों को दुनिया भर के बाजारों पर कब्जा करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है और इसके परिणामस्वरूप, बड़े पैमाने पर छिपकर बातें सुनने वाला नेटवर्क बना सकता है।
- ऐसी चिंताएं हैं कि चीन चीनी दूरसंचार कंपनियों को ग्राहक डेटा तक सरकार की पहुंच प्रदान करने के लिए मजबूर करके या भू-राजनीतिक उथल-पुथल के दौरान उन्हें 5G नेटवर्क बंद करने के लिए मजबूर करके 5G तकनीक को हथियार बना सकता है।

- परिणामस्वरूप, पिछले कई वर्षों से, संयुक्त राज्य अमेरिका 5G बाजार में चीनी दूरसंचार कंपनियों के आधिपत्य को चुनौती देने के प्रयास में सबसे आगे रहा है।
- अमेरिकी सरकार ने हुआवेई और ZTE को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरों के रूप में वर्गीकृत किया है, अमेरिकी व्यवसायों को सरकारी सब्सिडी के माध्यम से उपकरण प्राप्त करने से प्रतिबंधित कर दिया है, और विशेष लाइसेंस के बिना सेमीकंडक्टर चिप्स की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है।
- चीन और संयुक्त सरकारों के बीच वाणिज्य की गतिशीलता के अलावा, इन परिवर्तनों ने लोकतांत्रिक सरकारों और सत्तावादी शासनों के बीच वैश्विक तकनीकी प्रतिस्पर्धा को प्रभावित किया है।
- परिणामस्वरूप, प्रमुख लोकतांत्रिक सरकारों को एकजुट करने का प्रयास किया गया है जो चीन और रूस जैसे सत्तावादी शासनों द्वारा उत्पन्न तकनीकी खतरे को सहयोगात्मक रूप से संबोधित करने के लिए समान विचार साझा करते हैं।
- उदाहरण के लिए, ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन द्वारा प्रस्तावित दस लोकतंत्रों का D-10 गठबंधन, 5G और अन्य भविष्य की तकनीकों के लिए एक अलग आपूर्ति श्रृंखला स्थापित करेगा।
- इंटरऑपरेबिलिटी और सुरक्षा को बढ़ाने की प्रतिज्ञा के अलावा, चतुर्भुज सुरक्षा संवाद, या क्वाड (जो भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त राज्य अमेरिका को एक साथ लाता है), ओपन RAN पर काम करने के लिए भी प्रतिबद्ध है, जो नकल करने के लिए सॉफ्टवेयर का उपयोग करता है। सिग्नल-प्रोसेसिंग संचालन और 5G के लिए आपूर्तिकर्ता विविधीकरण।

साइबर खतरे का परिदृश्य:

- चीनी दूरसंचार कंपनियों के प्रभुत्व और हार्डवेयर से उत्पन्न खतरों से परे, 5G के साइबर खतरे का परिदृश्य विविध है।
- शत्रुतापूर्ण सरकारों और अन्य खतरे वाले कारकों द्वारा साइबर हमलों और डेटा उल्लंघनों में मौजूदा वृद्धि के अंतर्निहित कारण भू-राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता, वित्तीय प्रेरणा और डेटा संचयन समान हैं। इस प्रकार वे 5G नेटवर्क को भी खतरे में डाल देंगे।
- निस्संदेह, 5जी को आर्थिक प्रगति और सामाजिक उन्नति में इसके संभावित योगदान को देखते हुए एक आवश्यक बुनियादी ढांचे के रूप में देखा जा सकता है। इसके प्रकाश में, तोड़फोड़ जैसे हमलों के लिए 5G संचार नेटवर्क एक प्रमुख लक्ष्य होगा।
- इसके अतिरिक्त, जैसा कि पहले ही संकेत दिया गया था, 5जी नेटवर्क के परिणामस्वरूप IoT-सक्षम उपकरणों का एक बड़ा प्रसार होगा।
- एक भविष्यवाणी में कहा गया है कि 2025 तक 27 बिलियन से अधिक IOT डिवाइस जुड़े होंगे।
- मैलवेयर और बॉटनेट फैलाने के नए साधन प्रदान करने वाले इन गैजेट्स के परिणामस्वरूप, खतरे का परिदृश्य चौड़ा हो गया है। इसके परिणामस्वरूप मैन-इन-द-मिडिल अटैक या डिस्ट्रीब्यूटेड डेनियल-ऑफ-सर्विस अटैक जैसे हमलों के अधिक अवसर होंगे।
- द इंटरनेशनल मोबाइल सब्सक्राइबर आइडेंटिटी (IMSI), जिसका उपयोग मोबाइल नेटवर्क पर ग्राहकों की पहचान करने और उन्हें प्रमाणित करने के लिए किया जाता है, एक भेद्यता है जो 5G भी पिछली पीढ़ी के प्रोटोकॉल से आगे बढ़ती है। IMSI को हथियाने और एक विशिष्ट क्षेत्र में मोबाइल संचार को बाधित करके, खतरे के अभिनेता एक विशिष्ट उपयोगकर्ता की गतिविधियों की निगरानी कर सकते हैं, जिसमें उनके ठिकाने की निगरानी करना और उनकी कॉल सुनना शामिल है।

8: डिजिटल प्रकाशन- क्षितिज का विस्तार करना

- भारतीय संस्कृति, आदर्शों और श्रेष्ठता की नींव प्रकाशन क्षेत्र है।
- भारत में प्रकाशन क्षेत्र सीखने और शिक्षा का समर्थन करता है, लाखों नौकरियां पैदा करता है और देश के आर्थिक विकास में सहायता करता है।
- 2022 में, इसने 33.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर की सीमा को पार कर लिया। एक शोध का दावा है कि बाजार 2023 से 2028 तक 3.4% वार्षिक चक्रवृद्धि दर से विस्तार करेगा, जो $41.6 बिलियन के मूल्य तक पहुंच जाएगा।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के समग्र शैक्षिक खर्च में वृद्धि ने भी भारतीय प्रकाशन क्षेत्र के विस्तार में योगदान दिया है।

डिजिटल प्रकाशन का विकास:

- प्रौद्योगिकी के परिणामस्वरूप प्रकाशन क्षेत्र में काफी परिवर्तन देखा गया है।
- डिजिटल प्रकाशन ने पारंपरिक प्रिंट मीडिया की जगह ले ली है, जिससे प्रकाशकों को बड़े दर्शकों तक पहुंचने में मदद मिली है। भारत में, डिजिटल प्रकाशन अभी शैशवावस्था में है।
- यह देश के प्रकाशन बाजार में 8 से 10% के बीच है, हालांकि हाल के वर्षों में भारत में डिजिटल प्रकाशन में काफी वृद्धि हुई है। एक शोध में दावा किया गया है कि क्षेत्रीय और डिजिटल सामग्री भारतीय मीडिया के विस्तार को आगे बढ़ाएगी।
- FY 2019 और FY 2024 के बीच, डिजिटल उद्योग के 29.1% वार्षिक गति से विस्तार करने का अनुमान है।
- 2024 तक, यह क्षेत्रीय सामग्री की ताकत से संचालित 621 अरब रुपये तक पहुंच जाएगा। इस प्रवृत्ति से निस्संदेह डिजिटल प्रकाशन प्रभावित होगा।
- स्मार्टफोन, टैबलेट और E-रीडर के तेजी से प्रसार के कारण जानकारी तक पहुंच अब पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गई है।
- डिजिटल प्रकाशन, पारंपरिक प्रकाशन के विपरीत, मुद्रण, शिपिंग, या भंडारण के लिए कोई लागत शामिल नहीं है। प्रकाशक विनिर्माण और वितरण व्यय को कम कर सकते हैं, उन बचत को सस्ती कीमतों के रूप में ग्राहकों को दे सकते हैं।
- भारत में डिजिटल प्रकाशन के विस्तार के लिए E-पुस्तकें महत्वपूर्ण रही हैं। नीलसन के एक अध्ययन से पता चला है कि 2018 में भारत में बेची गई 20% किताबें इलेक्ट्रॉनिक किताबें थीं। E-पुस्तकें मुद्रित पुस्तकों की तुलना में कई लाभ प्रदान करती हैं, जिसमें सामर्थ्य और सुगमता शामिल है।

चुनौतियां:

- डिजिटल प्रकाशन लाभ और कठिनाइयाँ दोनों प्रदान करता है। पायरेसी प्रमुख कठिनाइयों में से एक है।

- डिजिटल सामग्री व्यापक रूप से उपलब्ध है, जिससे उपयोगकर्ताओं के लिए अनुमति के बिना कॉपीराइट सामग्री प्राप्त करना और साझा करना आसान हो जाता है। परिणामस्वरूप, प्रकाशकों को अपनी सामग्री के अवैध संचलन को रोकने के लिए अतिरिक्त सावधानी बरतनी चाहिए।
- डिजिटल प्रकाशनों का निरंतर अद्यतनीकरण और रखरखाव एक अन्य कठिनाई है। डिजिटल सामग्री को अद्यतन और प्रासंगिक बनाए रखने के लिए, इसे अक्सर अद्यतन किया जाना चाहिए। इसमें काफी समय और संसाधन प्रतिबद्धता शामिल है।
- प्रकाशकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऑनलाइन उपलब्ध सामग्री की प्रचुरता को देखते हुए उनकी सामग्री दिलचस्प और आकर्षक हो। यह अद्वितीय, उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री का निर्माण करने पर जोर देता है जो शैक्षिक है।

9: शहरी नियोजन में प्रौद्योगिकी का उपयोग

- खुली जगहों, शहरों और निर्मित पर्यावरण को बनाने और बनाने की प्रक्रिया को शहरी नियोजन के रूप में जाना जाता है।
- चूँकि कस्बे और शहर अस्तित्व में थे, शहरी नियोजन का एक लंबा इतिहास रहा है। प्रारंभिक नगर नियोजन कई महत्वपूर्ण और मूलभूत घटकों पर केंद्रित था, जैसे कि किलेबंद इमारतें और गढ़, हालांकि समय के साथ इसमें काफी बदलाव आया है।
- शहरी नियोजन एक बहुआयामी प्रक्रिया है जिसमें भौतिक और सामाजिक अवसंरचना, उपयोगिता प्रणाली, संचार नेटवर्क, आपूर्ति श्रृंखला, और बहुत कुछ शामिल है। सिटी प्लानर्स, जिन्हें आमतौर पर शहरी योजनाकार कहा जाता है, शहरों को डिजाइन करते हैं और भविष्य में विस्तार और सुधार के लिए योजनाएं विकसित करते हैं।
- वर्तमान समय में, सूचना प्रौद्योगिकी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विस्फोटक विकास में कई शहर नियोजन कठिनाइयों को एक सार्वभौमिक मंच में एकीकृत करने और जटिलता चुनौतियों से निपटने के लिए बेहतर समाधान का मार्ग प्रशस्त करने की अधिक क्षमता है।
- शहरी योजनाकारों को सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग से विशेष रूप से GIS (भौगोलिक सूचना प्रणाली)-आधारित सॉफ्टवेयर के उपयोग से बहुत लाभ हुआ है।

शहरी नियोजन में सहायता के लिए समकालीन प्रौद्योगिकियां:

- शहरी नियोजक विभिन्न प्रकार के शहरी नियोजन अनुप्रयोगों को नियोजित कर सकते हैं जो आधुनिक तकनीक और खुले डेटा दोनों का उपयोग करके निवासियों और वाणिज्यिक उद्यमों के लिए पूर्ण और जीवंत वातावरण बनाते हैं।
- कई नियोजन उपकरण हैं जो शहरी डिजाइन की प्रक्रिया में सहायता करते हैं और शहर की आबादी के लिए आवश्यक स्थान बनाने में मदद करते हैं।
- समय के साथ शहरी नियोजन GIS से उत्तरोत्तर अधिक लाभान्वित हुआ है। कई अन्य GIS सॉफ्टवेयर ओपन सोर्स डेटा का उपयोग कर मुक्त और ओपन-सोर्स क्रॉस-प्लेटफॉर्म समाधान के रूप में उभरे हैं।
- यह पुराने मैपिंग और ड्राइंग टूल्स के साथ प्राप्त करने योग्य नहीं था, लेकिन GIS की सहायता से, उन्नत मैपिंग, स्थानीय डेटा के साथ मिलकर।
- सभी सरकारी कार्यालय रिकॉर्ड रखने के उद्देश्यों के लिए GIS का उपयोग करते हैं, जिसमें जल आपूर्ति और स्वच्छता प्रणाली के कवरेज को देखने के लिए संपत्ति मानचित्रण, जल आपूर्ति और सीवरेज नेटवर्क जैसी उपयोगिता सेवाएं और नगर निगम के ठोस अपशिष्ट प्रबंधन शामिल हैं ताकि प्रबंधन के लिए क्षेत्रों की पहचान की जा सके।
- परिवहन नियोजक सड़क नेटवर्क का अध्ययन करने, विभिन्न चौराहों पर संघर्ष स्थलों का पता लगाने, विभिन्न सड़क पदानुक्रम की पहचान करने आदि के लिए नेटवर्क विश्लेषण के लिए जीआईएस का भी उपयोग करते हैं।
- शहरी नियोजक क्लाउड प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके विशिष्ट महानगरीय क्षेत्रों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए एक डेटाबेस स्थापित कर सकते हैं।
- क्लाउड कंप्यूटिंग प्रौद्योगिकियां बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की योजना बनाने में भी सहायता कर सकती हैं।
- शहरी नियोजक इंटरनेट का उपयोग उन शहरों को बनाने के लिए कर सकते हैं जो दूर के श्रमिकों को समायोजित कर रहे हैं। नतीजतन, शहरी डिजाइनों में बेहतर परिवहन विकल्प हैं और यातायात की भीड़ कम हो गई है।

इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड अर्बन प्लानिंग

- भारत में, कुछ प्रमुख IoT डिवाइस पहले से ही उपयोग में हैं, जिनमें स्मार्ट स्ट्रीट लाइट शामिल हैं जो ऊर्जा बचाने के लिए स्वचालित रूप से बंद हो जाती हैं।
- स्व-प्रबंधन तकनीकों को उत्पन्न करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करके, शहरी नियोजक उन अवधारणाओं को डिजाइन कर सकते हैं जो पड़ोस और समुदायों के विकास पर अधिक जोर देते हुए शहर के बुनियादी ढांचे को मजबूत करते हैं।
- यह शहरों को अधिक हरित स्थान, वित्तीय स्वतंत्रता और वित्तीय स्थिरता प्रदान करने की अनुमति देता है। इन उदाहरणों से पता चलता है कि स्मार्ट सिटी योजनाएं बनाने और अधिक सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग कैसे किया जा सकता है।
- शहरी नियोजक प्रौद्योगिकी की बदौलत समुदायों के निर्माण पर अधिक ध्यान केंद्रित करने में सक्षम होंगे, जिससे नगरपालिका की स्वतंत्रता बढ़ेगी।
- नागरिक इस तरह टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल शहरों के निर्माण में अधिक सक्रिय रूप से भाग ले सकते हैं।

11 कुरुक्षेत्र जून 2023 : ग्रामीण शिल्प

1: ग्रामीण शिल्प की क्षमता

- भारत में शिल्प का एक लंबा इतिहास रहा है जो पिता से पुत्र को हस्तान्तरित होता है।
- भारतीय ग्रामीण इलाकों में कई आबादी आय के स्रोत के रूप में ग्रामीण शिल्प पर निर्भर करती है।

ग्रामीण शिल्प के लाभ

- वे उद्यमिता और कौशल विकास के अवसर प्रदान करते हैं, जिससे आय और रोजगार में वृद्धि होती है।
- वे ग्रामीण अर्थव्यवस्था में एक प्रमुख योगदान प्रदान करते हैं। यह ग्रामीण निवासियों के आय स्रोतों में विविधता लाने में भी मदद करता है।
- भारत अपने ग्रामीण शिल्प के लिए आगंतुकों के बीच लोकप्रिय है। वे ग्रामीण यात्रा को बढ़ावा देते हैं।
- यह स्थानीय कृषि और खाद्य उत्पादन में मदद करेगा, पारंपरिक कौशल को बढ़ावा देगा, और पर्यावरण-पर्यटन गतिविधियों को प्रोत्साहित करेगा, जो सभी सतत विकास का समर्थन करेंगे।
- यह भारत की समृद्ध संस्कृति और विरासत को संरक्षित करता है।
- यह ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में प्रवासन को और कम कर सकता है।
- वे "मेड इन इंडिया" विचारधारा और "आत्मनिर्भर भारत मूल्य" का समर्थन करते हैं।
- वे निर्यात का भी समर्थन करते हैं। उदाहरण के लिए, हस्तशिल्प का निर्यात 2019-20 में 19171 करोड़ रुपये से बढ़कर 2020-21 में 20151 करोड़ रुपये हो गया।

सरकार की पहल

- भारत के प्रत्येक जिले में पारंपरिक हस्तकला वस्तुओं को बढ़ावा देने के लिए, भारत सरकार ने एक जिला एक उत्पाद (ODOP) ग्रामीण विकास पहल शुरू की।
- यह रोजगार के अवसर पैदा करते हुए और ग्रामीण कलाकारों और व्यापार मालिकों की आय में वृद्धि करते हुए पारंपरिक शिल्प को संरक्षित करना चाहता है।
- सरकार ने पर्यटन योजना के साथ कपड़ा जोड़ने के लिए देश भर के आठ शिल्प गांवों को भी चुना है, जिसका उद्देश्य एक क्षेत्र में शिल्प और पर्यटन दोनों को बढ़ावा देना है।
- इसका उद्देश्य विस्तारित यात्रा और पर्यटन क्षेत्र के माध्यम से भारत की सांस्कृतिक विरासत को एकजुट करना है।
- इसके अतिरिक्त, ट्राइब्स इंडिया, भारतीय शिल्प परिषद, सरस (ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा संचालित), और राज्य एम्पोरियम जैसे समूहों/संगठनों ने जागरूकता बढ़ाई है, कुटीर उद्योग को अधिक से अधिक आउटलेट प्रदान किए हैं और वर्तमान मांगों को पूरा करने में उनकी सहायता की है।
- ग्रामीण शिल्प को उजागर करने के लिए सरकार द्वारा प्रायोजित अवसरों के कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं:
- सरस आजीविका मेला नामक एक वार्षिक उत्सव ग्रामीण आजीविका और वस्तुओं को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया जाता है।
- सूरजकुंड शिल्प मेला मनोरंजनकर्ताओं, कलाकारों और शिल्पकारों को अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए एक मंच प्रदान करता है।
- आदि महोत्सव: यह त्योहार आदिवासी संस्कृति की ऊर्जा का सम्मान करता है।
- निर्यात संवर्धन परिषद, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो और प्रदर्शनियों के माध्यम से सरकार हस्तशिल्प के निर्यात को भी बढ़ावा दे रही है।
- इसके अतिरिक्त, यह शिल्पकारों और शिल्पकारों को वित्तीय सहायता देता है।

एकता मॉल

- ग्रामीण शिल्प को बढ़ावा देने के लिए गुजरात के केवडिया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में एकता मॉल एक शानदार परियोजना है।
- यह क्षेत्रीय कलाकारों और शिल्पकारों को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने और अपने सामान की मार्केटिंग करने के लिए एक स्थान प्रदान करता है।
- यह पर्यटकों और आगंतुकों को आकर्षित करता है और स्थानीय शिल्पकारों के व्यवसायों का समर्थन करता है।
- अन्य स्थान भी इस कार्यनीति का उपयोग कर सकते हैं।

पोचमपल्ली गांव

- तेलंगाना में पोचमपल्ली को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा शीर्ष पर्यटन स्थल के रूप में चुना गया था।
- टोले में हथकरघा व्यवसाय विशेष रूप से पोचमपल्ली साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, जिसे इकत साड़ियों के रूप में भी जाना जाता है।
- 2018 में, पोचमपल्ली हैंडलूम पार्क बनाया गया था। यह आगंतुकों को आकर्षित करता है और उद्योग के विकास और विरासत पर प्रकाश डालता है।

RAO'S ACADEMY

2: अनुष्ठानिक और स्वदेशी परंपराओं के माध्यम से ग्रामीण शिल्प

- ग्रामीण कला और शिल्प स्थानीय रीति-रिवाजों में गहराई से शामिल हैं और इनका महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और धार्मिक मूल्य है।
- उनका एक व्यापक और आकर्षक अतीत है जो हजारों साल पहले का है। उदाहरण के लिए, सिंधु घाटी सभ्यता के मिट्टी के बर्तन, बुनाई और धातु से संबंधित वस्तुएं ग्रामीण शिल्प का सबसे पुराना संकेत हैं।
- मौर्य साम्राज्य के तहत वस्त्रों के प्रचार में विशिष्ट बुनाई और रंगाई कार्यशालाएं शामिल थीं।

छाया कठपुतली

- पारंपरिक छाया कठपुतली शैलियों जैसे थोलपावकूथु और थोलू बोम्मलता की जड़ें दक्षिण भारत में हैं।
- वे चमड़े की कठपुतलियों को बारीक रूप से तैयार और चित्रित करते हैं।
- राजस्थान सहित भारत के अन्य क्षेत्रों में कठपुतली परंपरा है जिसे कठपुतली के नाम से जाना जाता है।

खिलौने

- माना जाता है कि कोंडापल्ली के नाम से जाने जाने वाले खिलौने विजयनगर राजवंश से आए थे।
- कोंडापल्ली गुड़िया आर्यक्षत्रिय जाति द्वारा बनाई गई थी, जो अपनी लकड़ी की नक्काशी की प्रतिभा के लिए प्रसिद्ध थी।
- संक्रांति उत्सव के दौरान बोम्माला कोवुलु नामक एक शो बनाने के लिए कोंडापल्ली गुड़िया का उपयोग किया जाता है।

कला और शिल्प में अनुष्ठान और परंपराएं

- कई संस्कृतियाँ किसी भी प्रकार का शिल्पकार्य शुरू करने से पहले कार्य-पूर्व अनुष्ठानों का पालन करती हैं। ऐसा ही एक उदाहरण गुजरात में कच्छी कारीगरों द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला "गढ़वी" अनुष्ठान है, जो पारंपरिक धुनों को गुनगुनाते हुए और सुरक्षा और आशीर्वाद मांगते हुए अपनी कार्यशाला में दीपक जलाते हैं।
- बिहार में मधुबनी कलाकार केवल चंद्रमा के वैक्सिंग चरण के दौरान अपनी कृतियों का निर्माण करते हैं।
- आंध्र प्रदेश की कलमकारी कला के कलाकार शुरू होने से पहले व्रत रखते हैं और औपचारिक स्नान से खुद को शुद्ध करते हैं।
- ग्रामीण शिल्पों को पूजा स्थलों में भी महत्व दिया जाता है।
- चौरी बनाना सिख धर्म में एक महत्वपूर्ण कौशल है। इसका उपयोग गुरु ग्रंथ साहिब को पंखा करने के लिए आराधना और श्रद्धा के प्रतीक के रूप में किया जाता है।
- जैन धर्म में जटिल रंगोली को अत्यधिक महत्व दिया जाता है।

3: बाँस पर बड़ा दाँव लगाना

- बांस एक नवीकरणीय संसाधन है जिसका उपयोग पर्यावरण की दृष्टि से लाभकारी वस्तुओं के उत्पादन के लिए कई तरीकों से किया जा सकता है।

- यह रेखांकित किया जाना चाहिए कि विशिष्ट बांस के सामानों की उच्च मांग है, और एक स्थायी मूल्य श्रृंखला की गारंटी देने का एकमात्र तरीका उत्पादकों, शिल्पकारों, विपणक और निर्माताओं के बीच संबंधों को बढ़ाना है।

बांस: हरा सोना

- ब्रश, बर्तन, फर्नीचर, बायोमास छर्रों आदि सभी बांस से बने होते हैं।
- वे एल्यूमीनियम, लकड़ी और यहां तक कि प्लास्टिक के लिए लागत प्रभावी और पर्यावरण की दृष्टि से लाभकारी विकल्प हैं।
- इसके संरचनात्मक गुण बहुत अच्छे हैं और पर्यावरण पर इसका प्रभाव बहुत कम है। इसे भविष्य की निर्माण सामग्री माना जाता है।
- यह लकड़ी का एक मजबूत और उत्कृष्ट विकल्प है।

भारत का बांस धन

- लगभग 14 मिलियन हेक्टेयर में बिखरी हुई 136 से अधिक प्रजातियों के साथ, भारत दुनिया में बांस की दूसरी सबसे बड़ी समृद्धि वाला देश है।
- 2021 के लिए भारतीय वन सर्वेक्षण के अनुमानों के अनुसार, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र और ओडिशा सबसे अधिक बांस वाली भूमि वाले राज्य हैं।
- राष्ट्रीय बांस मिशन का अनुमान है कि भारत प्रति वर्ष 1 से 3 टन प्रति हेक्टेयर की दर से 14.6 मिलियन टन बांस का उत्पादन करता है।
- भारत 154 से अधिक देशों को बांस और बांस से संबंधित सामान निर्यात करता है।
- भारत ने 2020-21 (अप्रैल से नवंबर) में 107 मिलियन डॉलर मूल्य का बांस खरीदा और 140.47 मिलियन डॉलर मूल्य का बांस निर्यात किया।
- बांस भारत में शुद्ध आयातक है।
- भारत के सबसे पुराने पारंपरिक कुटीर व्यवसायों में से एक बांस का उत्पादन है। इसके अलावा, महिलाएं सूक्ष्म और लघु उद्यमों में मजदूर और शिल्पकार दोनों के रूप में काम करती हैं।

राष्ट्रीय बांस मिशन:

- 2018-19 से, कृषि और किसान कल्याण विभाग पुनर्गठित राष्ट्रीय बांस मिशन (NBM) चला रहा है।
- यह बाँस उद्योग के लिए संपूर्ण मूल्य श्रृंखला बनाने का इरादा रखता है, जिसमें उत्पादकों को ग्राहकों से जोड़ने के लिए वृक्षारोपण, संग्रह, प्रसंस्करण, विपणन, कौशल विकास और ब्रांड प्रचार शामिल है।
- राज्य बांस मिशनों और बांस प्रौद्योगिकी सहायता समूहों के माध्यम से इसे व्यवहार में लाया जाता है।
- पूर्वोत्तर क्षेत्र में बांस उद्योग के विकास को भी बाहरी सहायता प्राप्त करने वाली पहलों के लिए सरकार की मंजूरी मिली है।
- NBM ने बांस मूल्य श्रृंखला विकसित करने के लिए 416 उत्पाद विकास और प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित करने में मदद की है।
- 2018-19 से 2022-23 तक लगभग 12119 व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया है।
- इसके अलावा, महिलाओं के स्वयं सहायता समूह (SHG) जो परंपरागत रूप से बांस के उत्पाद बनाने में शामिल हैं, उन्हें कौशल वृद्धि और सूक्ष्म ऋण वितरण में प्राथमिकता दी जाती है।

S. No	States	Processing units for value addition of Bamboo	Management of Bamboo waste in primary processing units	Micro & Medium processing units	Total
1	Andhra Pradesh	-	-	-	-
2	Bihar	-	-	1	1
3	Chhattisgarh	4	-	-	4
4	Gujarat	-	-	-	-
5	Himachal Pradesh	1	-	4	5
6	Jharkhand	2	-	7	9
7	Karnataka	5	3	3	11
8	Kerala	-	-	-	-
9	Madhya Pradesh	16	11	52	79
10	Maharashtra	8	3	8	19
11	Orissa	3	1	22	26
12	Tamil Nadu	-	-	-	-
13	Telangana	-	-	-	-
14	Uttarakhand	1	1	7	9
15	Uttar Pradesh	-	-	5	5
16	Arunachal Pradesh	3	3	48	54
17	Assam	-	-	4	4
18	Manipur	3	-	2	5
19	Meghalaya	2	-	7	9
20	Mizoram	3	3	20	26
21	Nagaland	7	4	14	25
22	Sikkim	1	1	28	30
23	Tripura	22	5	65	92
Other Institutes					
1	BTSG, KFRI (Peechi)	-	1	1	2
2	BTSG, ICFRE (Dehradun)	-	-	-	-
3	BTSG, NECBDC/CBTC (Guwahati)	-	-	1	1

- NBM ने गैर-वन कृषि भूमि, सामुदायिक भूमि, कृषि योग्य बंजर भूमि आदि में बांस के रोपण में मदद की है।

4: जम्मू-कश्मीर हस्तशिल्प क्षेत्र की बदलती गतिशीलता

- शॉल, बुनाई, कालीन, कागज की लुगदी, और तांबे के बर्तन सहित पारंपरिक शिल्प जम्मू और कश्मीर में अच्छी तरह से जाने जाते हैं।
- हस्तशिल्प उद्योग लंबे समय से जम्मू-कश्मीर की संस्कृति और अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण घटक रहा है।
- सबसे महान और सबसे विशिष्ट शिल्पकार वहां पाए जा सकते हैं और वे बड़ी संख्या में रोजगार की संभावनाएं प्रदान करते हैं।
- यह उल्लेख किया जाना चाहिए कि क्योंकि वस्तुओं को अक्सर मानव हाथों द्वारा बनाया जाता है, हस्तकला उद्योग मानव कार्य पर निर्भर करता है।
- दुनिया भर में लोग कश्मीरी हस्तनिर्मित वस्तुओं की तारीफ कर रहे हैं।

पृष्ठभूमि

- शाही हमदान, एक फारसी सूफी संत, जो 14वीं शताब्दी में रहते थे, को जम्मू-कश्मीर में हस्तशिल्प के विकास में उल्लेखनीय रूप से प्रभावित करने के लिए जाना जाता है।
- वह कश्मीर गया और अपने साथ फारस के कई प्रतिभाशाली शिल्पकारों को ले गया जिन्होंने देशी कारीगरों को नई विधियों और शैलियों को सिखाया।
- पर्शिया आधुनिक कैलीग्राफी, वुडकार्विंग, कालीन बुनाई, धातु विज्ञान आदि तकनीकों के लिए प्रेरणा का स्रोत है।
- मुगल साम्राज्य के दौरान जम्मू-कश्मीर एक प्रमुख शॉल उत्पादन केंद्र था। महान कला और शिल्प संरक्षकों में मुगल शामिल थे।

जम्मू और कश्मीर में हस्तशिल्प उद्योग

- वैश्वीकरण का जम्मू और कश्मीर के हस्तकला और हथकरघा उद्योगों पर बड़ा प्रभाव है।
- दुनिया भर के दर्शकों के पास इसकी पहुंच है।

- शिल्पकारों की मदद के लिए सरकार कई तरह के कार्यक्रम चला रही है।
- यह क्षेत्र भी प्रौद्योगिकी का अधिक से अधिक उपयोग कर रहा है। अपना सामान बेचने और बड़े दर्शकों तक पहुंचने के लिए, कई शिल्पकार इंटरनेट मार्केटप्लेस का उपयोग करते हैं।
- क्षेत्र के समग्र विकास के लिए, सरकार ने "ऊन प्रसंस्करण, हथकरघा और हस्तशिल्प नीति 2020" का अनावरण किया।
- यह शिल्प को बढ़ावा देने, कच्चे संसाधनों की पहुंच, शिक्षा, बुनियादी ढांचे के विकास और विपणन के लिए एक बहुआयामी रणनीति को व्यवहार में लाने की इच्छा रखता है।
- इसके अतिरिक्त, यह शिल्पकारों की मदद के लिए कई नई योजनाओं की शुरुआत करता है।
- भौगोलिक संकेत (GI) अधिनियम को वास्तविक हस्तकला उत्पादों से सस्ते मशीन निर्मित नकली उत्पादों को रोकने के उद्देश्य से पेश किया गया था। यह उत्पादों की प्रामाणिकता को सत्यापित करने में मदद करता है।
- जम्मू-कश्मीर से पंजीकृत GI उत्पादों में शामिल कुछ नए उत्पादों में कश्मीर सोज़नी, कानी शॉल, कश्मीर वालनट वुड कार्विंग्स आदि शामिल हैं।

श्रीनगर

- कला और शिल्प के रचनात्मक शहरों के नेटवर्क में श्रीनगर भी शामिल है।
- उनकी सदस्यता ने इसे वैश्विक स्तर पर अपनी करतूत को विज्ञापित करने का मौका दिया है।
- हस्तकला पारिस्थितिकी तंत्र को बेहतर बनाने और बढ़ाने के लिए, हस्तकला विभाग ने शिल्प सफारी का भी शुभारंभ किया।
- विश्व स्तर पर, पर्यावरण के अनुकूल और टिकाऊ उत्पादों में बढ़ती रुचि के परिणामस्वरूप दस्तकारी वस्तुओं के लिए एक पुनर्जीवित सम्मान है।

ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म

- कहा जाता है कि ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के उद्भव का हस्तकला क्षेत्र पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है।
- वे व्यापक दर्शकों के सामने अपने काम को प्रदर्शित करने में बुनकरों और शिल्पकारों की सहायता करते हैं।
- इसके उपभोक्ता आधार और आय दोनों में विस्तार हुआ है।
- कई जाने-माने ई-कॉमर्स पोर्टल्स में हैंडीक्राफ्ट मॉल, ETC और अमेज़न हैंडमेड शामिल हैं।

5: आजीविका के लिए ग्रामीण शिल्प

- ऋग्वेद, रामायण, महाभारत और अन्य प्राचीन ग्रंथों में भारतीय कताई, बुनाई और महीन कपास और रेशम का वर्णन किया गया है।
- प्राचीन काल में भी, इन खनिजों का आदान-प्रदान किया जाता था और कई देशों को निर्यात किया जाता था।
- एक्ज़िम बैंक (2019) ने एक अध्ययन में कहा है कि भारत की रचनात्मक अर्थव्यवस्था में कला और शिल्प शामिल हैं।
- शिल्प एक नौकरी, पेशे या गतिविधि को संदर्भित करता है जो शारीरिक निपुणता या रचनात्मक क्षमताओं की मांग करता है। सौंदर्य की दृष्टि से सुन्दर होने के साथ-साथ ये उपयोगी भी हैं।

शिल्प का महत्व

- यह संपूर्ण ग्रामीण अर्थव्यवस्था का समर्थन करता है और कई व्यक्तियों को नौकरी देता है। कहा जाता है कि भारत में लगभग 200 मिलियन शिल्पकार मौजूद हैं।
- एक बार सही तरीके से प्रचार करने के बाद, वे विदेशी मुद्रा लाभ ला सकते हैं।
- यह विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त प्रदान कर सकता है।
- यह भारत की विशाल परंपरा और संस्कृति की रक्षा करता है।

चुनौतियां

- भारत की अर्थव्यवस्था में, हस्तशिल्प क्षेत्र प्राय: असंगठित है।
- बाजार की गतिशीलता का अनुमान लगाना कारीगरों के लिए कठिन है। उनके पास अपने सोशल मीडिया एक्सपोजर को अधिकतम करने के लिए विशेषज्ञता की कमी है।
- ग्रामीण क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी अपनाने का स्तर निम्न है।
- अन्य महत्वपूर्ण समस्याओं में कमजोर संस्थागत नींव और धन की कमी शामिल है।
- भले ही श्रमिकों की क्षमताएं अधिक हों, वेतन अन्य उद्योगों में आय में वृद्धि के साथ तालमेल नहीं बिठा पाता है।
- चौथी अखिल भारतीय हथकरघा जनगणना 2019-20 से पता चलता है कि 66.3% बुनकर परिवारों की मासिक आय 5000 रुपये से कम है।

हस्तकला उद्योग को बढ़ावा देने के लिए हस्तक्षेप

- कपड़ा मंत्रालय का कार्यालय विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) व्यापक हस्तशिल्प क्लस्टर विकास योजना और राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम सहित कार्यक्रमों का संचालन करता है।
- अम्बेडकर हस्तशिल्प विकास योजना के तहत, कारीगरों को सीधे लाभ, प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचे के लिए समर्थन, विपणन सहायता आदि देने के लिए जुटाया जाता है।
- कपड़ा मंत्रालय उत्कृष्ट कारीगरों को उनकी प्रतिभा के लिए "शिल्प गुरु" पुरस्कार और राष्ट्रीय सम्मान प्रदान करता है।
- ट्राइफेड जनजातीय मामलों के मंत्रालय के तहत एक राष्ट्रीय शीर्ष निकाय है। इसका मुख्य उद्देश्य आदिवासी हस्तशिल्प और हथकरघा उत्पादों का खुदरा विपणन विकास है।
- इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज (INTACH) जैसे कई NGO समुदाय आधारित उद्यम विकसित करने के लिए शिल्प समूहों के साथ काम करते हैं।

6: एक जनपद एक उत्पाद के माध्यम से ग्रामीण शिल्प को बढ़ावा देना

- भारत में समावेशी विकास, उत्पादकता और संपत्ति के लिए इन-सीटू विकास और उद्यमशीलता के माहौल का निर्माण महत्वपूर्ण है।
- वैश्विक वाणिज्य में भारत के हिस्से का विस्तार करने के लिए, भारत सरकार अपनी विदेश वाणिज्य नीति 2023 में निर्यात केंद्रों के रूप में जिलों पर आधारित नए संभावित निर्यात स्थानों पर जोर देती है।

O.D.O.P

- एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा संतुलित क्षेत्रीय विकास की योजना के आधार पर लागू किया गया था।
- एक गांव एक उत्पाद (OVOP), एक जापानी कंपनी की विकास अवधारणा, इस विचार द्वारा संवर्धित की गई है।
- इसे पहली बार 1979 में उपलब्ध कराया गया था।
- OVOP क्षेत्रीय शिल्पकारों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए स्थानीय रूप से उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं को बढ़ावा देने का प्रयास करता है।
- इसके अतिरिक्त, इसका उद्देश्य राष्ट्र निर्माण में क्षेत्रीय योगदान को सुविधाजनक बनाना है।
- पारंपरिक ज्ञान को संरक्षित करने के लिए, ओडीओपी का एकमात्र लक्ष्य विलुप्त रचनात्मक वस्तुओं और प्रक्रियाओं का पुनर्निर्माण और पुनर्जीवन करना है।
- यह एक ऐसा वातावरण प्रदान करने का प्रयास करता है जो कला और शिल्प वस्तुओं के लिए टिकाऊ हो।
- 2018 में उत्तर प्रदेश में ODOP की शुरुआत हुई। राज्य में इसकी सफलता के बाद इसे भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पेश किया गया था।
- इसमें कृषि और गैर-कृषि सामान, जैसे कपड़ा, हस्तशिल्प, हथकरघा, खाद्य पदार्थ, अनाज और अन्य सामान शामिल हैं।
- यह न केवल कारीगरों/शिल्पकारों की भारत के बाहर के बाजारों तक पहुंच को सुविधाजनक बनाएगा, बल्कि यह उन्हें अपनी प्रतिभा को आकर्षक व्यवसायों में बदलने में भी सक्षम करेगा।
- विदेश व्यापार महानिदेशालय के 'जिला निर्यात हब' (DEH) को ODOP के साथ मिला दिया गया है।

चुनौतियां

- खराब संस्थागत व्यवस्था
- पैसों की कमी
- मार्केटिंग के लिए अक्षम लिंकेज
- प्रौद्योगिकी का कम अंगीकरण
- विपणन कौशल की कमी

Art and Crafts (Products)	Main Places of Production (City / District / State)
Zari (Zardozi Embroidery)	Surat, Bareilly, Varanasi, Agra, Hyderabad, Lucknow, Vadodara, Lathur, Jaipur, Barmer
Carpet	Bhadohi, Varanasi, Mirzapur, Agra, Jaipur, Bikaner, Kashmir, Panipat, Gwalior, Elluru. In states like West Bengal, Uttarakhand, Karnataka, Andhra Pradesh
Rugs and Durries	Agra, Bhadoi, Mirzapur, Jaipur, Panipat, Kashmir, Bhavani, Navalgund, Warangal, Jaisalmer, Barmer. In states Uttar Pradesh, Rajasthan, Haryana, Tamil Nadu, Karnataka, Andhra Pradesh
Textile (Handloom)	Bahraich, Bhuj, Karimnagar, Patan, Varanasi, Nawan, Shaher, Boudh
Textile (Hand Embroidery)	Lucknow, Barabanki, Unnao, Sitapur, Rae Bareli, Hardoi, Amethi
Textile (Hand Printing)	Hyderabad, Machalipattanam, Varanasi, Farrukabad, Bagh, Behrongarh, Indore, Mandsar, Burhanpur, Ahmedabad, Rajkot, Kutch, Bagru, Chittroli, Sanganer, Jaipur, Jodhpur. In states like Andhra Pradesh, Uttar Pradesh, Odisha, Madhya Pradesh, Gujarat, Maharashtra, Rajasthan
Wood (Carving)	Bhopal, Nagpur, Chennai, Madurai, Mysore, Kashmir. State like Manipur
Wood Inlay	Mysore, Bengaluru, Bijnor, Saharanpur. In states like Punjab, Uttar Pradesh, Karnataka
Wood (Turning & Lacquer Ware)	Etikoppaka, Ernakulam, Chennapatna, Chitrakoot, Davangere, Medak, Sankheda, Varanasi
Stone Cravings	Agra, Bhubaneswar, Puri, Jaisalmer, Cuttack, Cuddapah, Bankura, Kanchipuram, Patna, Mysore, Rajkot, Gwalior, Puducherry, Mahanandi
Stone Inlay	Jodhpur, Jaisalmer, Agra. State like Rajasthan
Cane and Bamboo Crafts	Lakhimpur, Bongaigaon, Guwahati, Agartala, Nelaghar. In states like Assam, West Bengal, Odisha, Arunachal Pradesh, Manipur, Arunachal Pradesh, Tripura
Pottery and Clay Objects	Asharikandi, Bulandshahar, Bhadrawati, Nizamabad, Pune, Chandrapur. State like Assam
Terracotta	Several parts of India like Pottery
Horn and Bone Work	Lucknow, Moradabad, Sambhal, Sarai Tarin, Honawar, Gajapati, Jodhpur, Thiruvananthapuram. In states like Uttar Pradesh, Odisha, Rajasthan, Kerala
Folk Paintings	In states like Odisha, West Bengal, Madhya Pradesh, Rajasthan, Bihar, Gujarat, Andhra Pradesh
Conch-Shell Crafts	In states like West Bengal, Tamil Nadu
Theatre, Costumes and Puppet	In states like Odisha, Karnataka, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Bihar, Kerala

7: हथकरघा और हस्तशिल्प क्षेत्र का संवर्धन और विकास

- भारत ने विभिन्न संस्कृतियों को आत्मसात किया है और एक मजबूत और अधिक लचीला देश के रूप में विकसित हुआ है।
- कला के विभिन्न रूप कई कारकों के परिणामस्वरूप विकसित हुए हैं जैसे:
  - कच्चे माल की उपलब्धता
  - विरासत कौशल हस्तांतरण
  - पर्यावरण
  - स्थानीय कृषि परंपराएं
  - धार्मिक विश्वास

महत्वपूर्ण तथ्य

- भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रवेश ने कपड़ा और हस्तशिल्प उद्योगों को काफी नुकसान पहुंचाया।
- ब्रिटिश काल के दौरान, कला और शिल्प उत्पादन में गिरावट आई थी।
- केवल स्थानीय जरूरतों और समर्थन वाले क्षेत्र ही इसका समर्थन कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, शाही परिवारों ने पीतल के बर्तनों र चांदी के महीन आभूषणों जैसे कीमती आभूषणों के उपयोग को प्रायोजित किया।
- परिवारों में कुछ कलाओं को संरक्षित करने का जुनून था। उदाहरण के लिए, पाटन, गुजरात में साल्वी परिवार द्वारा पटोला साड़ी बुनाई परंपरा को बनाए रखा गया था।
- सिल्क मार्क और हैंडलूम मार्क जैसे कई प्रयास हैं, जो गुणवत्ता प्रमाणन संकेतक के रूप में काम करते हैं। भौगोलिक संकेत लेबलिंग के उपयोग के माध्यम से, वे शिल्प की पहचान और मूल स्थान की रक्षा भी करते हैं।

YOUR SUCCESS OUR PRIORITY
RAO'S ACADEMY

RAO'S ACADEMY

for Competitive Exams

BHOPAL | INDORE

DR. M. MOHAN RAO
IAS (Retd)
CHAIRMAN

M. ARUNA MOHAN RAO
IPS (Retd)
DIRECTOR (ACADEMICS)

YOUR SUCCESS OUR PRIORITY

RAO'S ACADEMY
for Competitive Exams
(A unit of **RACE**)

Coming Soon in INDORE

EMAIL: office@raosacademy.in | WEBSITE: www.raosacademy.in

Bhopal Branch: Plot No. 132, Near Pragati Petrol Pump, Zone II, M.P. Nagar, Bhopal(M.P.) 462011
95222 05553 , 95222 05554

Indore Branch: 10,Vishnupuri, A.B.Road, Near Medi-Square Hospital Bhawar Kuwar Square, Indore (M.P.)-452001
95222 05551, 95222 05552

" विद्याधनं सर्व धनं प्रधानम् "

YOUR SUCCESS OUR PRIORITY

RAO'S ACADEMY
for Competitive Exams
(A unit of **RACE**)

"YOUR SUCCESS OUR PRIORITY
आपकी सफलता हमारी प्राथमिकता"

BHOPAL CENTRE

Plot No. 132,
Near Pragati Petrol Pump,
Zone II, Maharana Pratap
Nagar, Bhopal (M.P) - 462011

Contact:-
95222-05553, 95222-05554

INDORE CENTRE

10, Vishnupuri Colony,
Bhanwarkua Square,
A.B. Road, Near Medi-Square
Hospital, Indore - 452001

Contact:-
95222-05551, 95222-05552

Email Id:- office@raosacademy.in

Website:- www.raosacademy.in

raosacademybhopal | raosacademyforcompetitiveexams | raosacademyforcompetitiveexams